



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 1—खण्ड 1

PART 1—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 10, 2012/चैत्र 21, 1934

No. 95]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 10, 2012/CHAITRA 21, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2012

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जन.गण. और इण्डोनेशिया के मूल के या वहां से निर्यातित “बांस के फाइबर को छोड़कर” विस्कोस स्टेपल फाइबर” के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच-के संबंध में निर्णयोपरांत मौखिक सुनवाई-अंतिम जांच परिणाम।

आदेश सं. 14/6/2009-डीजीएडी.—माननीय न्यायाधिकरण (सेस्टेट) के दिनांक 11 अगस्त, 2011 के अंतिम आदेश सं. ए डी/31-51/2011-ए डी के अनुसरण में उपर्युक्त विषय पर 14 दिसम्बर, 2011 को निर्णयोपरांत सुनवाई आयोजित की गई थी जिसमें उन सभी हितबद्ध पक्षकारों से भाग लेने का अनुरोध किया गया था। जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग लिया था।

2. उक्त सुनवाई के संपन्न होने के बाद जिन हितबद्ध पक्षकारों ने अपने मौखिक अनुरोध किए थे उन्हें पाटनरोधी नियमों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर लिखित अनुरोध दायर करने की सलाह दी गई थी। तत्पश्चात उन्हें उत्तर दायर करने की सलाह भी दी गई थी।

3. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर लिखित अनुरोधों और उत्तरों पर संगत समझी गई सीमा तक इस आदेश में विधिवत विचार किया गया है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की है :—

घरेलू उद्योग की ओर से किए गए लिखित अनुरोध

4. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :—

विचारधीन उत्पाद और समान वस्तु

स्टेपल फाइबर" के रूप में वर्णित है और इसे समान बाजारों में "रेयन फाइबर" के नाम से भी जाना जाता है । विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क शीर्ष 5504.10.00 के अंतर्गत वर्गीकृत है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है ।

6. समान वस्तु के बारे में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार उपबंध है :-

"समान वस्तु" का अर्थ एक ऐसी वस्तु है जो भारत में पाटन के लिए जांच के अधीन वस्तु के समान हो या प्रत्येक दृष्टि से उसके जैसी हो अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य ऐसी वस्तु जो यद्यपि प्रत्येक दृष्टि से समान न हो तब भी उसमें जांचाधीन वस्तु से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं हो;

7. प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई सूचना से यह पर्याप्ततः स्पष्ट हो जाता है कि घरेलू समान वस्तु और आयातित संबद्ध वस्तु में कोई खास अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय है । किसी भी विरोधी हितबद्ध पक्षकार ने इस बारे में कोई आपत्ति नहीं की है । इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियमों के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जाना चाहिए ।

घरेलू उद्योग का आधार और क्षेत्र

8. यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता आधार संबंधी अपेक्षा को पूरा नहीं करता है और ग्रासिम कानून के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग नहीं है ।

9. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. आधार संबंधी अपेक्षा को पूरा करती है और वह नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है । इस संबंध में निम्नलिखित संगत है ।

(क) नियम 5(3) के संगत भाग में निम्नानुसार उपबंध है :-

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी उप नियम (1) के अंतर्गत किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए तब तक कोई जांच शुरू नहीं करेंगे जब तक कि वह-

(क) समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों द्वारा व्यक्त आवेदन के समर्थन या विरोध के सतर की जांच के आधार पर यह निर्धारित न करें कि उक्त आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया है।

परंतु उस स्थिति में कोई जांच शुरू नहीं की जाएगी यदि स्पष्ट रूप से आवेदन का समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन के पच्चीस प्रतिशत से कम बनता हो, और

(ख) आवेदन में दिए गए साक्ष्य की सत्यता और पर्याप्तता की जांच न करें और स्वयं को इस बात से संतुष्ट न करें कि निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त साक्ष्य है।

(i) पाटन,

(ii) क्षति, जहां लागू हो; और

(iii) जहां लागू हो ऐसे पाटित आयातों तथा आरोपित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजनार्थ आवेदन को उस स्थिति में घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया समझा जाएगा यदि इसका समर्थन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया हो जिनका सामूहिक उत्पादन आवेदन का समर्थन या विरोध, जैसा भी मामला हो, करने वाले घरेलू उद्योग के उक्त भाग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन के पच्चीस प्रतिशत से अधिक बनता हो।

ख. यह देखा जा सकेगा कि कि प्राधिकारी उस स्थिति में जांच को शुरू करने में न्यायोचित हैं यदि याचिका का समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन उक्त उत्पादन के 25% से अधिक बनता है बशर्ते आवेदन का समर्थन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया हो जिनका सामूहिक उत्पादन आवेदन का समर्थन या विरोध, जैसा भी मामला हो, करने वाले घरेलू उद्योग के उक्त भाग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन के पच्चीस प्रतिशत से अधिक बनता हो। वर्तमान मामले में स्पष्ट तौर पर याचिकाकर्ता देश में उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है और इसलिए नियम 5(3) की अपेक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकमात्र मुद्दा जिस पर विचार किया जाना है वह यह है कि क्या विदेशी उत्पादकों के साथ याचिकाकर्ता का संबंध ऐसा है जिससे याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के रूप में विचार किए जाने का अपात्र बन जाता हो। इस संबंध में निम्नलिखित संगत हैं।

ग. जांच की शुरुआत के समय नियम 2(ख) निम्नानुसार था :-

(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे

उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा ।

घ. प्रारंभिक जांच परिणाम के बाद और अंतिम जांच परिणाम से पूर्व नियम 2(ख) में संशोधन किया गया था । संशोधित नियम निम्नानुसार है :-

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ केवल शेष उत्पादकों के उल्लेख के रूप में निकाला जाएगा "।

ङ इस नियम में 1 दिसंबर, 2011 को आगे और संशोधन किया गया है । वर्तमान नियम निम्नानुसार है :-

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के उल्लेख के रूप में निकाला जाएगा "।

च. इस प्रकार ऐसी स्थिति में जब नियम 2(ख) के अंतर्गत परिभाषा जांच की शुरुआत, अंतिम जांच परिणाम और इस समय अलग-अलग थी, प्राधिकारी के लिए सर्वप्रथम इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या बजट 2010 में यथासंशोधित नियम 2(ख) ऐसे संशोधन से पूर्व शुरू की गई जांचों पर लागू होगा, खासकर तब जब नियमों में अब आगे और संशोधन किया गया हो । अंतिम जांच परिणाम के समय प्रचलित नियम वह नियम नहीं है जो जांच की शुरुआत के समय या अब जब निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच परिणाम दर्ज करेंगे, प्रचलित था ।

छ. जाहिर तौर पर जांच की शुरुआत के समय लागू नियम 2(ख) में स्पष्ट तौर पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास कुछेक स्थितियों में घरेलू उत्पादक को पात्र या अपात्र मानने के विवेकाधिकार का प्रावधान है । 2(ख) के अंतर्गत साधारण नियम यह है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी समग्र घरेलू उत्पादकों पर घरेलू उद्योग के रूप में विचार करेंगे । नियम 2(ख) में ऐसी केवल कुछेक स्थितियां ही दी गई हैं जिनमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि ऐसे घरेलू उत्पादकों जो स्वयं उक्त उत्पाद के आयातक हैं या उक्त उत्पाद के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हैं, को अपात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए ।

ज. यह मानते हुए यद्यपि, उसे स्वीकार न करते हुए कि प्राधिकारी के लिए वर्तमान मामले में बजट, 2010 के दौरान यथासंशोधित नियम 2(ख) को लागू करना अपेक्षित है, घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि किसी भी नियम पर विचार करते हुए ग्रासिक इंडस्ट्रीज को पात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए ।

झ. नियम 2(ख) में 2 प्रकार के अपवर्जनों का उपबंध किया गया है जिनमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या ऐसे घरेलू उत्पादकों को पात्र या अपात्र घरेलू उत्पादक माना जाना चाहिए । दोनों स्थितियां निम्नानुसार हैं :-

- i. घरेलू उत्पादक स्वयं विचाराधीन उत्पाद का आयातक है;
- ii. घरेलू उत्पादक पाटित उत्पाद के किसी निर्यातक या किसी आयातक से संबंधित है ।

ञ. निर्विवाद रूप से ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने उत्पाद का आयात नहीं किया है और इसलिए वर्तमान मामले में पहली स्थिति लागू नहीं होती है ।

ट. जहां तक दूसरी स्थिति का संबंध है, याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि नियम 2(ख) में ऐसे घरेलू उत्पादकों में भेद या अंतर नहीं किया गया है जो ऐसे घरेलू उत्पादकों जो आयातकों से संबंधित हो सकते हैं, के साथ निर्यातकों से संबंधित हो सकते हैं । सुनवाई के समय यह कहते हुए अधिक जोर दिया गया था कि घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित निर्णय किसी निर्यातक से संबंध की स्थिति से संबंधित नहीं है और घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित सभी मामले ऐसी स्थितियों से संबंधित हैं जिनमें घरेलू उत्पादक आयातकों से संबंधित हैं । याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि नियमों में भेद नहीं किया गया है और उनमें ऐसे घरेलू उत्पादकों के लिए अलग स्थिति नहीं दी गई है जो आयातकों से संबंधित हो सकने वाले घरेलू उत्पादकों की स्थिति से भिन्न निर्यातकों से संबंधित हो सकते हैं । ऐसा मामला होने के कारण ऐसे निर्णय समान रूप से संगत हैं और वर्तमान मामले में लागू होते हैं जिनमें घरेलू उत्पादक आयातकों से संबंधित हो सकते हैं ।

ठ. याचिकाकर्ता ने जांच की शुरुआत के समय संबंध को स्वीकार किया था । याचिकाकर्ता ने पूर्व में किए गए अनुरोधों के विकल्प के रूप में यह अनुरोध किया है कि प्राधिकारी इस बात पर विचार करें कि क्या सभी याचिकाकर्ता निर्यातक से संबंधित हैं । सुनवाई के समय इस बात पर जोर दिया गया था कि विदेशी उत्पादकों और घरेलू उद्योग के बीच संबंध के स्वरूप की पूर्ण जानकारी प्राधिकारी को थी । इसलिए प्राधिकारी को जांच की शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए थी । तथापि, घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि प्राधिकारी ने इस मुद्दे पर विस्तृत जांच परिणाम के बाद ही स्वयं यह स्थापित किया कि किसी मामले में स्थिति जांच की शुरुआत के समय अलग नहीं हो सकती । बहरहाल प्राधिकारी के रिकॉर्ड में समस्त संगत तथ्यपरक सूचना उपलब्ध है जिसपर भरोसा किया जाता है ।

ड **विवेकाधिकार के प्रयोग हेतु अपनाए गए मापदंड-** यह तर्क दिया गया है कि विवेकाधिकार के प्रयोग हेतु प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मापदंड किसी कानूनी आधार से रहित हैं और इस विषय पर निर्धारित कानून के प्रतिकूल हैं। याचिकाकर्ता इस बात का कड़ा विरोध करता है और असहमति व्यक्त करता है। जहां तक इस विषय पर आरोपित "निर्धारित कानून" का संबंध है, ऐसी कोई सामग्री प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं की गई है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा केवल कथनों पर अपने मामले को आधारित करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मापदंडों का संबंध है, याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी विषय पर कई प्रमुख पाठ्यपुस्तकों, यूरोपीय आयोग के कई निर्णयों और निर्दिष्ट प्राधिकारी के कई निर्णयों से संगत उद्धरण लेते हुए विस्तृत सामग्री प्रदान की है। याचिकाकर्ता ने ऐसी स्थितियों से संबंधित कई मामले उपलब्ध कराए हैं जिनमें याचिकाकर्ता किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित था या वह स्वयं संबद्ध उत्पाद का आयातक था।

ढ. उभरते हुए न्याय शास्त्र का संक्षेप में उल्लेख निम्नानुसार है :-

- i. क्या संबद्ध पक्षकारों का व्यवहार असंबद्ध पक्षकारों की तुलना में विशिष्ट और भिन्न है।
- ii. क्या ऐसा कोई साक्ष्य है जिससे यह पता चले कि ऐसे संबद्ध उत्पादक ने भारतीय बाजार में पाटन शुरू किया है या उसकी मात्रा में वृद्धि की है।
- iii. क्या संबद्ध घरेलू उत्पादक को पाटन के प्रभाव से बचाया गया है या इसका अनुचित लाभ दिया गया है।
- iv. क्या संबद्ध घरेलू उत्पादक भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में बाधा डालना चाहता है।
- v. क्या यह मामला स्वतः स्फूर्त क्षति का है।
- vi. किसी मामले में हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए निर्यात, यदि कोई हो, का प्रभाव। क्या ऐसे संबद्ध पक्षकार ने जांच अवधि के दौरान भारत को उत्पाद का निर्यात किया था। यदि हां, तो क्षति के दावों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है। यदि नहीं तो क्या उसके अपवर्जन को अभी भी न्यायोचित ठहराने के लिए कोई अन्य आधार है। यदि संबद्ध पक्षकार ने भी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है तो निम्नलिखित का भी मूल्यांकन करना जरूरी है:

- ऐसे संबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा;
- संबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए ऐसे निर्यातों का प्रयोजन;
- क्या यह प्रदर्शित करने का कोई साक्ष्य है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए ऐसे निर्यातों के कारण हुई थी।

- क्या संबद्ध घरेलू उत्पादक का सामान्य जोड़ संबद्ध वस्तु के उत्पादन पर था अथवा क्या उक्त सामान्य जोड़ धीरे-धीरे या सतत रूप से आयातों की ओर चला गया ।
- क्या ऐसे संबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा इतनी अधिक थी कि संबद्ध निर्यातक ने धीरे-धीरे या निरंतर रूप से असंबद्ध घरेलू उत्पादक के बाजार को विस्थापित कर दिया ।
- ऐसा कोई अन्य कारक जिसे जांच की कार्यवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी की जानकारी में लाया गया हो ।

ण. चीन के संबद्ध उत्पादकों द्वारा निर्यात - यह आरोप लगाया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी यह समझने में विफल रहे हैं कि जांच अवधि को 6 माह तक सीमित रखने के कारणों में से एक कारण यह हो सकता है कि संबद्ध पक्षकार ने जुलाई, 2008 से पूर्व भारत को नगण्य निर्यातों से अधिक निर्यात किए हैं । तथापि, याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि -

- i. आवेदन प्रपत्र में वस्तुतः ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके के बारे में काफी तर्क दिए गए हैं और अभी भी यह तर्क दिया गया है कि चीन के संबद्ध उत्पादकों द्वारा ऐसा कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है भले ही ऐसी कोई निर्धारित अपेक्षा न हो ।
 - ii. आवेदक के लिए ऐसी संगत सूचना प्रदान करना आपेक्षित है जिसे प्रदान किया गया है और जिसकी सत्यता प्रमाणित की गई है । अब हितबद्ध पक्षकार को यह सिद्ध करना है कि घरेलू उद्योग के दावे गलत हैं ।
 - iii. चीन के उत्पादकों ने वस्तुतः एक प्रमाण पत्र केवल उस अनावश्यक शंका को दूर करने के लिए दिया है जिसे उत्पन्न करने का प्रयास किया गया था ।
 - iv. याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि यह मात्र कल्पना है कि याचिकाकर्ता द्वारा इस वजह से 6 माह की जांच अवधि का प्रस्ताव किया गया है । प्राधिकारी द्वारा निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली में न केवल जांच अवधि के लिए अपितु पूर्ववर्ती वर्षों के लिए भी सूचना देनी अपेक्षित होती है । निर्यातक द्वारा दायर और प्राधिकारी द्वारा सत्यापित सूचना में इस बात की स्पष्ट पुष्टि की गई है कि संबद्ध पक्षकार द्वारा जांच अवधि से पूर्व किए गए निर्यात नगण्य से अधिक नहीं थे ।
10. यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से एसोसिएशन ऑफ़ मैन मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ़ इंडिया द्वारा दायर किया गया था । मै. ग्रासिम इंड लि. भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और उसने इस संबंध में क्षति तथा लागत के बारे में संगत सूचना प्रदान की है । भारत में समान वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है । प्राधिकारी ने जांच परिणाम में यह सही निर्धारित किया है कि मै. ग्रासिम इंड लि. का उत्पादन

घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है क्योंकि मै. ग्रासिम इंड लि. का उत्पादन भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक है ।

11. आवेदक की चीन जन.गण. और इंडोनेशिया में संबद्ध कंपनियां हैं जो इस उत्पाद का उत्पादन व बिक्री करती हैं अर्थात् बिरला जिगवाई फाइबर्स कंपनी लिमिटेड, चीन तथा पी टी इंडो भारत रेयान, इंडोनेशिया । इन सत्ताओं के संबंध का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

क्र.सं.	सत्ता का नाम	समान निदेशक
1	ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि.	श्री कुमार मंगलम बिरला श्री राजश्री बिरला श्री एस.के. जैन
2	बिरला जिगवाई फाइबर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.	श्री एस.के. जैन
3	पी टी इंडो भारत रेयान, इंडोनेशिया	श्री कुमार मंगलम बिरला श्री राजश्री बिरला श्री एस.के. जैन

12. चूंकि याचिकाकर्ता ने स्वयं यह बताया था कि ये कंपनियां संबद्ध देशों में संबद्ध उत्पादक हैं, इसलिए वह आधार अप्रासंगिक बन गया है जिसके अनुसार ये कंपनियां संबंधित हैं । इसके अलावा, नियमों में "निर्यातकों" के संबंध में और न केवल "उत्पादकों" के संबंध में सूचना अपेक्षित है । ये उत्पादक मोटे तौर पर अपने उत्पादों की बिक्री या तो संबंधित घरेलू बाजार में कर रहे हैं या उनका निर्यात तीसरे देशों को कर रहे हैं । सामान्यतः भारत को कोई निर्यात नहीं हुआ है । खासकर चीन की कंपनी ने भारत को उत्पाद का निर्यात नहीं किया है जबकि इंडोनेशियाई कंपनी ने भारत को अल्प मात्रा में निर्यात किया है जो आयातों के 3% से कम है और भारतीय उत्पादन के संदर्भ में नगण्य है । निर्यात इसलिए किए गए हैं क्योंकि याचिकाकर्ता के ग्राहक शुल्क छूट स्कीमों के अंतर्गत आयातित सामग्री चाहते थे । संगत साक्ष्य गोपनीय आधार पर ¹ निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध कराया गया है । चूंकि इन आयातों की मात्रा अति अल्प है, इसलिए प्राधिकारी ने इस बात पर सही ढंग से विचार किया है कि याचिकाकर्ता को नियमों के अंतर्गत अपात्र नहीं माना जाना चाहिए ।

13. प्राधिकारी का यह अभिमत सही है कि आवेदक ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) की अपेक्षाओं को संतुष्ट किया है, अतः मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि. को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" माना जा रहा है ।

¹ घरेलू बाजार के अन्य ग्राहकों ने यह स्वीकार किया है कि अधिम लाइसेंस श्रेणी के अंतर्गत बी एस एफ के आयात लगभग 90% हैं ।

14. वर्तमान मामले में विचारार्थ एवं निर्धारणार्थ एक मुद्दा यह है कि ऐसी स्थिति में जब उत्पादक निर्यातक देशों में से एक देश के निर्यातक से संबंधित है, तो क्या उस उत्पादक को पात्र घरेलू उद्योग समझा जाए। अन्य शब्दों में क्या नियम 2(ख) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी को विवेकाधिकार है और यदि हां तो उस विवेकाधिकार को किस प्रकार लागू किया जाना अपेक्षित है। यद्यपि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस संबंध में दी गई चुनौती के मदेनजर तथ्यों और कानून पर विधिवत विचार करने के बाद प्रारंभिक जांच परिणाम तथा अंतिम जांच परिणाम जारी किए हैं। तथापि, याचिकाकर्ता ने विभिन्न पाठ्यपुस्तकों, अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों की पद्धतियों तथा अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा दिए गए निर्णयों का उल्लेख करते हुए इस मुद्दे पर व्यापक अनुसंधान किया है। इन पर निम्नानुसार चर्चा की गई है :-

क. यह स्मरणीय है कि पाटनरोधी नियमावली में वर्ष 1999 में संशोधन किया गया था, जिसके संशोधनों में से एक संशोधन घरेलू उद्योग की परिभाषा से संबंधित था। इस संशोधन से पूर्व नियम 2(ख) निम्नानुसार था :-

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा।

ख. संशोधन के बाद यह नियम निम्नानुसार है :-

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग माना जा सकता है।

ग. प्रारंभिक जांच परिणाम के बाद और अंतिम जांच परिणाम से पूर्व नियम 2(ख) में संशोधन किया गया था। संशोधित नियम निम्नानुसार है :-

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ केवल शेष उत्पादकों के उल्लेख के रूप में निकाला जाएगा।"

घ. इस नियम में 1 दिसंबर, 2011 को आगे और संशोधन किया गया है । वर्तमान नियम निम्नानुसार है :-

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के उल्लेख के रूप में निकाला जाएगा ।

ङ यह स्पष्ट है कि नियम में संशोधन गुण-दोष के आधार पर यह निर्णय लेने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान करने की दृष्टि से किया गया था कि क्या ऐसी कंपनी जो विचाराधीन उत्पाद का आयात कर रही है अथवा जो किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित है, को घरेलू उद्योग के निर्धारण हेतु शामिल किया जाना चाहिए या उसे अलग रखा जाना चाहिए ।

च. नियम 2(ख) के अंतर्गत सभी प्रकार के आयातों को अपवर्जित नहीं किया गया है । अतः नियम 2(ख) में संशोधन यह निर्णय लेने के लिए प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य से किया गया है कि क्या ऐसी किसी कंपनी को शामिल किया जाए या अलग रखा जाए जिसने स्वयं आरोपित पाटित उत्पाद का आयात किया है अथवा जो संबद्ध वस्तु के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित है । इस प्रकार के किसी विवेकाधिकार का प्रयोग वर्तमान मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसी ढंग से किया गया है । इस संबंध में निम्नलिखित संगत हैं :-

(क) पाठ्य पुस्तकों में स्पष्ट किए गए अनुसार उभरता हुआ न्यायशास्त्र

(क) पाटन एवं सब्सिडीज- यूरोपीय समुदाय में पाटनरोधी तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को शासित करने वाला कानून व प्रक्रियाएं-मै. क्लाइव स्टानब्रुक तथा फिलिप बेंटिली, कुमेर लॉ इंटरनेशनल, तीसरे संस्करण से उद्धरण

5.1.3 ऐसे सामुदायिक उत्पादक जो निर्यातकों/आयातकों से संबंधित हैं अथवा उत्पाद के आयातक हैं

सामुदायिक उत्पादक किसी शिकायत का समर्थन इस वजह से करना नहीं चाहते कि वे निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हैं या आरोपित पाटित अथवा सब्सिडीशुदा उत्पाद के स्वयं आयातक हैं । ऐसे मामलों में यह माना जाता है कि शेष सामुदायिक उत्पादकों को केवल इस वजह से कोई शिकायत करने से रोका नहीं जाना चाहिए कि वे आवश्यक सहायता नहीं जुटा समर्थन नहीं जुटा सकते । अतः नियम में संशोधन किया गया है ताकि सामुदायिक प्राधिकरण उक्त सामुदायिक उद्योग को ऐसे उत्पादकों की परिभाषा के रूप में मान सकें जो निर्यातकों या

आयातकों से संबंधित नहीं हैं और जो स्वयं क्षतिकारी उत्पाद के आयातक नहीं हैं । सामुदायिक प्राधिकरण इस मामले में विवेकाधिकार रखते हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि 50 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत का नियम अभी भी उन निर्यातकों को अपवर्जित करने के बाद बचे हुए उत्पादकों पर लागू होता है जो निर्यातकों आदि से संबंधित हैं । अन्यथा कुछ भी कहना निरर्थक होगा जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण से पता चलता है । यदि सामुदायिक उत्पादन का 51% निर्यातकों से संबंधित है तो वे विरोध करेंगे और असंबद्ध उत्पादकों के लिए कोई पाटनरोधी या सब्सिडीरोधी शिकायत करना ही असंभव हो जाएगा । विनियम (ई ई सी) संख्या 2423/88 के विपरीत विनियम (ई सी) सं. 384/96 तथा विनियम (ई सी) सं. 3284/94 में "संबद्ध" की परिभाषा दी गई है । ...

यह प्रतीत होगा कि उत्पाद के आयात का कारण मुख्यतः रक्षात्मक होने की स्थिति में सामुदायिक प्राधिकरण उत्पादक को अपवर्जित नहीं करेंगे । ऐसे कई मामले हैं जिनमें सामुदायिक प्राधिकरणों ने यह माना है कि उत्पादक द्वारा केवल पाटन या सब्सिडियों द्वारा उत्तरोत्तर प्रभावित हो रहे बाजार में स्थिति का बचाव करने की कोशिश करते हुए आरोपित क्षतिकारक उत्पाद का आयात किया जा रहा है । उदाहरणार्थ यूगोस्लाविया से कॉपर सल्फेट में सामुदायिक प्राधिकरण ने यह पाया था कि -

सामुदायिक प्राधिकरण सामुदायिक उत्पादकों के लिए यथासंभव समस्त मॉडलों "के साथ बाजार में बने रहने" अथवा विशिष्ट बाजार को सुरक्षित करने के लिए भी खरीद करने के लिए वाणिज्यिक आत्मरक्षा का एक विधिसम्मत कार्य मानते हैं अन्यथा संदर्भाधीन मॉडलों की बिक्री के बिना ये लुप्त हो गए होते ।

... इस संबंध में महत्वपूर्ण कारकों में से एक कारक विनिर्माण तथा आयात के बीच कंपनी के व्यापार का संतुलन होगा । यदि कंपनी कुछ पूरक व्यापारगत आयात योग्य उत्पादों के साथ सामुदायिक बाजार में मुख्यतः विनिर्माण तथा संयोजन में संलग्न है तो इसे शामिल किए जाने की संभावना है । दूसरी ओर यदि कोई सामुदायिक उत्पादक अपना उत्पादन बंद कर देता है और इसके स्थान पर आयात करता है अथवा उसके व्यापार का सामान्य जोर आयात पर है तो उसे अपवर्जित किया जाएगा । अपवर्जन उस स्थिति में होने की संभावना होगी यदि जांच के उपरान्त यह प्रतीत होता है कि आयातक उत्पादों का आयात कर किसी कंपनी ने पाटन के प्रभावों से स्वयं को "बचाया" है । ऐसा होने की संभावना भी है जब यह प्रतीत हो कि उत्पादकों ने किसी रूप में पाटन के व्यवहार में भाग लिया है अथवा उससे अनुचित लाभ प्राप्त किया है । ऐसी कंपनियों को शामिल किए जाने से क्षति संबंधी निष्कर्षों पर विकृतिकारी प्रभाव पड़ेगा ।

ऐसा प्रतीत होता है कि सामुदायिक प्राधिकरण ऐसे सामुदायिक उत्पाद को अलग रखने की पद्धति अपनाते हैं जो जांच के संबद्ध उत्पाद का आयात करते हैं परंतु जो सहयोग नहीं करते हैं क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में सामुदायिक प्राधिकरण यह निर्धारित नहीं कर सकते कि क्या सामुदायिक उत्पादक प्रतिरक्षात्मक रूप से कार्य कर रहा था अथवा किसी अन्य वजह से।

(ख) पाटनरोधी जांच संबंधी पुस्तिका-जूडिथ जैको, जोहान ह्यूमन एवं जॉर्ज मिरांडा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, पृष्ठ-234 से उद्धरण

संबद्ध उत्पादकों का अपवर्जन

... ..

पाटनरोधी करार में यह निर्धारित करने में लागू किया जाने वाला कोई विशिष्ट मापदंड या जांच की सूची नहीं है कि क्या संबद्ध उत्पादकों या आयातकों को घरेलू उद्योग की परिभाषा से अलग रखा जाना चाहिए। जांच प्राधिकरण सामान्यतः संबद्ध पक्षकार के मुद्दे पर मामला दर मामला आधार पर विचार करते हैं। संबद्ध पक्षकारों को अलग रखने के बारे में निर्णय लेने में सदस्यों द्वारा विचार किए गए मानदंड निम्नानुसार हैं इ

- संदर्भाधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादन का प्रतिशत जिसे संबद्ध उत्पादकों ने हिसाब में लिया है;
- क्या संबद्ध उत्पादकों द्वारा संदर्भाधीन उत्पाद के आयातों से उन्हें लाभ मिला है अथवा पाटन के प्रभाव से सुरक्षा मिली है।
- क्या संबद्ध पक्षकारों के अपवर्जन से उद्योग के शेष सदस्यों के लिए आंकड़ों में अनुचित कमी की जाएगी।
- आयातक कार्यकलापों के प्रतिकूल घरेलू उत्पादन के लिए उत्पादक द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता का स्तर या दीर्घावधिक स्वरूप।
- संबद्ध उत्पादकों के लिए घरेलू उत्पादन में आयात खेपों का अनुपात।

(ग) परिशिष्ट-च, पाटनरोधी एवं प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी पुस्तिका-प्रकाशन 3482, 9वां संस्करण, संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग, पृष्ठ एफ-33 से उद्धरण।

... .. इस प्रकार उदाहरणार्थ यदि कोई अमरीकी उत्पादक किसी विदेशी निर्यातक से संबंधित है और उक्त विदेशी उत्पादक अमरीका को अपना निर्यात करता है ताकि संबद्ध अमरीका उत्पादक से प्रतिस्पर्धा न हो तो आयोग यह निर्धारित कर सकता है कि घरेलू उद्योग से उक्त संबद्ध अमरीकी उत्पादक को अलग रखने के लिए उचित परिस्थितियां मौजूद हैं।

आयोग ने यह निर्धारित करने में कि क्या संबद्ध पक्षकार को अलग रखने के लिए उचित परिस्थितियाँ मौजूद हैं, निम्नलिखित कारकों की जांच की है ।

- (i) संबद्ध उत्पादक के हिस्से में घरेलू उत्पादन का प्रतिशत ।
- (ii) इस आशय का कारण कि संबद्ध उत्पादक ने विचाराधीन वस्तु का आयात करने का निर्णय लिया है अर्थात् अनुचित व्यापार व्यवहार से लाभ उठाना अथवा उसे उत्पादन जारी रखने में समर्थ बनाना और घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा करना; और
- (iii) शेष उद्योग की तुलना में संबद्ध उत्पादक की स्थिति अर्थात् क्या संबद्ध पक्षकार को शामिल किए जाने या अलग रखे जाने से शेष उद्योग के आंकड़ों का पता चलेगा ।

(ख) जांच प्राधिकारियों के विभिन्न निर्णय

घरेलू उद्योग ने भी यूरोपीय आयोग की पद्धति का हवाला दिया है और उस पर भरोसा किया है । इस संबंध में मौखिक सुनवाई के समय प्रस्तुत पेपर बुक का अवलोकन किया जाए । यूरोपीय आयोग द्वारा यह निर्णय लेते समय कि सामुदायिक उत्पादक को कब शामिल किया जाए, जिसने संबद्ध वस्तु का स्वयं आयात किया है, निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जाता है :-

(क) "प्रमुख व्यापार" संबंधी जांच

यह निर्णय लेने के लिए कि क्या सामुदायिक उत्पादकों-आयातकों को उत्पादकों या आयातकों का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए, आयोग खासकर इस बात पर विचार करता है कि क्या समुदाय में प्रचालनरत कंपनियों ने सामुदायिक उत्पादन या संयोजन कार्यकलाप में आयातों के आधार पर अतिरिक्त कार्यकलाप के साथ योगदान किया है अथवा क्या ये कंपनियाँ समुदाय में तुलनात्मक रूप से सीमित अतिरिक्त उत्पादन कार्यकलाप के साथ आयातकों के रूप में कार्य कर रही थीं । (ख) आयात कम कीमत के आयातों के विरुद्ध मात्र एक रक्षात्मक कार्य है- आयोग इस बात पर विचार करता है कि क्या आयात कम कीमत के आयातों के विरुद्ध मात्र रक्षात्मक कार्य के लिए किए गए थे ।

याचिकाकर्ता ने किसी उत्पादक द्वारा किए गए आयात को निम्नलिखित श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया है :

- I. संबद्ध निर्यातक से स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयात
- II. असंबद्ध निर्यातक से स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयात

- III. संबद्ध देश से इतर देश से स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयात
- IV. संबद्ध निर्यातक से भारत में संबद्ध कंपनी द्वारा किए गए आयात
- V. असंबद्ध निर्यातक से भारत में संबद्ध कंपनी द्वारा किए गए आयात
- VI. जांच अवधि के दौरान निर्यात करने वाले निर्यातक से संबंध
- VII. जांच अवधि के दौरान निर्यात न करने वाले निर्यातक से संबंध

● संबद्ध निर्यातक से स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयात

1. दिनांक 3 मार्च, 1997 का परिषद विनियमन (ईसी) सं. 423/97, जिसमें थाईलैंड, फिलीपींस एवं मैक्सिको के मूल के गैस फ्यूएल्ड, नॉन रिफिलेबल पॉकेट फ्लैंट लाइटों के आतों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाते हुए विनियमन (ई ई सी) सं. 3433/91 में संशोधन । ऑफिशियल जर्नल एल 065, 06/03/1997 पृ. 0001-0016

घ. सामुदायिक उद्योग

(क) जांच से इस बात की पुष्टि हुई है कि शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादकों जिनका ई एफ एल एम (जिसकी ओर से थाई आयातों के संबंध में अंतरिम समीक्षा हेतु अनुरोध दायर किया गया है) द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है अथवा दो अलग-अलग समूहों में कार्यरत हैं (एक ने फिलीपींस के मूल के आयातों के बारे में शिकायत दायर की है और दूसरे ने मैक्सिको के मूल के आयातों के बारे में शिकायत की है) का हिस्सा सभी मामलों में समान उत्पाद के कुल सामुदायिक उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है ।

ख. उपर्युक्त कंपनियों के संबंध में की गई जांच के दौरान यह स्पष्ट हो गया है कि समुदाय में अपनी एक बिक्री सहायक कंपनी और स्वीडिस मैच ग्रुप की कंपनियों के साथ दोनों उत्पादक अथवा उत्पादक समूह अर्थात् टोकाई सीकीजीएमबीएच क्रमशः एकमात्र मैक्सिकन निर्यातक और फिलीपींस के एक निर्यातक से संबंधित थीं और ये संबद्ध देशों से पाटित उत्पाद का आयात भी कर रही थीं ।

इन परिस्थितियों में आयोग ने इस बात की जांच की कि क्या मूल पाटनरोधी विनियम के अनुच्छेद-4 (1) (क) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए इन कंपनियों को "सामुदायिक उद्योग" से अलग रखा जाना चाहिए । इस संबंध में यह स्मरण किया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 4(1)(क) में ऐसे उत्पादकों के स्वतः अपवर्जन का प्रावधान नहीं है जो निर्यातकों से संबंधित है और/अथवा पाटित उत्पादों के स्वयं आयातक हैं परंतु इसमें आयोग पर यह दायित्व डाला गया है कि वह इस बात की मामला दर मामला आधार पर जांच करे कि क्या ऐसी स्थिति में किसी उत्पादक का अपवर्जन अपेक्षित है । जहां तक टोकाई सी पी जी एम बी एच का संबंध है, सर्वप्रथम यह नोट किया जाता है कि इस कंपनी ने यह स्पष्ट किया था कि उसने फिलीपींस और थाईलैंड के खिलाफ कार्रवाई

का मात्र समर्थन किया है और यह कि संभावित सामुदायिक उत्पादक के रूप में उसका सहयोग इन दोनों देशों के संबंध में जांचों तक सीमित है । द्वितीयतः जांच से यह पता चला कि यह उत्पादक न केवल मैक्सिको के एकमात्र निर्यातक से संबंधित है अपितु वह मैक्सिको के मूल की घोषित डिस्पोजेबल फिल्ट लाइटर्स के समुदाय में कुल आयातों के अत्यंत बड़े अनुपात के लिए भी उत्तरदायी है ।

इस संबंध में यह स्मरणीय है कि मैक्सिकन और फिलीपिंस से हुए आयातों के बारे में जांच एकल कार्यवाई के ढांचे में की गई थी (उद्धरण 5 देखें) और यह कि थाइलैंड से पाटित आयातों के प्रभाव के संचयी निर्धारण में फिलीपिंस और मैक्सिको को अपेक्षित पाया गया था (देखें उद्धरण 40 से 44) । इस संदर्भ में इस बात पर विचार किया गया था कि समग्र क्षति निर्धारण में टोकाई सीकीजीएमबीएच की स्थिति को ध्यान में रखना उचित नहीं था क्योंकि मैक्सिकन आयातों के महत्व को देखते हुए इससे अविश्वसनीय परिणाम निकलते । तदनुसार, टोकाई सीकीजीएमबीएच को "सामुदायिक उद्योग" से अलग रखना उचित माना गया था ।

जहां तक स्वीडिस मैच ग्रुप की ऐसी कंपनियों जो फिलीपिंस के निर्यातक स्वीडिस मैच फिलिपींस इंक से संबंधित हैं, का प्रश्न है, इस बात का निर्धारण करना उचित प्रतीत होता है कि क्या वे कंपनियां (जो तीनों मामलों में शिकायतकर्ता थीं और जिन्होंने तीनों जांचों में पूर्ण सहयोग किया था) आयातों पर आधारित अतिरिक्त कार्यकलाप और अपने सामुदायिक उत्पादन में मात्र पूरकता प्रदान करने वाले प्राथमिक उत्पादक थीं अथवा क्या वे समुदाय में तुलनात्मक रूप से सीमित अतिरिक्त उत्पादन के साथ आयातक थीं ।

जांच से यह पता चला कि फिलीपिंस के मूल के संबद्ध उत्पाद के बारे में स्वीडिस मैच ग्रुप की कंपनियों के आयात कार्यकलाप अत्यंत सीमित थे जिससे यह संकेत मिलता है कि संबद्ध उत्पाद से जुड़े उसके कार्यकलापों का आधार समुदाय में पूर्णतः निहित था । तदनुसार संबद्ध कंपनियों को "सामुदायिक उद्योग" में रखना उचित समझा गया था ।

अतः निम्नलिखित क्षति संबंधी जांच परिणाम टोकाईसीकीजीएमबीएच से इतर सहयोगी कंपनियों अर्थात् बी आई सी ग्रुप और स्वीडिस मैच ग्रुप तथा स्पेनिश कंपनी फ्लेमिंग्स के उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित हैं ।

2. दिनांक 27 सितंबर, 1995 का आयोग विनियमन (ईसी) सं. 2318/95 जिसमें चीन जनवादी गणराज्य के मूल के लोहे अथवा इस्पात के कतिपय ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग्स पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था और स्लोवाक गणराज्य और ताइवान के मूल की उन

फिटिंग्स के आयातों के संबंध में पाटनरोधी कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया । ऑफिशियल जर्नल एल-234, 03/10/1995 पृ. 0004-0015

घ. सामुदायिक उद्योग

(37) चूंकि समुदाय में स्थापित सभी उत्पादकों ने जांच में भाग नहीं लिया है और समुदाय के एक उत्पादक को ऐसे विशेष ट्यूब या पाईप फिटिंग का विनिर्माण करते हुए पाया गया था जो इस कार्रवाई का विषय नहीं है, इसलिए आयोग को यह जांच करनी पड़ी थी कि क्या शिकायतकर्ताओं का उत्पादन समान उत्पाद के कुल सामुदायिक उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है । इस तथ्य को भी ध्यान में रखना पड़ा था कि यूनाइटेड किंगडम में शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादकों में से एक ने थाइलैंड के एक निर्यातक जो भी एक संबद्ध पक्षकार है, से आरोपित पाटित उत्पादों का आयात किया था ।

(38) यू के के शिकायतकर्ता उत्पादक के आयातों के संबंध में तथ्यों की जांच से यह पता चला कि उद्योग की इस विशेष शाखा के लगभग सभी उत्पादक उनके विनिर्माण कार्यक्रम से बाहर के फिटिंग टाइपों की खरीद पर कुछ हद तक भरोसा करते हैं । वस्तुतः फिटिंग के उत्पादकों ने उत्पाद के सभी प्रकारों की पेशकश की है ताकि ग्राहकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके और इस प्रकार बाजार में प्रतिस्पर्धा की जा सके ।

वस्तुतः इस बात की पुष्टि की गई थी कि यू के के संदर्भाधीन शिकायतकर्ता उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान थाइलैंड के एक संबद्ध निर्यातक से जांचाधीन उत्पाद का आयात किया था जिसके बारे में पाटन पाया गया था । तथापि, इन आयातों का स्तर सामुदायिक बाजार में यू के उत्पादक द्वारा की गई कुल बिक्री के 2% से अधिक नहीं पाया गया था । इसके अलावा, आयातित मात्रा में मुख्यतः उत्पादों की अपनी रेंज को पूरा करने के लिए इस उत्पादक द्वारा विनिर्मित न किए जा रहे उत्पाद के प्रकार शामिल थे जिनका मुख्यतः आयात अपनी बाजारी स्थिति को बचाने के लिए किया गया था । अतः यह माना जाता है कि यद्यपि, ये संबंधित पक्षकार हैं, तथापि आयातों के इतने कम स्तर से यू के उत्पादक का पाटन के प्रभाव से बचाव नहीं हो सकता और न ही उसे कोई खास लाभ मिला होगा और यह कि इस उत्पादक को "सामुदायिक उद्योग" की परिभाषा से अलग रखने का कोई उचित आधार नहीं है ।

जांच के दौरान इटली के शिकायतकर्ता उत्पादकों में से एक ने इस आधार पर शिकायत वापस ले ली कि उसके द्वारा विनिर्मित उत्पादों का निर्यात संबद्ध निर्यातक देशों द्वारा नहीं किया गया था ।

शिकायत में प्रतिनिधित्व करने वाले उत्पादकों के उत्पादन के हिस्से के निर्धारण के संबंध में आयोग ने शिकायतकर्ता उत्पादकों द्वारा मौके पर जांच के दौरान प्रदत्त अन्य आंकड़ों के साथ-साथ प्रस्तुत की गई सूचना का उपयोग किया जो उत्पादक उक्त समुदाय में स्थापित सबसे बड़े उत्पादक हैं। आयोग ने भरोसेमंद बाजार अनुसंधान आंकड़ों का भी उपयोग किया।

उपर्युक्त विचारों के आधार पर जांच अवधि के दौरान शिकायतकर्ता उत्पादकों द्वारा किया गया कुल सामुदायिक उत्पादन 85% पर परिकलित किया गया था और इस प्रकार यह कुल सामुदायिक उत्पादक का एक बड़ा हिस्सा बनता है।

3. 16 अगस्त, 1995 का परिषद विनियमन (ई सी) सं. 2022/95 जिसमें रूस के मूल के अमोनियम नाइट्रेट के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया। ऑफिशियल जर्नल एल 198, 23/08/1995 पृ. 0001-0014

ग. सामुदायिक उद्योग

शिकायतकर्ता उत्पादकों का अमोनियम नाइट्रेट के सामुदायिक उत्पादन का 94% बनता है और इसलिए सामुदायिक उद्योग विनियम (ई ई सी) सं. 2423/88 के अनुच्छेद 4(5) के अनुसार घरेलू उद्योग है।

सामुदायिक आयातकों का प्रतिनिधित्व करते हुए ई एफ आई ए ने यह आरोप लगाया कि हाइड्रोफर्टीलाइजर्स लि. (यू.के.) को सामुदायिक उद्योग से अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि उसने कथित रूप से फर्टाकेम यू.के. जो एक संबद्ध कंपनी है, के जरिए रूस और लिथवानिया से अमोनियम नाइट्रेट का आयात किया है। तथापि, यह सिद्ध किया गया था कि फेर्टाकेम द्वारा जांच अवधि में ऐसा कोई आयात नहीं किया गया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि एक अन्य शिकायतकर्ता उत्पादक बी ए एस एफ को इसी आधार पर अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि उसने कथित रूप से एक संबद्ध कंपनी काली (यू.के.) लि. के जरिए समुदाय में रूसी और लिथवानियन अमोनियम नाइट्रेट का आयात किया है। इस बात की पुष्टि की गई थी कि काली (यू.के.) लि. ने लिथवानिया और रूस से जांच अवधि के दौरान अमोनियम नाइट्रेट का आयात किया और उसने सीधे या किसी सहायक कंपनी के जरिए इस अवधि के दौरान बी ए एस एफ से संबद्ध किसी कंपनी के साथ कोई करार नहीं किया था और उसने अमोनियम नाइट्रेट की खरीद के बारे में बी ए एस एफ से संबद्ध किसी कंपनी से कोई करार नहीं किया था।

परिणामतः हाइड्रोफर्टीलाइजर्स लि. (यू.के.) अथवा बी ए एस एफ को सामुदायिक उद्योग से अलग रखने से विचार करने का कोई औचित्य नहीं है।

4. दिनांक 10 अप्रैल, 1995 का आयोग विनियमन (ईसी) सं. 823/95, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के डाई सोडियम कार्बोनेट के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया । आफिशियल जर्नल एल 083, 13/04/1995 पृ. 0008-0018 ।

घ. सामुदायिक उद्योग

यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ निर्यातकों और समुदाय में प्रमुख प्रसंस्करण उद्योग के प्रतिनिधियों अर्थात् ग्लास उद्योग ने यह तर्क दिया है कि शिकायतकर्ता कंपनियों में से दो कंपनियां अमरीका के निर्यातकों से संबंधित थीं जिन्होंने जांच अवधि के दौरान अमरीकी सोडा ऐश का स्वयं आयात किया था और इसलिए उन पर मूल विनियम के अनुच्छेद 4(5) के मददेनजर सामुदायिक उद्योग के भाग के रूप में विचार न किया जाए ।

इस संबंध में यह स्मरणीय है कि अनुच्छेद 4(5) में ऐसे निर्यातकों या उत्पादकों से संबंधित उत्पादकों के स्वतः अपवर्जन का प्रावधान नहीं है जिन्होंने स्वयं कथित पाटित उत्पाद का आयात किया है अपितु ऐसे सामुदायिक संस्थानों पर इस बात को सिद्ध करने का दायित्व सौंपा गया है कि वे मामला दर मामला आधार पर इस बात की जांच करें कि क्या ऐसी स्थिति में किसी उत्पादक का अपवर्जन अपेक्षित है ।

तदनुसार आयोग ने इस बात पर विचार किया कि क्या समुदाय के दोनों उत्पादक केवल आयात पर आधारित अतिरिक्त कार्यकलाप के साथ अपने सामुदायिक उत्पादन की पूर्ति कर रहे थे अथवा क्या वे समुदाय में अपेक्षाकृत सीमित अतिरिक्त उत्पादन के साथ आयात कर रहे थे । यह नीति "सामुदायिक उद्योग" की परिभाषा के बारे में न्यायालय द्वारा हाल ही में निर्णीत मामले के अनुरूप है ।

आयोग ने समुदाय में उत्पादित मात्रा और आयातित मात्रा के बीच संबंध की जांच की । जांच में पुष्टिकृत तथ्यों के आधार पर यह पाया गया था कि ऐसे दोनों सामुदायिक उत्पादकों जो निर्यातकों से संबंधित हैं और जो स्वयं अमरीका से आयात करने वाले हैं, ने अपेक्षाकृत कम मात्रा में आयात किया है (एक मामले में ये आयात समुदाय में बेचे गए सामुदायिक उत्पादक के उत्पादन का 10% बनते हैं और दूसरे मामले में ये 1% से कम हैं) । इसके अलावा, समुदाय के एक ऐसे उत्पादक जिसने 1992 में अमरीकी उत्पादक की खरीद की थी, इसलिए मौजूदा संविदाओं का सम्मान किया जाना चाहिए था; इस कंपनी से आयात 1993 में बंद हो गए । दूसरा उत्पादक मुख्यतः अपनी कैपिटल खपत के लिए आयात करता है ।

इन परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों संबंधित सामुदायिक उत्पादक उक्त समुदाय में स्थित कारपोरेट मुख्यालयों के साथ जहां से उनकी वाणिज्यिक नीति तैयार की जाती है और उनके वाणिज्यिक कार्यकलापों के सामान्य व्यापारिक विस्तार के रूप में विदेशी निवेश की योजना बनाई जाती है, आयातकों के रूप में मुख्यतः कार्य नहीं करते हैं अपितु अपने प्रमुख कार्यकलाप के रूप में सोडा ऐश के विनिर्माण को बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं

आयात की अपेक्षाकृत कम मात्रा को देखते हुए इन उत्पादकों के बारे में यह नहीं माना जा सकता कि उन्होंने आयातकों के बारे में पाटन के प्रभावों के खिलाफ स्वयं को सुरक्षित रखा है ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विचार किया गया था कि किसी शिकायतकर्ता उत्पादक को सामुदायिक उद्योग की परिभाषा से बाहर रखने का कोई आधार नहीं है ।

5. दिनांक 15 अक्टूबर, 1997 का परिषद विनियमन (ई सी) सं. 2025/97 जिसमें जापान के मूल के कंप्यूनिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग मैचेज के भीतर आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया और लगाए गए अनंतिम शुल्क का निश्चयात्मक संग्रहण । आफिशियल जर्नल एल 284, 16/10/1997 पृ. 0057-0067

ड सामुदायिक उद्योग

(33) एडवर्टाइजिंग मैचिज के सामुदायिक उत्पादकों की बड़ी संख्या एफ ई एफ ए (फेडरेशन यूरोपीने डैस फैब्रिकेंट्स डि एल्युमेन्स) के सदस्य हैं जो एक यूरोपियन एसोसिएशन है जिसने अपने सदस्यों की ओर से शिकायत दर्ज की है । फ्रांस, स्पेन, इटली, बेल्जियम, पुर्तगाल और युनाइटेड किंगडम में स्थित ये उत्पादक सामान्यतः छोटे और मझोले उद्यम हैं जिनके संसाधन सीमित हैं । परिणामतः भले ही उन सभी ने शिकायत का समर्थन किया है तथापि, केवल प्रमुख उत्पादकों का उत्पादन संबद्ध उत्पाद के कुल सामुदायिक उत्पादन का 78% बनता है और इस प्रकार मूल विनियम के अनुच्छेद 4(5) में निर्धारित मानदंड को स्पष्ट तौर पर पूरा करते हुए उन्होंने इस जांच में आयोग के साथ सक्रिय सहयोग किया है ।

(34) जापान के एक निर्यातक ने फ्रांस में स्थित एक सामुदायिक उत्पादक जिसने आयोग की प्रश्नावली का उत्तर दिया है, के प्रकाशित अनंतिम निर्धारणों से अलग रखे जाने का प्रश्न उठाया है

(35) इस स्थिति को इस तथ्य द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि यह उत्पादक जिसने यद्यपि शिकायत का समर्थन किया है, प्रमुख आंतरिक कठिनाइयों के कारण मौके पर जांच हेतु आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं था । अतः यह निर्णय लिया गया था कि इस उत्पादक पर कार्यवाही में सक्रिय सहयोगकर्ता के रूप में विचार नहीं किया जा सकता और इसे सामुदायिक उद्योग की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया था ।

(36) यह निर्णय अनंतिम शुल्क विनियम के उद्धरण 25 की विषय वस्तु में प्रदर्शित किया गया है जिसमें यह उल्लेख है कि "सामुदायिक उद्योग" पद का अर्थ निरूपण समान उत्पाद के ऐसे सामुदायिक उत्पादकों के रूप में किया जाना चाहिए जिनका सामूहिक उत्पादन ऐसे कुल

सामुदायिक उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है जिन्होंने शिकायत का समर्थन किया है और जिन्होंने कार्यवाही में सक्रिय सहयोग दिया है ।

(37) अनंतिम शुल्क विनियम के उद्धरण 26 में प्रदत्त स्पष्टीकरण के बावजूद समुदाय में जापानी एडवरटाइजिंग मैचेज के एक आयातक ने यह दावा किया कि सामुदायिक उत्पादक के प्रमुख शिकायतकर्ता पर इस आधार पर सामुदायिक उद्योग के भाग के रूप में विचार नहीं किया जाना चाहिए कि उसने सीधे या संबद्ध कंपनियों के जरिए ऐसी मात्रा में जापान से पाटित एडवरटाइजिंग मैचेज का आयात किया है जिनका हिस्सा उसके खुद के उत्पादन के 4% से अधिक बनता है । अपने दावे के समर्थन में उसने उपर्युक्त शिकायतकर्ता की ऐसी सहायक कंपनियों की सूची भेजी थी जिन्होंने कथित तौर पर जापान से एडवरटाइजिंग मैचेज का आयात किया था ।

(38) आयोग ने इस सामुदायिक उत्पादक द्वारा किए गए आयातों के इस तर्क की पुनः जांच की और अपने अनंतिम जांच परिणाम की पुष्टि की अर्थात् यह कि इस उत्पादक द्वारा आयात की मात्रा एडवरटाइजिंग मैचेज के उसके खुद के कुल उत्पादन की लगभग 4% बनती है ।

(39) एक अन्य निर्यातक ने यह दावा किया कि शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादकों में से दो उत्पादकों द्वारा अब एडवरटाइजिंग मैचेज का उत्पादन नहीं किया जा रहा है । यद्यपि इस निर्यातक द्वारा उन घटनाओं का हवाला दिया जा रहा है जो कथित तौर पर जांच अवधि के बाद घटित हुई थी अतः इन पर सामान्यतः ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए । तथापि, यह नोट करना होगा कि इस आशय का कोई संकेत नहीं है कि शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादकों में से किसी ने भी इस जांच में शामिल उत्पाद का विनिर्माण बंद किया है ।

(40) निष्कर्षतः वर्तमान कार्यवाही और इस संबंध में आयोग द्वारा निकाले गए अनंतिम जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ सामुदायिक उद्योग की परिभाषा की एतद् द्वारा पुष्टि की जाती है ।

6. दिनांक 27 अगस्त, 1998 का आयोग विनियमन (ई सी) सं. 1845/98, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के तथा थाईलैंड के मूल के कतिपय बड़े इलेक्ट्रोलिटिक-एल्युमिनियम संधारियों के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया ।

घ. सामुदायिक उद्योग

सामुदायिक उत्पादन

(39) एल ए ई सी के 4 बड़े उत्पादक अर्थात् फिलिप्स, बी एच सी एरोवॉक्स लि. (यूनाइटेड किंगडम), विसाय रोडस्टीन जी एन बी एच (जर्मनी) तथा सीमेंस - मतुसुशिता कंपोनेंट्स जी एम बी एच एंड कंपनी, के जी (जर्मनी) और कुछ छोटे से लेकर मझौले उत्पादक समुदाय में स्थापित हैं ।

(40) बड़े उत्पादकों में से एक उत्पादक सीमेंस - मतुसुशिता कंपोनेंट्स जी एम बी एच एंड कंपनी, के जी (मन्चेन जर्मनी), जर्मन की एक कंपनी तथा जापान की एक कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम है और यह अमरीका में निर्यातक उत्पादकों में से एक से संबंधित है। अतः इस उत्पादक को इस आधार पर मूल विनिमय के अनुच्छेद 4(1) के अनुसार सामुदायिक उद्योग से अलग रखा गया था कि इस संबंध के जरिए इस उत्पादक को पाटित आयातों के क्षतिकारी प्रभावों से सुरक्षा प्रदान की गई थी। यह नोट किया जाना चाहिए कि इस उत्पादक को एल ए ई सी से संबंधित दोनों पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में भी सामुदायिक उद्योग से अलग रखा गया था।

(41) कुछ उत्पादकों/निर्यातकों ने यह दावा किया कि शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादकों में से एक उत्पादक, फिलिप्स पर इस आधार पर सामुदायिक उद्योग के भाग के रूप में विचार नहीं किया जा सकता कि फिलिप्स ग्रुप के भीतर एक अन्य कंपनी अर्थात् फिलिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बी वी ने जांच अवधि के दौरान अमरीका से एल ए ई सी का आयात किया था।

जांच से यह पता चला कि फिलिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बी वी जिसने फिलिप्स के उत्पादन के लगभग 40% की खरीद की थी और जो उसका सबसे बड़ा पारंपरिक खरीददार थी, ने जांच अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के अपने उत्पादन के संघटकों के रूप में अमरीका से एल ए ई सी का आयात किया था। यह नोट किया गया था कि आयातित एल ए ई सी का उपयोग फिलिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बी वी का अनन्य रूप से उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में से एक के उत्पादन के संघटकों के रूप में किया गया था और यह कि आयातित एल ए ई सी की बिक्री कभी भी सामुदायिक बाजार में नहीं की गई थी।

फिलिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बी वी की पसंद की आंशिक आपूर्ति अमरीकी निर्यातकों द्वारा अलग-अलग लाभ केन्द्रों के फिलिप्स ग्रुप की संरचना द्वारा संभव की गई थी जो सभी स्वतंत्र हैं और ऐसे किसी उत्पादक से सामग्री प्राप्त करने से मुक्त हैं जो सर्वोत्तम बाजारी स्थिति प्रदान कर सकते हैं। इस पसंद का तात्पर्य यह नहीं है कि फिलिप्स के प्राथमिक हित उत्पादन के बजाए आयात में थे।

इन कारणों से यह माना गया था कि फिलिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बी वी द्वारा किए गए आयात को एक पूर्णतः विधिसम्मत व्यापारिक निर्णय के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि उसने पाटित उत्पादों का आयात अपनी अधिकांश जरूरतों के लिए अपनी मूल कंपनी पर भरोसा करने हेतु जारी रखा था। इन आयातों को तब तक एक आवश्यक वाणिज्यिक उपाय माना गया था जब तक कि सामुदायिक बाजार में प्रतिस्पर्धा की उचित स्थितियां उत्पन्न नहीं हुई थीं।

अतः यह निष्कर्ष निकाला गया था कि सामुदायिक उद्योग से फिलिप्स को अलग रखने का कोई उचित आधार नहीं है। यह नोट किया जाना चाहिए कि कुछ निर्णय जापान² के मूल के एल

² ओ जे एल 152, 4.6.1992, पृष्ठ 22

ए ई सी के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी उपाय लागू करते हुए आयोग के विनियम (ई ई सी) सं. 1451/92 के उद्धरण (10) से (12) में निकाले गए थे ।

(42) निर्यातक उत्पादकों में से एक ने आगे यह तर्क दिया कि फिलिप्स को सामुदायिक उद्योग की परिभाषा से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह अमरीका में एक उत्पादक नॉर्थ अमरीकन फिलिप्स से संबंधित है जो एल ए ई सी का उत्पादन कर रहा है ।

आयोग को उपलब्ध कराई गई सूचना से यह पता चला कि नॉर्थ अमरीकन फिलिप्स केवल उत्तर अमरीका बाजार के लिए उत्पादन करता है और इस उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान समुदाय को एल ए ई सी का निर्यात नहीं किया था ।

अतः आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि फिलिप्स को सामुदायिक उत्पादन से अलग नहीं रखा जाना चाहिए ।

(43) उपर्युक्त के आधार पर सामुदायिक उत्पादन में सीमेंस-मतसुश्ता कंपोनेंट्स जी एम बी एच एंड कंपनी, के जी (जर्मनी) को छोड़कर समुदाय में एल ए ई सी का उत्पादन करने वाली सभी कंपनियां शामिल हैं । इन कंपनियों को एतदपश्चात् सामुदायिक उत्पादक कहा गया है ।

सामुदायिक उद्योग

(44) उपर्युक्तानुसार दो सामुदायिक उत्पादकों ने शिकायत का सक्रिय समर्थन किया है । तथापि, इन दोनों शिकायतकर्ता उत्पादकों में से एक बी एच सी एरो वॉक्स लि. निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना प्रस्तुत नहीं कर सका और इसलिए उसे सामुदायिक उद्योग के क्षेत्र से अलग रखा गया था ।

(45) एक अन्य बड़े सामुदायिक उत्पादक विषय रोडर्सटीन जी एम बी एच (जर्मनी) ने शिकायत के प्रति समर्थन व्यक्त किया परंतु उसने आयोग की प्रश्नावली को पूरा नहीं किया ।

(46) एक लघु से लेकर मध्यम सामुदायिक उत्पादक ट्रुबो एस ए (स्पेन) ने शिकायत के लिए समर्थन व्यक्त किया परंतु वह आयोग को पूर्ण सूचना प्रदान नहीं कर सका । लघु से लेकर मध्यम सभी सामुदायिक उत्पादक शांत रहे ।

(47) इन परिस्थितियों में एकमात्र सहयोगी शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादक फिलिप्स की स्थिति पर विचार किया गया था । इसका उत्पादन समुदाय में जांचाधीन उत्पाद के कुल अनुमानित सामुदायिक उत्पादन का 41% बनता है और इस प्रकार इसका उत्पादन मूल विनियम के अनुच्छेद 5(4) के अनुसरण में सामुदायिक उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है । परिणामतः इस उत्पादक को एतदपश्चात् मूल विनियम के अनुच्छेद 4(1) के अर्थ के भीतर "सामुदायिक उद्योग" कहा जाएगा ।

7. इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, थाइलैंड और ताइवान से नाइलोन टायर कोर्ड फैब्रिक (एन टी सी एफ) के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम

ड घरेलू उद्योग

8(ii) पाटनरोधी जांच हेतु वर्तमान याचिका घरेलू उत्पादकों अर्थात् मै. एस आर एफ लि., मै. निरलोन लि., मै. सेंचुरी एंका लि. तथा मै. एन आर सी लि. की ओर से एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री (ए एस एफ आई) द्वारा दायर की गई है। इस याचिका का समर्थन एक अन्य घरेलू उत्पादक मै. बड़ौदा रेयन लि. द्वारा किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि चारों याचिकाकर्ता कंपनियां और समर्थनकर्ता एक अन्य कंपनी मै. बड़ौदा रेयन लि. भारत में एन टी सी एफ के एकमात्र उत्पादक हैं और इस प्रकार याचिका को भारत में एन टी सी एफ के सभी घरेलू विनिर्माताओं का समर्थन प्राप्त है और ये नियमों के अंतर्गत अपेक्षित आधार संबंधी अपेक्षा की पूर्ति करते हैं।

(ii) निर्यातको और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि मै. एस आर एफ लि. ने जांच अवधि के दौरान एक संबद्ध कंपनी मै. एस आर एफ ओवरसीज लि. के जरिए संबद्ध वस्तु का आयात किया है। आयातकों से संबंधित होने के कारण ये पाटनरोधी जांच हेतु याचिका दायर नहीं कर सकते। इसी प्रकार मै. बड़ौदा रेयन्स लि. एक निर्यातक मै. थाई बड़ौदा इंड लि. से संबंधित है जो जांच अवधि के दौरान एक निर्यातक है। अतः ये दोनों कंपनियां पाटनरोधी जांच में याचिकाकर्ता नहीं हो सकतीं। इन दोनों कंपनियों का उत्पादन भारत में एन टी सी एफ के घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है और इसलिए इस याचिका में नियमों के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार घरेलू उद्योग हेतु अपेक्षित समर्थन का अभाव है।

(iii) प्रारंभिक जांच परिणामों में प्राधिकारी ने यह माना था कि मै. एस आर एफ लि. द्वारा किए गए कुल आयात जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से हुए कुल आयातों के 0.24% बनते हैं। इसके अलावा, मै. एस आर एफ लि. द्वारा किए गए आयात जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के एन टी सी एफ के कुल उत्पादन का मात्र 0.08% बनते हैं। जांच अवधि के दौरान मै. एस आर एफ लि. द्वारा अपनी संबद्ध कंपनी मै. एस आर एफ ओवरसीज लि. से कोई अन्य आयात किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. एस आर एफ लि., दुबई द्वारा अपनी संबद्ध कंपनी मै. एस आर एफ ओवरसीज से किए गए आयातों की मात्रा अत्यंत नगण्य थी और यह एस आर एफ लि. को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखने के लिए उचित नहीं होगी। जहां तक मै. बड़ौदा रेयन लि. का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. बड़ौदा रेयन लि. मै. थाई बड़ौदा इंड लि. से संबंधित है जो स्वयं संबद्ध वस्तु के निर्यातक हैं और जिनके बारे में वर्तमान मामले में जांच की जा रही है। तथापि, वर्तमान याचिका घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 उत्पादकों द्वारा दायर की गई है। मै. बड़ौदा रेयन लिमिटेड ने घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व

करने वाले अन्य उत्पादकों द्वारा दायर याचिका का मात्र समर्थन किया है और इस प्रकार मै. बड़ौदा रेयन लि. वर्तमान याचिका में सक्रिय आवेदक नहीं है।

च. हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के आधार के बारे में प्रारंभिक जांच परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क दिए हैं।

9. याचिकाकर्ता के तर्क

i. मै. एस आर एफ लि., मै. निरलोन लि., मै. सेंचुरी एंका लि. तथा मै. एन आर सी लि. वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग हैं। मै. एस आर एफ दुबई से मै. एस आर एफ द्वारा किए गए आयात आरोपित पाटित वस्तु के आयात नहीं बनते हैं और परिणामतः मै. एस आर एफ को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखने का प्रश्न नहीं उठता है। यह स्थिति जुलाई, 1999 में किए गए संशोधन से पूर्व विद्यमान घरेलू उद्योग की परिभाषा के मद्देनजर लागू होगी।

ii. इस प्रश्न पर गौर किए बिना कि क्या जुलाई, 1999 का संशोधन भूतलक्षी है या भविष्यलक्षी, दोनों ही मामलों में मै. एस आर एफ को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखने की अपेक्षा ही नहीं की गई है।

iii. यह तर्क भी गलत है कि मै. एस आर एफ और मै. बड़ौदा रेयन कार्पोरेशन को अलग रखे जाने की स्थिति में शेष उत्पादकों का उत्पादन एन टी सी एफ के घरेलू उत्पादन के 50% से कम बनेगा और इस प्रकार वे आवेदन दायर नहीं कर सकते हैं। ऐसे मामले में शेष उत्पादकों का उत्पादन पात्र घरेलू उत्पादन का 100% बनेगा और वे अपने खुद के अधिकार से आवेदन दायर करने के पात्र होंगे।

10. निर्यातकों के तर्क

i. निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की उस असंशोधित परिभाषा लागू करनी चाहिए थी जिसे वर्तमान जांच की शुरुआत के समय लागू किया गया था। इन नियमों के अनुसार कुछेक घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग से बाहर रखना अनिवार्य है। प्राधिकारी ने यह अनंतिम जांच परिणाम निकाला है कि मै. एस आर एफ संबद्ध वस्तु के एक ज्ञात निर्यातक मै. एस आर एफ ओवरसीज लिमिटेड से संबंधित है और इसने भी अपनी संबद्ध कंपनी से जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात किया है। घरेलू उद्योग के क्षेत्र से मै. एस आर एफ को अलग रखना अनिवार्य है न कि एच्छिक संबद्ध वस्तु की मात्रा पर विचार किए बिना उसका आयात मै. एस आर एफ लि. को घरेलू उद्योग के दायरे से अलग रखने के लिए पर्याप्त है।

ii. इसके अलावा, मै. एस आर एफ, मै. बड़ौदा रेयन कॉर्प भी मै. थाई बड़ौदा इंड लि. से संबंधित हैं। मै. एस आर एफ और मै. बड़ौदा रेयन कार्पो को अलग रखे जाने का तात्पर्य ऐसे घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग के दायरे से अलग रखना होगा जिनका कुल मिलाकर उत्पादन संबद्ध वस्तु के भारतीय घरेलू उत्पादन के 50% से अधिक बनता है। इस प्रकार शेष घरेलू

उत्पादकों का हिस्सा भारतीय घरेलू उत्पादन के 50% से कम बनता है और वे नियम 2(ख) के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग नहीं बन सकते हैं। अतः मै. एस आर एफ और मै. बड़ौदा रेयन कापों से भिन्न घरेलू उत्पादकों की ओर से दायर आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया आवेदन नहीं हो सकता। अतः वर्तमान जांच स्वीकार्य नहीं है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

11. प्राधिकारी द्वारा जांच

i. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के आधार से संबंधित मुद्दे की जांच की गई है। इस संबंध में पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) और नियम 5(3)(क) संगत है।

ii. इस मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच 26.2.99 को शुरू की गई थी। याचिका भारत में एन टी सी एफ के 4 घरेलू उत्पादकों अर्थात् मै. एस आर एफ लि., मै. निरलोन लि., मै. सेंचुरी एंका लि. और मै. एन आर सी लि. द्वारा दायर की गई है। इसके अलावा, इस याचिका का समर्थन एन टी सी एफ के एक अन्य घरेलू उत्पादक मै. बड़ौदा रेयन कॉर्प द्वारा किया गया है।

iii. अतः रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह याचिका 4 घरेलू विनिर्माताओं द्वारा दायर की गई थी जिसका समर्थन एक अन्य विनिर्माता ने किया था। संबद्ध वस्तु के किसी भी घरेलू विनिर्माता ने याचिका का विरोध नहीं किया था। इस प्रकार इस याचिका को दिनांक 26.2.1999 को प्रचलित पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3)(क) के अंतर्गत अपेक्षित जांच की शुरुआत हेतु घरेलू उद्योग का आवश्यक समर्थन हासिल है।

iv. जांच के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी की जानकारी में यह बात लाई गई थी कि वर्तमान जांच में एक याचिकाकर्ता मै. एस आर एफ लि. ने मै. एस आर एफ ओवरसीज लि. जो एक संबद्ध कंपनी है, से एन टी सी एफ की पर्याप्त मात्रा में आयात किया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी की जानकारी में आगे यह बात लाई गई थी कि घरेलू उत्पादकों में से एक उत्पादक मै. बड़ौदा रेयन लि. मै. थाई बड़ौदा इंड लि. से संबंधित है, जिसके खिलाफ जांच शुरू की गई है।

v. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू उद्योग के दर्जे के बारे में 15 जुलाई, 1999 में संशोधन किया गया था। अतः यह वह समय था जब निर्दिष्ट प्राधिकारी की जानकारी में इन तथ्यों की जांच की बात लाई गई थी। अपने प्रारंभिक जांच परिणाम में प्राधिकारी ने यह पाया कि चूंकि मै. एस आर एफ लि. द्वारा किए गए आयात जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से हुए कुल आयातों के मात्र 0.24% बनते हैं इसलिए संशोधित नियम 2(ख) के अंतर्गत आयातों की ऐसी नगण्य मात्रा मै. एस आर एफ लि. को घरेलू उद्योग के दायरे से अलग रखने के लिए न्यायोचित नहीं होगी।

vi. प्राधिकारी द्वारा 15 जुलाई, 1999 से पूर्व विद्यमान नियमों के संदर्भ में घरेलू उद्योग के आधार से संबंधित मुद्दे की भी जांच की गई थी। नियम 2(ख) में यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग से ऐसे घरेलू उत्पादकों को बाहर रखा गया माना जाएगा जो आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों

या उत्पादकों से संबंधित हैं या वे स्वयं उसके आयातक हैं। इन उपबंधों का पाठन संगत नियमों के नियम 5(3) (क) के उपबंधों के साथ करना होगा। 15 जुलाई, 1999 से पूर्व विद्यमान नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार यह मानते हुए भी कि मै. एस आर एफ लि. और मै. बड़ौदा रेयन लि. आयातकों से संबंधित हैं या वे स्वयं आयातक हैं, घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व केवल मै निरलोन लि., मै. सेंचुरी एंका लि. और मै. एन आर सी लि. द्वारा किया जाएगा। ऐसे किसी आवश्यकता की स्थिति में याचिका को एन टी सी एफ के 100% घरेलू उत्पादकों का समर्थन हासिल था।

vii. अतः घरेलू उत्पादकों के पास 15 जुलाई, 1999 को पाटनरोधी नियमों में किए गए संशोधन से पूर्व भी उक्त नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने का अपेक्षित आधार था।

viii. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि याचिकाकर्ताओं के पास नियमों में यथापेक्षित याचिका दायरे करने का अपेक्षित आधार है और वर्तमान याचिका घरेलू उद्योग की ओर से दायर की गई है।

12. चीन जन.गण. और स्वीडन के मूल के और वहां से निर्यातित पेंटाएरीथ्रिटोल के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच

6. आवेदक ने अनुरोध किया है कि पर्सटार्प द्वारा भारत में बेचा जा रहा उत्पाद तकनीकी पेंटाएरीथ्रिटोल 95% है जो 2 अलग-अलग शुद्धताओं अर्थात् तकनीकी पेंटाएरीथ्रिटोल 88% (30%) तथा पेंटाएरीथ्रिटोल मोनोग्रेड 98% (70%) के पेंटाएरीथ्रिटोल के मिश्रण के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने आगे यह तर्क दिया है कि अलग-अलग ग्राहक अपनी प्रक्रियागत अपेक्षाओं के अनुकूल अलग-अलग शुद्धताओं, संघटकों और गलनांक के पेंटाएरीथ्रिटोल की अपेक्षा करते हैं और अपेक्षित मापदंडों के उत्पाद की ग्राहकों को आपूर्ति उत्पाद के मिश्रण द्वारा की जा रही है। पेंटाएरीथ्रिटोल तकनीकी ग्रेड जिसमें मोनो पेंटाएरीथ्रिटोल 89% होता है, का उपयोग उन्हीं उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है जिनका विनिर्माण मोनो पेंटाएरीथ्रिटोल 98% के पेंटाएरीथ्रिटोल (मोनो) ग्रेड से किया जाता है। पेंटाएरीथ्रिटोल (मुख्यतः मोनोपेंटा के रूप में परिभाषित) और अन्य संघटकों की शुद्धता उत्पाद के विनिर्माण तथा अन्य प्रक्रियागत स्थितियों के लिए प्रयुक्त मोलर अनुपात के अनुसार अलग-अलग होती है। पेंटाएरीथ्रिटोल की शुद्धता न्यूनतम 92% से लेकर अधिकतम 98% तक होती है। अलग-अलग शुद्धता का पेंटाएरीथ्रिटोल और कुछ नहीं है बल्कि समान उत्पाद है और यह वर्तमान जांच के दायरे में आता है। पर्सटार्प ने यह अनुरोध किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तु के एक प्रमुख उत्पादक हैं और वे तकनीकी पेंटा 95% का विनिर्माण करते हैं औ स्वीडन से मोनोपेंटा 98% तथा तकनीकी पेंटा 89-90% जैसी कच्ची सामग्री का आयात करते हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि अलग-अलग ग्रेडों के इन तीनों पेंटा को समान उत्पाद माना जा सकता है।

7. हितबद्ध पक्षकार द्वारा दायर अनुरोधों की जांच के बाद यह नोट किया जाता है कि पर्सटार्प एजेज के इस दावे की पुष्टि साक्ष्य के साथ नहीं की गई थी कि आयातित कच्ची सामग्री का आगे और प्रसंस्करण जांचाधीन संबद्ध वस्तु के विनिर्माण के लिए किया जाता है और उनकी इकाई में किए गए भौके पर सत्यापन के दौरे के समय यह पाया गया था कि 89%-98% के पेंटा की अलग-अलग शुद्धताओं की आपूर्ति पेंट उद्योग को की गई थी। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त विभिन्न सामग्री के अलावा, प्राधिकारी ने पर्सटार्प एजेज के परिसर में किए गए सत्यापन पर भरोसा किया। यह पाया गया था कि कंपनी ने विचाराधीन संबद्ध वस्तु की दो अलग-अलग शुद्धताओं के पेंटाएरीथ्रीटोल की ब्लेंडिंग और रीबैगिंग की है। यह भी पाया गया था कि आयातित उत्पादों की ब्लेंडिंग की प्रक्रिया में न तो उत्पाद की अनिवार्य विशेषताओं में कोई खास परिवर्तन होता है और न ही कंपनी किसी खास संयंत्र व उपकरण, निवेश, विनिर्माण प्रक्रिया और उत्पादन कार्यकलाप का उपयोग करती है। उत्पाद के बारे में उपलब्ध तकनीकी साहित्य में पेंटाएरीथ्रीटोल और डाई पेंटाएरीथ्रीटोल को दो अलग उत्पादों के रूप में भेद किया गया है। तथापि, पर्सटार्प एजेज द्वारा अपने इस दावे की पुष्टि हेतु ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिया गया था कि मोनोपेंटा और तकनीकी पेंटा दो अलग-अलग उत्पाद हैं जिनके अलग-अलग उत्पाद गुणधर्म, उत्पादन प्रक्रिया, कार्य एवं उपयोग हैं और कीमत के संबंध में ये अत्यधिक भिन्न हैं। इसके विपरीत जांच से ये पता चला कि दोनों प्रकार में अनिवार्यता समान उत्पाद गुणधर्म हैं जिनका उत्पादन समान उत्पाद प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जिनके समान कार्य एवं उपयोग हैं और जो समान सीमाशुल्क वर्गीकरण में आते हैं। घरेलू उद्योग ने पेंटा (सभी ग्रेड) के लिए एस आई ओ एन मानदंड प्रस्तुत किए हैं जिनका तात्पर्य यह है कि पेंटा के विभिन्न ग्रेड समान उत्पाद हैं और इनकी पुष्टि प्रयोक्ता घरेलू उद्योग के उत्तर से भी की गई थी। इस विषय पर उपलब्ध तकनीकी साहित्य में पेंटाएरीथ्रीटोल और डाई पेंटाएरीथ्रीटोल के बीच दो अलग-अलग उत्पादों के रूप में भेद किया गया है न कि मोनोपेंटा और तकनीकी पेंटा के बीच और किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने मोनोपेंटा तथा तकनीकी पेंटा दो अलग-अलग उत्पाद होने के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पेंटाएरीथ्रीटोल तकनीकी ग्रेड (टी जी) अथवा नाइट्रेशन ग्रेड (एन जी) के रूप में ज्ञात दो ग्रेडों में हो सकता है लेकिन इन दोनों ग्रेडों के बीच कोई खास अंतर नहीं पाया गया है और इन ग्रेडों का उत्पादन समान प्रक्रिया से होता है। घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री सूचना के सत्यापन के दौरान उनकी बिक्री और उत्पाद शुल्क रजिस्टर से इस बात की पुष्टि की गई थी कि पेंट उद्योग अपने विनिर्माण ढांचे में पेंटा की अलग-अलग शुद्धताओं का उपयोग कर रहा है। सत्यापन दौरे के दौरान घरेलू उद्योग ने यह दर्शाया कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पेंटा के समग्र उत्पादन के 2% से कम का उत्पादन नाइट्रेशन ग्रेड के उत्पादन में होता है जबकि 97% से अधिक का उत्पादन तकनीकी ग्रेड के रूप में होता है और ये पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर समान उत्पाद हैं। प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर यह नोट किया जाता है कि नाम के साथ-साथ शुद्धता में मात्र परिवर्तन (जो 92%-98% के बीच है) से आयातित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद अर्थात् पेंटाएरीथ्रीटोल से भिन्न नहीं हो जाता है। यह भी नोट किया जाता है कि हालांकि पर्सटार्प एजेज द्वारा पुनः बिक्रीत उत्पाद आयातित उत्पाद से भिन्न हो सकता

है और बिक्री से पूर्व उसका प्रसंस्करण किया जा सकता है । तथापि, पुनः बिक्रीत उत्पाद पेंटाएरीथ्रीटोल ही रहता है और पर्सटार्प एजेज ने ऐसा कोई सत्यापनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि आयातित उत्पाद और पुनः बिक्रीत उत्पाद पाटनरोधी उत्पाद की बिक्री के भीतर समान उत्पादन नहीं है ।

8. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में यह विनिर्दिष्ट है कि "समान वस्तु" का तात्पर्य ऐसे किसी वस्तु से है जो जांचाधीन उत्पाद के समनुरूप या हर प्रकार से समान है और ऐसे किसी वस्तु के अभाव में ऐसी अन्य वस्तु से है जिसकी विशेषताएं जांचाधीन वस्तुओं की विशेषताओं से अत्यधिक मिलती-जुलती हैं । इस नियम के संदर्भ में घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद संबद्ध वस्तु के बीच अंतर की पुष्टि करने के लिए कोई पर्याप्त/वास्तविक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था । आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को ऐसे अनेक मापदंडों के अनुसार आयातित उत्पाद से तुलनीय पाया गया है जिनमें उत्पाद के गुणधर्म, उत्पादन प्रक्रिया, कार्य एवं उपयोग, कीमत, सीमाशुल्क वर्गीकरण शामिल है । घरेलू उत्पाद को आयातित उत्पाद से वाणिज्यिक और तकनीकी दृष्टि से प्रतिस्थापनीय पाया गया है । निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष लाए गए साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु है ।

9. कंपनी के दावों का सत्यापन करने के लिए प्राधिकारी ने मै. पर्सटार्प एजेज के संयंत्र का मौके पर सत्यापन किया । यह पाया गया था कि सिल्वासा स्थित यूनिट-II (जहां आयातित उत्पाद का मिश्रण किया जाता है) प्रचालनरत नहीं है । कंपनी से यह कहा गया था कि वह उसके द्वारा किए गए उत्पादन कार्यकलापों का विस्तार से स्पष्टीकरण दें और निम्नलिखित के बारे में सूचना भी प्रदान करें :

- उत्पादन प्रौद्योगिकी
- स्थापित संयंत्र एवं उपकरण
- निवेश
- उत्पादन प्रक्रिया
- लागत सूचना के प्रपत्र के अनुसार खपत की गई कच्ची सामग्री की सूची और खपत का ब्यौरा तथा लागत सूचना के प्रपत्र के अनुसार प्रति इकाई खपत का ब्यौरा ।
- खपत की गई "कच्ची सामग्री"/उत्पादित "तैयार उत्पाद" के विनिर्देशन
- आयाति पेंटा/घरेलू बाजार में बेचे गए पेंटा के विभिन्न कार्य एवं उपयोग ।

10. कंपनी ने पूर्ण सूचना प्रदान नहीं की । यह पाया गया कि उत्पादन प्रक्रिया महज दो अलग-अलग शुद्धता के पेंटा का मिश्रण है जिससे अलग शुद्धता के पेंटा का उत्पादन होता है । पर्सटार्प द्वारा न तो इस बात की पुष्टि की गई है कि आयातित उत्पाद और पुनः बिक्रीत उत्पाद पर्याप्तः अलग हैं और न ही वे यह सिद्ध कर सके कि उनके द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया की वजह से अलग उत्पाद का उत्पादन होता है । कंपनी से यह भी कहा गया था कि वह दो अलग-अलग संयंत्रों में उत्पादित पेंटाएरीथ्रीटोल की उत्पादन लागत का पृथक ब्यौरा प्रदान करें । तथापि, उत्पादन लागत के बारे में ऐसी कोई सूचना प्रदान नहीं की गई थी । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि आयातित पेंटाएरीथ्रीटोल और कंपनी द्वारा दो अलग-अलग इकाइयों में उत्पादित और बिक्रीत पेंटाएरीथ्रीटोल तथा घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्त पेंटाएरीथ्रीटोल समान उत्पाद नहीं हैं ।

11. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि, कंपनी ने यह दावा किया है कि वह भी घरेलू उद्योग है तथापि, वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं कर सकी । कंपनी न तो यह सिद्ध करने में समर्थ रही कि उसके द्वारा आयातित वस्तु उसके द्वारा बेची गई वस्तु के समान उत्पाद नहीं है और न ही कंपनी यह सिद्ध कर सकी कि उसके द्वारा आयातित वस्तु और घरेलू उद्योग (कनोरिया कैमिकल्स) द्वारा उत्पादित और बिक्रीत वस्तु समान उत्पाद नहीं हैं ।

15. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके इस दावे के संबंध में किए गए अनुरोधों कि पर्सटार्प एजेज द्वारा आयातित वस्तु कच्ची सामग्री है न कि जांचाधीन वस्तु है, की जांच करने के बाद प्राधिकारी ने यह पाया कि पर्सटार्प एजेज द्वारा आयातित वस्तु और कुछ नहीं है बल्कि विभिन्न ग्रेडों का पेंटाएरीथ्रीटोल है । प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु का एक आयातक और संबद्ध वस्तु के निर्यातक से संबद्ध पर्सटार्प एजेज को घरेलू उद्योग के घटक से अलग रखना स्वयं पर्याप्त है । अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस कंपनी को बाहर रखना न्यायोचित है क्योंकि उसने अपनी संबद्ध कंपनी से पर्याप्त मात्रा में संबद्ध वस्तु का आयात किया है और उसने निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किए गए अनुरोधों के बावजूद घरेलू उद्योग माने जाने के उसके दावे के बारे में लागत या क्षति से संबंधित कोई सूचना प्रदान नहीं की है । एशियन पेंट्स एक अन्य उत्पादक है जिसने अपनी आबद्ध जरूरतों के लिए उत्पाद का पर्याप्त उत्पादन किया है । आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि एशियन पेंट्स के उत्पादन को अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि एशियन पेंट्स का उत्पादन पण्य बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता और उसने भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु के ऐसे पाटन से हुई क्षति का अनुभव नहीं किया है । आवेदक के तर्कों की जांच के बाद प्राधिकारी ने आवेदक के आधार के निर्धारण हेतु एशियन पेंट्स के उत्पादन को शामिल करने के लिए इसे उचित पाया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि पर्सटार्प, स्वीडन और पर्सटार्प एजेज, इंडिया पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के मद्देनजर एक-दूसरे से संबंधित हैं । चूंकि पर्सटार्प, इंडिया पर्सटार्प, स्वीडन की एक सहायक कंपनी है और इसलिए परवर्ती कंपनी पूर्ववर्ती पर नियंत्रण रखने की स्थिति में है और

इसलिए घरेलू उद्योग के घटक के रूप में बाहर रखना उचित पाया गया था । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(क) और (ख) तथा नियम 2(ख) की अपेक्षा के अनुसार आवेदक आधार संबंधी मानदंड को पूरा करता है और वह घरेलू उद्योग है ।

13. आस्ट्रिया, चीन जन.गण., ईरान, मलेशिया, रूस और थाइलैंड के मूल के या वहां से निर्यातित "रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांचों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम

(घ) घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

16. पाटनरोधी नियम के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग का निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा ।

17. घरेलू उद्योग की ओर ए एसोसिएशन ऑफ कार्बन ब्लैक मैनुफैक्चरर्स ने आवेदन किया है, मैसर्स फिलिप्स कार्बन ब्लैक लि. और मै. हाई-टैंक कार्बन ने अति की सूचना उपलब्ध करवा दी है जबकि मै. कॉन्टीनेन्टल कार्बन इंडिया लि. ने आवेदन का समर्थन किया है ।

हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए मुद्दे

18. मै. जियांग्सी ब्लैक कैट कार्बन ब्लैक कंपनी लि. (ब्लैक कैट) ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क किया है कि आवेदन का मै. हाई-टैंक कार्बन इंडिया का मैसर्स लाओजिंग बिरला कंपनी लि. (चीन) और मै. थाई कार्बन ब्लैक पब्लिक कंपनी लि. (थाईलैंड) के साथ संबंध के आलोक में कोई आधार नहीं है । इसके अलावा, फिलिप्स कार्बन ही मै. सीएट लि., जो उनकी संबद्ध कंपनी है, द्वारा किए गए आयातों के मदेनजर पात्र नहीं है ।

घरेलू उद्योग के विचार

19. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि नियम 2(ख) में इस कारण से संशोधन किया गया है क्योंकि ऐसी किसी कंपनी, जिसे विदेशी आपूर्तिकर्ता या किसी भारतीय आयातक से संबद्ध पाया गया है, या जो स्वयं उक्त सामग्री की आयातक है, को शामिल करने या अलग रखने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान करना अपेक्षित था। चूंकि आयातों या संबंध की वास्तविकता से स्वतः अलग रखने का अर्थ नहीं निकलता है और चूंकि सामान्य/साधारण नियम सभी पार्टियों को शामिल करने का है, इसलिए अलग रखने की मांग करने वाली हितबद्ध पार्टियों को यह सिद्ध करना अपेक्षित होता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इस प्रकार से अलग रखा जाना वस्तुतः आवश्यक है। तथापि, महज दावे को छोड़कर हितबद्ध पार्टियों ने कोई तथ्यपरक सामग्री प्रदान नहीं की है जिससे इन दोनों कंपनियों को अलग रखना न्यायोचित ठहराया जा सके। मै. सिएट लि. तथा मै. फिलिप्स कार्बन ब्लैक लि. संबद्ध कंपनियां नहीं हैं। आवेदक ने आगे यह अनुरोध किया है कि यद्यपि हितबद्ध पार्टियों ने अलग रखने की जरूरत को न्यायोचित नहीं ठहराया है, तथापि मामले के तथ्यों से किसी कंपनी को अलग रखना न्यायोचित नहीं ठहरता है। आवेदक ने इस संबंध में पाटनरोधी पाठ्य पुस्तकों और अन्य जांच प्राधिकारियों की पद्धतियों का हवाला दिया है और यह तर्क दिया है कि इन कंपनियों को अलग रखने का कोई भी औचित्य नहीं है। दोनों कंपनियों ने अपना उत्पादन कम नहीं किया है और व्यापार शुरू नहीं किया है। वस्तुतः मै. हाईटैक कार्बन, जो संबद्ध थाई कंपनी है, ने अग्रिम लाइसेंस के तहत ही समूची सामग्री का निर्यात किया है। (जबकि चीन की संबद्ध कंपनी से कोई आयात नहीं हुआ है)। मै. सिएट लि. के मामले में भी अधिकांश आयात अग्रिम लाइसेंस पर हुए हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि हाईटैक कार्बन की संबद्ध कंपनी द्वारा थाईलैंड से किए गए निर्यातों की मात्रा भारत में उत्पाद के कुल आयातों और खपत के अनुसार काफी कम है। इसी प्रकार मै. सिएट लि. द्वारा किए गए आयातों का हिस्सा उसकी कुल बिक्री का अत्यंत कम बनता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

20. प्राधिकारी ने नोट किया है कि मै. हाई टैक कार्बन का मै. थाई कार्बन ब्लैक पब्लिक कंपनी और मै. लिओविंग बिरला कंपनी लि. से संबंध है। मै. हाई-टैक कार्बन ने दावा किया है कि मै. लिओविंग बिरला कंपनी ने भारतीय बाजार में कार्बन ब्लैक का निर्यात नहीं किया है। हालांकि मैसर्स थाई कार्बन ब्लैक पब्लिक ने भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है तथा जांच अवधि में एम.टी. में 518624 एम.टी. के कुल निर्यात योग में से उनका पूरी निर्यात मात्रा केवल 21.8 एम.टी. ही है। कुछ हितबद्ध पार्टियों ने मै. हाईटैक की संबद्ध कंपनी द्वारा किए गए निर्यात के मद्देनजर उसे बाहर रखने के बारे में दिए गए अपने तर्क को दोहराया है, तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाई संबद्ध कंपनी द्वारा किए गए निर्यात इतने अधिक नहीं हैं और यह ऐसी स्थिति में नहीं किए गए हैं जिससे यह माना जा सके कि मै. हाईटैक पर घरेलू उद्योग के भाग के रूप में अपात्र मानने की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हाईटैक कार्बन ने आयात और व्यापार नहीं किया है। कंपनी का मुख्य ध्यान उत्पादन पर अधिक केन्द्रित रहा है।

इसके अलावा, रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि मै. फिलिप्स कार्बन ब्लैक लि. और मै. सिएट लि. संबद्ध कंपनियां हैं। यद्यपि एटीएमए ने एक हितबद्ध पार्टी के रूप में वर्तमान जांच में भाग लिया है और मै. सिएट लि. उनका सदस्य है, तथापि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि मै. सिएट लि. ने सीमाशुल्क के भुगतान के बाद संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का भारी मात्रा में आयात किया है।

21. प्राधिकारी ने नोट किया है कि थाई कार्बन ब्लैक द्वारा किया गया निर्यात भारत के उत्पादन और खपत की तुलना में बहुत ही कम है। इसके साथ-साथ यह स्थापित नहीं किया गया है कि मै. हाई टैक कार्बन को घरेलू उद्योग की परिधि से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि निर्यात संबंध रखने वाले कंपनी द्वारा किए गए हैं। प्राधिकारी उचित समझते हैं कि हाई-टेक कार्बन को घरेलू उद्योग के क्षेत्र में शामिल किया जाए। जहां तक मै. फिलिप्स कार्बन की पात्रता का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसे बाहर रखने को न्यायोचित ठहराने के लिए हितबद्ध पार्टियों ने पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।

22. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार मै. फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड और हाई टैक कार्बन का उत्पादन समान वस्तु के घरेलू उत्पादन के बड़े हिस्से में शामिल है जो भारत के उत्पादन के 50% से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा, याचिका समर्थन मै. कंटीनेंटल कार्बन ने किया है। इस प्रकार आवेदन, पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) और 5(3) की अपेक्षाओं का समाधान करता है। इसके आगे, मै. फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड और मैसर्स हाई-टैक कार्बन को वर्तमान प्रयोजन से पाटन-रोधी नियमों के नियम 2(ख) के साथ पढ़ने पर नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग के तहत माना जा रहा है।

• याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं असंबद्ध निर्यातक से आयात

14. आयोग का निर्णय सं. 307/2000/ईसीएससी दिनांक 10 फरवरी, 2000, जिसमें चीन जन.गण., भारत तथा रोमानिया के मूल के नॉन एलॉय स्टील के कतिपय हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया। ऑफिशियल जर्नल एल 036, 11/02/2000 पृ. 0004-0019

1. सामुदायिक उद्योग की परिभाषा

1.1 कुल सामुदायिक उत्पादन

(39) समुदाय के भीतर संबद्ध उत्पाद का विनिर्माण निम्नलिखित द्वारा किया जाता है :

- 12 उत्पादक जिन्होंने शिकायत दर्ज की है।

- 5 सामुदायिक उत्पादक जिन्होंने शिकायत का समर्थन किया है, और

- 1 सामुदायिक उत्पादक जिसने शिकायत का समर्थन नहीं किया।

(40) कुछ निर्यातक उत्पादकों ने यह तर्क दिया है कि कुछेक शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादकों ने "जांच अवधि" से पूर्व की अवधि में संबद्ध देशों से गैरे अलॉय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों का आयात किया था । अतः आयोग ने यह जांच की कि क्या उनमें से किसी को सामुदायिक उत्पादन की परिभाषा से अलग रखा जाना चाहिए ।

यह पाया गया था कि उपर्युक्त किसी भी उत्पादक ने स्वयं संदर्भाधीन उत्पाद का आयात नहीं किया । तथापि, शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादक के रूप में उसी कारपोरेट ग्रुप की एक व्यापारिक कंपनी ने जांच अवधि के दौरान ऐसे आयात किए थे । यह कंपनी जिसने उसी ग्रुप के उत्पादक सहित विश्व भर से इस्पात की खरीद कर उसकी बिक्री मुख्यतः अपने खुद के खाते से तीसरे देशों को की थी, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए पाई गई थी । वस्तुतः ऐसे समूह की संरचना जिसकी ये दोनों कंपनियां हैं, ऐसी है कि प्रत्येक कंपनी अपने खुद के वित्तीय लेखे रखती है, पृथक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और नियंत्रक कंपनी के साथ कोई लाभ तथा हानि अंतरण करार नहीं रखती है । इसके अलावा, पृथक आय कर विवरणी दायर की जाती है, प्रत्येक का अपना निदेशक मंडल है और समूह की अन्य कंपनियों के साथ व्यापारिक संबंध ऐसी अन्य कंपनियों पर लागू समान शर्तों पर दूरवर्ती आधार पर रखे जाते हैं जिनके साथ कोई विधिक संबंध मौजूद नहीं है । अतः इन खरीददारी से संबद्ध उत्पादक के दर्जे पर प्रभाव नहीं पड़ता है और यह माना गया था कि हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के किसी उत्पादक को सामुदायिक उत्पादक की परिभाषा से अलग रखने का कोई आधार नहीं है ।

(41) अतः उपर्युक्त गैर-अलॉय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के 18 सामुदायिक उत्पादक मूल निर्णय के अनुच्छेद 4(1) के मूल अर्थ के भीतर सामुदायिक उत्पादन करते हैं ।

1.2 सामुदायिक उद्योग

(42) जिन 12 उत्पादकों ने शिकायत दर्ज की है, उनमें से 10 ने आयोग की प्रश्नावली का उत्तर दिया, मौके पर जांच की अनुमति दी और आयोग को अनुरोध किए जाने पर अतिरिक्त सूचना प्रदान की; अतः उन्हें जांच में सहयोगकर्ता माना गया था ।

ये 10 सामुदायिक उत्पादक हैं : एसीरालिया (सपेन), ब्रिटिश स्टील (यूनाइटेड किंगडम), डिलिंगर (जर्मनी), जी टी एस (फ्रांस), आ एल वी ए (इटली), पालिनी एंड बरटोली (इटली), सेलजिडुर (जर्मनी), थिसेन (जर्मनी), ट्रामेटल (इटली), वोईस्ट अल्पाइन (ऑस्ट्रिया) । आई पी में इन कंपनियों का उत्पादन कुल सामुदायिक उत्पादन के 75% से अधिक बनता है और इस प्रकार इनका उत्पादन मूल निर्णय के अनुच्छेद 5(4) के अर्थ के भीतर सामुदायिक उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है और इसलिए इन्हें "सामुदायिक उद्योग" कहा गया है ।

(43) इनमें से 8 कंपनियां पूर्णतः एकीकृत हैं अर्थात् वे उस समूह के भीतर, जिस समूह की वे हैं, संबद्ध उत्पाद की रोलिंग हेतु प्रयुक्त स्टील रलैबों की खरीद या बिक्री करती हैं । शेष दो

कंपनियां तथाकथित वीरोलर्स हैं जो संबद्ध उत्पाद के विनिर्माण हेतु मुक्त बाजार से स्टील स्लैबों की खरीद करती हैं ।

अनंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ 7 शिकायतकर्ता उत्पादकों के परिसरों में मौके पर जांच की गई थी । इन 7 कंपनियों का कुल उत्पादन सामुदायिक उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 80% बनता है ।

1.3 अन्य सामुदायिक उत्पादक

(44) 12 शिकायतकर्ता उत्पादकों के कुल उत्पादन के 2% से कम उत्पादन करने वाले शेष दो शिकायतकर्ता उत्पादकों ने आयोग की प्रश्नावलियों का उत्तर नहीं दिया; अतः उन्हें वर्तमान जांच के दायरे में सहयोगकर्ता नहीं माना गया और इस प्रकार उन्हें सामुदायिक उद्योग का भाग नहीं माना गया ।

6 अन्य उत्पादकों में से एक समर्थक ने आयोग की प्रश्नावलियों का आंशिक उत्तर दिया और मौके पर जांच की सैद्धांतिक अनुमति दी जबकि अन्य 5 कंपनियों ने आयोग की प्रश्नावलियों का उत्तर ही नहीं दिया ।

इन 8 कंपनियों को एतदपश्चात् "अन्य सामुदायिक उत्पादक" कहा गया है ।

15. आयोग विनियमन (ईसी) सं. 1497/2001 दिनांक 20 जुलाई, 2001, जिसमें बेलारूस, बुल्गारिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, लीबिया, लिथुआनिया, रोमानिया और यूक्रेन के मूल के यूरिया के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया और बुल्गारिया के निर्यातक उत्पादक का अभिवचन स्वीकार किया गया एवं मिस्र एवं पौलैण्ड के मूल के यूरिया के आयातों से संबंधित कार्यवाही समाप्त की गई । ऑफिशियल जर्नल एल 197, 21/07/2001 पृ. 0004-0027

1. सामुदायिक उद्योग की परिभाषा

(154) 10 शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादकों में से एक (कैमीरा एग्रो रोजेनबर्ग बी वी) ने आयोग के साथ सहयोग नहीं किया और इसलिए उसे सामुदायिक उद्योग का भाग नहीं माना गया । एक अन्य सामुदायिक भागीदार (आयरिस फर्टीलाइजर इंड लि.) ने अपेक्षित प्रपत्र में अनुरोध की गई सूचना प्रदान नहीं की और उसे आयोग के साथ सहयोग न करने वाला पाया गया और इस प्रकार वह सामुदायिक उद्योग का भाग नहीं है ।

(115) कई निर्यातक उत्पादकों ने यह दावा किया कि चूंकि कुछ सामुदायिक उत्पादकों ने संबद्ध देशों से यूरिया की खरीद और उसका आयात भी किया है, इसलिए इन उत्पादकों को सामुदायिक उद्योग की परिभाषा से अलग रखा जाना चाहिए ।

(156) जांच से इस बात की पुष्टि हुई कि कुछ शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादकों ने संबद्ध देशों सहित समुदाय के भीतर और बाहर के दोनों स्रोतों से संबद्ध उत्पाद की खरीद की। तथापि, इन खरीदों का एक बड़ा हिस्सा अल्प मात्रा में था और यह खरीद रखरखाव के कारण आपूर्ति में आई कमी को पूरा करने के लिए की गई थी। एक कंपनी ने आई पी के दौरान पर्याप्त मात्रा में खरीद की जो उसके उत्पादन के 20% के बराबर है। ये खरीददारियां अपने खुद की उत्पाद रेंज की पूर्ति हेतु की गई थी जो कंपनी को यूरिया के सामुदायिक उत्पादक से इतर कुछ और मानने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। इन कारणों से अनंतिम रूप से यह निर्धारित किया जाता है कि सभी आठों कंपनियों को सामुदायिक उत्पादन में शामिल किया जा सकता है।

(157) चूंकि इन 8 शिकायतकर्ता सहयोगकर्ता सामुदायिक उत्पादकों का उत्पादन यूरिया के सामुदायिक उत्पादन के 76% से अधिक बनता है, इसलिए वे मूल विनियम के अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 5(4) के अर्थ के भीतर सामुदायिक उद्योग हैं।

16. आयोग विनियमन (ईईसी) सं. 1418/88 दिनांक 17 मई, 1988, जिसमें जापान के मूल के सीरियल इम्पेक्ट डॉट-मॉट्रिक्स प्रिंटर्स के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया। ऑफिशियल जर्नल एल 130, 26/05/1988 पृ.सं. 0012-0033

छ. सामुदायिक उद्योग

(60) समुदाय में एस आई डी एम प्रिंटर्स के 8 उत्पादक हैं। जांच से यह पता चला है कि जांच अवधि के दौरान 4 यूरो प्रिंट सदस्यों ने एस आई डी एम प्रिंटर्स के कुल सामुदायिक उत्पादन के लगभग 65% का विनिर्माण किया और इस प्रकार विनियम (ई ई सी) सं. 2176/84 के अनुच्छेद 4(5) के अर्थ के भीतर समान उत्पाद के कुल सामुदायिक उत्पादन का यह एक बड़ा भाग बनता है

(61) आयोग ने यह भी पाया कि यूरो प्रिंट के तीन सदस्यों अर्थात् मोनेसमैन-टैली, हीसी एंड फिलिप्स ने जांच अवधि के दौरान ऐसी मात्रा में जापान से एस आई डी एम प्रिंटर्स का आयात किया जो इन सामुदायिक उत्पादकों की कुल बिक्री की मात्रा के रूप में क्रमशः 51%, 42% और 11% बनती है (यह अनुमान लगाते हुए कि सभी आयातित प्रिंटर्स को बेच भी दिया गया है)

(62) इस संबंध में सी जे प्रिंट ने यह अनुरोध किया कि एक शिकायतकर्ता को उस स्थिति में अलग रखा जाना चाहिए। यदि उसके आयातों को अंतरिम रक्षात्मक उपाय माना जाता हो और यदि वह सामान्यतः अपने संसाधनों का उपयोग इन स्रोतों से उत्पादों के आयात हेतु बहुराष्ट्रीय निगम के रूप में कर रहा हो। जिसका तात्पर्य यह है कि वह विश्व में कहीं भी स्थित स्रोत से न्यूनतम कीमत पर सर्वोत्तम उत्पादों को उपलब्ध करवा सकता है। परिणामतः सी जे प्रिंट के अनुसार, तीनों आयातकर्ता सामुदायिक उत्पादकों को अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि उनके आयातों को अंतरिम रक्षात्मक उपाय नहीं माना जा सकता क्योंकि आयातित उत्पादों की मात्रा

पर्याप्त है जिनकी पुनः बिक्री भारी मुनाफे पर अपने खुद के ब्रांड नाम से की जाती है और इससे बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है ।

(63) इन तर्कों के संबंध में आयोग ने यह नोट किया कि विनियम (ई ई सी) सं. 2176/84 के अनुच्छेद 4(5) के अंतर्गत सामुदायिक संस्थानों के लिए इस आशय का कुछ विवेकाधिकार रह जाता है कि क्या उन्हें कुछेक आयातकर्ता सामुदायिक उत्पादकों में शामिल किया जाए या नहीं । इस विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए आयोग ने इस बात पर विचार किया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगी बड़ी फर्मों के लिए अन्य उत्पादकों से अपनी रेंज के मॉडलों के एक भाग की खरीद करना आम बात है । मात्र यह तथ्य कि एक सामुदायिक उत्पादक ने उस प्रकार की वस्तु का आयात किया है जिसके बारे में पाटन पाया गया है और जिसकी पुनः बिक्री उचित लाभ मार्जिन के साथ की है, स्वतः उसे पाटन के बारे में शिकायत करने और क्षति को हिसाब में लेने से वंचित नहीं करता है । यह निर्णय लेने में कि क्या किसी सामुदायिक उत्पादक पर अलग रखने के बारे में विचार किया जा सकता है, आयोग ने इस बात पर ध्यान दिया कि क्या पाटित उत्पादों के आयात और सामुदायिक बाजार में उनकी बिक्री के पीछे कारणों की वजह से ऐसे आयातों की मात्रा अथवा किसी अन्य परिस्थिति पर किसी उत्पादक की ओर से सामान्य एवं ठोस व्यापार पद्धति के रूप में विचार किया जा सकता है । इस संबंध में खास तौर पर यह महत्वपूर्ण है कि इन आयातों पर कितनी सीमा तक आत्मरक्षा में किए गए आयात के रूप में विचार किया जा सकता है ।

(64) जहां तक इन आयातों के कारणों का संबंध है, आयोग ने यह पाया है कि सामुदायिक उत्पादकों द्वारा आयातित सभी प्रिंटर मॉडल एस आई डी एम प्रिंटर बाजार के अंतिम खंड के हैं । वर्ष 1983 से पूर्व सभी तीनों कंपनियों का अपने खुद के विनिर्मित प्रिंटर्स के साथ इस बाजार खंड में प्रतिनिधित्व था । मौजूदा प्रिंटर मॉडलों के स्थान पर जापानी मूल के प्रिंटर लाने के निर्णय सर्वप्रथम इस आम धारणा पर आधारित थे कि बाजार में अपनी स्थिति बचाए रखी जाए अतः एस आई डी एम प्रिंटर विनिर्माता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह प्रिंटर्स की संपूर्ण रेंज की पेशकश करे और सभी बाजार खंडों में प्रतिनिधित्व करे । वस्तुतः पूरी रेंज की पेशकश किए बिना तीनों कंपनियों के समक्ष बिक्री गंवाने और अन्य बाजार खंडों में ग्राहकों को खोने का जोखिम उठाया होगा और परिणामतः ये पूर्णतः प्रिंटर बाजार से बाहर हो गई होती । द्वितीयतः जापान से आयातों के कारण सामुदायिक प्रिंटर बाजार में कम कीमत स्तर के कारण किसी नए प्रिंटर मॉडल के विकास और उत्पादन की लागत उचित समय के भीतर वसूल नहीं हुई होगी । जिस कीमत पर जापानी विनिर्माताओं ने पेशकश की है वह इतनी कम है कि सामुदायिक बाजार में पुनः बिक्री कीमत के न्यूनतम स्तर पर आयातित उत्पाद की पुनः बिक्री उचित लाभ पर की जा सकती है ।

(65) जहां तक इन आयातों की मात्रा और अन्य परिस्थितियों का संबंध है, आयोग ने इस बात पर विचार किया कि संबंधित मात्राएं इतनी अधिक हैं कि तीनों संबद्ध कंपनियों को बाहर रखना आवश्यक हो गया है । आयात की मात्रा तीनों कंपनियों की कुल निवल बिक्री की तुलना में अत्यंत लघु अनुपात में है । ऐसा इसलिए है कि समस्त आयात तुलनात्मक रूप से कम कीमत के प्रिंटर्स के हुए थे ।

(66) इसके अलावा, आयातित प्रिंटर्स की संख्या बाजार के अंतिम छोर में समुदाय में कुल बिक्री का एक संतुलित अनुपात है। वर्ष 1983 में सामुदायिक उत्पादकों द्वारा जापान से 4460 यूनितों का आयात किया गया था जो सामुदायिक खपत का 0,5% था। वर्ष 1986 में सामुदायिक उत्पादकों ने 91138 यूनितों का आयात किया अर्थात् यह कुल सामुदायिक खपत का लगभग 4,3% था।

(67) जहां तक इन आयातित प्रिंटर्स की बिक्री पर लाभ मार्जिन का संबंध है, जांच से यह पता चला है कि ये सामुदायिक उत्पादकों के प्रिंटर्स की बिक्री पर प्राप्त आय से 5% से अधिक नहीं था (बिक्री पर आय के % के रूप में)।

(68) इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग का यह मत है कि उन दोनों कारणों को बाजार में बने रहने के लिए आत्मरक्षा के लिए आवश्यक उचित उपाय के रूप में विचार किया जा सकता है जिसकी वजह से अन्य परिस्थितियों के साथ-साथ जापान से तीनों कंपनियों ने एस आई डी एम प्रिंटर्स का आयात किया। चूंकि 1983 के बाद सामुदायिक उत्पादकों के लिए बाजारी स्थितियां खराब हो गई, इसलिए इस तथ्य को इस कार्यवाही में निर्णायक नहीं माना जा सकता कि ये आयात अस्थायी उपाय नहीं हैं। इस प्रकार आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ जिन तीनों यूरो प्रिंट सदस्यों ने जापान से पाटित एस आई डी एम प्रिंटर्स का आयात किया है, उन्हें सामुदायिक उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले सामुदायिक उत्पादकों से अलग नहीं रखा जाना चाहिए।

(69) अतः आयोग ने "सामुदायिक उद्योग" शब्द का अर्थ निरूपण यूरो प्रिंट के सदस्य चारों सामुदायिक उत्पादकों के संदर्भ के रूप में किया है।

17. आयोग विनियमन (ई सी) सं. 165/97 दिनांक 28 जनवरी, 1997, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य एवं इंडोनेशिया के मूल के टेक्सटाइल अपर युक्त कतिपय फुटवियर के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया। ऑफिशियल जर्नल एल 029, 31/01/1997 पृ. 0003-0018

घ. सामुदायिक उद्योग

1. शिकायतकर्ता उत्पादक

(54) जांच से इस बात की पुष्टि हुई कि मद (3) में किया गया निर्धारण सही है और तदनुसार आयोग इस कार्यवाई के प्रयोजनार्थ यह मानता है कि शिकायतकर्ता कंपनियां मूल विनियम के अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 5(4) के अर्थ के भीतर सामुदायिक उद्योग हैं।

2. अनुच्छेद 4(1)(क) की प्रयोज्यता : "सामुदायिक उद्योग" की परिभाषा

55. जांच के दौरान यह स्पष्ट हो गया है कि (6) में यथापरिभाषित प्रथम गुप में एक सामुदायिक उत्पादक वर्तमान जांच से संबद्ध देशों से पाटित उत्पाद का आयात भी कर रहा था । इन परिस्थितियों में आयोग ने मूल विनियम के अनुच्छेद 4(1)(क) को ध्यान में रखते हुए इस बात की जांच की कि क्या उक्त कंपनी को सामुदायिक उद्योग की परिभाषा से अलग रखा जाना चाहिए ।

इस संबंध में यह स्मरणीय है कि अनुच्छेद 4(1)(क) में ऐसे उत्पादकों के स्वतः अपवर्जन का प्रावधान नहीं है जिन्होंने स्वयं पाटित उत्पाद का आयात किया है । इसके बजाए सामुदायिक संस्थानों पर यह दायित्व डाला गया है कि वे इस बात की मामला दर मामला आधार पर जांच करें कि क्या ऐसी किसी स्थिति में किसी उत्पादक का अपवर्जन अपेक्षित है ।

उक्त जांच करने के प्रयोजनार्थ यह उचित प्रतीत होता है कि इस बात का निर्धारण किया जाए कि क्या उक्त कंपनी आयात पर आधारित अतिरिक्त कार्यकलाप के साथ अपने सामुदायिक उत्पादन की मात्रा पूर्ति करने के लिए मुख्यतः कोई उत्पादक थी अथवा क्या यह उक्त समुदाय में अपेक्षाकृत सीमित पारस्परिक उत्पादन के साथ एक आयातक थी । ऐसी कोई नीति उचित तथा समुदाय की पद्धति और न्यायालय द्वारा निर्णीत मामले (5) से सुसंगत है ।

जांच से यह पता चला कि संबद्ध देशों से पाटित उत्पादों का आयात संदर्भाधीन कंपनी के कारोबार के 25% से कम बनता है । अतः आयोग की यह राय है कि कंपनी के लिए मुख्य व्यापार उक्त समुदाय में फुटवियर का उत्पादन करना था और यह कि इसे पाटन के व्यवहारों से सुरक्षा नहीं दी गई थी । अतः मूल विनियम के अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 5(4) के प्रयोजनार्थ अन्य सहयोगकर्ता उत्पादकों के साथ-साथ उक्त कंपनी को सामुदायिक उद्योग माना गया था ।

18. आयोग विनियमन (ईसी) सं. 1069/97 दिनांक 12 जून, 1997, जिसमें मिस्र, भारत तथा पाकिस्तान के मूल के सूती बिछावनों के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया । ऑफिशियल जर्नल एल-156 पृ. 13/06/1997 पृ. 0011-0033

ड सामुदायिक उद्योग

1. सामुदायिक उद्योग की परिभाषा

(52) शिकायत में शामिल कंपनियों की सूची से नाम हटाने के बाद उनमें से 7 को शिकायतकर्ता नहीं पाया गया था ! आयोग ने यह पाया कि शेष कंपनियों का उत्पादन बैड लिनेन के सामुदायिक उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है और इससे मूल विनियम के अनुच्छेद 5(4) की अपेक्षाओं की पूर्ति होती है ।

कार्रवाई शुरू करने के बाद संबद्ध देशों से बैड लिनेन के निर्यातकों और आयातकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई संगठनों ने यह आरोप लगाया कि जिन उत्पादकों ने सामुदायिक उद्योग बनाया है, उनमें से कई उत्पादक इस कार्यवाई से संबंधित देशों से पाटित उत्पाद का आयात कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में आयोग ने इस बात की पुनः जांच की कि क्या मूल-विनियम के अनुच्छेद 4(1)(क) के उपबंधों के मद्देनजर इन कंपनियों को "सामुदायिक उद्योग" से बाहर रखा जाना चाहिए।

(53) इस पुनः जांच को करने के प्रयोजनार्थ और सामुदायिक संस्थानों की सुसंगत परंपरा के अनुसार यह उचित प्रतीत होता है कि इस बात का निर्धारण किया जाए कि क्या ये कंपनियां आयात पर आधारित अतिरिक्त कार्यकलाप के साथ अपने सामुदायिक उत्पादन की मात्रा पूर्ति करने के लिए मुख्यतः कोई उत्पादक थी ताकि वे उत्पादों की पूर्ण रेंज की पेशकश करने में समर्थ हो सकें अथवा क्या यह उक्त समुदाय में अपेक्षाकृत सीमित पारंपरिक उत्पादन के साथ एक आयातक थी।

(54) एक मामले को छोड़कर सभी मामले में जिन कंपनियों के बारे में संबद्ध देशों से बैडलिनेन का आयात करने का आरोप लगाया गया था, वे सामुदायिक उत्पादकों के नमूने में से चुनी गई थीं। (देखें मद (58 से (61))) अतः आयोग मौके पर सत्यापन दौरों के दौरान इन आयातों की मात्रा की जांच करने में सफल हुआ था। इन नमूनागत कंपनियों में से एक को छोड़कर सभी के लिए की गई जांच से यह पता चला कि संबद्ध देशों से पाटित उत्पादकों के आयातों का हिस्सा जांच अवधि में संदर्भाधीन कंपनियों के कारोबार के 10% से कम था। अतः आयोग की यह राय है कि उन कंपनियों का बचाव पाटित आयातों के प्रभाव से नहीं किया गया था और यह कि मूल विनियम के अनुच्छेद 4 के प्रयोजनार्थ अन्य सहयोगी उत्पादकों के साथ-साथ इन कंपनियों को सामुदायिक उद्योग की कंपनियां माना जाए।

एक अन्य नमूनागत कंपनी के मामले में यह पाया गया था कि जांच अवधि में बैडलिनेन की बिक्री का एक बड़ा भाग पाकिस्तानी मूल का था और यह भी कि उसकी बिक्री का एक छोटा हिस्सा उसके खुद के उत्पादन का था। इसके अलावा, यह प्रतीत हुआ कि कंपनी के भावी कार्यकलाप पुनः आयातों पर केन्द्रित होने की संभावना है। अतः इस कंपनी, जिसके मूल हित समुदाय के भीतर बैडलिनेन के उत्पादन में स्पष्ट तौर पर नहीं माने गए थे, को सामुदायिक उद्योग से हटा लिया गया था।

(55) चूंकि नमूनागत कंपनियों में से एक कंपनी को छोड़कर सभी के बारे में संबद्ध देशों से बैडलिनेन के आयात करने का आरोप लगाया गया था और जांच करने पर अपवर्जन हेतु पर्याप्त मात्रा में ऐसा करते हुए नहीं पाया गया था। इसलिए इस बात पर विचार किया गया है कि इस संबंध में निर्यातकों द्वारा लगाए गए आरोप बवजह और अविश्वसनीय हैं। परिणामतः नमूने से संबंधित जांच परिणाम के आधार पर एक गैर-नमूना कंपनी का अपवर्जन अपेक्षित नहीं है। अतः

इस कंपनी को सामुदायिक उद्योग की परिभाषा में बनाए रखा जाना चाहिए । इस मुद्दे का हर हालत में सामुदायिक उद्योग के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(56) तीन अन्य कंपनियों को हटा दिया गया था । एक मामले में कंपनी को बैडलिनेन का उत्पादनकर्ता नहीं पाया गया था । दो अन्य मामलों में कंपनियों ने सूचना के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया जिन पर समग्र सामुदायिक उद्योग के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए उन शिकायतकर्ताओं जिनका चयन सामुदायिक उत्पादकों के नमूने में नहीं किया गया था, के बारे में यूरो कॉटन तथा नेशनल एसोसिएशनों के जरिए विचार किया गया था ।

(57) जिन शेष 35 कंपनियों ने पूछाताछ में सहयोग किया और जो फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, आस्ट्रिया तथा फिनलैंड में स्थित हैं, जांच अवधि में उनका उत्पादन कुल सामुदायिक उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है । अतः इन कंपनियों को मूल विनियम के अनुच्छेद 4(1) के अनुसार सामुदायिक उद्योग माना गया था ।

2. नमूना लेना

(58) सामुदायिक उद्योग में कंपनियों की बड़ी संख्या के कारण मूल विनियम के अनुच्छेद 17 के अनुसार नमूना लेने का निर्णय लिया गया था ।

(59) 35 कंपनियों में से 27 कंपनियों का उत्पादन वर्ष 1995 में सामुदायिक उद्योग के उत्पादन का 96,7% और कुल सामुदायिक उत्पादन का 32,5% (नमूनों के चयन के समय उपलब्ध नवीनतम आंकड़े) बनता था जो जर्मनी, इटली, फ्रांस और पुर्तगाल में स्थित थी ।

(60) सामान्य नियम के अनुसार सामुदायिक उत्पादक मानक उत्पादों एवं आकारों में सदस्य देशों के बीच अंतर के कारण अपने खुद के सदस्य देश में अपने बैड लिनेन के उत्पादन के एक बड़े हिस्से की बिक्री करते हैं । ऐसा जर्मनी, फ्रांस और इटली के मामले में सच है जो समुदाय में बैडलिनेन के सबसे बड़े उत्पादक और अत्यंत महत्वपूर्ण आयातक, दोनों हैं । अतः इन सदस्य देशों के उत्पादक सामुदायिक उद्योग पर आयातों के प्रभाव का निर्धारण हेतु स्पष्ट अभ्यर्थी थे ।

पुर्तगाल में उत्पादक अपनी ओर से अन्य सदस्य देशों में अपना उत्पादन बड़ी मात्रा में बेचते हैं और वे शिकायतकर्ता कंपनियों के उत्पादन के लगभग एक तिहाई का प्रतिनिधित्व करते हैं । यद्यपि, पुर्तगाल, एक महत्वपूर्ण आयातक नहीं है, तथापि, यह निर्णय लिया गया कि उत्पादकों पर आयातों के प्रभाव का निर्धारण किया जाना चाहिए और नमूने में पुर्तगाल को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ।

(61) शिकायतकर्ता यूरो कॉटन के परामर्श से 19 कंपनियों की आरंभिक सूची तैयार की गई थी (फ्रांस की 6, जर्मनी की 6, इटली की 4 और पुर्तगाल की 1)

जांच के दौरान इन कंपनियों में से एक को जांच में सहयोग न करने की वजह से नमूने से हटा दिया गया था । इस अपवर्जन और मूल विनियम के अनुच्छेद 4(1)(क) के अंतर्गत एक अन्य कंपनी

के अपवर्जन के परिणामस्वरूप (देखें मद (54)) "नमूनागत उत्पादकों" के लिए प्रदत्त निम्नलिखित क्षति विश्लेषण संबंधी सूचना शेष 17 उत्पादकों द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित है जिनका उत्पादन कुल सामुदायिक उत्पादन का 20,7% और सामुदायिक उद्योग के उत्पादन का 61,6% बनता है। उन्होंने जर्मनी, इटली और पुर्तगाल की बड़ी सामुदायिक उद्योग की कंपनियों और छोटे उत्पादकों को भी शामिल किया। अतः आयोग ने इस नमूने को सामुदायिक उद्योग का प्रतिनिधि माना था।

19. आयोग विनियमन (ईसी) सं. 1023/97 दिनांक 6 जून, 1997, जिसमें पोलैंड के मूल के काष्ठ के चपटे पैलेटों के कतिपय आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया और इन आयातों के संबंध में कतिपय निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत अभिवचन स्वीकार किया गया। ऑफिशियल जर्नल एल 150 07/06/1997 पृ. 0004-0017

घ. सामुदायिक उद्योग

1. परिभाषा

(32) जिन सामुदायिक उत्पादकों ने इस कार्रवाई में शिकायत का समर्थन किया है, मूल विनियम के अनुच्छेद 4(1) और 5(4) के अनुसार उनका उत्पादन संबद्ध उत्पाद के कुल सामुदायिक उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है।

एक आयातक ने यह दावा किया कि समुदाय में कई उत्पादक पोलैंड से आरोपित पाटित पैलेटों का आयात कर रहे हैं। तथापि, जांच से यह पता नहीं चला है कि कुछ सामुदायिक उत्पादकों द्वारा पोलैंड से आयातित पैलेटों की मात्रा तुलनात्मक रूप से ऐसे उत्पादकों जिनके मूल हित स्पष्ट तौर पर समुदाय में पैलेटों के उत्पादन में है, के उत्पादन की तुलना में कम है। संदर्भाधीन सीमित आयात पोलैंड से कम कीमत के आयातों के प्रति रक्षात्मक प्रतिक्रिया थे।

परिणामतः पोलैंड से पैलेटों का आयात करने वाले उत्पादकों को सामुदायिक उद्योग के निर्धारण से अलग रखना अपेक्षित नहीं होगा। अतः जिन सामुदायिक उत्पादकों ने शिकायत का समर्थन किया है वे मूल विनियम के अनुच्छेद 7(1) के अर्थ के भीतर सामुदायिक उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

20. आयोग विनियमन (ई सी) सं. 255/2001 दिनांक 7 फरवरी, 2001, जिसमें चीन जन.गण. के मूल के इटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पेक्स फ्लोरेसेंट लैम्पों (सी एफ एल - आई) के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया। ऑफिशियल जर्नल एल 038, 08/02/2001 पृ. 0008-0021

1. सामुदायिक उद्योग की परिभाषा

(49) कार्रवाई के दौरान फिलिप्स लाइटिंग बी वी ने आयोग को सूचित किया कि वह शिकायतकर्ताओं के ग्रुप के सदस्य के रूप में माने जाने के बारे में अब इच्छुक नहीं है। अतः

फिलिप्स लाइटिंग बी वी से संबंधित आंकड़ों पर सामुदायिक उद्योग के निर्धारण और सामुदायिक उद्योग को हुई क्षति के प्रयोजनार्थ ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। यह नोट किया जाना चाहिए कि क्षति और कारणात्मक संबंध से संबंधित अनंतिम निष्कर्ष भिन्न नहीं रहे होते यदि फिलिप्स लाइटिंग बी वी से संबंधित आंकड़ों पर ध्यान दिया गया होता।

(50) आई पी के दौरान शेष दो सहयोगी सामुदायिक उत्पादकों का उत्पादन सी एफ एल-आई के सामुदायिक उत्पादन के 85% से अधिक बनता था।

(51) कई निर्यातक उत्पादकों ने यह अनुरोध किया कि शिकायतकर्ता स्वयं पी आर सी से संबद्ध उत्पाद का आयात कर रहे हैं। इस संबंध में यह बात उभरकर आई कि शेष दोनों सहयोगी सामुदायिक उत्पादकों ने वस्तुतः संबद्ध देश से सी एफ एल-आई का आयात किया और इन आयातों की पुनः बिक्री की। मूल विनियम के अनुच्छेद 4(1)(क) के अनुसार, "(...) जब उत्पादक आरोपित पाटित उत्पाद के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो "सामुदायिक उद्योग" शब्द का अर्थनिरूपण शेष उत्पादकों के संदर्भ में किया जाए।" आई पी के दौरान संबद्ध देश के मूल की सी एफ एल-आई की कुल बिक्री की औसतन 14,6% की बिक्री समुदाय में इन उत्पादकों द्वारा की गई थी। तथापि, आयातित सी एफ एल-आई की इन बिक्रियों के बावजूद इन कंपनियों के प्राथमिक कार्यकलाप समुदाय में बने रहे। इसके अलावा, बिक्रियों का स्पष्टीकरण उनकी उत्पाद रेंज को पूरा करने के लिए शिकायतकर्ताओं की जरूरत के रूप में किया गया था ताकि वे मांग को पूरा कर सकें और पाटन के कारण कम कीमत के आयातों से स्वयं की सुरक्षा करने का प्रयास कर सकें। परिणामतः इन उत्पादकों के निर्धारित व्यापार कार्यकलाप का सामुदायिक उत्पादकों के रूप में उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ा।

(52) अतः शेष दोनों सामुदायिक उत्पादकों को मूल विनियम के अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 5(4) के अर्थ के भीतर सामुदायिक उद्योग माना गया है।

(53) इस प्रकार, सामुदायिक उद्योग में केवल दो उत्पादक शामिल हैं, इसलिए परवर्ती उत्पादक से संबंधित सभी आंकड़ों को गोपनीयता के कारणों से सूचीबद्ध करना होगा।

2. सामुदायिक खपत

(54) सामुदायिक खपत की बिक्री की पुष्टि सामुदायिक उद्योग तथा सामुदायिक बाजार में फिलिप्स लाइटिंग बी वी की बिक्री मात्रा, संबद्ध देश से आयातों की मात्रा के बारे में यूरो स्टेट के आयात के आंकड़ों और यथोचित रूप में विधिवत समायोजित अन्य तीसरे देशों से आयात के आंकड़ों के आधार पर की गई थी।

(55) इस संबंध में यह पाया गया था कि ऊपर किए गए उल्लेखानुसार, न केवल सी एन कोड 85393190 के अंतर्गत समुदाय में न केवल सी एफ एल-आई का अपितु अन्य उत्पादों का भी आयात किया गया था। परिणामतः इस कोड के अंतर्गत आयातित सभी उत्पादों में सी एफ एल-आई के % का अनुमान समुदाय को सी एफ एल-आई का निर्यात करने वाले एक देश के लिए

लगाया गया था । ये अनुमान ऐसे सहयोगी आयातकों द्वारा दिए गए प्रश्नावली के उत्तरों जिन्हें कुछेक देशों से सी एफ एल-आई का संपूर्ण आयात करने वाला पाया गया था, शिकायतकर्ता और चीन के निर्यातक उत्पादकों द्वारा प्रदत्त सूचना तथा आयोग द्वारा सत्यापित सूचना पर आधारित थे ।

(56) इस आधार पर सामुदायिक खपत वर्ष 1996 और आई पी के बीच 117% बढ़कर 56,9 मिलियन यूनिट से बढ़कर 123,3 मिलियन यूनिट हो गई । वर्ष 1997 और 1998 के बीच और 1998 तथा 1999 /आई पी के बीच विशेष तौर पर तेजी से वृद्धि हुई ।

21. आयोग विनियमन (ई सी) सं. 1833/98 दिनांक 25 अगस्त, 1998, जिसमें ताइवान के मूल की साइकिलों के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है । ऑफिशियल जर्नल एल 238, 26/08/1998 पृ. 0010-0026

(च) सामुदायिक उद्योग

1. प्रतिनिधित्व

(43) जांच की शुरुआत से पूर्व और शिकायत के लिए आवश्यक समर्थन की पुष्टि करने हेतु आयोग ने समुदाय के सभी ज्ञात उत्पादकों से यह अनुरोध किया कि वे अपने उत्पादन की मात्रा के बारे में मूल सूचना प्रस्तुत करें और दर्ज की गई शिकायत के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें । कुल सामुदायिक उत्पादन के लगभग 60% का उत्पादन करने वाले सामुदायिक उत्पादकों ने इस शिकायत का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है ।

(44) मूल विनियम के अनुच्छेद 4(1) के अनुसार आयोग ने इस बात की जांच की कि क्या शिकायत का समर्थन करने वाले ऐसे उत्पादकों, जिन्होंने ताईवान से आरोपित पाटित कुछ साइकिलों का स्वयं आयात किया है, को सामुदायिक उत्पादन के निर्धारण से अलग रखा जाना चाहिए या नहीं ।

यह पाया गया था कि ये आयात उक्त उत्पादकों के समुदाय में कुल उत्पादन की तुलना में अल्प मात्रा में हैं और यह कि उनके मूल हित इस प्रकार समुदाय में माने गए थे । इस बात की पुष्टि की गई थी कि उक्त उत्पादकों द्वारा किए गए सीमित आयात ताईवान से कम कीमत के आयातों से रक्षात्मक प्रतिक्रिया के रूप में थे और इन्हें इस वजह से नहीं किया गया था कि ये उत्पादक आयातित साइकिलों जैसी साइकिलों का उत्पादन करने में समर्थ नहीं थे । इस आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे उत्पादकों को सामुदायिक उत्पादन के निर्धारण से अलग नहीं रखा जाना चाहिए । इन आयातों से संबंधित आंकड़ों की तब अनदेखी की गई जब सामुदायिक उद्योगों की स्थिति से संगत क्षतिकारकों की पुष्टि हुई थी ।

(45) इसका तात्पर्य यह है कि मूल विनियम के अनुच्छेद 4(1) तथा 5(4) के अनुसार शिकायत का समर्थन करने वाले सामुदायिक उत्पादक सामुदायिक उद्योग हैं क्योंकि उनका सामूहिक

उत्पादन कुल सामुदायिक उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है । (जिनहें आगे "सामुदायिक उद्योग" कहा गया है)

22. चीन जन.गण. के मूल के या वहां से निर्यातित मैट्रोनिडाजोल की पाटनरोधी जांच (निर्णायक समीक्षा) के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम

घरेलू उद्योग

6. मूल जांच में पाटनरोधी जांच हेतु आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से मै. आरती ड्रग्स लि., मुंबई और मै. एरे ड्रग्स एंड फार्मास्युटीकल्स, मुंबई द्वारा दायर किया गया था । वर्तमान निर्णायक समीक्षा में सूचना/आंकड़े मै. आरती ड्रग्स लि., मुंबई, मै. यूनिकैम लेबोरेटरीज लि., मुंबई तथा मै. जे बी कैमिकल्स लि, मुंबई, द्वारा प्रदान किए गए हैं । मै. आरती ड्रग्स लि. और मै. यूनिकैम लेबोरेटरीज लि. द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के विश्लेषण हेतु विचार किया गया है । क्षति विश्लेषण हेतु मै. जे बी कैमिकल्स द्वारा प्रदत्त आंकड़ों पर ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि जांच अवधि के दौरान इस कंपनी की घरेलू बिक्री केवल 1 मी. ट. की हुई थी जबकि शेष उत्पादन का निर्यात किया गया था ।

7. इस मामले में घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के कुल आयातों के लगभग 50% का आयात किया जिसमें मै. आरती ड्रग्स लि. का कुल आयातों में हिस्सा 40% मै. यूनिकैम लेबोरेटरीज लि. का हिस्सा 3.07% और मै. जे बी कैमिकल्स का हिस्सा 7.15% था । यह तर्क दिया गया है कि ये आयात निर्यात प्रयोजन हेतु भी मैट्रोनिडाजोल बैजोट के विनिर्माण हेतु शुल्क छूट स्कीम के अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए थे और ये देश के वाणिज्य में नहीं आए थे । अतः आवेदकों को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता ।

8. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4.1 (i) के अनुसार इस मुद्दे की जांच की गई है । पाटनरोधी करार के अनुसार, "जब उत्पादक आरोपित पाटित उत्पाद के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक हैं तो "घरेलू उद्योग" शब्द का अर्थनिरूपण शेष उत्पादकों के संदर्भ में किया जाएगा ।" नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा ।

9. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा अग्रिम लाइसेंसों पर किए गए आयातों के मुद्दे की जांच की । भारत की विदेश व्यापार नीति के अनुसार निर्यात उत्पादन हेतु आयातित निविष्टियों की बिक्री भारत में नहीं की जा सकती । अग्रिम लाइसेंसों के अंतर्गत आयातित निविष्टियों का

प्रसंस्करण/विनिर्माण के पश्चात अनिवार्यतः निर्यात करना होता है । अतः प्राधिकारी का यह मत है कि शुल्कमुक्त अग्रिम लाइसेंसों के अंतर्गत आयातित निविष्टियों जब उनका उपयोग केवल निर्यात प्रयोजन के लिए किया गया हो, के कारण उत्पादक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के अपात्र नहीं बन जाएंगे ।

10. घरेलू उद्योग ने यह मुद्दा उठाया है कि जे बी कैमिकल्स को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) की परिभाषा के अनुसार घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए क्योंकि नियमों में समान वस्तु के विनिर्माण में लगे समग्र उत्पादकों का उल्लेख है । प्राधिकारी ने इस मुद्दे की जांच की और उनका यह मत है कि मै. जे. बी. कैमिकल्स नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का एक भाग है तथापि, उसके आंकड़ों का प्रयोग क्षति विश्लेषण के लिए नहीं किया गया है क्योंकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का विश्लेषण घरेलू बाजार में उसकी बिक्री के संदर्भ में किया जाता है । इस मामले में मै. जे बी कैमिकल्स ने जांच अवधि के दौरान अपने उत्पादन के केवल 1 मी.ट. की बिक्री घरेलू बाजार में की जबकि शेष उत्पादन का निर्यात किया गया था । चूंकि जे बी कैमिकल्स द्वारा की गई 1 मी.ट. की बिक्री घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर प्रभाव डालने के लिए नगण्य है, इसलिए क्षति विश्लेषण हेतु इस कंपनी के आंकड़ों पर ध्यान नहीं दिया गया है ।

23. आस्ट्रिया, चैक गणराज्य, रोमानिया और यूक्रेन से सीमलैस ट्यूबों के आयात के बारे में पाटनरोधी जांचों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम

6. आधार के बारे में : घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्क :

यह याचिका तीनों भागीदार कंपनियों अर्थात् एम एस एल, के एस टी एल तथा आई एस एम टी की ओर से एसोसिएशन ऑफ सीमलैस ट्यूब्स मैनुफैक्चरर्स द्वारा दायर की गई थी । भारत में ऐसी 6 कंपनियां हैं जिन्होंने सीमलैस ट्यूब के उत्पादन हेतु क्षमताएं सृजित की हैं । टिस्को, रेनीमैटल्स और बी एच ई एल 3 अन्य कंपनियां हैं जिनके पास संबद्ध वस्तु के उत्पादन की क्षमता है । याचिका का समर्थन रेनीमैटल्स ने किया है । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आधार का निर्धारण निम्नानुसार किया है :-

- i. रेनीमैटल्स और बी एच ई एल को संबद्ध वस्तु का आयातकर्ता माना गया है और इस प्रकार उन्हें अलग रखा गया है ।
- ii. एम एस एल को जिन्दल ड्रिलिंग एंड इंड लि. से संबंधित माना गया है जिसने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का बड़ी मात्रा में आयात किया है ।
- iii. आधार के निर्धारण हेतु टिस्को के उत्पादन पर विचार किया गया है ।

2. घरेलू उद्योग की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :-

i. रेनीमैटल्स और बी एच ई एल से आयात : घरेलू उद्योग निर्दिष्ट प्राधिकारी के इस जांच परिणाम से सहमत है कि इन कंपनियों ने संबद्ध वस्तु का आयात किया है और इसलिए इन्हें

वर्तमान जांच के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। बी एच ई एल मुख्यतः संबद्ध वस्तु का आबद्ध खपतकर्ता है। बी एच ई एल के उत्पादन को पात्र उत्पादन से अलग रखना अपेक्षित है।

ii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पात्र उत्पादन में टिस्को के उत्पादन पर विचार किया है। यद्यपि, वर्तमान याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ताओं के आधार के बारे में कोई निहितार्थ नहीं है तो क्या टिस्को पर पात्र उत्पादन के भीतर विचार किया जा सकता है क्योंकि स्थायी शर्तों की हर हालत में पूर्ति हो रही है। अतः अनुरोध है कि जहां टिस्को ने आरंभ में मौखिक रूप से यह सूचित किया था कि वह याचिका का समर्थन करेगी परंतु बाद में उसने तटस्थ रहना उचित समझा क्योंकि वह इस समय संबद्ध वस्तु का उत्पादन नहीं कर रही थी। अतः टिस्को को अलग रखा जाए।

iii. अनुरोध है कि एम एस एल को किसी आयातक से संबंधित नहीं माना जा सकता और उसे वर्तमान जांच के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता। दिनांक 15.7.1999 को पाटनरोधी नियमों में किए गए संशोधन में निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार दिया गया है कि क्या ऐसे किसी उत्पादक, जो आरोपित पाटित वस्तु के आयातक, निर्यातक से संबंधित है या वह स्वयं उसका आयातक है, को जांच में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पी एस एफ मामले में यह माना था कि यद्यपि, रिलायंस इंडस्ट्री ने स्वयं संबद्ध वस्तु का आयात किया है तथापि, वह घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल किए जाने की पात्र है। इसी प्रकार नायलोन टायर कोर्ड फैब्रिक के मामले में डी ए ने यह माना था कि एस आर एफ इस तथ्य के बावजूद कि वह एक आयातक से संबंधित है, घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल किए जाने की पात्र है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता कंपनी ने स्वयं किसी मात्रा का आयात नहीं किया है और क्षति विश्लेषण के साथ किसी रूप में भेदभाव नहीं होगा। इस संबंध में अनुरोध है कि :

क. जे डी आई एल और एम एस एल सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां हैं और ये कंपनी अधिनियम 1956 के किसी उपबंध के अंतर्गत संबंधित नहीं हैं। इनमें से कोई भी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अनुसार संबद्ध कंपनी या दूसरी कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है। ये न तो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 (1 ख) के अनुसार समान प्रबंधन के अधीन है और न ही वे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 372 (11) के अनुसार उसी ग्रुप में हैं।

ख. एम एस एल तथा जे डी आई एल द्वारा किया जा रहा मुख्य व्यापार अलग-अलग है। एम एस एल सीमलैस पाइपों का विनिर्माण करती है जबकि जे डी आई एल मुख्यतः अपतटीय तेलकूप खुदाई का कार्य करती है। यह सीमलैस पाइपों की थ्रेडिंग एंड फिनिशिंग, कोल्ड पिल्जर, हीट ट्रीटमेंट आदि में भी सीमित हद तक संलग्न है। जिंदल ने समस्त सामग्री का आयात वोलइंस्की पाइप संयंत्र से किया है जिसने प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है। कंपनी द्वारा आयातित मात्रा *** मी.ट. के बीच है जो भारतीय मांग का एक नगण्य अनुपात है।

ग. जे डी आई एल का दैनिक कार्यचालन पूर्णकालिक निदेशक द्वारा किया जाता है जो कंपनी के निदेशक मंडल के नियंत्रण में है। इसी प्रकार एम एस एल का दैनिक कार्यचालन प्रबंध

निदेशक द्वारा किया जाता है जो कंपनी के निदेशक मंडल के नियंत्रण में है। दोनों कंपनियों में पेशेवर निदेशक मंडल हैं। दोनों कंपनियों के निदेशक मंडल के गठन से यह स्पष्ट होता है कि दोनों कंपनियों के बोर्ड में केवल एक साझा निदेशक है जो श्री डी. पी. जिंदल हैं। यह बोर्ड तब तक कोई निर्णय नहीं ले सकता जब तक कि उस निर्णय का अनुमोदन एम एस एल में न्यूनतम 2 निदेशकों द्वारा अनुमोदित न किया जाए और यही स्थिति जे डी आई एल के मामले में भी है। अनुरोध है कि साझा निदेशक किसी भी स्थिति में निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास आवश्यक कोरम नहीं होता है।

घ. एम एस एल और जे डी आई एल जैसी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां मूलतः ऐसे निदेशक मंडल द्वारा संचालित होती हैं जो व्यापार के सभी पहलुओं पर नियंत्रण रखता है। चूंकि दोनों कंपनियों के बोर्ड में केवल एक साझा निदेशक है, इसलिए कंपनी किसी भी रूप में दूसरी कंपनी को निर्देश नहीं दे सकती या निवारित नहीं कर सकती है। नोट करने लायक एक अन्य प्रमुख तथ्य यह है कि जे डी आई एल ने ऐसे आकारों का आयात किया है जिसका उत्पादन एम एस एल नहीं करती है।

7. ओ एन जी सी एल तथा वोल्जखी द्वारा दिए गए तर्क :

इस मामले में जांच 21.5.1999 को शुरू की गई थी और उस दिन असंशोधित नियम 2(ख) लागू था। इस नियम में निर्दिष्ट प्राधिकारी को कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया था और ऐसा प्रत्येक घरेलू उत्पादक जो आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातक या आयातक से संबंधित है, या जो स्वयं उसका आयातक है, को "घरेलू उद्योग" के दायरे से बाहर रखना होता था। यह तथ्य कि महाराष्ट्र सीमलैस लि. आरोपित पाटित वस्तु के एक आयातक से संबंधित है, प्राधिकारी की जानकारी में ओ एन जी सी एल तथा वोल्जखी द्वारा लाया गया था। पाटनरोध के बारे में यूरोपीय परिषद के विनियम में "संबंधित" शब्द को परिभाषित करने के अलावा, ऐसी किसी कंपनी को दूसरी कंपनी से संबंधित रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जिसके पास दूसरी कंपनी में 50% से अधिक शेयर हैं। यूरोपीय आयोग द्वारा प्रयुक्त "संबंधित" शब्द की परिभाषा नीचे पुनः उद्धरित है।

"इस प्रश्नावली को पूरा करने के लिए किसी कंपनी को उस स्थिति में संबंधित माना जाना चाहिए जब वह आपकी पूंजी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 5% से अधिक भाग धारित करती हो अथवा वह अन्यथा आपकी कंपनी पर नियंत्रण रखती हो अथवा यदि आपकी कंपनी के पास उसकी शेयर पूंजी के 50% से अधिक हिस्सा है अथवा आप उस पर अन्यथा नियंत्रण रखते हैं। इसके अलावा उसी धारिता में कंपनियों को संबंधित माना जाता है।" वस्तुतः जे डी आई एल द्वारा जांचाधीन देशों से आयातित पाइपों की उसी बाजार में आपूर्ति एम एस एल द्वारा आपूर्ति पाइप के रूप में प्रतिस्पर्धा करती है और इस प्रकार एम एस एल को अलग रखना होगा।

9. घरेलू उद्योग

यह याचिका मै. महाराष्ट्र सीमलैस लिमिटेड, मै. कल्याणी सीमलैस ट्यूब्स लि. और मै. इंडियन सीमलैस मेटल ट्यूब्स लि. की ओर से एसोसिएशन ऑफ सीमलैस ट्यूब्स मैन्युफैक्चरर्स द्वारा दायर की गई है। संबद्ध वस्तु के अन्य घरेलू विनिर्माता टिफ्को, रेनीमैटल्स और बी एच ई एल हैं।

उपर्युक्त 6 कंपनियों ने सीमलैस ट्यूबों के उत्पादन की क्षमता सृजित की है। बी एच ई एल ने मुख्यतः आबद्ध खपत हेतु क्षमता सृजित की है। यह अनुरोध किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान रेनी मैटल्स ने संबद्ध देशों से 7884.79 मी.ट. संबद्ध वस्तु का आयात किया है। बी एच ई एल ने भी संबद्ध वस्तु का आयात किया है परंतु वह सूचीबद्ध देशों से इतर स्रोतों से हुआ है। उपर्युक्त पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकारी ने रेनीमैटल्स और बी एच ई एल को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया जिसकी वजह यह है कि बी एच ई एल ने आबद्ध खपत की रेनीमैटल्स द्वारा संबद्ध स्रोतों से संबद्ध वस्तु का भारी मात्रा में आयात किया। टिस्को ने उत्पादन रोक दिया और वह वर्तमान याचिका का समर्थक नहीं है।

जैसा कि इस अंतिम जांच परिणाम के पैरा 8 में उल्लेख है, घरेलू उद्योग में मै. महाराष्ट्र सीमलैस लिमिटेड, मै. कल्याणी सीमलैस ट्यूब्स लि. और मै. इंडियन सीमलैस मेटल ट्यूब्स लि. शामिल हैं जिनका उत्पादन संबद्ध वस्तु के कुल पात्र घरेलू उत्पादन का 100% बनता है और इस प्रकार उनके पास नियमों के अंतर्गत याचिका दायर करने का अपेक्षित आधार है।

● याचिकाकर्ता द्वारा संबद्ध देश से इतर देश से आयात

24. परिषद विनियम (ईसी) सं. 769/2002 दिनांक 7 मई, 2002, जिसमें चीन जन.गण. के मूल के कुपारीन के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनोधी शुल्क लगाया गया है। ऑफिशियल जर्नल एल 123, 09/05/2002 पृ. 0001-0009

सामुदायिक उद्योग की परिभाषा

(39) आवेदक के प्रतिनिधित्व वाली कंपनी जांच अवधि के दौरान समुदाय में कुमेरिन की एकमात्र उत्पादक थी।

(40) आई पी के दौरान सामुदायिक उत्पादक ने पी आर सी से इतर किसी देश से कुमेरिन का आयात किया। ऐसे आयातों का उद्देश्य तकनीकी कारणों की वजह से उत्पादक के सामुदायिक उत्पादन से संबंधित उत्पाद की कमी को पूरा करना था। ये आयात समुदाय में उत्पादक द्वारा की गई कुल बिक्री मात्रा का एक अल्प भाग है। इस प्रकार आयातित कुमेरिन की बिक्री के बावजूद कंपनी का प्राथमिक कार्यकलाप समुदाय में बना रहा और इस उत्पादक के आयात से सामुदायिक उत्पादक के रूप में उसकी स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ा। अतः सामुदायिक उत्पादक को मूल विनियम के अनुच्छेद 4(1) तथा अनुच्छेद 5(4) के अर्थ के भीतर सामुदायिक उद्योग माना जाता है।

● भारत में सहायक कंपनी द्वारा संबंधित निर्यातक से आयात

25. आयोग विनियमन (ईसी) सं. 362/1999 दिनांक 18 फरवरी, 1999, जिसमें चीन, भारत, मैक्सिको, द.अफ्रीका और यूक्रेन के मूल की इस्पात से बनी रस्सियो एवं केबलों के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है और हंगरी तथा पोलैण्ड स्थिति कतिपय निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत अभिवचन स्वीकार किए गए। ऑफिशियल जर्नल एल 045 19/02/1999 पृ. 0008-0025

घ. सामुदायिक उद्योग

1. सामुदायिक उत्पादन

(34) कई निर्यातक उत्पादकों ने यह आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादक को सामुदायिक उद्योग की परिभाषा से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि वह एक आयातक तथा ऐसी वितरण/व्यापार कंपनियों की श्रृंखला से संबंधित था जिसने मूल विनियम के अनुच्छेद 4(1) (क) और (2) के अनुसरण में जांच की गई जांच अवधि के दौरान उक्त देशों से समुदाय में संबद्ध उत्पाद का आयात किया था।

यह नोट किया जाना चाहिए कि संदर्भाधीन शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान स्वयं कोई आयात नहीं किया था।

जहां तक ग्रुप में व्यापार कंपनियों द्वारा किए गए आयातों का संबंध है, आयोग ने इस बात की पुष्टि की कि संदर्भाधीन शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादक वस्तुतः उक्त कंपनी ग्रुप का एक भाग था जिसमें एक आयातक और वितरण कंपनियां शामिल थीं और यह कि इन्होंने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से एस डब्ल्यू आर का आयात किया था। यह पाया गया था कि ग्रुप की संरचना में 1994 तथा जांच अवधि के बीच परिवर्तन किया गया था। तथापि, जांची गई समग्र अवधि के दौरान संदर्भाधीन शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादक और आयातक एवं वितरण कंपनियां ऋण कंपनियों के पास साझा धारिताएं थीं और इसलिए उन्हें संबंधित कंपनियां माना गया था।

आयोग ने ग्रुप संरचना के स्वरूप की जांच की और यह पाया कि उसे अलग नहीं रखा जा सकता क्योंकि कुछ सीमा तक नियंत्रण संबद्ध कंपनियों के बीच प्रत्यक्ष या साझा नियंत्रक कंपनियों के जरिए विद्यमान हो सकता है। आयोग ने इस बात की पुष्टि की कि जांच अवधि में संबद्ध कंपनियों द्वारा किए गए पाटित आयात की मात्रा सामुदायिक खपत की 2%, तीसरे देश को हुए कुल आयात की 6% और शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादक की उत्पादन मात्रा की मात्र 11% बनती है। अतः इस शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादक का प्रमुख कार्यकलाप एस डब्ल्यू आर का उत्पादन था।

चूंकि शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादक का सरोकार सामुदायिक बाजार से है, इसलिए आयोग ने यह पाया कि ऐसे किसी नियंत्रण की संभावित मौजूदगी के बावजूद संदर्भाधीन शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादक को उसी प्रकार से पाटित आयातों के कारण क्षतिकारी

प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है जैसा कि वर्तमान कार्रवाई के दौरान जांचे गए अन्य शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादकों पर पड़ रहा है । इस संबंध में यह नोट किया जाना चाहिए कि संबंधित कंपनी ने सामुदायिक बाजार में ऐसा कोई वाणिज्यिक व्यवहार नहीं अपनाया है जो संदर्भाधीन आयतों के परिणामस्वरूप दूसरे शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादकों से पर्याप्ततः भिन्न हो । संदर्भाधीन शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान संबंध देशों के मूल के आयातों के कारण लगातार और पर्याप्त कटौती की है ; (75, 8% की भारित औसत कटौती पाई गई थी) । अतः यह माना गया था कि संदर्भाधीन शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादक को संबंध आयातों से कोई अनुचित लाभ नहीं मिला और उसे पाटन के क्षतिकारी प्रभावों से कोई सुरक्षा नहीं मिली ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इस बात पर विचार किया कि क्या संदर्भाधीन शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादक को कुल सामुदायिक उत्पादन से अलग रखने का कोई आधार नहीं है ।

(35) आयोग ने यह पाया कि जांच अवधि के दौरान कुछेक शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादकों ने संबंध देशों सहित समुदाय से बाहर के विभिन्न स्रोतों से एस डब्ल्यू आर की खरीद की थी । तथापि, इन आयातों की मात्रा कुल उत्पादन में नगण्य थीं (अर्थात् शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादकों के एस डब्ल्यू आर के कुल उत्पादन के 1% से कम) । अतः आयोग ने इस बात पर विचार किया कि ये खरीददारी ऐसे उत्पादकों की मानक वाणिज्यिक प्रवृत्ति के अनुरूप थी जिन्होंने आयातों की अल्प मात्रा से उत्पादों की अपनी रेंज पूरी की थी । ये आयात उत्पादों की संपूर्ण रेंज प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक थे ताकि वे सामुदायिक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें ।

(36) उपर्युक्त के आधार पर आयोग ने जांच के समय समुदाय में एस डब्ल्यू आर का उत्पादन करने वाली सभी कंपनियों के उत्पादन को सामुदायिक उत्पादन माना । अतः इन कंपनियों को "सामुदायिक उत्पादक" कहा गया है ।

2. सामुदायिक उद्योग

(37) ऐसे कई लघु उत्पादकों ने आयोग की प्रश्नावलियों का उत्तर नहीं दिया है जिन्होंने शिकायत का समर्थन किया था । अनुच्छेद 4(1) के अनुसार सामुदायिक उद्योग के क्षेत्र को शेष सहयोगी उत्पादकों के रूप में परिभाषित किया गया है ।

(38) इस आधार पर निम्नलिखित 20 शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादकों ने "सामुदायिक उद्योग" बनाया है अर्थात् ब्रेमेर ड्रस्टसीलेरी लुलिग जी एम बी एच (जर्मनी), ब्रिडोन इंटरनेशनल लि. (यू.के.), बी टी एस ड्रास्टेसिली जी एम बी एच (जर्मनी), केबल्स वाई अलेम्ब्रेस स्पेशल्स एस ए (स्पेन), कैसार ड्रास्टसिल्वर्कसार जी एम बी एच (जर्मनी), कारडोरिया ओलीवियरा एस ए (पुर्तगाल), ड्रास्टेसिलेरी घुस्तव कॉक्स जी एम बी एच (जर्मनी), होल्डिंग फिकाडी (फ्रांस), स्कारफनी मैटेलिक मैटेलिक (इटली), डी कोरोनाकिस एस ए (ग्रीस), मैटलकाबी वायर रोप्स (इटली), मिडलैंड वॉयर कार्डेज कंपनी लि. (यू.के.), रेंडर्स रेसलजेरी (डेनमार्क), रेडायली टेक्नाकोरंडाटी एस पी ए (इटली), ट्रिफिलोरोप (फ्रांस), ट्रेंजाज वाई केबल्स

एस एल (स्पेन), वेरीनिगटे ड्रास्टसिल्वर्क जी एम बी एच (जर्मनी), वीयस्ट - अल्पाइन आस्ट्रिया ड्राट जी एम बी एच (आस्ट्रिया), वीनवायुमैन - स्टासिले जी एम बी एच और वाडरा जी एम बी एच (दोनों जर्मनी की) ।

- भारत में संबद्ध कंपनी द्वारा असंबद्ध निर्यातक से आयात

26. परिषद विनियमन (ईसी) सं. 2320/97 दिनांक 17 नवंबर, 1997 जिसमें हंगरी, पोलैण्ड, रूस, चेक गणराज्य, रोमानिया तथा स्लोवाक गणराज्य के मूल के इस्पात अथवा नॉन एलॉय इस्पात से निर्मित कतिपय सीमलेस पाइपों एवं ट्यूबों के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया, विनियम (ईईसी) सं. 1189/3 को वापस लिया गया और क्रोएशिया गणराज्य के मूल के ऐसे आयातों से संबंधित कार्यवाही को समाप्त किया गया । ऑफिशियल जर्नल एल एल 322, 25/11/1997 पृ. 0001-0024

घ. सामुदायिक उद्योग

(42) इन्हीं सामुदायिक उत्पादकों ने दोनों जांचों में सहयोग किया था (देखें उद्धरण 8) । इन कंपनियों का उत्पादन जाचाधीन उत्पाद के कुल सामुदायिक उत्पादन का 90% से अधिक बनता था और इस प्रकार उनका उत्पादन समुदाय में संबद्ध उत्पाद के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है (43) । कई निर्यातकों ने यह आरोप लगाया कि उनके उत्पादों की खरीद की गई है और उनका आयात कुछेक शिकायतकर्ता सामुदायिक उत्पादकों ने किया है । उन्होंने यह दावा किया कि इन उत्पादकों को मूल विनियम के अनुच्छेद 4 (1) (क) के अनुसरण में क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के निर्धारण से अलग रखा जाना चाहिए ।

इस कथन के समर्थन में कोई पुष्टिकारी साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया था । इसके अलावा, आयोग द्वारा की गई जांच से यह पता चला है कि किसी भी सामुदायिक उत्पादक ने संबद्ध उत्पादों का आयात नहीं किया है और यह कि ऐसे सामुदायिक उत्पादकों से संबद्ध कुछ उत्पादकों ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध उत्पादों की अल्प मात्रा में आयात किया था । इन आयातों की पुनः बिक्री अनन्य रूप से इन संबद्ध आयातकों द्वारा सामुदायिक बाजार में की गई थी जिनके बारे में यह पाया गया था कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से कार्य किया है और यहां तक कि उन्होंने अपने संबद्ध उत्पादकों के बिक्री विभागों के साथ प्रतिस्पर्धा की है । हर हालत में तथ्यों की जांच से यह पता चला कि इन आयातों की मात्रा प्रत्येक सामुदायिक उत्पादकों के लिए सामुदायिक बाजार में इन उत्पादों की कुल बिक्री मात्रा के 3% से कम बनती है ।

अतः यह माना जाता है कि आयातों के ऐसे कम स्तर के कारण सामुदायिक उत्पादकों को कोई क्षति नहीं हो सकती है और परिणामतः इन उत्पादकों को अलग रखने का कोई आधार नहीं है ।

परिणामतः उद्धरण (8) में उल्लिखित उत्पादकों को मूल विनियम के अनुच्छेद 4(1) के अर्थ के भीतर "सामुदायिक उद्योग" कहा जाएगा ।

- जांच अवधि के दौरान निर्यात करने वाले निर्यातक के साथ संबंध

27. आयोग विनियमन (ईसी) सं. 1742/2000 दिनांक 4 अगस्त, 2000 जिसमें भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गण. ताइवान एवं थाईलैंड के मूल के कतिपय पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया ।

ग. सामुदायिक उद्योग

(87) निम्नलिखित 9 सामुदायिक उत्पादकों ने जांच में सहयोग किया अर्थात् आयोग की प्रश्नावलियों का उत्तर दिया, मौके पर सत्यापन की अनुमति दी और अनुरोध किए जाने पर आयोग को अतिरिक्त सूचना प्रदान की :

- डूपोंट पॉलिस्टर्स लि. (यू के);
- ईस्टमैन कैमिकल्स बीवी (एल एल);
- आई एन सी ए इंटरनेशनल एस पी-ए (II)
- इटालपेट परफोर्मे एस पी ए (II)
- कोसा जी एम बी एच (डी)
- शैल कैमिकल्स लि. (यू.के.);
- वैलमैन पी ई टी रेजिन्स यूरोप (एन एल);
- असापोल एस पी ए (II)
- सी ई पी - टर्गल फाइबर (एफ)

(88) यह नोट किया जाना चाहिए कि यद्यपि, असापोल एस पी ए और सी ई पी टर्गल फाइबर्स उन कंपनियों में शामिल नहीं थीं जिनकी ओर से शिकायत दायर की गई है तथापि, इन कंपनियों ने शिकायत का समर्थन किया है और जांच में सहयोग किया है ।

(89) यह भी नोट किया जाना चाहिए यद्यपि यह महाराष्ट्र स्थित एक संयंत्र को प्रचालित करती है तथापि, ईस्टमैन को सामुदायिक उद्योग का भाग माना गया है क्योंकि उसकी सहायक कंपनी ने स्वयं ईस्टमैन को पी ई टी का नगण्य मात्रा में निर्यात किया है । किसी अन्य असहयोगी कंपनी ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पी ई टी का आयात नहीं किया ।

(90) यूरोप के तीनों अन्य उत्पादकों में से किसी ने भी आयोग की प्रश्नावलियों का उत्तर नहीं दिया अथवा कार्रवाई का विरोध नहीं किया ।

(91) जांच अवधि के दौरान 9 सहयोगी उत्पादकों का संयी उत्पादन 1220000 टन के कुल अनुमानित सामुदायिक उत्पादन में से 1042350 टन रहा था अर्थात् यह सामुदायिक उत्पादन का 85% था ।

(92) अतः आयोग ने यह माना है कि 9 सहयोगी उत्पादक मूल विनियम के अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 5(4) के अर्थ के भीतर "सामुदायिक उद्योग" हैं ।

28. आयोग विनियमन (ईसी) सं. 173/2000 दिनांक 24 जनवरी, 2000 जिसमें जापान, कोरिया गण. तथा ताइवान के मूल के कतिपय बड़े एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक संधारित्रों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी कार्यवाही को समाप्त किया गया ।

घ. सामुदायिक उद्योग

1. सामुदायिक उद्योग का गठन

(60) दोनों समीक्षाओं में समान उत्पाद शामिल हैं और दोनों मोटे तौर पर समान समयावधि से संबंधित आंकड़ों पर आधारित हैं । अतः इस बात पर विचार करना उचित माना जाता है कि इनकी साथ-साथ जांच की जाए । परिणामतः समुदाय के समान उत्पादक सामुदायिक उत्पादन करते हैं और दोनों इन समीक्षाओं में सामुदायिक उद्योग हैं ।

(61) समुदाय में एल ए ई सी के 4 बड़े उत्पादक अर्थात् बी सी कंपोनेंट्स, बी एच सी ऐरो वाक्स लि. (यू.के.), विषय रोडस्टरटीन जी एम बी एच (जर्मनी) और सीमेंस-मतसुस्ति कंपोनेंट्स जी एम बी एच एंड कंपनी के जी (जर्मनी) और छोटे से लेकर मझौले उत्पादक स्थापित किए गए थे ।

तीनों उत्पादकों अर्थात् बी सी कंपोनेंट्स, बी एच सी ऐरो वाक्स लि. (यू.के.), विषय रोडस्टरटीन जी एम बी एच ने जापान के बारे में समीक्षा हेतु अनुरोध का समर्थन किया था । तथापि, परवर्ती दो उत्पादकों ने आयोग के साथ सहयोग नहीं किया और इसलिए उन्हें सामुदायिक उद्योग का भाग नहीं माना गया था ।

(62) उपर्युक्तानुसार, बी सी कंपोनेंट्स एक नई कंपनी है जिसे जांच अवधि की समाप्ति के बाद निगमित किया गया था । इसने उल्लेखनीय रूप से एल ए ई सी के विनिर्माण और बिक्री में फिलिप्स कंपोनेंट्स बी वी के कार्यकलापों का अधिग्रहण किया था । कार्यकलापों का यह अधिग्रहण खासकर उक्त समुदाय में एल ए ई सी के विनिर्माण और बिक्री के बारे में प्रचालनरत कंपनी आधार पर किया गया था । इसके अलावा, बी सी कंपोनेंट्स बी वी ने दोनों समीक्षाओं के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया था ।

(63) सीमेंस-मतसुस्ति कंपोनेंट्स जी एम बी एच एंड कंपनी के जी (जिसे आगे " सीमेंस-मतसुस्ति " कहा गया है) और अन्य लघु तथा मध्यम उत्पादक उन उत्पादकों में शामिल नहीं थे जिन्होंने जापान के बारे में समीक्षा का अनुरोध किया था । तथापि, इन कंपनियों ने समीक्षा की शुरुआत की घोषणा करने वाली सूचनाओं के प्रकाशन के बाद स्वयं के बारे में जानकारी नहीं दी । अतः मूल विनियम के अनुच्छेद 5(4) के अनुसार इन उत्पादकों को सामुदायिक उद्योग का भाग नहीं माना जा सकता ।

(64) जापान के एक उत्पादक/निर्यातक ने इस तथ्य का तर्क दिया है कि सीमेंस-मतसुस्ति से आयोग ने संपर्क नहीं किया था और यह कि इस कंपनी को सामुदायिक उद्योग से बाहर रखा गया था । इन दावों को रवीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ऊपर किए गए उल्लेखानुसार, उपर्युक्त सूचनाओं के प्रकाशन के अनुसरण में सीमेंस-मतसुस्ति ने हितबद्ध पक्षकार के रूप में स्वयं के बारे

में जानकारी नहीं दी और उसने सहयोग करने में कोई रुचि नहीं दिखाई । इसके अलावा, इसने सामुदायिक उद्योग से अलग रखने का विरोध नहीं किया ।

इसके अलावा, उपलब्ध सूचना से यह पता चला कि सीमेंस-मतसुस्ति एक संयुक्त उद्यम है जिसका समान स्वामित्व सीमेंस ए जी (जर्मनी) और जापान के असहयोगी उत्पादक/निर्यातक मतसुस्ति इलेक्ट्रिक इंड लि. ग्रुप (जापान) के पास है । सीमेंस ए जी का नैगमिक प्रबंधन पर नियंत्रण है और मत बराबर रहने की स्थिति में उसके पास मताधिकार है । सीमेंस-मतसुस्ति ने संबद्ध देशों के मूल के किसी एल ए ई सी का आयात न करने और अपने ब्रांड से सामुदायिक बाजार में एल ए ई सी के अपने खुद के उत्पादन की बिक्री न करने की सूचना दी थी । तथापि, अपनी 50% शेयरधारिता के जरिए मतसुस्ति इलेक्ट्रिक इंड लि. ग्रुप नियंत्रण का उपयोग करने और सीमेंस-मतसुस्ति पर बंदिश लगाने की स्थिति में है । उपलब्ध सूचना से यह भी पता चला कि सीमेंस-मतसुस्ति को उसके दो शेयरधारकों की जानकारी से लाभ मिला । अतः ये दोनों कंपनियां मूल विनियम के अनुच्छेद 4(2) के अर्थ के भीतर संबद्ध हैं ।

(65) सीमेंस-मतसुस्ति में मतसुस्ति इलेक्ट्रिक इंड लि. की प्रमुख शेयरधारिता और उपर्युक्त जानकारी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सीमेंस-मतसुस्ति बी सी कंपोनेंट्स की तुलना में मूलतः अलग स्थिति में है । अतः मूल विनियम के अनुच्छेद 4(1)(क) के अनुसार, सीमेंस-मतसुस्ति को सामुदायिक उद्योग की परिभाषा से अलग रखना उचित समझा गया था ।

(66) इस बात को अंततः रेखांकित किया जाए कि सीमेंस-मतसुस्ति को पहले ही मूल जांच में जापान से आयातों और कोरिया गण तथा ताइवान से हुए आयातों के संबंध में घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर रखा गया था । इस नीति का इन दोनों जांचों में विरोध नहीं किया गया है ।

(67) जापान के कई उत्पादकों/निर्यातकों ने यह दावा किया कि बी सी कंपोनेंट्स को सामुदायिक उद्योग से अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि जांच अवधि की समाप्ति पर जो कंपनियां और खासकर फिलिप्स कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स बी वी संबंधित थीं, उन्होंने जापान से एल ए ई सी का पर्याप्त मात्रा में आयात किया था ।

(68) आयोग ने इस बात की जांच की कि क्या यह तथ्य कि फिलिप्स कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स बी वी ने जापान से एल ए ई सी का आयात किया, बी सी कंपोनेंट्स को सामुदायिक उद्योग से बाहर रखने का पर्याप्त कारण है और यह कि उस समय केवल एल ए ई सी विनिर्माता फिलिप्स ग्रुप में थे ।

यह पाया गया था कि फिलिप्स ग्रुप द्वारा किए गए लगभग सभी आयात आगे पुनः बिक्री के लिए नहीं थे अपितु, उन्हें फिलिप्स कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स बी वी ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के अपने उत्पादों में शामिल किया था । इसके अलावा, जांच से यह पता चला कि इनमें से अधिकांश आयात (85% से अधिक) "रेडियल" उत्पादों के थे, जिनका न तो बी सी कंपोनेंट्स ने अभी उत्पादन किया था अथवा अभी तक उसका उत्पादन शुरूआती चरण में नहीं था । इन परिस्थितियों

में फिलिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बी वी के पास संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा की गई आपूर्ति के अलावा, कोई अन्य विकल्प नहीं था ।

फिलिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बी वी के उत्पाद बी सी कंपोनेंट्स के उत्पादन से सीधी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और समुदाय में हुए कुल आयातों में उसका हिस्सा नगण्य था । यह भी नोट किया गया था कि उपर्युक्त आयातों के बावजूद फिलिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बी वी बी सी संघटकों का सबसे बड़ा पारंपरिक ग्राहक था क्योंकि उसका हिस्सा जांच अवधि में हुई कुल बिक्रियों का लगभग 40% था । फिलिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बी वी की पसंद की आंशिक आपूर्ति संबद्ध देशों में उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा फिलिप्स ग्रुप का विभिन्न लाभ केन्द्रों में पुनर्गठन करने से संभव हुई थी जो सभी स्वतंत्र हैं और पसंद के आपूर्तिकर्ता हैं और ऐसा तब हुआ है जब फिलिप्स ग्रुप के भीतर प्रस्तुत उत्पादों की रेंज को पूर्ण या पूरकता प्रदान करना आवश्यक था । (जैसा कि "रेडियल" एल ए ई सी के मामले में हुआ है ।)

(69) उपर्युक्त कारणों से फिलिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बी वी द्वारा किए गए आयातों को तब तक सामान्य वाणिज्यिक विभाग माना गया था जब तक कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियां सामुदायिक बाजार में उत्पन्न नहीं होती हैं ।

(70) बी सी कंपोनेंट्स का उत्पादन कुल अनुमानित सामुदायिक उत्पादन का एक बड़ा भाग (41%) बनता है ।

(71) मूल विनियम के अनुच्छेद 4(1)(क) के आधार पर सीमेंस-मतसुस्ति के अनुमानित उत्पादन पर सामुदायिक उद्योग के प्रतिनिधित्व के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कुल सामुदायिक उत्पादन के निर्धारण में विचार नहीं किया गया था ।

जापान के एक सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने यह दावा किया कि यदि सीमेंस-मतसुस्ति के अनुमानित उत्पादन को हिसाब में लिया जाता तो बी सी कंपोनेंट्स के पास कुल सामुदायिक उत्पादन का प्रतिनिधित्व करने का पर्याप्त आधार नहीं रहा होता ।

तथापि, यह पाया गया था कि सहयोगी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर पुष्टिकृत सीमेंस-मतसुस्ति के उत्पादन को कुल सामुदायिक उत्पादन के निर्धारण में शामिल किया गया होता तो सामुदायिक उद्योग के पास तब भी मूल विनियम के अनुच्छेद 5(4) के अनुसरण में इस उत्पादन का एक बड़ा भाग होता ।

(72) अतः इस बात की पुष्टि की गई थी कि बी सी कंपोनेंट्स मूल विनियम के अनुच्छेद 4(1) के अर्थ के भीतर दोनों समीक्षाओं में सामुदायिक उद्योग है ।

29. आयोग विनियमन (ई सी) सं. 1472/2000 दिनांक 6 जुलाई, 2000, जिसमें भारत तथा कोरिया गण. के मूल के पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया । ऑफिशियल जर्नल एल 166, 06/07/2000 प. 0001-0013

ड सामुदायिक उद्योग की परिभाषा

(60) दोनों शिकायतें समुदाय में पी सी एफ का उत्पादन करने वाले 14 सामुदायिक उत्पादकों में से 8 क्री ओर से दायर की गई थी । इन शिकायतकर्ता उत्पादकों में से एक ने सहयोग नहीं किया और दूसरे को असहयोगी मानना पड़ा क्योंकि उसने प्रश्नावली का पर्याप्त उत्तर प्रदान नहीं किया था ।

(61) जांच अवधि के दौरान सहयोगकर्ता 6 सामुदायिक उत्पादकों द्वारा धारित पी एस एफ के कुल सामुदायिक उत्पादन में हिस्सा 71.5% था । इस आधार पर ये 6 शिकायतकर्ता मूल विनियम के अनुच्छेद 4(1) के अर्थ के भीतर सामुदायिक उद्योग हैं । उन्हें एतदपश्चात "सामुदायिक उद्योग" कहा गया है ।

(62) यह तर्क दिया गया था कि 6 शिकायतकर्ता उत्पादकों को सामुदायिक उद्योग से अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि वे इंडोनेशिया के एक निर्यातक उत्पादक से संबंधित हैं । यह देश पी एस एफ के बारे में पाटनरोधी और सब्सिडीरोधी दोनों जांचों में शामिल था ।

(63) यह स्मरणीय है कि वर्तमान कार्यवाही में कोरिया गण और भारत के मूल के आयातों के खिलाफ एक शिकायत की जांच की जा रही है । यह भी स्मरणीय है कि निर्यातकों से संबंधित उत्पादकों को उस स्थिति में सामुदायिक उद्योग की परिभाषा से अलग रखा जा सकता है यदि ऐसे संबंध से ऐसा व्यवहार हो रहा हो जो असंबद्ध सामुदायिक उत्पादकों से भिन्न हो क्योंकि ऐसे संबद्ध उत्पादकों को पाटन, पाटन के व्यवहार से प्राप्त अनुचित लाभ और यहां तक कि पाटन के व्यवहार में भाग लेने के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान की जाती है । जांच के दौरान ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया गया था कि इंडोनेशियाई निर्यातकों से संबद्ध सामुदायिक उत्पादक तीनों उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत आएंगे । खास तौर पर यह पाया गया था कि इन दोनों कंपनियों के लिए विभिन्न क्षति संकेतकों से संबंधित सूचना अन्य शिकायतकर्ताओं से पर्याप्ततः भिन्न थी । इससे यह पता चलता है कि दोनों कंपनियों को पाटन के प्रभावों, पाटन के व्यवहार से प्राप्त अनुचित लाभों और ऐसे व्यवहारों में भागीदारी से सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी । अतः इन दोनों सामुदायिक उत्पादकों को सामुदायिक उद्योगों की परिभाषा से बाहर नहीं रखा गया है ।

30. चीन जन.गण. के मूल के या वहां से निर्यातित पैराक्रीशोल के आयात के बारे में पाटनरोधी जांच के बारे में अंतिम जांच परिणाम

7. घरेलू उद्योग

प्राधिकारी घरेलू उद्योग के मुद्दे पर प्रारंभिक जांच परिणामों को समरण करते हैं। यह याचिका मै. अतुल लि. (एरोमैटिक्स डिविजन) जिला वलसाड, गुजरात द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता कंपनी भारत में पेराक्रिसोल की एकमात्र उत्पादक है। अतः उन्होंने संबद्ध वस्तु के 100% घरेलू उत्पादन का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया है। याचिकाकर्ता ने निर्यात दायित्व की पूर्ति हेतु अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत जांच अवधि के दौरान 32 मी.ट. पेराक्रिसोल के आयात के बारे में याचिका में सूचना दी थी। कुछ आयातकों ने यह तर्क दिया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने जांच अवधि में आयात किए हैं इसलिए उसे पात्र घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जा सकता। प्राधिकारी ने यह नोट किया कि जांच अवधि के दौरान मै. अतुल लि. द्वारा किया गया 32 मी.ट. का आयात निर्यात उत्पादन के लिए था और यह आयात पेराक्रिसोल संयंत्र को योजनाबद्ध ढंग से बंद करने के लिए आवश्यक था। प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" मानने के लिए याचिकाकर्ता को अपात्र बनाने हेतु निर्यात उत्पादन के लिए इस अल्प मात्रा में किए गए आयात पर विचार नहीं किया। अतः याचिकाकर्ता को घरेलू उद्योग का प्रतिनिधि माना गया था।

आयातकों अर्थात् मै. ब्लैकरोज एक्सपोर्ट प्रा. लि., मैट्रोकेम इंड लि., नंदोलिया आर्गेनिक कैमिकल्स प्रा. लि. और यूनिवर्सल कैमिकल इंड लि. की ओर से यह उल्लेख करते हुए तर्क दिए गए हैं कि याचिकाकर्ता के पास याचिका दायर करने का आधार नहीं है क्योंकि उसने संबद्ध वस्तु का आयात किया है। इसके अलावा यह तर्क दिया गया है कि मै. अतुल लि. को घरेलू उद्योग मानते समय प्राधिकारी द्वारा विचारित निम्नलिखित 3 कारण पर्याप्त नहीं हैं :-

- i. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयात नगण्य हैं।
- ii. अग्रिम लाइसेंस पर किए गए आयात
- iii. ये आयात उत्पादन सुविधाओं को अस्थायी रूप से बंद किए जाने के समय किए गए हैं।

यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयात आयातों के 3% से अधिक हैं जबकि पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत आयातों की 3% मात्रा को पर्याप्त मात्रा माना जाता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए ये आयात उत्पाद की मांग के 1% से अधिक थे। जहां तक अग्रिम लाइसेंस पर याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयातों से संबंधित दूसरे कारण का संबंध है, आयातकों ने यह तर्क दिया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी की यह पद्धति रही है कि ऐसे सभी उत्पादकों को पात्र घरेलू उद्योग से बाहर रखा जाए। यह तर्क दिया गया है कि चीन से मैट्रोनिडाजोल के आयातों के मामले में 3 उत्पादकों को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा गया था। यद्यपि, इन कंपनियों ने अग्रिम लाइसेंस पर आयात किया था। जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा अस्थायी बंदी की स्थिति में अग्रिम लाइसेंस पर आयात करने के बारे में दिए गए तीसरे कारण का संबंध है, आयातक ने यह तर्क दिया है कि यह तर्क निराधार है क्योंकि एक स्थान पर घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि आयात निर्यात हेतु उसकी खुद की जरूरत के लिए आवश्यक थे और इसके साथ ही साथ उसने यह उल्लेख किया है कि आयात संयंत्र को

अस्थायी रूप से बंद किए जाने के कारण किए गए थे । प्रकटन विवरण के उत्तर में आयातकों ने अपने पूर्ववर्ती स्थिति को दोहराया है ।

घरेलू उद्योग ने नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग की परिभाषा के बारे में विधिक स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया है । उन्होंने यह तर्क दिया है कि उक्त नियम में विद्यमान "जाएगा" शब्द में 15.7.1999 के संशोधन सं. 44/99-सी.शु. के तहत संशोधन किया गया है जिसे "सकता है" पढ़ा जाएगा । इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह विशिष्ट विवेकाधिकार यह निर्णय लेने के लिए निहित किया गया था कि क्या किसी विशेष मामले में आयातकर्ता घरेलू उद्योग को नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जा सकता । वर्तमान मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट थे कि याचिकाकर्ता को इस तथ्य के बावजूद पात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए कि उसने उक्त उत्पाद का आयात किया है । वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने अग्रिम लाइसेंस पर आयात किए थे जो सीमाशुल्क और पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हैं । यह छूट इस तथ्य पर आधारित है कि ऐसे आयात देश की मुख्य धारा के वाणिज्य में प्रवेश नहीं करते हैं । जिन उत्पादकों ने विचाराधीन उत्पादकों का आयात नहीं किया था उन्हें बाहर रखने का निर्णय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उचित और समान आधार पर एवं समस्त शामिल विधिक और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद मामला दर मामला आधार पर लिया जाता है । कुछ उत्पादकों को बाहर रखे जाने से संबंधित उपबंधों का प्रयोजन पाटित आयातों के उद्देश्य और प्रभावों के बारे में सुस्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त करना है । यह नोट करना प्रासंगिक है कि वर्तमान याचिकाकर्ता ने पाटन के व्यवहार में किसी भी रूप में भाग नहीं लिया है अथवा उसके प्रभावों से बचाव नहीं किया है अथवा उनसे अनुचित लाभ प्राप्त नहीं किया है । आयातकों का यह तर्क कि आयातकर्ता घरेलू उद्योग को सामान्यतः अलग रखा जाए की पुष्टि कानून के साधोरण पठन अथवा इस विषय पर न्यायशास्त्र से नहीं होती है । याचिकाकर्ता ने "निकोलस खान" लिखित ई सी पाटनरोधी कानून, विनियम 384/96 पर टिप्पणी नामक पुस्तक से उद्धरण भी दिए हैं जिनमें ई सी इस संबंध में अपनाई गई पद्धति निहित है ।

याचिकाकर्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि "घरेलू उद्योग" के मुद्दे से संबंधित प्रारंभिक जांच परिणामों की आयातकों के अनुरोधों में गलत व्याख्या की गई है और उनमें विकृति पैदा की गई है । उक्त जांच परिणाम में यह पूर्णतः साफ किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों पर घरेलू उद्योग के आधार के निर्धारण हेतु ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि ये आयात निर्यात प्रतिबद्धताओं का पूरा करने के लिए आवश्यक थे और न कि आयातकों/उपभोक्ताओं के अनुरोधों में उल्लिखित कारणों से । निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय पर प्रश्न उठाने के समर्थन में दिए गए कारण प्रारंभिक जांच परिणामों के गलत अर्थ निरूपण पर आधारित हैं और इन्हें आदितः अस्वीकार करना जरूरी है । आयातकों द्वारा उल्लिखित आयातों की 3% की मात्रा का मानदंड याचिका दायर करने के लिए घरेलू उद्योग की स्थिति से कोई संबंध या संपर्क नहीं

रखता है। आयातकों द्वारा फेनोल के मामले पर किया गया विश्वास भी कपटपूर्ण और भ्रामक है।

प्राधिकारी ने "घरेलू उद्योग" के मुद्दे पर अंतिम जांच परिणामों के बारे में आयातकों द्वारा दिए गए तर्कों तथा याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्कों की जांच की है। प्राधिकारी का यह मत है कि नियम 2(ख) में प्राधिकारी को यह निर्धारित करने में विवेकाधिकार दिया गया है कि क्या ऐसे घरेलू उत्पादक जिसने संबद्ध वस्तु का आयात किया है, को घरेलू उद्योग का भाग माना जा सकता है अथवा उसे अलग रखा जा सकता है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता, जो भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है, ने जांच अवधि के दौरान 32 मी.ट. का आयात किया था। ये आयात निर्यात उत्पादन के लिए किए गए थे और ये उनके पैराक्रीसोल संयंत्र की योजनाबद्ध बंदी के लिए आवश्यक रहे थे। प्राधिकारी ने इन आयातों को खासकर उस स्थिति में पर्याप्त नहीं माना है जब ये निर्यात उत्पादन के लिए किए गए थे। घरेलू उद्योग के आधार के निर्धारण के संदर्भ में आयातों की 3% मात्रा के मानदंड का हवाला देना कोई प्रासंगिकता नहीं रखता है क्योंकि ये उपबंध आयातों की न्यूनतम मात्रा के निर्धारण से संबंधित हैं। आयातकों द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में उल्लिखित अन्य मामलों के तथ्य और परिस्थितियां वर्तमान मामले से भिन्न हैं। अतः प्राधिकारी "घरेलू उद्योग" के मुद्दे पर अपने प्रारंभिक जांच परिणामों को दोहराते हैं और उनकी पुष्टि करते हैं।

• जांच अवधि के दौरान कोई निर्यात न करने वाले निर्यातक के साथ संबंध

31. परिषद विनियमन (ई सी) सं. 771/98 दिनांक 7 अप्रैल, 1998, जिसमें चीन जन.गण. के मूल के टंगस्टन कारबाइड एवं फ्यूज्ड टंगस्टन कारबाइड के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया। ऑफिशियल जर्नल एल III, 09/04/1998 पृ. 0001-0009

घ. सामुदायिक उद्योग

(22) चीन के निर्यातकों/उत्पादकों और कुछ प्रयोक्ताओं ने सामुदायिक उद्योग की परिभाषा और समीक्षा अनुरोध का समर्थन करने वाले उत्पादकों के आधार के बारे में कई दावे किए थे।

(23) चीन के निर्यातकों/उत्पादकों ने यह दावा किया कि समीक्षा अनुरोध का समर्थन करने वाले उत्पादकों में से एक उत्पादक चीनी कार्बाइड के एक आयातक से संबंधित है और इसलिए उसे मूल विनियम के अनुच्छेद 4(1) (क) और (2) के अनुसरण में घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर रखा जाना चाहिए।

जांच के दौरान इस बात की पुष्टि की गई थी कि संबंधित दोनों कंपनियां यद्यपि संबंधित हैं, तथापि, उनका एक दूसरे पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा, इन कंपनियों के पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने के बारे में विरोधाभासी हित थे। एक कंपनी कार्बाइड का उत्पादन कर रही थी जबकि दूसरी कंपनी संबद्ध उत्पाद का आयात कर रही थी। यह पाया गया था कि दोनों कंपनियां अपनी व्यापार कार्यनीति को परिभाषित करते समय और अनुपालन करते समय स्वायत्त

रूप से कार्य कर रही थीं। कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकाला गया था कि उनके संबंध से व्यवहार पर प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही संबद्ध उत्पाद के बारे में संदर्भाधीन सामुदायिक उत्पादक के आर्थिक विश्लेषण में विकृत उत्पन्न नहीं होती है और इसलिए इस उत्पादक को सामुदायिक उद्योग की परिभाषा से बाहर रखने का कोई कारण नहीं है।

(24) उद्धरण (2) में किए गए उल्लेखानुसार समीक्षा हेतु अनुरोध खुले बाजार में बिक्री के लिए नियत कार्बाइड के लगभग समग्र उत्पादन का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तदनुसार वे घरेलू उद्योग थे।

इसका विरोध खासकर आंतरिक खपत हेतु कार्बाइड की लघु मात्रा का उत्पादन करने वाले समुदाय में टंगस्टन अंतिम उत्पादों (औजार, ठोस धातु) के कई समेकित उत्पादकों द्वारा किया गया था। उन्होंने विशेष रूप से यह तर्क दिया था कि समीक्षा का समर्थन करने वाले उत्पादकों के प्रतिनिधित्व का निर्धारण संबद्ध उत्पाद की कुल सामुदायिक उत्पादन के संदर्भ में किया जाना चाहिए (जिसमें उनका आबद्ध उत्पादन भी शामिल है) और उस आधार पर समीक्षा का समर्थन करने वाले उत्पादक घरेलू उद्योग के प्रतिनिधि नहीं हैं।

(25) इस मुद्दे की जांच की गई थी और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि यह तर्क गलत है। वस्तुतः यदि ऐसी कंपनियों जो केवल आबद्ध उपयोग हेतु उत्पादन करती हैं, के उत्पादन को ध्यान में रखा जाए तो भी समीक्षा अनुरोध का समर्थन करने वाले उत्पादकों का उत्पादन संबद्ध उत्पाद के समग्र सामुदायिक उत्पादन का 60% बनता है और इस प्रकार वे मूल विनियम के अनुच्छेद 5(4) के मानदंड को पूरा करते हैं। इसके अलावा, इस बात की पुष्टि की गई थी कि समीक्षा का समर्थन करने वाले उत्पादकों द्वारा खुले बाजार में बिक्री के लिए नियत कार्बाइड के लगभग समस्त सामुदायिक उत्पादन का उत्पादन किया जा रहा है।

(26) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए समीक्षा अनुरोध का समर्थन करने वाले उत्पादक मूल विनियम के अनुच्छेद 4(1) और 5(4) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं। इस विनियम के शेष भाग के लिए "सामुदायिक उद्योग" शब्द का उपयोग समीक्षा का समर्थन करने वाली कंपनियों के रूप में किया जाएगा।

32. परिषद विनियमन (ई ई सी) सं. 535/87 दिनांक 23 फरवरी, 1987, जिसमें जापान के मूल के प्लेन पेपर फोटोकॉपियर के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया।
ऑफिशियल जर्नल एल 054, 24/02/1987 पृ. 0012-0035

(iii) कार्रवाई के संदर्भ में सामुदायिक उद्योग की परिभाषा

इस मामले में आयोग का यह दायित्व है कि वह इस तथ्य पर विचार करे कि इस कार्रवाई से संबंधित सभी सामुदायिक उत्पादक जापानी निर्यातकों के साथ निगमित या वाणिज्यिक स्वरूप का कोई संबंध रखते हैं। इससे विनियम (ई ई सी) संख्या 2176/84 के अनुच्छेद 4(5) के अंतर्गत सामुदायिक उद्योग की परिभाषा के बारे में जटिल प्रश्न उत्पन्न हो गए हैं और इसके लिए प्रत्येक

कंपनी की स्थिति से संबंधित विशिष्ट तथ्यों के आधार पर प्रत्येक शिकायतकर्ता कंपनी की स्थिति की विस्तृत जांच करना आवश्यक हो गया है ।

(क) रैंक जीरोक्स की स्थिति

(50) विनियम (ई ई सी) सं. 2640/86 में कार्रवाई के संदर्भ के भीतर क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ जापानी आपूर्तिकर्ता फ्यूजी जीरोक्स के साथ रैंक जीरोक्स के निगमित संबंध के मद्देनजर यह प्रश्न अनिवार्यतः अछूता रह गया था क्योंकि आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला था कि सामुदायिक उत्पादकों को क्षति हुई है भले ही रैंक जीरोक्स के कम मात्रा के कॉपियरों के उत्पादन को "सामुदायिक उद्योग" शब्द में शामिल किया गया हो अथवा नहीं । तथापि, चूंकि क्षति को समाप्त करने के लिए अपेक्षित शुल्क की गणना उस समय न्यून स्तर पर की गई थी जब क्षति निर्धारण हेतु रैंक जीरोक्स को सामुदायिक उद्योग में शामिल किया गया था । तब यदि उसे अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ अलग रखा गया था तो आयोग ने उद्योग के भाग के रूप में रैंक जीरोक्स पर विचार करने का निर्णय लिया । इस कार्रवाई में रैंक जीरोक्स की स्थिति के बारे में निश्चयात्मक निर्णय लेने के लिए आयोग ने इस बात के निर्धारण के लिए समस्त मामलों की पुनः जांच की कि क्या विनियम (ई ई सी) सं. 2176/84 के अनुच्छेद 4(5) में यथापरिभाषित घरेलू उद्योग में रैंक जीरोक्स को शामिल किया जाना चाहिए । शुरुआत में आयोग ने रैंक जीरोक्स के प्रचालनों के सापेक्ष महत्व की समीक्षा समुदाय में फोटो कॉपियर उद्योग में कंपनी के अन्य प्रचालनों की तुलना में उसकी सहायक कंपनी फ्यूजी जीरोक्स के साथ की ।

(52) अंतिम रूप में पुष्टिकृत तथ्यों से यह पता चलता है कि रैंक जीरोक्स द्वारा पी पी सी का फ्यूजी जीरोक्स से आयात किया जाता है जिसकी बिक्री समुदाय में की गई थी जिसका हिस्सा कंपनी की कुल बिक्री का लगभग 7% बनता है और वर्ष 1981 से संदर्भ अवधि की समाप्ति तक खंड 1 से 5 में नई मशीनों का समुदाय का किराया भी इतना बनता है । वर्ष 1984 में फ्यूजी जीरोक्स से 1055 मध्यम मात्रा के मॉडल के आयातों को छोड़कर ये आयात सभी खंडों 1 और 2 कॉपियरों में किए गए थे जिनका हिस्सा रैंक जीरोक्स के खंड 1 और 2 मशीनों की बिक्री और उसी अवधि में इन मशीनों के समुदाय में किराए का लगभग 8% बनता है । वर्ष 1981 से जुलाई, 1985 की अवधि के दौरान सभी उत्पादकों द्वारा सामुदायिक बाजार में खंड-1 से 5 में बिक्री तथा नई मशीनों के किराए के संबंध में फ्यूजी जीरोक्स के आयातों की रैंक जीरोक्स द्वारा की गई बिक्री 1% से कम बनती है ।

(53) समुदाय में समतुल्य मॉडल के विनिर्माण की अग्रिम स्थापना हेतु मुख्य रूप से आयात किए जाने के बारे में और फ्यूजी जीरोक्स की पुनः बिक्री कीमत समुदाय में पुष्टिकृत विनिर्मित मॉडलों के समान होने के बारे में विनियम (ई ई सी) 2640/86 (उद्धरण 74) में दिए गए जांच परिणामों के प्रतिकूल कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(54) वर्ष 1981 से संदर्भ अवधि के अंत तक फ्यूजी जीरोक्स द्वारा संपूर्ण इकाइयों में अनापूर्त खंड 1 और 2 कॉपियरों की रैंक जीरोक्स बिक्री के संबंध में यह आरोप लगाया गया था कि

समुदाय में इनका उत्पादन फ्यूजी जीरोक्स द्वारा रैंक जीरोक्स को बड़ी मात्रा में आपूर्त किए गए अंशों से किया गया था । इन आरोपों के बाद आयोग ने समुदाय में रैंक जीरोक्स द्वारा विनिर्मित सभी फोटो कॉपियरों के उत्पादन की जांच की । इस संदर्भ में आयोग ने यूनाइटेड किंगडम (कम मात्रा की मशीनों) और नीदरलैंड (मध्यम मात्रा की मशीनों में रैंक जीरोक्स के विनिर्माण संयंत्रों का दौरा किया और प्रत्येक संयंत्र किए जा रहे विनिर्माण प्रचालनों के स्वरूप की जांच की) ।

(55) नीदरलैंड के मामले में यह पाया गया था कि समेकित विनिर्माण प्रचालन समुदाय में रैंक जीरोक्स द्वारा या उसकी ओर से किए जा रहे हैं । इन विनिर्माण प्रचालनों में समुदाय के भीतर मूल्यवर्धन 7% से अधिक था । नीदरलैंड में रैंक जीरोक्स द्वारा उत्पादित फोटोकॉपियर सामुदायिक मूल के हैं ।

यूनाइटेड किंगडम में रैंक जीरोक्स उत्पादों का विनिर्माण मुख्यतः जापान और मामूली तौर पर समुदाय के मूल के पुर्जों के आधार पर किया गया था । तथापि, रैंक जीरोक्स ने पहले ही जापानी मूल के कुछेक प्रमुख संघटकों को हटाने के लिए समुदाय में उत्पादित पुर्जा स्थापित करने हेतु ठोस योजना तैयार की थी । इन योजनाओं को इस बीच अमल में लाया गया जिससे कम मात्रा के इन उत्पादों के लिए समुदाय के भीतर मूल्यवर्धन में पर्याप्त वृद्धि हुई ।

जहां तक यूनाइटेड किंगडम में किए गए प्रचालनों के स्वरूप का संबंध है, इनमें फ्यूजर्स, मॉड्यूलर्स, डिवलप बॉक्सेज, कैसेट्स, सैमी आटोमोटिव डाकुमैट हैंडलर्स, आप्टिक्स तथा अन्य छिटपुट संयोजनों सहित उत्पादन लाइन हेतु उप संयोजनों का निर्माण शामिल था । इन प्रचालनों को फ्रेम संयोजन और उप संयोजनों तथा संघटकों की अंतिम मेन लाइन संयोजन द्वारा पूरा किया जाता है । विनिर्माण प्रक्रिया फोटो कॉपियरों की जांच और पैकिंग के बाद पूरी होती है । कुल मिलाकर संदर्भ अवधि में रैंक जीरोक्स के कम मात्रा के कॉपियरों के उत्पादन में समुदाय में मूल्यवर्धन 20 प्रतिशत और 35% के बीच रहा था ।

(56) आयोग ने इस बात की जांच की है कि क्या इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रैंक जीरोक्स को विनियम (ई ई सी) संख्या 2176/84 के अनुच्छेद 4(5) के अर्थ के भीतर खंड 1 और 2 कॉपियरों का सामुदायिक उत्पादक माना जा सकता है । आयोग ने यह नोट किया है कि इस विनियम में इस संदर्भ में कोई विशिष्ट दिशानिर्देश निहित नहीं हैं । खास तौर पर किसी सामुदायिक विधान या किसी पूर्ववर्ती मामले में न्यूनतम मूल्यवर्धन हेतु ऐसी कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसे सामुदायिक उद्योग के भाग के रूप में अर्ह बनाने के लिए किसी उत्पादक पर विचार किया जा सके । अतः आयोग का यह दायित्व है कि वह वर्तमान मामले की खास बातों पर गौर करें ।

(57) नोट करने वाला पहला बिन्दु यह है कि समुदाय में यह कंपनी लंबे समय से एक विनिर्माता है और यह बाजार में सबसे बड़ी कंपनी है ।

यद्यपि, यू के में रैंक जीरोक्स के उत्पादन प्रचालन संदर्भ अवधि के दौरान नीदरलैंड में उसके संयंत्र में किए जा रहे कार्यकलापों की तुलना में सीमित हैं तथापि, कंपनी ने बाजार हेतु कॉपियरों का उत्पादन करने के लिए आवश्यक विनिर्माण प्रचालनों की बहुलता नहीं की है। इसके अलावा, रैंक जीरोक्स जापान के पुर्जो के स्थान पर स्वयं अपने विनिर्माण हेतु या समुदाय के भीतर उप ठेकेदारों से अन्य प्रमुख संघटकों को लगाने में सक्षम रूप से संलग्न रही है।

जांच से यह पता चला कि यदि खंड 1/2 कॉपियरों को शामिल करते हुए कोई रक्षात्मक उपाय नहीं किया गया था तो जापान से प्राप्त प्रमुख पुर्जो के स्थान पर समुदाय द्वारा उत्पादित आपूर्तियों को लगाने के रैंक जीरोक्स द्वारा शुरू की गई सक्रिय प्रक्रिया बाधित होगी। विनियम (ई ई सी) सं. 2176/84 के अनुच्छेद 4(1) के अंतर्गत किसी उद्योग की स्थापना में बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में रक्षात्मक उपाय का प्राधिकार दिया गया है। यदि इस मामले में कोई पाटनरोधी उपाय न किया जाता तो न केवल समुदाय से उत्पादों की प्राप्ति के बारे में रैंक जीरोक्स के भावी संयंत्रों को धक्का पहुंचता जो पहले से ही सुस्थापित हैं अपितु, इस क्षेत्र में पहले से शुरू की गई प्रक्रिया के लिए भी खतरा उत्पन्न होता। इससे समुदाय में विनिर्मित पुर्जो पर आधारित कम मात्रा के कॉपियरों के रैंक जीरोक्स के उत्पादन को बढ़ाने की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न हो सकता था।

(58) बहरहाल चूंकि इस कार्रवाई में समान उत्पाद को व्यक्तिगत कॉपियरों से लेकर डाटा क्वैस्ट खंड-5 में वर्गीकृत मशीनों को शामिल करते हुए समस्त फोटो कॉपियरों को परिभाषित किया गया है, इसलिए यह उचित होगा कि इस बात का विश्लेषण किया जाए कि क्या कोई सामुदायिक उत्पादक एक मॉडल या मॉडलों की सीमित रेंज के अपने उत्पादन के कसबंध में ही सामुदायिक उद्योग का भाग होगा। इस मामले पर यदि अकेले विचार किया जाए तो इस बात की शंकाएं उठती हैं कि क्या युनाइटेड किंगडम में रैंक जीरोक्स के विनिर्माण प्रचालन खंड 1/2 कॉपियरों के लिए विनियम (ई ई सी) संख्या 2176/84 के अनुच्छेद 4(5) की मूल भावना में किसी सामुदायिक उत्पादक की स्थिति को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। खंड 1 से खंड 4 के बीच रैंक जीरोक्स द्वारा विनिर्मित समस्त पी पी सी हेतु समुदाय में भारित औसत मूल्य वर्धन संदर्भ अवधि में 50% से अधिक है। इसके अलावा, कंपनी की यह नीति है कि समुदाय के भीतर अपने संघटकों के अनुपात में वृद्धि की जाए।

(59) यदि इन कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ यू के में रैंक जीरोक्स के उत्पादन को सामुदायिक उद्योग का भाग माना भी लिया जाए तो भी जापानी उत्पादों या समपवर्ती खंडों के रूप में बाजार के उसी खंड में पी पी सी का सामुदायिक उत्पादन बना रहेगा। इस विनियम में प्रयुक्त मानदंड के अनुसार समुदाय की सुरक्षा करने के लिए लागू शुल्क की दरें अप्रभावित रहेंगी।

(60) आयोग ने इस बात की भी जांच की कि क्या फ्यूजी जीरोक्स से पाटित आयातों के कारण प्राप्त हुए लाभों की वजह से रैंक जीरोक्स को समग्र रूप में या एक भाग के रूप में सामुदायिक उद्योग की परिभाषा से अलग रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, इस प्रश्न की जांच की गई थी कि क्या फ्यूजी जीरोक्स से खरीद करने में रैंक जीरोक्स को स्वयं क्षति हुई थी और क्या आयात

करने में उसकी मंशा आत्मरक्षा के लिए मुख्यतः कार्य करने की थी या अपने मूल जीरोक्स निगम के संदर्भ में लाभ को अधिकतम बनाने, कॉपीयर उत्पादन को विश्वभर में युक्तिसंगत बनाने की थी ।

(61) फ्यूजी जीरोक्स के साथ अपने निगमित संबंध से रैंक जीरोक्स को प्राप्त लाभों के संबंध में यह स्पष्ट होता है कि समुदाय में उत्पादन शुरू करने से पूर्व सरस्ती मशीनों की आपूर्ति से लाभ प्राप्त हो रहे थे । तथापि ये लाभ अल्पकालिक और सीमित हैं । इसके अलावा, जब संबद्ध आयातों की मात्रा पर विचार किया जाता है तो यह स्पष्ट होता है कि ये लाभ जापान के अन्य निर्यातकों द्वारा पाटन के जरिए रैंक जीरोक्स को हो रही क्षति के निर्धारण के समय काफी अधिक हैं ।

(62) जहां तक इस संभावना का संबंध है, कि रैंक जीरोक्स ने बाजार में कीमतों में गिरावट लाकर या ऐसा ही कुछ कार्य करके स्वयं को क्षति पहुंचाई है, इस बात का कोई कोई साक्ष्य नहीं है । सर्वप्रथम रैंक जीरोक्स द्वारा फ्यूजी जीरोक्स से आयातित खंड 1 और 2 उत्पादों की पुनः बिक्री कीमत प्रतिवादी रैंक जीरोक्स समुदाय द्वारा उत्पादित मशीनों के समान थीं और इन कीमतों से सामान्यतः सामुदायिक बाजार में जापानी सहायक कंपनियों की कीमत में कटौती हुई थी । इस तथ्य से यह पता चलता है कि रैंक जीरोक्स के बारे में यह नहीं माना जा सकता कि उसने फ्यूजी जीरोक्स से मशीनों की खरीद और पुनः बिक्री के जरिए स्वयं को क्षति पहुंचाई है ।

(63) जहां तक इस संभावना का संबंध है, कि रैंक जीरोक्स द्वारा पाटित कीमतों पर फ्यूजी जीरोक्स द्वारा आपूर्त फोटो कॉपियरों की पुनः बिक्री के जरिए अन्य सामुदायिक उत्पादकों को क्षति पहुंचाई है, साक्ष्य से यह पता चला कि जब इन मॉडलों की अलग-अलग विशेषताओं और तुलनीय सामुदायिक उत्पादित मॉडल पर ध्यान दिया जाता है तो रैंक जीरोक्स की पुनः बिक्री कीमत सामान्यतः संबद्ध सामुदायिक उत्पादक की बिक्री से कम थी और इस प्रकार इसे उक्त उत्पादक के लिए क्षतिकारक माना जाना चाहिए । अतः इसका तात्पर्य यह है कि अन्य सामुदायिक उत्पादकों को हुई क्षति का निर्धारण करने में इन आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

(64) अंततः जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि क्या रैंक जीरोक्स ने जापानी उत्पादकों से कम कीमत पर प्रतिस्पर्धा के खिलाफ स्वयं की रक्षा करने के लिए कार्य किया है, आयोग ने रैंक जीरोक्स द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की समीक्षा की । हालांकि कंपनी ने यह मत व्यक्त किया कि वर्ष 1978 से जापान में उसकी सहायक कंपनी से कम मात्रा में फोटो कॉपियरों की खरीद का निर्णय लेने में एक प्रमुख कारक सामुदायिक बाजार में प्रचलित कम कीमत रही थी जिसका निर्धारण जापानी निर्यातकों द्वारा किया गया था । तथापि, इस विवरण के समर्थन में कोई आश्वस्तकारी साक्ष्य नहीं दिया गया था । इसके विपरीत स्वतंत्र स्रोतों से यह संकेत मिलता है कि उक्त निर्णय मुख्यतः जीरोक्स कार्पोरेशन के समक्ष कम मात्रा में नए उत्पादों के उत्पादन में आ रही आंतरिक कठिनाइयों के कारण लिया गया था । ऐसी स्थिति में रैंक जीरोक्स ने फ्यूजी जीरोक्स की ओर रुख किया जिसमें जापान में बिक्री हेतु कम मात्रा के मॉडल (2202) तैयार किया था और इस उत्पाद का आयात समुदाय में किया था । इस मॉडल ने रैंक

जीरोक्स के पूर्ववर्ती समुदाय उत्पादित मॉडल (660) का स्थान लिया परंतु इसका उत्पादन समुदाय में नहीं हुआ था ।

(65) रैंक जीरोक्स के साथ यह आरंभिक आपूर्ति अल्पकालिक थी और इसके स्थान पर उद्धरण 53 में उल्लिखित आपूर्ति की व्यवस्था वर्ष 1979 में स्थापित हो गई थी । आपूर्ति की ऐसी व्यवस्थाओं का प्रयोजन स्पष्टतः रैंक जीरोक्स को सामुदायिक उत्पादों के रूप में समुदाय में अपना विनिर्माण अग्रिम रूप से करने हेतु तैयार करना और नए उत्पादों का विपणन करना था । हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि रैंक जीरोक्स आत्मरक्षात्मक प्रयोजनों के लिए फ्यूजी जीरोक्स से मशीनों की खरीद करने के लिए बाध्य था । तथापि, यह स्पष्ट होता है कि बाजार के कम मूल्य वाले खंड में जो वर्तमान परिस्थितियां थीं उनकी वजह जापानी आपूर्तिकर्ता थे, समुदाय के उत्पादन की प्रतीक्षा करने की बजाए बाजार में कोई उत्पाद अधिक शीघ्रता से प्रस्तुत करने की क्षमता की वजह से यह कंपनी अपनी समग्र स्थिति का बेहतर बचाव करने में समर्थ बनी ।

(66) यद्यपि, आयात करने में कंपनी के कार्यकलाप अत्मरक्षात्मक नहीं माने गए थे तथापि, समुदाय में फोटो कॉपियरों की रैंक जीरोक्स की कुल रेंज के संबंध में फ्यूजी जीरोक्स से आपूर्तियों की कम मात्रा इस विचार के पक्ष में निर्णयात्मक है कि फ्यूजी जीरोक्स से संपूर्ण पी पी सी की खरीद करने के कारण इस कार्यवाही में कम मात्रा के कॉपियरों के कंपनी के उत्पादन को सामुदायिक उद्योग की परिभाषा से अलग रखने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है ।

(67) सारांश रूप में और इस मामले में विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनियम (ई ई सी) सं. 2176/84 के अनुच्छेद 4(5) के अंतर्गत आयोग का यह मानना है कि इस कार्यवाही के प्रयोजनार्थ रैंक जीरोक्स को फोटो कॉपियरों का एक सामुदायिक उत्पादक माना जाना चाहिए ।

(ख) टैट्राज की स्थिति

(68) नवंबर, 1986 में सीकॉम का एक सदस्य और समुदाय में पर्सनल कॉपियर का उत्पादक टैट्राज ने जापानी निर्यातक कैन्नन के साथ संबंध कायम किया जिसके द्वारा कैन्नन ने पूर्व निर्धारित समयावधि में अन्य निवेशकों से कंपनी के स्टॉक के अतिरिक्त 30% की खरीद के विकल्प के साथ टैट्राज में 19% शेयरधारित ग्रहण की । कैन्नन के साथ अल्पशेयरधारित के संबंध के कारण सामुदायिक उत्पादक के रूप में अथवा शिकायतकर्ता के रूप में टैट्राज की स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ा है और परिणामतः इस कार्यवाही के प्रयोजनार्थ टैट्राज सामुदायिक उद्योग का भाग बना हुआ है ।

(ग) ओसी एवं ओलीवेटी की स्थिति

(69) जहां तक ओसी एवं ओलीवेटी की स्थिति का संबंध है, कई निर्यातकों और ओ ई एम ने इस आशय के अभ्यावेदन दिए थे कि इन कंपनियों को जापानी आपूर्तिकर्ताओं के साथ उनके संबंध होने के आधार पर विनियम (ई ई सी) सं. 2176/84 के अनुच्छेद 4(5) के अंतर्गत कार्यवाहियों में सामुदायिक उद्योग के क्षेत्र से अलग रखा जाना चाहिए । सारांश में उनका तर्क यह था कि

जापानी आपूर्तिकर्ताओं के साथ इन कंपनियों के व्यापक और लंबे पारंपरिक संबंध की वजह से इस कार्यवाही में इन पर सामुदायिक उत्पादकों के रूप में विचार नहीं किया जाना चाहिए ।

(70) जापानी आपूर्तिकर्ताओं के साथ इन कंपनियों के संबंधों के तुलनात्मक महत्व के बारे में आंकड़ों से यह पता चलता है कि ओसी एंड ओलीवेटी द्वारा आयातित मशीनों की बिक्री समुदाय में की जाती है जो प्रत्येक कंपनी की बिक्री के 35 और 40% के बीच बनती है और बाजार में नई मशीनों का किराया वर्ष 1981 से जुलाई, 1985 की अवधि में लागू किया गया था । पुनः बिक्री हेतु ओ सी द्वारा जापान से आयातित मॉडल ओ सी की स्वयं उत्पादित मशीनों की कीमत की तुलना में खंड-1 और 2 कॉपियरों के लिए कम रही हैं । ओलीवेटी ने वर्ष 1981 से जुलाई, 1985 की अवधि में मुख्यतः खंड 1 कॉपियरों का आयात किया है परंतु 1984 के बाद उसने कैनन से भी पर्सनल कॉपियरों की खरीद की है ।

(71) इस प्रश्न पर व्यापक रूप से विचार विनियम (ई ई सी) सं. 2640/86 में किया गया था कि क्या ओलीवेटी एवं ओसी द्वारा पाटित पी पी सी के आयात में कार्यवाही के जरिए स्वयं को क्षति पहुंचाई जा सकती है । परिषद इन जांच परिणामों की पुष्टि करती है और यह मानती है कि इन कंपनियों को निम्नलिखित कारणों से समुदाय उद्योग की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए :

- दोनों कंपनियों ने कई बार मॉडलों की पूर्ण रेंज तैयार करने और उसका विपणन करने का प्रयास किया परंतु जापानी आयातों द्वारा बाजार कीमत कम किए जाने के कारण उनके प्रयासों में बाधा पहुंची । यह परियोजनाओं के प्रबंधन मूल्यांकनों तथा बाजार में उतारने के लिए तैयार एक प्रोटोटाइप मॉडल के मामले में पूर्ण प्रलेखन से स्पष्ट होता है ।
- कंपनियों ने ओ ई एम आधार पर जापान में विनिर्मित मशीनों का वितरण किया है जो अपने ग्राहकों को मॉडलों की पूर्ण रेंज प्रस्तुत करने की जरूरत के लिए एक प्रतिक्रिया थी । ऐसा करके कंपनियों द्वारा ऐसे अन्य आपूर्तिकर्ताओं जो संपूर्ण मॉडल रेंज की पेशकश करने में समर्थ थे, से प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध ग्राहक आधार की स्पष्ट सुरक्षा की जा रही थी ।
- वर्ष 1981 से संदर्भ अवधि की समाप्ति तक कंपनियों ने आयातित पी पी सी की तुलना में स्वयं द्वारा विनिर्मित उत्पादों की अधिक इकाइयों की बिक्री की और किराए पर उठाया ।
- जिन कीमतों पर दोनों कंपनियों ने ओ ई एम आधार पर आयातों की पुनः बिक्री की है वे सामुदायिक बाजार में उनके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बेची गई उन्हीं मशीनों की कीमत की तुलना में सामान्यतः अधिक हैं जिससे इस बात की संभावना नहीं बनती है कि ओ सी एवं ओलीवेटी ने अपनी कीमत नीति के जरिए स्वयं को क्षति पहुंचाई है और इस तर्क का समर्थन किया है कि ये ओ ई एम बिक्रियां सहायक कंपनी को

की गई थीं जिनका उद्देश्य उनकी स्वविनिर्मित मशीनों को उतारने में सुविधा प्रदान करना था ।

जापान में उत्पादित समस्त मशीनों के कुल आयातों की तुलना में कोसी एवं ओलीवेटी ओई एम आयात की अत्यंत अल्प मात्रा (1981 से 1985 की अवधि में औसतन 4%) और इस तथ्य कि उनकी बिक्री उनके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई बिक्री की तुलना में कम कीमत पर की गई थी, से यह पता चलता है कि कि इन सीमित आयातों का उनकी खुद की कीमतों और अन्य सामुदायिक उत्पादों द्वारा स्वविनिर्मित पी पी सी की कीमतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । निष्कर्षतः परिषद इस बात की पुष्टि करती है कि इस कार्यवाही के संदर्भ में ओसी एवं ओलीवेटी ने ओ ई एम आधार पर वितरण हेतु जापान से कम लागत के पी पी सी का आयात कर स्वयं को क्षति नहीं पहुंचाई ।

(72) अंततः विनियम (ई ई सी) सं. 2640/86 के उद्धरण 73 में आयोग के तर्क को इस निष्कर्ष को न्यायोचित ठहराने के साक्ष्य के अभाव के आधार पर चुनौती दी गई थी कि ओ सी एवं ओलीवेटी के बारे में यह नहीं माना जा सकता कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे उन्हें अधिक नुकसान हो सकता हो । यदि उन्होंने मॉडलों की अधिक सीमित रेंज के विपणन में अपने खुद के पी पी सी के कारोबार को चलाने का प्रयास किया है । इसके उत्तर में परिषद ने इन कंपनियों द्वारा विगत में झेली गई कठिनाइयों और मॉडलों के सीमित रेंज के विपणन के बारे में अपने फोटो कॉपीन व्यापार तथा उसकी जरूरत को प्रस्तुत करने का संकेत दिया और इस बात पर जोर दिया कि लगभग सभी सफल उत्पादक ग्राहकों की समस्त कॉपीन जरूरतों पर प्रतिक्रिया देने की स्थिति में है । इन विचारों से आयोग के निष्कर्षों का समर्थन मिलता है ।

(73) निष्कर्षतः परिषद इस बात की पुष्टि करती है कि ओ सी एवं ओलीवेटी को इस कार्यवाही के प्रयोजनार्थ सामुदायिक उद्योग की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए ।

(घ) डेवलप की स्थिति

(74) डेवलप जो फोटो कॉपियरों का एक सामुदायिक उत्पादक है, का प्रभावी अधिग्रहण जापान के एक निर्यातक मिनोल्टा द्वारा मई, 1986 में किया गया था और बाद में उसने शिकायत हेतु अपना समर्थन वापस ले लिया । हालांकि डेवलप एक उत्पादक बना हुआ है तथापि, प्रश्न यह उठता है कि क्या उसे क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ सामुदायिक उद्योग माना जाना चाहिए । सीकॉम के विचार से डेवलप को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि संदर्भ अवधि और उससे पूर्व कंपनी को जापानी निर्यातकों के पाटन के व्यवहारों के कारण क्षति पहुंची थी ।

(75) आयोग का यह विचार है कि चूंकि उसने याचिका हेतु अपना समर्थन वापस ले लिया है, इसलिए डेवलप को इस कार्यवाही के प्रयोजनार्थ सामुदायिक उद्योग का भाग अब नहीं माना जाना चाहिए। जहां तक इस तर्क का संबंध है कि संदर्भ अवधि और उससे पूर्व डेवलप को आरोपित क्षति हुई थी और इसलिए उस पर विचार किया जाना चाहिए, परिषद आयोग के उस मत की पुष्टि करती है कि पाटन के व्यवहारों का निवारण करके के लिए उप निवारक उपाय उन उत्पादकों द्वारा पहुंचाई गई क्षति को समाप्त करने के लिए ही लागू किए जा सकते हैं जिन्हें कार्यवाही में सामुदायिक उद्योग के भाग के रूप में परिभाषित किया गया है। अतः इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे किसी उत्पादक, जिसे उद्योग का भाग नहीं माना गया है, द्वारा पहुंचाई गई आरोपित क्षति को ध्यान में रखने के लिए लागू किए जाने वाले उपायों का निर्धारण करना अतार्किक होगा। परिणामतः इस कार्यवाही के प्रयोजनार्थ डेवलप को सामुदायिक उद्योग का भाग नहीं माना जाता है।

(ड) कैनन की स्थिति

(76) कैनन द्वारा आयोग को यह अभ्यावेदन दिए गए थे कि सामुदायिक उद्योग को इस ढंग से परिभाषित किया जाना चाहिए ताक उसमें न केवल शिकयतकर्ता अपितु जर्मनी में फोटोकॉपियरों के उत्पादक कैनन जीसेन और केनन ब्रेटग्ने को भी शामिल किया जा सके। परंतु जिन्होंने शिकायत का समर्थन नहीं किया है, आयोग का यह मानना है कि शिकायतकर्ताओं का उद्योग में एक बड़ा भाग है चाहे कैनन की सहायक कंपनियों को शामिल किया जाए अथवा नहीं। इसलिए इस कार्यवाही में यह पर्याप्त है कि इस बात का निर्धारण किया जाए कि क्या क्षति उद्योग के इस बड़े भाग को हुई क्षति हुई है।

(च) निष्कर्ष

(77) सारांशतः इस कार्यवाही के प्रयोजनार्थ सामुदायिक उद्योग को सामुदायिक उत्पादकों, रैंक जीरोक्स, ओलीवेटी, ओसी एवं टैक्टाज के रूप में परिभाषित किया जाता है जो समुदाय में फोटो कॉपियरों का विनिर्माण करते हैं।

छ. उपर्युक्त का ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि प्राधिकारी ने संबंध निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों के बारे में किए गए अनुरोधों और धरेलू उद्योग के रूप में याचिकाकर्ता कंपनी की पात्रता को सही ढंग से नोट किया है।

ड जांच अवधि का चयन

33. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाया गया एक अन्य मुद्दा वर्तमान मामले में चुनी गई जांच अवधि से संबंधित है। आवेदक धरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किया है :-

क. याचिका में जांच अवधि के रूप में 6 माह का चयन करने के पर्याप्त कारण निहित हैं ;

- ख. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी जांच शुरुआत की सूचना में जांच अवधि के रूप में 6 माह का चयन करने के कारण निहित हैं ।
- ग. जांच अवधि के रूप में 6 माह की अवधि लेने के निर्णय को वरचाऊ लेबोरेटरीज लि. बनाम वित्त मंत्रालय के मामले में माननीय न्यायाधिकरण ने बरकरार रखा है जिसमें सेस्टेट ने निम्नानुसार निर्णय दिया है ।

34. निर्दिष्ट प्राधिकारी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी द्वारा अनिवार्यतः पाटन के निर्धारण हेतु 12 माह की अवधि लिए जाने के बारे में कोई नियम नहीं है । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह पाया है कि 6 माह के दौरान संबद्ध देशों से एच ए एस की आयात कीमत में भारी गिरावट आई है । पिछले चार वर्षों में कीमत में 50% से अधिक की गिरावट आई है और आयातों का पहुंच मूल्य लगातार घट रहा है । जांच की कार्यवाही के दौरान किसी भी पक्षकार द्वारा अवधि के चयन के मामले में प्राधिकारी के खिलाफ दुराशय का कोई आरोप नहीं लगाया गया था ।

35. आवेदक द्वारा दिए गए तर्क के अनुसार जांच अवधि को 12 माह रखने का कोई नियम नहीं है । दूसरी ओर टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 के अनुच्छेद vi के कार्यान्वयन संबंधी करार के भाग-I अनुच्छेद 2.2.1 की पाद टिप्पणी से अलग संकेत मिलेगा । अनुच्छेद 2.2.1 में यह उपबंध है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ऐसी बिक्रियों पर विचार करेंगे जिन्हें पर्याप्त मात्रा में विस्तारित समयावधि के दौरान किया गया है । इस खंड की पाद टिप्पणी में यह स्पष्ट किया गया है कि विस्तारित समयावधि सामान्यतः 1 वर्ष की होगी और यह किसी भी हालत में 6 माह से कम नहीं होगी । इससे यह पता चलेगा कि 6 माह की अवधि का चयन किए जाने पर निषेध नहीं है ।

36 इसी प्रकार के तर्क को रद्द करते हुए न्यायाधिकरण ने अंतिम आदेश सं. 22/2000-ए डी, दिनांक 2.2.2000 (2000 (119) ई एल टी 157(टी)) में निम्नानुसार मत व्यक्त किया है :

"हम आवेदकों की ओर से दिए गए इन तर्कों के प्रति आश्चर्य नहीं हैं कि निर्धारण स्वैच्छिक है क्योंकि डी ए ने निर्धारण के प्रयोजनार्थ जांच अवधि के रूप में केवल 6 माह अर्थात् अक्टूबर, 1994 से मार्च, 1995 तक का चयन किया है । डी ए का यह मत सही है कि जांच अवधि का सुझाव देने के बारे में नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है । तथापि, यह सुझाव देने के लिए अप्रत्यक्ष संदर्भ उपलब्ध है कि जांच अवधि 6 माह से कम नहीं होनी चाहिए । हमारा पाटनरोधी कानून टैरिफ एवं व्यापार संबंधी करार के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार (डब्ल्यू टी ओ करार) पर आधारित है । अनुबंध-1.2.1 और डब्ल्यू टी ओ के लिए नोट (अनुच्छेद 2.2.1) से यह संकेत मिलता है कि जांच अवधि 6 माह से कम नहीं होनी चाहिए । पाटनरोधी कानून के संबंधित उपबंधों में जांच अवधि के बारे में कोई निर्धारण या प्रतिबंध न होने की स्थिति में हमने जांच अवधि के रूप में 6 माह लिए जाने के बारे में डी ए द्वारा अनाई गई कार्यवाही में कोई सुसंगत कानून नहीं पाया है ।"

अतः हम यह मानते हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 6 माह की अवधि चुनने में प्रयोग किया गया विवेकाधिकार किसी भी रूप में त्रुटिपूर्ण है ।

घ. यद्यपि, डब्ल्यू टी ओ करार में जांच अवधि के चयन के बारे में कोई विधिक प्रावधान नहीं है, तथापि, पाटनरोधी व्यवहार संबंधी समिति ने निम्नानुसार उल्लेख किया है :-

(i) पाटनरोधी व्यवहार संबंधी समिति की सिफारिश

20. आंकड़ों के संग्रहण की उचित अवधि के बारे में 4-5 मई, 2000 को हुई अपनी बैठक में पाटनरोधी व्यवहार संबंधी समिति ने पाटन की मौजूदगी और परिणामी क्षति के निर्धारण हेतु मूल जांच के संबंध में सिफारिश की :

"1. सामान्य नियम के रूप में:

- (क) पाटन की जांच हेतु आंकड़ों के संग्रहण की अवधि सामान्यतः 12 माह की होनी चाहिए और यह किसी भी हालत में जांच की शुरुआत की तारीख की समाप्ति के आस-पास के व्यावहारिक रूप से 6 माह से कम नहीं होनी चाहिए;
 - (ख) कम लागत पर बिक्री की जांच हेतु आंकड़ों के संग्रहण की अवधि और पाटन की जांच हेतु आंकड़ों के संग्रहण की अवधि किसी विशेष जांच में समवर्ती होनी चाहिए;
 - (ग) क्षति जांच हेतु आंकड़ा संग्रहण की अवधि सामान्यतः कम से कम तीन वर्ष की होनी चाहिए बशर्ते जिस पक्षकार से आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं वह उससे कम अवधि से विद्यमान न हो और इसमें पाटन की जांच हेतु आंकड़ों के संग्रहण की समूची अवधि शामिल होनी चाहिए ।
 - (घ) सभी मामलों में जांच प्राधिकारियों को आंकड़ों के संग्रहण में शामिल समयावधि निर्धारित करनी चाहिए और इसकी जानकारी अग्रिम रूप से हितबद्ध पक्षकारों को दी जानी चाहिए और वे आंकड़ों के संग्रहण को पूरा करने औ/अथवा उन्हें प्रस्तुत करने हेतु कुछ तारीखें भी निर्धारित कर सकते हैं । यदि ऐसी तारीखें निर्धारित की जाती हैं तो उनकी जानकारी हितबद्ध पक्षकारों को दी जानी चाहिए ।
2. किसी विशेष जांच में आंकड़ों के संग्रहण की विशिष्ट अवधि निर्धारित करने में जांच प्राधिकारी, यदि संभव हो, ऐसी फर्मों के व्यवहारों पर विचार कर सकते हैं जिनसे वित्तीय रिपोर्टिंग और लेखा संबंधी आंकड़ों की उपलब्धता पर उसके प्रभाव के बारे में आंकड़े मांगे जाएंगे । जिन दूसरे कारकों पर विचार किया जा सकता है, उनमें मौसम एवं चक्रीयता सहित संदर्भाधीन उत्पाद की विशेषताएं एवं विशेष आदेश या ग्राहकोनुकूल बिक्री शामिल होगी ।

3. कार्यवाहियों में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए जांच प्राधिकारियों को करार के अनुच्छेद 12.2 के अनुसरण में सार्वजनिक सूचनाओं या प्रदत्त पृथक रिपोर्टों में उस स्थिति में आंकड़ों के संग्रहण हेतु किसी विशेष अवधि के चयन के लिए कारण का स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए यदि वह इस सिफारिश के पैरा 1, राष्ट्रीय विधान, विनियम या स्थापित राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों में उपबंधित अवधि से भिन्न हो।"

21. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि इस मामले में विचारित 6 माह की जांच अवधि पूर्णतः न्यायोचित है। याचिका में पर्याप्त कारण निहित हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच शुरुआत की सूचना में कारण दिए हैं।

22. पाटन -घरेलू उद्योग ने पाटन से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में इससे पूर्व विस्तृत अनुरोध किए थे। घरेलू उद्योग द्वारा इससे पूर्व किए गए अनुरोधों का उल्लेख किया जाता है और उन पर भरोसा किया जाता है। इसके अलावा, वर्तमान जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अन्य अनुरोधों पर वर्तमान अनुरोधों के भाग के रूप में विचार किया जाए। इन्हें संक्षिप्तता की वजह से दोहराया नहीं जा रहा है। तथापि, इन सभी अनुरोधों को कृपया वर्तमान अनुरोधों में शामिल किया गया माना जाए।

23. क्षति एवं कारणात्मक संबंध -घरेलू उद्योग ने क्षति एवं कारणात्मक संबंध से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में इससे पूर्व विस्तृत अनुरोध किए थे। घरेलू उद्योग द्वारा इससे पूर्व किए गए अनुरोधों का उल्लेख किया जाता है और उन पर भरोसा किया जाता है। इसके अलावा, वर्तमान जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अन्य अनुरोधों पर वर्तमान अनुरोधों के भाग के रूप में विचार किया जाए। इन्हें संक्षिप्तता की वजह से दोहराया नहीं जा रहा है। तथापि, इन सभी अनुरोधों को कृपया वर्तमान अनुरोधों में शामिल किया गया माना जाए।

24. मांग में कमी- यह तर्क दिया गया है कि मांग में कमी की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इस संबंध में निम्नलिखित संगत हैं-

क. जांच अवधि के दौरान कुछ कमी को छोड़कर विचाराधीन उत्पाद की मांग में नकारात्मक वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। जहां तक जांच अवधि में मांग का संबंध है, याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि हालांकि मांग में गिरावट आई है तथापि यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एकमात्र और प्रमुख कारण नहीं है। प्रथमतः मांग में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादकों का समान प्रभाव पड़ना चाहिए था। तथापि, जहां विदेशी उत्पादकों ने पर्याप्त बाजार हिस्सा हासिल किया वहीं घरेलू उद्योग ने इसे गंवाया। द्वितीयतः विदेशी उत्पादकों ने कीमतों में भारी कमी की। परिणामतः घरेलू उद्योग कीमत में भारी कटौती करने के लिए बाध्य हुआ था। कीमत मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट पाटित आयातों के कारण आई है।

- ख. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी द्वारा कारणात्मक संबंध के विश्लेषण के बारे में मांग में गिरावट की समुचित जांच नहीं की गई है। याचिकाकर्ता इस बात का खंडन करते हैं और अनुरोध करते हैं कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर उसके प्रभाव में मांग में कमी के मुद्दे की पर्याप्त जांच की है। वस्तुतः मांग में किसी कमी का सभी पक्षकारों पर समान प्रभाव पड़ना चाहिए था। तथापि, जहां आयातों में मांग में कमी के साथ वृद्धि हुई है, वहीं घरेलू उद्योग की बिक्री में अननुपातिक गिरावट आई है। हालांकि यह माना जाता है कि घरेलू उद्योग को मांग में गिरावट के कारण बिक्री को कुछ हद तक गंवाया होगा। तथापि, एक ओर मांग में गिरावट की तुलना में बिक्री में उच्च स्तर पर गिरावट और दूसरी ओर समग्र रूप में तथा उत्पादन एवं खपत की तुलना में आयातों में वृद्धि से इस बात की स्पष्ट पुष्टि होती है कि घरेलू उद्योग को क्षति आयातों के कारण हुई है। इसके अलावा, निम्नलिखित संगत है।
- ग. यह सच है कि आर्थिक मंदी के कारण उत्पाद की मांग में गिरावट आई थी। यह भी सच है कि इस सीमा तक घरेलू उद्योग को क्षति मांग में कमी के कारण हुई है। तथापि, इस तथ्य कि आयातों में उस स्थिति में वृद्धि हुई है जब मांग में गिरावट आई है, से कम से कम संवर्धित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति की पुष्टि होती है। यद्यपि, घरेलू उद्योग मांग में कमी का सामना पहले से कर रहा था तथापि आयातों में वृद्धि के कारा घरेलू उद्योग की कठिनाइयां और बढ़ गईं। इसके अलावा, जहां बिक्री मात्रा में गिरावट (और परिणामतः उत्पादन एवं क्षमता उपयोग), को आंशिक रूप से मांग में गिरावट के रूप में देखा जा सकता है, वहीं इससे लाभप्रदता में अत्यधिक गिरावट न्यायोचित नहीं ठहरती है।
- घ. यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि यदि मांग में कमी न आई होती तो पाटित आयातों की मात्रा में और अधिक वृद्धि नहीं होती। यदि उत्पाद के बाजार में वृद्धि जारी रहती तो पाटित आयातों की मात्रा में भी आगे और वृद्धि हुई होती। कीमत लाभ के कारण इस बात की प्रबल संभावना है कि यदि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमत में तुरंत सुधार न किया होता तो अन्य उपभोक्ताओं ने भी आयात किए होते।
- ड. हम निम्नलिखित मामलों ई ई सी के निर्णय का भी उल्लेख करते हैं, जिनके संगत उद्धरण निम्नानुसार हैं :-

परिषद विनियम (ई सी) सं. 2080/2001, 23 अक्टूबर, 2001 जिसमें जापान के मूल के साइकिलों के आंतरिक गियर हबो के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

(ख) 1999 में खपत में गिरावट और बाजार विकास

(92) इस बात की जांच की गई है कि क्या 1999 में खपत में आई गिरावट सामुदायिक उद्योग को हुई क्षति का एक प्रमुख कारक थी। सामुदायिक बाजार में मूलतः दो बड़े प्रचालकों को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विचार किया गया था कि खपत में गिरावट के संभावित प्रभाव और परवर्ती बाजार विकास की जांच दोनों प्रचालकों के निष्पादन को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

(93) वर्ष 1998 की तुलना में 1999 में सामुदायिक उद्योग की बिक्री मात्रा में लगभग 18% की गिरावट आई जबकि मांग में 8% की गिरावट आई अर्थात् काफी कम गिरावट आई । सामुदायिक उद्योग ने लगभग 9% बाजार हिस्सा भी गंवाया । इसी अवधि के दौरान निर्यातकर्ता उत्पादक बिक्री मात्रा में 17% और बाजार हिस्से में 30% की वृद्धि करने में सफल रहा ।

(94) वर्ष 1999 की तुलना में जांच अवधि के दौरान सामुदायिक उद्योग ने बिक्री मात्रा में 4% की वृद्धि की और उसके बाजार हिस्से में 4% की गिरावट आई । इस बीच निर्यातकर्ता उत्पादक अपनी बिक्री मात्रा (22%) तथा बाजार हिस्से (11%) में आगे और वृद्धि करने में सफल हुआ अर्थात् बाजार सुधार (8%) की तुलना में काफी अधिक सीमा तक वृद्धि हुई है ।

(95) उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1999 में सामुदायिक उद्योग की स्थिति में आई गिरावट खपत में किसी कमी की तुलना में अधिक नाटकीय थी । इसी प्रकार जांच अवधि के दौरान जब बाजार में सुधार हुआ तो सामुदायिक उद्योग का निष्पादन बाजार विकास से काफी कम था । इसी बीच पाटित आयातों में सामुदायिक बाजार में पर्याप्त वृद्धि हुई । परिणामतः पाटित आयातों के विपरीत यह माना जाता है कि खपत में गिरावट ने सामुदायिक उद्योग की क्षतिकारक स्थिति में कोई खास भूमिका नहीं निभाई थी ।

कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष

(102) विचारित जांच अवधि के दौरान अत्यधिक संवर्धित पाटित आयातों, कीमत कटौती और कीमत हास का खासकर बिक्री कीमत और बिक्री मात्रा के संबंध में सामुदायिक उद्योग की आर्थिक स्थिति पर पर्याप्त नकारात्मक प्रभाव पड़ा था जिसके प्रत्युत्तर में बाजार हिस्से और लाभप्रदता भी प्रभावित हुई । पाटित आयातों का प्रभाव इतना अधिक था कि इसे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई । उपर्युक्त तथ्यों और विचारों के आधार पर यह भी निष्कर्ष निकाला जाता है कि ऐसा कोई अन्य कारक जिसकी वजह से सामुदायिक उद्योग को क्षति हो सकती है, ऐसा नहीं था जिससे पुष्टिकृत क्षति तथा संबद्ध पाटित आयातों के प्रभाव के बीच कारणात्मक संबंध टूटता हो ।

आयोग विनियम (ई सी) संख्या 1629/2000, 25 जुलाई, 2000 जिसमें पोलैंड और यूक्रेन के मूल के अमोनियम नाइट्रेट के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

(ख) प्रत्यक्ष खपत में गिरावट

(47) मांग में वृद्धि के साथ-साथ वर्ष 1995 और जांच अवधि (वार्षिक) के बीच अमोनियम नाइट्रेट की प्रत्यक्ष खपत में 950 000 टन की गिरावट आई अर्थात् 16.7% की गिरावट आई । यह गिरावट मुख्यतः वर्ष 1998 और वार्षिकीकृत जांच अवधि के बीच पाई गई थी । ऊपर किए गए उल्लेखानुसार अमोनियम नाइट्रेट के बाजार की विशेषता उसकी अलग मौसमी पद्धति है । अधिकांश बिक्री प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर और मार्च के बीच (बेहतरीन मौसम) होती है जबकि वर्ष के शेष भाग के दौरान मांग तुलनात्मक रूप से कम (सुस्त मौसम) रहती है । चूंकि 18 माह की जांच अवधि में दो सुस्त मौसम और केवल एक बेहतरीन मौसम शामिल हैं इसलिए वार्षिक प्रत्यक्ष खपत कम रही होगी । इसके अलावा, इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि मांग में गिरावट (यद्यपि, इसे जांच अवधि में काफी अधिक बताया गया है) विभिन्न नाइट्रोजन उर्वरकों के बीच कुछेक

प्रतिस्थापन प्रभावों के परिणामस्वरूप आई है। यू ए एन सॉल्यूशन से संबंधित हाल के एक मामले में इस बात की पुष्टि की गई है कि हाल के वर्षों में यू ए एन सॉल्यूशंस की प्रत्यक्ष खपत में वृद्धि हुई है (देखें आयोग विनियम (ई सी) सं. 617/2000 (1)) यह प्रवृत्ति वर्ष 1999 के उत्तरार्ध में जारी रही। तथापि, जहां मांग में गिरावट के कारण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई वहीं इसका कीमतों पर अधोगामी दबाव पड़ा जिससे सामुदायिक उद्योग को क्षति हुई तथापि, सामुदायिक उद्योग को मांग में गिरावट आने की आशा थी इसे वह स्वीकार कर रहा है जैसा कि हाल ही में अलग-अलग संयंत्रों को बंद करने की घोषणा से पता चलता है। इसके अलावा, पाटित आयातों के कारण कीमत दबाव के अभाव में कीमतों में गिरावट तथा सामुदायिक उद्योग की लाभप्रदता काफी कम रही होगी।

कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष

(49) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रत्यक्ष खपत में गिरावट अथवा कुछेक तीसरे देश से हुए आयातों के कारण सामुदायिक उद्योग को निश्चित तौर पर क्षति हो सकती है। यह क्षति खासकर उत्पादन एवं बिक्री मात्रा में गिरावट के रूप में हो सकती है। तथापि, जहां तक सामुदायिक उद्योग की कीमत और लाभ में वृद्धि का संबंध है, पाटित आयात विशेष रूप से एक प्रमुख कारक रहे हैं। जहां एक ओर बीच का समय समवर्ती है जिसमें आयातों की वजह से कीमत में गिरावट और कीमत कटौती की पुष्टि हुई है, वहीं दूसरी ओर संबद्ध देशों के मूल के पाटित आयातों ने अत्यधिक बाजार हिस्सा हासिल कर लिया है और सामुदायिक उद्योग को बिक्री में गिरावट तथा अपने बिक्री कीमतों में कमी तथा अपनी लाभप्रदता में गिरावट आई है। अतः अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि संबद्ध देशों के मूल के पाटित आयातों के कारण सामुदायिक उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। अतः यह भी निष्कर्ष निकाला गया था कि पाटित आयातों से इतर कारकों का प्रभाव इतना नहीं था कि पाटित आयातों और उनसे घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध तोड़ा जा सके।

आयोग विनियम (ई सी) सं. 1845/98, 27 अगस्त, 1998 जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका और थाइलैंड के मूल के कुछेक बड़े इलेक्ट्रोलिटिक एल्युमिनियम कैपेसिटर्स के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

सामुदायिक खपत

(90) एक प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक ने यह दावा किया कि वर्ष 1995 के बाद सामुदायिक उद्योग की बिक्री में आई गिरावट एल ए ई सी बाजार के आर्थिक चक्र में सामान्य मंदी के कारण आई थी। यह नोट किया जाना चाहिए कि सामुदायिक खपत में 1995 और जांच अवधि के बीच 8% की गिरावट आई और इसी अवधि के दौरान सामुदायिक उद्योग की बिक्री में 25% की गिरावट आई अर्थात् सामुदायिक खपत की तुलना में काफी अधिक गिरावट आई थी। इसके अलावा, वर्ष 1995 और जांच अवधि के बीच खपत में गिरावट के बावजूद अमरीका और थाइलैंड के मूल के संचयी पाटित आयात वर्ष 1995 के उच्च स्तर पर मात्रा के रूप में स्थिर रहे परंतु उनके बाजार हिस्से में वृद्धि हुई।

निष्कर्ष

(98) यद्यपि, इस बात को छोड़ा नहीं जा सकता कि अन्य तीसरे देशों से हुए कुछेक आयातों और सामुदायिक खपत में हाल में आई गिरावट के कारण बाजार हिस्से में कमी और सामुदायिक उद्योग की अलाभकारी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तथापि, अब तक हुई जांच से यह भी पता चलता है कि ये कारक ऐसे नहीं हैं जिससे कि जांचाधीन आयातों और सामुदायिक उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को तोड़ा जा सके। यह निष्कर्ष उस अवधि के दौरान जब समुदाय में मांग में वैश्विक रूप से वृद्धि हुई है जिसके साथ-साथ अमरीका और थाइलैंड के मूल के आयातों की मात्रा में उस कीमत पर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिससे सामुदायिक उद्योग की कीमत में कटौती हुई है, खासकर सामुदायिक उद्योग की बिक्री में गिरावट और बाजार हिस्से में कमी को देखते हुए निकाला गया है। परिणामतः ऐसी अवधि में जब सामुदायिक उद्योग अन्य तीसरे देशों से पिछले पाटन से उबरने की कोशिश कर रहा था, तो वह सामुदायिक बाजार में संवर्धित मांग से लाभ प्राप्त करने में असमर्थ था। परंतु यह किफायतों से भी लाभ उठाने में असमर्थ था जिसकी परिणति उस स्थिति में संवर्धित बिक्री मात्रा के रूप में होती यदि घरेलू उद्योग अपना बाजार हिस्सा बनाए रख सकता। इसके अलावा, बिक्री में इस गिरावट के परिणामस्वरूप वर्ष 1995 के बाद सामुदायिक उद्योग की औसत लाभप्रदता में पुनः गिरावट आई और ऐसा ही रोजगार के स्तरों और निवेशों के संबंध में हुआ। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि विचारित अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण सामुदायिक उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

25. मौखिक सुनवाई के समय या रिट याचिका में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य प्रमुख मुद्दे

क. गोपनीयता : याचिकाकर्ता ने ऐसी सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है जो गोपनीय प्रकृति की है क्योंकि उसके प्रकटन से किसी प्रतिस्पर्धी को पर्याप्त प्रतिस्पर्धी नुकसान होगा और अथवा क्योंकि इसके प्रकटन से सूचना प्रदाता किसी व्यक्ति पर अथवा उस व्यक्ति पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे उक्त सूचना हासिल की गई है। याचिकाकर्ता ने गोपनीयता का दावा करने के लिए पर्याप्त कारण दिए हैं जिस पर प्राधिकारी ने विचार किया था। अतः यह ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें प्राधिकारी ने पक्षकारों द्वारा किए गए मात्र दावों के आधार पर गोपनीयता के दावे स्वीकार किए हैं। जहां तक क्लोर अल्कली के बारे में गोपनीयता के दावे अथवा ऐसी ही अन्य सूचना का संबंध है, याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि इस संबंध में गोपनीयता के दावे पूर्णतः संगत हैं। बहरहाल पक्षकारों द्वारा किसी पूर्वाग्रह की पुष्टि नहीं की गई है। यह उल्लो करना भी प्रासंगिक है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के हाथ याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग या विदेशी उत्पादकों द्वारा किए गए दावों तक ही बंधे हुए नहीं हैं। यह प्राधिकारी को संगत सूचना प्रदान करने के लिए किसी निर्यातक या एसोसिएशन/आयातक/प्रयोक्ता के लिए पूर्णतः मुक्त है। खासकर यह उन पक्षकारों के लिए निविष्टि आदि की प्रचलित कीमत के बारे में संगत सूचना प्रदान करने के लिए मुक्त है। वस्तुतः नियम 6 के संगत भाग में आयातकों और उपभोक्ताओं को निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास संगत सूचना उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। संगत नियम नीचे उद्धृत हैं :

(5) निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे मामलों में जहां वस्तु की सामान्य बिक्री खुदरा स्तर पर की जाती है, विचाराधीन वस्तु के औद्योगिक प्रयोक्ताओं और उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों

को ऐसी सूचना प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान करेंगे जो पाटन, क्षति, जहां लागू हो और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच से संगत हैं ।

उपभोक्ताओं या उनकी एसोसिएशन ने किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्रदान नहीं की है । याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह जांच परिणाम में इस बात को विशिष्ट रूप से दर्ज करें कि एसोसिएशन अथवा उसके किसी सदस्य/उपभोक्ता ने कोई तथ्यात्मक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है ।

ख. **संयंत्रवार विश्लेषण** - यह तर्क दिया गया है कि क्षति के बारे में समुचित निष्कर्ष निकालने के लिए संयंत्रवार कोई उचित विश्लेषण नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि यह तर्क अवैध है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए । नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग के बारे में क्षति निर्धारित करना अपेक्षित है । संगत नियम नीचे उद्धृत हैं ।

11. **क्षति का निर्धारण-** (1) विनिर्दिष्ट देशों से आयातों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे इस आशय का एक जांच परिणाम दर्ज करेंगे कि भारत में ऐसी किसी वस्तु के आयात से किसी स्थापित उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है या क्षति होने का खतरा उत्पन्न हो गया है या उससे भारत में किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा उत्पन्न हुई है ।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमत पर उसके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए और इन नियमों के अनुबंध-11 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार घरेलू उद्योग को हुई क्षति, घरेलू उद्योग को क्षति के खतरे, घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए वास्तविक बाधा और पाटित आयातों तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण किया जाएगा ।

26. यह देखा जा सकेगा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए "घरेलू उद्योग" के संबंध में क्षति का निर्धारण करना अपेक्षित है । वस्तुतः ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग में एक से अधिक उत्पादक शामिल हैं, यह सुस्थापित नियम है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्धारण हेतु समग्र घरेलू उद्योग पर विचार करेंगे । निर्दिष्ट प्राधिकारी क्षति विश्लेषण हेतु अलग-कंपनी के निष्पादन पर विचार नहीं कर सकते । ऐसा मामला होने के कारण सूचना को किसी भी हालत में संयंत्रवार विश्लेषण के लिए विभाजित नहीं किया जा सकता । बहरहाल ऐसा कोई विश्लेषण इस वजह से अत्यंत भ्रामक/विकृत होगा कि यह समग्र कंपनी है जिसके निष्पादन की जांच की जा सकती है न कि संयंत्र विशिष्ट निष्पादन । कानून के अंतर्गत संयंत्रवार निष्पादन का निर्धारण करना इस वजह से व्यवहार्य ही नहीं हो सकता कि कंपनी के लिए सभी संयंत्रों/प्रचालनों हेतु समेकित वित्तीय निष्पादन रखना अपेक्षित है । संयंत्रवार वित्तीय रिकॉर्डों का रखरखाव केवल उस सीमा तक अपेक्षित होता है जिस सीमा तक ये कंपनी के खाते में एकीकरण के प्रयोजन हेतु संगत होते हैं । इस बात की प्रबल संभावना है कि कुछ आय एवं व्यय को संगत संयंत्र प्रचालनों में प्रभारित/दर्ज नहीं किया जाता है (ऐसी कोई सांविधिक अपेक्षा नहीं है वस्तुतः इस बात की संभावना है कि संयंत्र स्तर पर

समस्त उत्पादन व्यय को दर्ज किया जाए और अन्य सभी व्यय तथा आय को किसी दूसरे संयंत्र या कार्यालय में दर्ज किया जाए) । वस्तुतः इन नियमों में क्षति के निर्धारण के बारे में निम्नानुसार प्रावधान है ।

- (vi) समान वस्तु के घरेलू उत्पादन के संबंध में पाटित आयातों के प्रभाव का निर्धारण उस स्थिति में किया जाएगा जब उपलब्ध आंकड़ों से उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादकों की बिक्री और लाभ जैसे मानदंडों के आधार पर उक्त उत्पादन के बारे में अलग से पता चलता हो । यदि उक्त उत्पादन के बारे में अलग से ऐसा पता लगाना संभव नहीं है तो पाटित आयातों के प्रभाव का निर्धारण उत्पादों के निकटतम समूह या रेंज जिसमें समान उत्पाद भी शामिल है, के उत्पादन की जांच द्वारा किया जाएगा जिसके लिए आवश्यक सूचना प्रदान की जा सकती है ।

27. यह देखा जा सकेगा कि नियमों में वस्तुतः प्राधिकारी को ऐसी सूचना पर विचार करने का प्राधिकार दिया गया है जिसमें अन्य उत्पाद भी शामिल हो सकते हैं । ऐसी स्थिति में संयंत्रवार निष्पादन की किसी भी हालत में परिकल्पना नहीं की जा सकती ।

क. कोई संवर्धित पाटन नहीं - यह तर्क दिया गया है कि डी ए इस बात को समझने में विफल रहे हैं कि पहुंच मूल्य में गिरावट उत्पादन लागत का एक कार्य होता है जिसका अनिवार्यतः यह परिणाम नहीं निकलता है कि पाटन मार्जिन में वृद्धि हुई है ।

यह अनुरोध किया जाता है कि पाटन मार्जिन सीधे उत्पादन लागत से संबंधित नहीं होता है । ऐसा केवल इस स्थिति में होता है जब उत्पादन लागत बिक्री कीमत से अधिक होती है जिसकी वजह से उत्पादन लागत प्रासंगिक बन जाती है । अन्यथा पाटन मार्जिन घरेलू कीमत और निर्यात कीमत के बीच अंतर होने की वजह से यह अप्रासंगिक है कि उत्पादन लागत में कोई परिवर्तन होना चाहिए । पहुंच कीमत में गिरावट से सर्वप्रथम पाटन में वृद्धि का स्पष्ट तौर पर पता चलता है ।

ख. ग्रे और डायड फाइबर की तुलना - यह तर्क दिया गया है कि ग्रे और डायड के आंकड़े को जोड़ दिया गया है । याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि संगत सूचना प्रदान करने और उचित दावे करने का दायित्व आयातकों, विदेशी उत्पादकों और उपभोक्ता का होता है । हितबद्ध पक्षकार स्वयं को केवल तर्कों तक सीमित नहीं रख सकते । यदि उपभोक्ता या विदेशी उत्पादक यह समझता है कि ग्रे और डायड की लागत और कीमत में भारी अंतर था और उसके लिए पृथक निर्धारण अपेक्षित है तो प्राधिकारी को संगत आंकड़े प्रदान किए जाने चाहिए थे और दावे जांच शुरूआत संबंधी सूचना में निर्धारित समयावधि में किए जाने चाहिए थे । ऐसे तथ्यगत प्रश्न कार्रवाई की ऐसी विलंबित स्थिति में प्राधिकारी के समक्ष नहीं लाए जा सकते ।

28. किसी पूर्वाग्रह के बिना यह अनुरोध किया जाता है कि इस बात की पुष्टि की गई है कि वस्तुतः ग्रे और डायड के आंकड़ों को मिला दिया गया है । आयात आंकड़ों से डायड फाइबर के पर्याप्त आयातों का पता नहीं चलता है । बहरहाल यह मुद्दा पूर्णतः असंगत है ।

29. अधिकांश आयात अग्रिम लाइसेंस पर किए गए थे - याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि एसोसिएशन द्वारा कोई तथ्यात्मक सूचना प्रदान नहीं की गई है । निर्दिष्ट प्राधिकारी

रिकॉर्ड में उपलब्ध संगत सूचना के बिना ऐसे तथ्यात्मक तर्क पर विचार नहीं कर सकते । निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए स्वयं को दावों की सत्यता के बारे में संतुष्ट करना अपेक्षित है जो तभी हो सकता है जब किसी हितबद्ध पक्षकार ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को संगत सूचना प्रदान की है । तथापि, वर्तमान मामले में एसोसिएशन और उसके सदस्यों ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया और इसलिए इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि आयात केवल अग्रिम लाइसेंस पर किए गए थे । उनके खुद के तर्कों से वे स्वयं इस बात का खंडन कर रहे हैं कि अधिकांश आयात अग्रिम लाइसेंस पर हुए हैं । अधिकांश का तात्पर्य मात्र 50% से अधिक हो सकता है । इस बात की संभावना है कि पूर्ववर्ती वर्षों में समूचे आयात अग्रिम लाइसेंस पर हुए थे और केवल 50% या इतने ही आयात जांच अवधि में लाइसेंस पर हुए थे । यदि हां, तो इससे इस बात की स्पष्ट पुष्टि होती है कि उपभोक्ताओं ने शुल्क भुगतान के आधार पर भी विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है ।

30. किसी पूर्वाग्रह के बिना यदि यह तर्क दिया भी जाए कि समूचे आयात अग्रिम लाइसेंस पर हुए थे, तब भी उनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है । जैसा कि जांच के दौरान व्यापक रूप से और बार-बार अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग की कीमत आयात कीमतों पर आधारित की गई हैं । इसके अलावा, उपभोक्ता अलग-अलग आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित तुलनात्मक कीमतों के आधार पर अपने स्रोतों के बारे में निर्णय लेने की स्थिति में है । जाहिर तौर पर ये आयात डी जी एफ टी की नकारात्मक सूची में नहीं है । विदेशी उत्पादकों द्वारा उद्धृत कीमत को भली भांति उस कीमत में बदला जा सकता है जिस पर उपभोक्ता अपनी घरेलू खपत के लिए सामग्री का आयात कर सकता है - केवल अग्रिम लाइसेंस पर हुए आयातों और शुल्क प्रदत्त आयात के बीच अंतर ही सीमाशुल्क का घटक होता है । सीमाशुल्क को विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रदत्त कीमत में जोड़ दिए जाने के बाद उपभोक्ताओं को उस कीमत का पता चलता है जिस कीमत पर वे सामग्री का आयात कर सकते हैं । अतः ऐसा कोई कानूनी या तथ्यात्मक आधार या तर्क नहीं है कि अग्रिम लाइसेंस पर किए गए आयात की वर्तमान प्रयोजन के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है और इससे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती ।

31. सामान्य मूल्य का निर्धारण- यह तर्क दिया गया है कि अनुबंध-1 का पैरा 7 को प्राधिकारी ने लागू नहीं किया है । याचिकाकर्ता इस बात से असहमत है और यह अनुरोध करता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वस्तुतः पैरा 7 लागू किया है । इस संबंध में निम्नलिखित संगत हैं । पैरा 7 के अनुसार चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर किया जा सकता है ।

- (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत,
- (ख) बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में परिकलित मूल्य,
- (ग) ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश के लिए कीमत
- (घ) उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समायोजित भारत में वास्तव में भुगतान की गई कीमत ।

(ड) उचित लाभ मार्जिन शामिल करने हेतु समायोजित भारत में वास्तव में भुगतान की जाने वाली कीमत

सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकल्पित मूल्य के आधार पर इस वजह से नहीं किया जा सकता कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि ऐसा सामान्य मूल्य "समान वस्तु के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलनीय कीमत होनी चाहिए जब वह ऐसे बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में खपत के लिए हो"। इस आधार पर सामान्य मूल्य निकालने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए ऐसे तीसरे देश में किसी सहयोगी उत्पादक द्वारा की गई घरेलू बिक्रियों के बारे में पूर्ण एवं व्यापक सत्यापनीय सूचना के साथ-साथ उत्पादन लागत तथा अन्य सभी संबंधित सूचना तथा साक्ष्य (जिसमें व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान सभी सूचना शामिल है) अपेक्षित होती है। इस संबंध में पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 में निर्धारित तुलना के सिद्धांत भी प्रासंगिक हैं।

याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि चीन के उत्पादकों के लिए भारत एक उचित प्रतिनिधिक देश है। प्रतिनिधिक देश के रूप में भारत पर विचार किए जाने से न केवल सही और पर्याप्त सूचना प्राप्त हुई है अपितु इस बात पर विचार करने का भी कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है कि भारत एक उचित प्रतिनिधिक देश नहीं है। भारत को अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा भी उचित प्रतिनिधिक देश माना गया है।

चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण उपर्युक्त में से किसी एक आधार पर किया जा सकता है। इस प्रकार चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण (1) भारत में कीमत, और (ख) बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ सहित विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया जा सकता है।

किसी पूर्वाग्रह के बिना याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि हितबद्ध पक्षकार पैरा 7 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी को संगत सूचना प्रदान कर सकते थे और निर्दिष्ट प्राधिकारी से उस पर विचार करने का अनुरोध कर सकते थे। परंतु किसी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसी कोई तथ्यात्मक सूचना प्रदान नहीं की है। नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी का दायित्व विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई सूचना के बारे में है।

32. दुराशयपूर्ण याचिका - यह तर्क दिया गया है कि आवेदक की कार्यवाही दुराशयपूर्ण और प्रतिस्पर्धा से बचने की मंशा से युक्त है क्योंकि आवेदक ने तुलन पत्र तथा सार्वजनिक प्रकटन विवरण के रिकॉर्डों के आंकड़ों में जानबूझकर छेड़छाड़ की है। याचिकाकर्ता इस बात का कड़ा विरोध करता है और यह अनुरोध करता है कि ऐसा कोई कोरा विवरण किसी विधिक आधार से रहित है जिसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। याचिकाकर्ता देश में सर्वाधिक सम्मानित व्यापार घरानों में से एक है। किसी भी आंकड़े के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और तुलनपत्र अथवा सार्वजनिक प्रकटन विवरण के रिकॉर्डों में दिए गए आंकड़ों के साथ कोई हेराफेरी नहीं की है। ऐसे विवरण पूर्णतः काल्पनिक हैं।

33. याचिकाकर्ता के आधार से संबंधित अन्य मुद्दे : प्रश्न 6 का पूरा जवाब नहीं दिया गया है

निम्नलिखित प्रासंगिक है :-

- क. समस्त संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी के रिकॉर्ड में है ।
- ख. याचिकाकर्ता ने यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि उसके पास संबद्ध देशों में उत्पादन सुविधाएं हैं ।
- ग. चूंकि याचिकाकर्ता ने स्वयं इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि ये कंपनियां संबंधित हैं इसलिए जिस आधार पर ये कंपनियां संबंधित हैं, वह अप्रासंगिक बन जाता है । संबंध की पुष्टि करने वाली सूचना केवल उन स्थितियों में संगत होती है जब कोई पक्षकार ऐसे संबंध की मौजूदगी का विरोध करता है ।
- घ. याचिकाकर्ता की इंडोनेशिया और चीन में सहायक कंपनियां हैं जो इस उत्पाद का उत्पादन और बिक्री कर रही हैं । ये कंपनियां हैं - बिड़ला जिगवाई फाइबर्स कंपनी लि., चीन तथा पी टी इंडो भारत रेयन, इंडोनेशिया । इन कंपनियों के बीच संबंध का उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है :-

क्र.सं.	सत्ता का नाम	समान निदेशक
1	प्रेसिम इंडस्ट्रीज लि.	श्री कुमार मंगलम बिरला श्री राजश्री बिरला श्री एस के. जैन
2	बिरला जिगवाई फाइबर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.	श्री एस के. जैन
3	पी टी इंडो भारत रेयन, इंडोनेशिया	श्री कुमार मंगलम बिरला श्री राजश्री बिरला श्री एस के. जैन

34. याचिकाकर्ता के इस प्राथमिक तर्क के प्रति पूर्वाग्रह के बिना कि संपूर्ण सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी के रिकॉर्ड में है और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विवेकाधिकार का सही प्रयोग किया है, पूर्व में किए गए अनुरोधों के विकल्प के रूप में याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस बीच सर्कुलर वीविंग मशीनों के मामले में अंतिम जांच परिणाम जारी किए जिनमें निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबंध के बारे में शासित करने वाला सिद्धांत निर्धारित किया है । याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि यदि सर्कुलर वीविंग मशीनों में लागू जांच को वर्तमान मामले में लागू किया जाता है तो यह देखा जाएगा कि याचिकाकर्ता इंडोनेशियाई कंपनी से संबंधित ही नहीं है । अतः इस बारे में विरोधी पक्षकारों द्वारा दिए गए बार-बार तर्कों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी पूर्ववती निर्धारण का पुनर्विलोकन कर सकते हैं और इस बात पर विचार कर सकते हैं कि क्या सभी याचिकाकर्ताओं को संबंधित कंपनी माना जाना चाहिए ।

35. यह तर्क दिया जा सकता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबंध के आधार पर जांच शुरू की है और याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं संबंध की मौजूदगी के बारे में सहमत होने के बाद इसका पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता या प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता। तथापि, याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि प्राधिकारी को पक्षकारों द्वारा किए गए दावों से हटकर अपने खुद के निर्धारण पर पहुंचना चाहिए। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने किसी अन्य मामले में संबंध के बारे में कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं तो ये याचिकाकर्ता के मामले में भी समान रूप से लागू होते हैं। चीन की कंपनी आदित्य बिड़ला ग्रुप की 100% सहायक कंपनी है। वर्तमान प्रयोजनार्थ यह संबंध पूर्णतः अप्रासंगिक है। नियम 2(ख) के अंतर्गत संबंध केवल "निर्यातकों" या "आयातकों" के साथ प्रासंगिक होता है। विदेशी उत्पादकों के साथ संबंध सर्वथा महत्वहीन है और इससे ऐसे घरेलू उत्पादक की अपात्रता सिद्ध नहीं होती है। इंडोनेशियाई कंपनी के साथ संबंध के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। संगत सूचना प्राधिकारी के रिकॉर्ड में है।

36. याचिकाकर्ता ने मनगढ़ंत सूचना के आधार पर जांच शुरू करवाई और अब वह यह दावा कर रहा है कि कोई संबंध नहीं है : जांच के दौरान एकत्र किए गए तथ्यों से भी यह सिद्ध होता है कि जांच की शुरुआत विधिसम्मत है।

37. 6% को अत्यधिक पाटन नहीं कहा जा सकता : अत्यधिक पाटन जांच अवधि के भीतर हुआ था। यदि जांच अवधि के आंकड़ों पर माह दर माह आधार पर विचार किया जाए तो इससे स्पष्ट तौर पर अत्यधिक पाटन की पुष्टि हो जाएगी।

निर्यात कीमत अम.डा. प्रति किग्रा.

	जुलाई, 08	अगस्त, 08	सितंबर, 08	अक्टूबर, 08	नवंबर, 08	दिसंबर, 08
चीन	2.02	2.02	2.10	2.28	2.09	1.78
इंडोनेशिया	2.28	2.17	2.17	2.18	2.24	2.05

जनवरी-मार्च, 09 की अवधि में हुए आयातों से संबंधित सूचना से यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से कीमत में आगे और भारी गिरावट हुई है।

जन.मार्च,09	अम.डा. किग्रा.
चीन	1.57
इंडोनेशिया	1.79

जनवरी-मार्च, 2009 में संबद्ध देशों से निर्यात कीमत में आगे और गिरावट आई है। वस्तुतः ये ऑर्डर जांच अवधि के अंत में बुक किए गए हैं और इसलिए इन्हें प्रतिवादी निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तरों में शामिल किया जाना चाहिए था।

38. हित की समानता है। घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला काउंसलर संबंधित निर्यातक का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है; कानून में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। न तो याचिकाकर्ता और न ही इंडोनेशियाई कंपनी के पास निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास छिपाने की कोई बात है।

39. इस विवण के मद्देनजर कि घरेलू उद्योग चीन या इंडोनेशिया की किसी भी कंपनी से संबंधित नहीं है, जांच की शुरुआत, प्रारंभिक जांच परिणाम और अंतिम जांच परिणाम पुष्टिकरणीय नहीं है; इस तर्क को निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत किया जाए - (1) यह तर्क उस तर्क के विकल्प के रूप में दिया गया है कि याचिकाकर्ता कंपनी को पात्र घरेलू उत्पादक मानने के लिए कोई औचित्याधार नहीं है; (ख) यदि पक्षकार याचिकाकर्ता की इस बात से सहमत हैं कि वह निर्यातकों से संबंधित नहीं है तो समूचा तर्क निष्फल हो जाना चाहिए। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी याचिकाकर्ता के तर्क में कोई दम नहीं पाते हैं तो प्राथमिकता बरकरार रहती है; (ग) यदि कोई दूसरा रास्ता होता अर्थात् ऐसी स्थिति उत्पन्न होती, जिसमें याचिकाकर्ता ने किसी संबंध का दावा किया होता और प्राधिकारी ने ऐसा संबंध पाया होता तो जांच की संभावित अवैधता सही हो सकती थी। तथापि, जहां याचिकाकर्ता ने यह सिद्ध किया है कि ऐसे संबंध से याचिकाकर्ता अपात्र नहीं बनता है, तो बाद में किए गए इस दावे से विधिक स्थिति निष्फल नहीं होती है कि याचिकाकर्ता संबंधित नहीं है।

40. सामान्य मूल्य आंकड़ों की सामान्यता पर आधारित है और वह अभी भी गोपनीय है; निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी निर्यात कीमत एवं पाटन मार्जिन का प्रकटन नहीं कर सकते क्योंकि इससे सामान्य मूल्य का प्रकटन होगा।

41. संक्षेप में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि:

(क) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच सही ढंग से शुरू की गई है।

(ख) याचिकाकर्ता कंपनी घरेलू उद्योग है भले ही उसका संबंध एक इंडोनेशियाई उत्पादक से है। इंडोनेशियाई उत्पादक ने भारत को अत्यंत अल्प मात्रा में निर्यात किया था और वह भी अल्प मात्रा में पर।

(ग) यद्यपि, याचिकाकर्ता ने जांच की शुरुआत के समय संबंध को स्वीकार किया था तथापि, याचिकाकर्ता ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से अब यह अनुरोध किया है कि वह इसकी आगे जांच करें क्योंकि सर्कुलर वीविंग मशीन के मामले में प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि क्या सभी याचिकाकर्ताओं को पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर इंडोनेशियाई उत्पादक से संबंधित कंपनी के रूप में माना जाना चाहिए ।

(घ) भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात संबंधित सामान्य मूल्य से कम कीमत पर संबद्ध देशों से किया गया है ।

(ङ) घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद के संबंध में वास्तविक क्षति हुई है ।

(च) यह वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है ।

(छ) भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना अपेक्षित है ।

पी टी साउथ पैसिफिक विसकोस, इंडोनेशिया; इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन्स और राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की ओर से किए गए लिखित अनुरोध

42. इन हितबद्ध पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

43. प्रारंभिक आपत्तियां : इस मामले में जांच की शुरुआत निम्नलिखित कारणों से क्षेत्राधिकारों से बाहर है:

क. यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने आवेदन प्रपत्र में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानबूझकर और कपटपूर्ण ढंग से परिवर्तन किया है । प्रश्न 6 का भाग "ख" महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातक या आयातक के साथ आवेदक के संबंध के बारे में सूचना दी जाती है । इस प्रकार के संबंध के स्वरूप का यह प्रश्न जो नियम 2(ख) से जुड़ा है, जिसका जांच की शुरुआत से पूर्व उत्तर अवश्य दिया जाना चाहिए था । घरेलू उद्योग के प्रतिनिधि द्वारा यह बताया गया था कि उसने अपेक्षित सूचना प्रदान की है भले ही प्रश्न में परिवर्तन कर दिया गया हो । सादर निवेदन है कि घरेलू उद्योग प्राधिकारी को आश्वस्त करने का निरर्थक प्रयास कर रहा है । अगोपनीय रूपांतरण जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह इस तथ्य के मद्देनजर गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति है, की जांचाधीन देश में उत्पादक/निर्यातक के साथ उसके संबंध के बारे में घरेलू उद्योग ने कोई सूचना प्रदान नहीं की थी । इस बात को इस तथ्य से बल मिलता है कि जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में भी संबंध के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । स्पष्ट तौर पर ऐसा तब हुआ है जब हितबद्ध पक्षकारों ने इस बारे में गंभीर आपत्ति व्यक्त की है कि घरेलू उद्योग ने ऐसा मुद्दा उठाने का प्रयास किया है जो इस मामले के लिए घातक है ।

ख. नियम 2(ख) की संशोधित परिभाषा को ध्यान में रखते हुए भारत में एकमात्र उत्पादक कानून में विशिष्ट उपबंधों के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग नहीं रह जाता है । नियम 2(ख) निम्नानुसार है :-

"नियम 2 (ख) :- "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ केवल शेष उत्पादकों के उल्लेख के रूप में निकाला जाएगा "।

परंतु नियम 11 के उप नियम (3) में उल्लिखित आपवादिक परिस्थितियों में संदर्भाधीन वस्तु के संदर्भ में घरेलू उद्योग के बारे में यह माना जाएगा कि उसमें दो या अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार शामिल हैं और ऐसे प्रत्येक बाजार के उत्पादक एक पृथक घरेलू उद्योग हैं यदि इ

- (i) ऐसे किसी बाजार के भीतर उत्पादक सभी या संदर्भाधीन वस्तु के अपने उत्पादन के अधिकांश भाग की बिक्री उक्त बाजार में करते हैं; और
- (ii) बाजार में मांग उक्त क्षेत्र के किसी भी स्थान पर स्थित उक्त वस्तु के उत्पादकों द्वारा आपूर्त पर्याप्त मात्रा में नहीं है।

ग. फरवरी, 2010 में संशोधन पश्चात् नियम 2(ख) के क्षेत्र का विश्लेषण निम्नलिखित तालिका के जरिए किया गया है :

	27.2.2010 से पूर्व नियम 2(ख)	27.2.2010 से नियम 2(ख)
मुख्य परिभाषा	"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है,	"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है,
अपवर्जन	परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं।	परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं।
विवेकाधिकार का क्षेत्र	ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के उल्लेख के रूप में निकाला जाएगा "।	ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ केवल शेष उत्पादकों के उल्लेख के रूप में निकाला जाएगा "।
निहितार्थ	श्रेणी ख के संबंध में विवेकाधिकार	केवल श्रेणी क + ग के संबंध में विवेकाधिकार

उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि "मुख्य परिभाषा" और "अपवर्जनों" के बारे में नियम 2(ख) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। किया गया परिवर्तन केवल "विवेकाधिकार के क्षेत्र" के

बारे में है। यह अनुरोध किया जाता है कि नियम की स्पष्ट भाषा के अनुसार घरेलू उद्योग की पात्रता का निर्धारण करने के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए कि क्या पात्र घरेलू उत्पादकों को पात्र "घरेलू उद्योग" माना जाए या नहीं। "प्रमुख उत्पादन" की जांच लागू करनी होती है। इस संबंध में यह एकमात्र विवेकाधिकार संशोधित नियम में निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध है।

घ. उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 27.2.2010 की अधिसूचना सं. 18/2010-सी.शु. (एंटी) के तहत पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में किए गए संशोधन के पश्चात प्राधिकारी के पास ऐसे घरेलू उत्पादकों को शामिल करने के बारे में कोई विवेकाधिकार नहीं बचा था जो आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित है या वे स्वयं विचाराधीन उत्पाद के आयातक हैं। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि उक्त संशोधन से पूर्व नियमों में विशेष रूप से निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उत्पादकों की उपर्युक्त श्रेणी के बारे में विवेकाधिकार के प्रयोग की शक्ति दी गई थी जबकि पूर्ववर्ती विवेकाधिकार उक्त संशोधन द्वारा विशेष रूप से वापस ले लिया गया है। यह नोट करना प्रासंगिक है कि संशोधित नियम 2(ख) में "सकता है" शब्द के तहत सीमित विवेकाधिकार दिया गया था और वह "शेष उत्पादकों" और न कि अपवर्जित श्रेणी तक सीमित था। अतः प्राधिकारी द्वारा संशोधित नियम 2(ख) के अंतर्गत "घरेलू उद्योग" की परिभाषा के भीतर आवेदकों को मानने के विवेकाधिकार का कोई प्रयोग क्षेत्राधिकार से बाहर होगा और कानूनसम्मत नहीं होगा।

ङ यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान मामले में दिनांक 1.12.2011 के संशोधन से पूर्व नियम 2(ख) लागू होता है क्योंकि नियम 2(ख) में यह संशोधन सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होता है।

आवेदक का आधार: हितबद्ध पक्षकारों की ओर से हम यह नोट करते हैं कि आवेदक इस नियम के अंतर्गत और इस विषय पर उपलब्ध न्यायशास्त्र के तहत वर्तमान आवेदन दायर करने का पात्र नहीं है। इस संबंध में हमारा निम्नानुसार अनुरोध है :-

च. नियम 2(ख) में यह निर्धारित है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग नहीं मान सकते यदि ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित उत्पाद के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हैं या वे स्वयं उसके आयातक हैं। वर्तमान मामले में जाहिर तौर पर मै. ग्रासिव की चीन और इंडोनेशिया में संबंधित कंपनियां हैं। यह भी अनुरोध किया जाता है कि पी टी इंडो भारत रेयन, इंडोनेशिया संदर्भाधीन आवेदक के 100% स्वामित्व में है जिसने न केवल भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है अपितु उसे पाटन करते हुए भी पाया गया है।

छ. अंतिम जांच परिणाम में यह दर्ज है कि पी टी इंडो भारत रेयन, इंडोनेशिया (एकमात्र घरेलू उत्पादक की 100% सहायक कंपनी) ने अनुचित कीमत व्यवहार का सहारा लिया और जिस पर 0.164% के अधिकतम पाटनरोधी शुल्क के योग्य पाया गया। जबकि अन्य सहयोगी निर्यातक से पाटन मार्जिन केवल 0.103% है। इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि एकमात्र घरेलू उत्पादक

को यह क्षति हर हालत में स्वतः स्फूर्त क्षति है जिसका संरक्षण पाटनरोधी उपाय के रूप में नहीं किया जाना चाहिए ।

ज. यह स्पष्ट है कि क्षति, यदि कोई हुई है, तो उसका कारण संबंधित कंपनी से हुए पाटित आयात हैं । यह कहना व्यर्थ है कि असंबद्ध निर्यातकों के पास इंडोनेशिय के अन्य सहयोगी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत कीमत की बराबरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो एकमात्र भारतीय उत्पादक की 100% ग्रुप कंपनी बताई जाती है । इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि भारतीय उत्पादक और इंडोनेशिया में उसकी सहायक कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए साठ-गांठ की है कि अन्य कंपनियों को सर्वप्रथम कीमत कम करने के लिए बाध्य किया जाए और उसके बाद भारतीय कंपनी भारतीय बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धा को अवरुद्ध करने के एकमात्र उद्देश्य से पाटनरोधी जांच शुरू करवाएं । अनुरोध है कि पाटनरोधी जांच की अनुमति भारत में एकमात्र एकाधिकार प्राप्त उत्पादक की सनक पर नहीं दी जानी चाहिए ।

झ. रिकॉर्ड में यह भी दर्ज किया जाए कि यह सच है कि पी टी इंडो भारत रेयन जो आवेदक की पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कंपनी थी, ने इस जांच में समस्त हितबद्ध पक्षकारों से स्वयं को अलग कर लिया । वस्तुतः आज भी संबंध की वास्तविक प्रकृति आवेदक और इंडोनेशिया के उसके संबद्ध निर्यातक को छोड़कर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ अवरुद्ध है जिनमें से दोनों का प्रतिनिधित्व एक ही प्रतिनिधि के जरिए किया गया है । अतः पक्षकार आधार के बारे में आपत्ति दर्ज करने से वंचित हुए थे ।

ञ. उपर्युक्त के प्रति किसी भेदभाव के बिना यह स्पष्ट है कि संबद्ध आवेदक कंपनी पृथक पाटन मार्जिन के निर्धारण की मांग कर रही है । यह नियम 2(ख) की मान्य परिभाषा के उद्देश्य और प्रयोजन के प्रतिकूल है जिसमें ऐसे उत्पादकों का अपवर्जन निर्धारित है जो निर्यातकों से संबंधित हैं । यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसा करना उचित समझें । घरेलू उद्योग के पक्ष में विवेकाधिकार का प्रयोग नियम 2(ख) में उल्लिखित घटक के उद्देश्य और प्रयोजन के प्रतिकूल होगा ।

ट. जहां तक अंतिम जांच परिणाम में लिए गए इस तर्क का संबंध है कि संबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए आयातों की मात्रा 3% से कम थी, हमारा अनुरोध है कि ऐसी कोई नीति निम्नलिखित पैराग्राफों में उल्लिखित कारणों से विधिसम्मत नहीं है :-

- (i) कानून या सिद्धांत में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि आयातों की मात्रा नियम 2(ख) के अंतर्गत विवेकाधिकार के प्रयोग हेतु एक निर्णायक कारक हो सकती है । यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि जहां कहीं विधान में संख्यात्मक मानदंड लागू करना अपेक्षित होता है, वहां ऐसा विशिष्ट रूप से किया गया है । उदाहरणार्थ न्यूनतम पाटन मार्जिन के रूप में 2%, प्रत्येक देश से न्यूनतम मात्रा के रूप में 3% और 7% का उल्लेख

भारतीय पाटनरोधी नियम के अनुसार डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार में किया गया है । नियम 2(ख) अथवा पाटनरोधी करार में तदनुरूपी अनुच्छेद के अंतर्गत विवेकाधिकार के प्रयोग हेतु ऐसा कोई संख्यात्मक मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है ।

- (ii) नियम 2(ख) हेतु संख्यात्मक मानदंड प्रदान न करने का बेहतरनीन कारण है क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा संबंध की प्रकृति का है और साठ-गांठ वाले व्यवहार की संभावना का है ।
- (iii) यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र में स्वयं संबंध की प्रकृति के बारे में सूचना मांगी जाती है न कि किसी पक्षकार द्वारा किए गए आयातों की मात्रा के बारे में ।

ठ. संबद्ध पक्षकार के सौदों का समूचा मुद्दा "एकल आर्थिक उद्यम" के सिद्धांत पर आधारित है । अमरीकी हॉट रोल्ड स्टील, पैरा 141 से 158 : संदर्भ डब्ल्यू टी/डी एस-184/एबी/आर में अपीलीय निकाय ने यह निर्णय लिया है कि "निगमित कानून और कार्यनीति तथा वित्तीय कानून से संबंधित ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से एकल आर्थिक उद्यम के भीतर इस प्रकार से संसाधन स्थापित किए जा सकते हैं " ।

ड ई सी न्यायशास्त्र और अकादमिक साहित्य के अंतर्गत प्राधिकरणों ने "घरेलू उद्योग" की परिभाषा से उस स्थिति में घरेलू उत्पादक को अलग रखा है यदि यह पाया गया है कि

- (i) संबद्ध निर्यातक ने पाटन के व्यवहार में भाग लिया था, अथवा
- (ii) संबंधित निर्यातक ने बाजार में कीमतों में गिरावट की है या उसमें योगदान किया है ।

क. वर्तमान मामले में स्वयं निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि :

- (i) भारतीय आवेदक इंडोनेशिया के प्रमुख उत्पादक और निर्यातक से संबंधित हैं ।
- (ii) इंडोनेशिया के संबंधित निर्यातक ने पाटित कीमत पर भारत को निर्यात किया है । संबंधित निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन अन्य सहयोगी निर्यातक की तुलना में लगभग दोगुना है । (उपर्युक्त मानदंड (ज) (i)) । अतः यह स्पष्ट होता है कि ऐसी स्थिति में हुई क्षति स्वतः स्फूर्त है जिसमें कोई भी पाटनरोधी प्राधिकारी कभी भी शुल्क नहीं लगा सकता ।
- (iii) विस्तृत विश्लेषण से यह पता चलेगा कि संबंधित निर्यातक ने स्वयं अन्य निर्यातकों की तुलना में कम कीमत पर सामग्री को प्रस्तुत कर कीमत में गिरावट की है । अतः इंडोनेशिया के संबंधित निर्यातक अर्थात् पी टी इंडो भारत रेयन ने न केवल भारतीय

बाजार में कीमत में कटौती की है अपितु उसमें सहारा भी दिया है । (उपर्युक्त मानदंड (ज) (ii)) ।

- (iv) यह कहना व्यर्थ है कि असंबद्ध निर्यातकों के पास इंडोनेशिया के अन्य सहयोगी निर्यातक द्वारा प्रस्तावित कीमत की बराबरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो जाहिर तौर पर आवेदक की एक संबंधित कंपनी है । इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि भारतीय उत्पादक और इंडोनेशिया में उसके समूह की कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए सांठगांठ की है कि प्रतिस्पर्धियों को सर्वप्रथम कीमत कम करने के लिए बाध्य किया जाए और उसके बाद आवेदक द्वारा कार्यनीतिक रूप से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा बाधित करने के एकमात्र उद्देश्य से पाटनरोधी जांच शुरू करवाई जाए ।
- (v) ई सी न्यायशास्त्र को भी ध्यान में रखते हुए ऐसे संबंधित उत्पादक जो उपर्युक्त में से कोई भी मानदंड को पूरा करते हैं, घरेलू उद्योग की परिभाषा से अलग रखे जाएंगे ।

44. अल्प एवं अनुचित जांच अवधि:- यह अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान मामले में आवेदक ने 6 माह की जांच अवधि का अनुरोध किया था जिसे प्राधिकारी ने किसी ठोस आधार या कारण के बिना व्यवहार और दिशा-निर्देशों में अपवाह करते हुए स्वीकार किया गया था । माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस बात को नहीं समझा है कि आवेदक ने कार्यनीतिक ढंग से केवल 6 माह में हुई क्षति के बारे में दावा किया है और विशिष्ट दिशा-निर्देशों तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पद्धति के प्रतिकूल ऐसे दावों के आधार पर नियम 5 की पूर्व शर्तों की जांच करने का अनुरोध किया है । 6 माह की जांच अवधि का चयन पाटनरोधी व्यवहार संबंधी समिति के दिशा-निर्देशों के भी प्रतिकूल है । डी जी ए डी का यह सुसंगत विचार रहा है कि सर्वाधिक वांछनीय जांच अवधि एक वित्त वर्ष है । कई मामलों में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस बात पर जोर दिया है कि सूचना आवश्यक रूप से कम से कम एक वर्ष की होनी चाहिए । न्यूनतम 6 माह की जांच अवधि का नियतन करते समय आंकड़ों की उपलब्धता पर प्रभाव डालने वाले वित्तीय रिपोर्टिंग, संदर्भाधीन उत्पाद की विशेषताओं और उसकी मौसमगत उपलब्धता तथा चक्रीयता आदि में से किसी भी कारक को ध्यान में नहीं रखा गया है ।

क. जांच अवधि के रूप में 6 माह की ऐसी अवधि को स्वीकार करते समय डी ए ने निर्णयाधीन प्रारंभिक जांच परिणामों में निम्नानुसार दर्ज किया है :

"5.3 प्राधिकारी ने जांच अवधि के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नोट किया है और उसका यह विचार है कि वर्तमान मामले में चुनी गई जांच अवधि का चयन मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित ढंग से किया गया है जिसमें इस विषय पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़े भी शामिल हैं । इसके अलावा, जांच अवधि के रूप में 6 माह की अवधि को लेने के निर्णय को बरचाऊ लेबोरेटरीज बनाम वित्त मंत्रालय के मामले में माननीय न्यायाधिकरण ने भी बरकरार रखा है " ।

ख. यह देखा जा सकता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणाम में मात्र यह उल्लेख किया है कि "उसका यह विचार है कि वर्तमान मामले में चुनी गई जांच अवधि का समुचित रूप से चयन मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए किया गया है जिसमें इस विषय पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़े भी शामिल हैं"। सादर निवेदन है कि यह मात्र ऐसा कथन है जिसे तर्कसम्मत कारण के आधार पर विवेकाधिकार की समुचित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में जुलाई-दिसंबर, 2008 में अत्यधिक पाटन किए जाने की बात कही गई है। यह जांच अवधि के रूप में 6 माह की आपवादिक अवधि का चयन करने के लिए किसी आधार या तर्क से रहित है। वस्तुतः जांच अवधि के रूप में सामान्यतः एक वर्ष को लिए जाने की परंपरा यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई है कि अल्पावधिक कीमत घट-बढ़ के कारण कोई पाटनरोधी जांच शुरू न की जाए। इसके अलावा प्राधिकारी को इस बात की पूरी जानकारी है कि 6 माह की अल्पतम अनुमत्य जांच अवधि में लगभग 4 ऐसे माह शामिल हैं जब समूचा विश्व अप्रत्याशित आर्थिक और वित्तीय संकट से गुजर रहा था जिसमें फैब्रिक और बाद में यार्न तथा फाइबर उद्योग पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अन्यथा उभरते हुए बाजार में मांग में भारी गिरावट आई थी और इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा चुनी गई अवधि को नहीं लिया जाना चाहिए था भले ही वह कानूनी रूप से अनुमत्य हो। यह स्पष्ट किया जा सकता है कि यह मुद्दा 6 माह की जांच अवधि का चयन करने की विधि मान्यता के बारे में नहीं है अपितु इसके औचित्य के बारे में है। उपर्युक्त के समर्थन में पाटनरोधी व्यवहार संबंधी समिति के निम्नलिखित दिशा-निर्देशों से लिए गए उद्धरणों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

"1. सामान्य नियम के रूप में:

- i. पाटन की जांच हेतु आंकड़ों के संग्रहण की अवधि सामान्यतः 12 माह की होनी चाहिए और यह किसी भी हालत में जांच की शुरुआत की तारीख की समाप्ति के आस-पास के व्यावहारिक रूप से 6 माह से कम नहीं होनी चाहिए;

3. कार्यवाहियों में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए जांच प्राधिकारियों को करार के अनुच्छेद 12.2 के अनुसरण में सार्वजनिक सूचनाओं या प्रदत्त पृथक रिपोर्टों में उस स्थिति में आंकड़ों के संग्रहण हेतु किसी विशेष अवधि के चयन के लिए कारण का स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए यदि वह इस सिफारिश के पैरा 1, राष्ट्रीय विधान, विनियम या स्थापित राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों में उपबंधित अवधि से भिन्न हो।" (जोर दिया गया)।

गुण-दोष के आधार पर कोई मामला नहीं बनता है:

45. जांच की शुरुआत के बारे में ही उपर्युक्त आपत्तियों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के गुण-दोष के अनुसार क्षति या कारणात्मक संबंध, कुछ भी हो के बारे में मामला बनाने में असमर्थ रहा है।

46. बाजार हिस्सा: आवेदक ने यह दावा किया है कि उसने संबद्ध देशों से आयातों के कारण बाजार हिस्सा गंवाया है। इस संबंध में अनुरोध है कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि आवेदक का बाजार हिस्सा 6 माह की जांच अवधि के दौरान 99.91% से घटकर 94.10% हो गया जिसमें मामूली 5.81% का नुकसान हुआ। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस बात को नहीं समझा है कि बाजार हिस्से में यह मामूली गिरावट अपूर्ण आंकड़ों पर आधारित है। बहरहाल 6 माह की अल्प अवधि के भीतर बाजार हिस्से में लगभग 6% की गिरावट क्षति का आधार नहीं हो सकती जो बृहत आर्थिक समस्याओं के लिए अल्पावधि है, वास्तविक क्षति की बात छोड़ ही दी जाए।

47. घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग: यह दावा किया गया है कि जांच अवधि के दौरान आवेदक के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसा कोई विश्लेषण पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसमें इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया है कि आवेदक ने वर्ष 2008-09 के दौरान स्थापित क्षमता में 41.40% की वृद्धि की थी। स्पष्टतः यह आशा नहीं की जा सकती कि नई क्षमता उसी स्तर पर प्रचालन करेगी जिस स्तर पर मौजूदा क्षमता प्रचालन कर रही थी। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग में गिरावट निश्चित रूप से अल्प जांच अवधि के दौरान उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट के कारण आई है जिसका कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

48. कीमत में कोई कटौती नहीं: यह देखा जा सकता है कि इंडोनेशिया से कीमत में कोई कटौती नहीं हुई है और चीन से कीमत कटौती नगण्य है। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाने का कोई मामला नहीं बनाया गया है।

अन्य कारक और कारणात्मक संबंध का अभाव:

49. यह मानते हुए भी कि आवेदक ने अल्पावधि के लिए संयंत्र को बंद किया है तथापि, इस बात को सिद्ध करने का पर्याप्त साक्ष्य है कि यह क्षति स्वतः स्फूर्त थी अथवा यह पाटन से इतर कारकों की वजह से हुई थी। पाटनरोधी नियमों के अनुसार पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी पाटन की वजह से घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति को सिद्ध करने के लिए एक अनिवार्य पूर्व अपेक्षा है। पाटनरोधी कार्रवाई में यह सिद्ध करना अनिवार्य है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। क्षति के निर्धारण के सिद्धांतों से संबंधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के खंड (V) के उपबंधों में निम्नानुसार उल्लेख है :-

" यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है; जैसा कि उपर्युक्त पैराग्राफ (ii) तथा (iv) में उल्लेख किया गया है। पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का प्रदर्शन निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष सुसंगत साक्ष्य की जांच पर आधारित होगा। इसके साथ ही निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटित आयातों से इतर अन्य ज्ञात कारकों जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, की भी जांच करेंगे और इन कारकों से हुई क्षति को पाटित आयातों का कारण नहीं माना जाएगा। इस संबंध में जो कारक

प्रासंगिक हो सकते हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ आयातों की मात्रा एवं कीमतें; जिन्हें पाटित कीमतों पर नहीं बेचा गया, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां एवं विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास एवं घरेलू उद्योग का निर्यात कार्यनिष्पादन एवं उत्पादकता शामिल हैं ... ।"

50. बिक्री मात्रा : घरेलू उद्योग ने बिक्री मात्रा में गिरावट की वजह से क्षति होने का दावा भी किया है। यहां पुनः घरेलू उद्योग की विभिन्न रिपोर्टों से इस बात का स्पष्ट पता चलता है कि बिक्री मात्रा में गिरावट आई है परंतु यह याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार आरोपित पाटन के कारण नहीं आई है। बिक्री मात्रा में गिरावट की वजह निम्नलिखित कारक रहे हैं :-

- वैश्विक मंदी के कारण उपभोक्ता खरीददारी से वंचित रहे क।
- ऋण की कमी और ऋण जोखिम कारक की वजह से मांग में कमी को देखते हुए वस्त्र उत्पन्न करने वालों के निर्यात में तेजी से आई गिरावट।
- घरेलू मांग में संयतन।
- कीमत वृद्धि के प्रभाव के साथ वैश्विक मंदी।
- मूल श्रृंखला में माल सूची का परिसमापन।

51. बिक्री मात्रा में गिरावट के उपर्युक्त कारणों का उल्लेख स्वयं घरेलू उद्योग ने अपनी विभिन्न रिपोर्टों/अभ्यावेदनों में किया है। अतः उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में गिरावट का कारण आरोपित पाटन को नहीं माना जा सकता।

52. आवेदक की कीमत नीति : हम माने गए निर्यातों के बारे में याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई कीमत नीति और कार्यनीति के बारे में अपने अनुरोधों को दोहराते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता का यह मानना है कि घरेलू उद्योग रिबेटों के रूप में माने गए निर्यातों पर अपनी आपूर्तियों के लिए घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है।

क. आवेदक की कीमत नीति के अनुसार रिबेट तब प्रदान किए जाते हैं यदि माने गए निर्यातों पर की गई आपूर्तियों के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों :-

- ग्राहक को विदेशी क्रेता के साथ वी एस एफ आधारित यार्न की निर्यात संविदा को अमल में लाने के तुरंत बाद उसकी सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

- रिबेट के साथ वी एस एफ की आपूर्ति डी ई बी पी तथा शुल्क प्रति अदायगी स्कीम के अंतर्गत निर्यात साक्ष्य की प्राप्ति पर पुनः पूर्ति आधार पर की जाएगी । पुनः पूर्ति के प्रयोजनार्थ उत्पाद शुल्क बीजक और ए आर आई ई की प्रति पर्याप्त होगी । तथापि, नौवहन बिल/लदान बिल के रूप में निर्यात के आगे साक्ष्य के लिए निर्यात बीजक आदि की प्रति ए आर आई आई की तारीख से 30 दिन के भीतर हमें प्राप्त होना जरूरी है ।
- छूट स्कीमों के अंतर्गत किसी रिबेट का लाभ उठाने के लिए किसी स्पिनर विनिर्माता वी एस एफ आधारित ब्लेंडेड एवं ट्विस्टेड यार्न को रेंज के चरण में विभिन्नित अंतिम उत्पाद के न्यूनतम 35% वी एस एफ तत्व को सुनिश्चित करना होगा ।

ख. अतः उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता उपर्युक्त शर्तें पूरी होने पर ग्राहकों को प्रस्तुत संबद्ध वस्तु की मूल कीमत से रिबेटों के रूप में ये प्रोत्साहन स्कीमों पेश कर रहा है । प्राधिकारी को यह मानना होगा कि यदि संबद्ध वस्तु की पेशकश ग्राहकों को सामान्य घरेलू बिक्री के लिए की गई होती तो याचिकाकर्ता द्वारा प्रभारित कीमत अधिक रही होती ।

ग. यह पाया गया है कि माने गए निर्यातों पर की गई आपूर्तियों के लिए प्रभारित कीमत घरेलू बिक्री के लिए प्रभारित कीमत से काफी कम है । इसे याचिकाकर्ता की कीमत सूचियों से देखा जा सकता है ।

घरेलू उद्योग की कीमत कार्यनीति और नीति से यह प्रतीत होता है कि आकस्मिक निर्यातों के लिए ग्राहकों को की गई कुछेक बिक्रियां भी क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू बिक्री में शामिल कर दी गई हैं ।

पाटनरोधी उपायों का प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्र एवं उचित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित करना है । ये अनुचित व्यापार व्यवहारों के कारण घरेलू बाजार में याचिकाकर्ता को हुई क्षति को दूर करने के लिए निवारक उपाय के रूप में कार्य करते हैं ताकि घरेलू उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा का समान अवसर प्रदान करते हुए उचित और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके । अतः क्षति विश्लेषण हेतु ज्ञात निर्यात बिक्री को शामिल करना पाटनरोधी नियम एवं विनियम के असंगत है ।

घ. क्षति विश्लेषण के संदर्भ में यहां पाटनरोधी नियमों के उपबंध उद्धृत करना संगत है । क्षति निर्धारण के सिद्धांतों के बारे में अनुबंध-II निम्नानुसार है :-

"(i) क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और ; (ख) पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातकों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होगी ।"

ड यह देखा जा सकता है कि आवेदक को इस बात की पूरी जानकारी है कि संबद्ध वस्तुएं आकस्मिक निर्यातों के लिए हैं और इसलिए वह निर्यात बाजार को न गंवाना सुनिश्चित करने के लिए अलग कीमत नीति अपना रहा है । इसका घरेलू बाजार में निष्पादन से कोई लेना-देना नहीं है जो कानूनी अपेक्षा है । घरेलू उद्योग उस स्थिति में आरोपित पाटन के अंतर्गत क्षति का बचाव नहीं कर सकता जब तथाकथित क्षति उसकी खुद की कीमत नीतियों के कारण हुई हो

। अतः आरोपित पाटन और याचिकाकर्ता को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का स्पष्ट अभाव है ।

च. हम यह भी समझते हैं कि याचिकाकर्ता ने अपनी संबंधित कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में आपूर्तियां की हैं । हम आभारी होंगे यदि इस पर गौर किया जाए और ऐसी सभी सूचना का अगोपनीय रूपांतरण हमारी टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराया जाए ।

53. यह भी अनुरोध है कि कार्यवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से किए गए विभिन्न अनुरोधों पर लिखित अनुरोधों के भाग के रूप में विचार किया जाए क्योंकि उन्हें संक्षिप्तता की वजह से दोहराया नहीं जाता है ।

54. उपर्युक्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए हम माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि अब जांच समाप्त कर दी जाए ।

घरेलू उद्योग की ओर से किए गए उत्तर संबंधी अनुरोध

क. प्राधिकारी सेस्टेट के रिमांड ऑर्डर स्वीकार न करने के कारणों का खुलासा करें ।

55. इसका उत्तर निर्दिष्ट प्राधिकारी को देना है ।

ख. जांच की शुरुआत निम्नलिखित कारणों से क्षेत्राधिकार रहित है ।

क. घरेलू उद्योग ने आवेदन प्रपत्र में जानबूझकर परिवर्तन किया है और उसने प्रश्न 6 के भाग ख का उत्तर नहीं दिया है जिसका उत्तर जांच की शुरुआत से पूर्व देना जरूरी था ।

56. लिखित अनुरोधों का अवलोकन किया गया है और उन पर भरोसा किया गया है जिनमें इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया गया है । ऐसी कोई मंशा नहीं है । तथ्य रिकॉर्ड में । इसके अलावा, प्राधिकारी द्वारा दर्ज जांच परिणाम से इस बात की पुष्टि होती है कि घरेलू उद्योग के क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है ।

ख. प्राधिकारी के पास ऐसे घरेलू उत्पादकों को शामिल करने के बारे में कोई विवेकाधिकार नहीं है जो या तो आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हैं या फिर वे स्वयं विचाराधीन उत्पाद के आयातक हैं ।

57. लिखित अनुरोधों का अवलोकन किया गया है और उन पर भरोसा किया गया है जिनमें इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया गया है ।

ग. दिनांक 1.12.2011 को किए गए संशोधन से पूर्व नियम 2(ख) लागू होता है क्योंकि यह संशोधन सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होता है ।

58. संशोधन लागू होगा ।

59. प्राधिकारी ने चल रहे मामलों में बजट 2010 संशोधन लागू किया है । अतः वर्तमान संशोधन भी लागू किया जाना चाहिए ।

60. याचिकाकर्ता ने यह सिद्ध किया है कि इससे स्थिति में कोई बाधा नहीं पहुंचती है ।

ग. आवेदक निम्नलिखित कारणों से वर्तमान आवेदन दायर करने का पात्र नहीं है ।

क. मै. ग्रासिम की संबंधित कंपनियां हैं ।

61. लिखित अनुरोधों का अवलोकन किया गया है और उन पर भरोसा किया गया है जिनमें इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया गया है । इस संबंध से याचिकाकर्ता राहत मांगने से वंचित नहीं होता है । यह हमारी मंशा के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना है कि संबंध भी ऐसे नहीं हो सकते जिन पर नियम 2(ख) के उपबंध लागू होते हों । सर्कुलर वीविंग मशीन मामले में प्राधिकारी के निर्णय तथा उभरते हुए न्यायशास्त्र पर भरोसा किया जाता है ।

ख. अंतिम जांच परिणाम में पी टी इंडो भारत रेयन, इंडोनेशिया (एकमात्र घरेलू उत्पादक की 100% सहायक कंपनी) का आकलन अधिकतम पाटनरोधी शुल्क के साथ किया गया था । यह स्पष्ट होता है कि एकमात्र घरेलू उत्पादक को हुई क्षति स्वतः सफूर्त क्षति है जिसका बचाव पाटनरोधी क्षति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए था ।

62. अनुरोध है कि वर्तमान मामले में पुष्टिकृत सकारात्मक पाटन मार्जिन से स्पष्ट होता है कि असंबद्ध इंडोनेशियाई उत्पादक ने पाटन नहीं किया जिसे अप्रेरित पाया गया है और इसकी वजह पी टी इंडो भारत रेयन द्वारा किए गए 3 छोटे पोतलदान नहीं हैं । पी टी साउथ पैसिफिक विस्कोस द्वारा पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु का पर्याप्त मात्रा में निर्यात किया गया है । संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों से भी घरेलू उद्योग को "क्षति" हुई है । यह भी अनुरोध किया जाता है कि ऐसी क्षति में छोटे और छितरे हुए निर्यात भी एक प्रमुख कारक नहीं रहे हैं । इसके अलावा, मै. ग्रासिम इंड लि. का फोकस संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिक्री पर जारी है । अतः स्वतः सफूर्त क्षति का मामला प्रतीत नहीं होता है ।

ग. क्षति, यदि कोई है, तो वह संबद्ध कंपनी से पाटित आयातों के कारण हुई है । संबद्ध निर्यातक के साथ घरेलू उत्पादक ने यह सुनिश्चित करने के लिए सांठगांठ की है कि अन्य प्रतिस्पर्धियों को पहले कीमत कम करने के लिए बाध्य किया जाए और फिर उचित प्रतिस्पर्धा अवरुद्ध करने के लिए पाटनरोधी जांच कराई जाए ।

63. कार्रवाई की जा चुकी है । इन निर्यातों के कारण ऐसी कोई क्षति नहीं हुई है । अन्य निर्यातकों के संबंध में सकारात्मक पाटन मार्जिन को देखते हुए यह निराधार है कि यहां उचित प्रतिस्पर्धा थी ।

क. भारतीय उत्पादक और पी टी इंडो भारत रेयन के बीच संबंध के सही स्वरूप को जांच के दौरान रोका गया है । जिनका उसी प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व किया गया है और इस प्रकार पक्षकारों को आधार के बारे में आपत्तियां करने से वंचित किया गया था ।

64. कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है । न तो याचिकाकर्ता और न ही इंडोनेशियाई कंपनी ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से कुछ भी छिपाया है और न ही इससे स्थिति में किसी भी रूप में व्यवधान उत्पन्न हुआ है ।

ख. अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण की मांग करने वाली संबद्ध कंपनी ने नियम 2(ख) के निहितार्थ के विरुद्ध कार्य किया है ।

65. न तो भारतीय कानून में और न ही डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी को किसी घरेलू उत्पादक को उस स्थिति में अपात्र माना जाना चाहिए यदि वह विदेशी उत्पादक से संबंधित है और ऐसे मामले में ऐसा संबंधित विदेशी उत्पादक जांच में भाग लेता है और उसके निर्यातों के बारे में सकारात्मक पाटन मार्जिन की पुष्टि होती है। इसके अलावा, प्रत्येक ज्ञात निर्यातक के संबंध में पृथक पाटन मार्जिन निर्धारित करना अपेक्षित होता है और अधिनियम तथा पाटनरोधी नियमों में इस बारे में संबद्ध एवं असंबद्ध निर्यातक के बीच कोई भेद नहीं किया गया है। जहां तक नियम 2(ख) के निहितार्थ का संबंध है, इसके अंतर्गत ऐसे किसी मामले में प्राधिकारी में स्पष्ट विवेकाधिकार निहित है। तथापि, ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग निष्पक्ष रूप में और तथ्यपरक ढंग से करने की जरूरत है।

ग. जहां तक अंतिम जांच परिणाम में अपनाए गए इस तर्क का संबंध है, कि संबद्ध पक्षकारों से आयात 3% से कम हैं, यह दृष्टिकोण वैध नहीं है क्योंकि नियम 2(ख) के अंतर्गत विवेकाधिकार के प्रयोग हेतु आयातों की कोई मात्रा कोई निर्णयात्मक कारक नहीं हो सकती है।

66. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के पास यह तर्क देने का कोई आधार नहीं है कि निर्यातों की मात्रा पर आधारित मानदंड कोई तर्कसम्मत मानदंड नहीं है। चूंकि वर्तमान मुद्दा किसकी संबद्ध निर्यातक द्वारा किए गए "निर्यातों" का है, इसलिए घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि संबद्ध घरेलू उद्योग के अपवर्जन का निर्णय करने के लिए आयात की मात्रा वस्तुतः एक प्रमुख कारक है।

67. निर्दिष्ट प्राधिकारी को वैश्विक पद्धतियां दिखाई गई हैं। इसके विपरीत विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने इस बारे में कोई सामग्री प्रदान नहीं की है।

घ. जांच की कम अवधि ली गई है। मौसम एवं चक्रीयता आदि सहित उत्पाद की वित्तीय रिपोर्टिंग, विशेषताओं जैसा कोई कारक नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विवेकाधिकार के किसी उचित प्रयोग के बिना 6 माह की जांच अवधि चुनी है। इन 6 महीनों में मांग में भारी गिरावट आई है और इन 6 महीनों में मंदी के वे चार माह भी शामिल हैं जिनमें यार्न और फाइबर उद्योग को नुकसान हुआ है।

68. लिखित अनुरोधों का अवलोकन किया गया है और उन पर भरोसा किया गया है जिनमें इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया गया है। याचिकाकर्ता ने यह दोहराया है कि जहां तक निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए दिशा निर्देशों और पद्धति अथवा पाटनरोधी व्यवहार समिति के दिशा निर्देश का संबंध है, यह अनुरोध किया जाता है कि (क) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कई मामलों में 6 माह की जांच अवधि अपनाई है, (ख) हितबद्ध पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि जांच अवधि के रूप में 6 माह पर विचार करना अवैध नहीं है, (ग) उल्लिखित दिशा निर्देशों का पाटन अनिवार्यतः लागू शर्त के रूप में नहीं किया जा सकता। भले ही मामले के तथ्य कुछ भी हों। वित्तीय रिपोर्टिंग जैसे कारकों पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें केवल एक अवधि अर्थात् अप्रैल-मार्च पर जांच अवधि के रूप में विचार किया

जाएगा । जहां तक इस तर्क का संबंध है, कि 6 माह की जांच अवधि में 4 माह की मंदी की अवधि शामिल है, याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि निर्यात कीमत से कम सामान्य मूल्य के समर्थन में मंदी के तथ्य का चुनिन्दा ढंग से तर्क नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मंदी का तथ्य सामान्य मूल्य पर सामान्य रूप से लागू होगा । अतः यह अनुरोध है कि इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमत भारत को निर्यात कीमत की तुलना में काफी अधिक थी । अतः विश्व बाजार में मंदी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह जांच अवधि तय करने में विचार किए जाने वाला न्यायोचित कारण है ।

ड क्षति स्वतः स्फूर्त है अथवा यह मुख्यतः अन्य कारकों से हुई है ।

69. वर्तमान मामले में पुष्टिकृत सकारात्मक पाटन मार्जिन से स्पष्ट होता है कि असंबद्ध इंडोनेशियाई उत्पादक ने पाटन नहीं किया जिसे अप्रेरित पाया गया है और इसकी वजह पी टी इंडो भारत रेयन द्वारा किए गए 3 छोटे पोतलदान नहीं हैं । पी टी साउथ पैसिफिक विस्कोस द्वारा पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु का पर्याप्त मात्रा में निर्यात किया गया है । संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों से भी घरेलू उद्योग को "क्षति" हुई है । यह भी अनुरोध किया जाता है कि ऐसी क्षति में छोटे और छिछरे हुए निर्यात भी एक प्रमुख कारक नहीं रहे हैं । इसके अलावा, मै. ग्रासिम इंड लि. का फोक्स संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिक्री पर जारी है । अतः स्वतः स्फूर्त क्षति का मामला प्रतीत नहीं होता है ।

70. जहां तक क्षति पहुंचाने वाले अन्य कारकों का संबंध है, याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि प्रथमतः हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात का गलत अनुमान लगाया है कि उत्पाद का पाटन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एकमात्र कारण होना चाहिए । यद्यपि, उत्पादन और बिक्री पर निर्विवाद रूप से मांग में कमी के कारण प्रभाव पड़ा है परंतु संबद्ध वस्तु के पाटन से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है । जहां तक लाभप्रदता का संबंध है, चूंकि घरेलू उद्योग आयात कीमत के आधार पर अपनी कीमतें निर्धारित करता है इसलिए बाजार में कम कीमत पर पाटित आयातों की उपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग ऐसी कीमत की पेशकश करने के लिए बाध्य हुआ जिससे उसे निविष्टि की लागत में वृद्धि करने की अनुमति नहीं मिली ।

च. 6 माह की अल्पावधिक के भीतर बाजार हिस्से में केवल 6% की गिरावट आई जिसमें अधिकांश अवधि में प्रचलित सूक्ष्म आर्थिक समस्याएं क्षति का आधार नहीं हो सकती ।

71. हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग को हुई क्षति के तर्क का खंडन करने के लिए आर्थिक संकट का सहारा ले रहे हैं परंतु वे इस तथ्य को समझने में असमर्थ हैं कि निर्यातकों पर भी उसी अवधि के दौरान प्रभाव पड़ना चाहिए था । परंतु वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई और संबद्ध देशों के हिस्से में वृद्धि हुई । इसके अलावा, जांच अवधि के दौरान जब उत्पाद की मांग में गिरावट आई तो निर्यातक घरेलू बाजार पर कब्जा करते हुए उच्च दर पर भारत में वस्तु का निर्यात करने में सफल हुए ।

छ. उत्पादन एवं क्षमता उपयोग में गिरावट का विश्लेषण करते समय कंपनी द्वारा स्थापित की जा रही नई क्षमताओं, मांग में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गिरावट जैसे कारकों पर विचार नहीं किया गया है ।

72. याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि यदि घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच समान क्षमता स्तर पर जो ऐसे विस्तार से पूर्व मौजूद था, की जाएगी और यह देखा जाएगा कि समान क्षमता स्तर पर भी क्षमता उपयोग वर्ष 2007-08 में 104.27% से घटकर जांच अवधि में 85.8% हो जाएगा । अतः इस बात की स्पष्ट पुष्टि होती है कि क्षमता उपयोग में गिरावट क्षमता में वृद्धि के कारण नहीं आई है अपितु संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण आई है ।

ज. इंडोनेशिया से कीमत में कोई कटौत नहीं हुई है और चीन से कीमत कटौती नगण्य है ।

73. जैसा कि पूर्व में अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर आवधिक रूप से अपनी कीमतें तय करता है । यह निर्विवाद तथ्य है कि घरेलू उद्योग की कीमतें आयात कीमतों पर आधारित होती हैं । वस्तुतः इस तथ्य से स्वतः यह द्वि हो जाता है कि बिक्री कीमत में वृद्धि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं हुई थी । इसके अलावा, कीमत कटौती के निर्धारण का प्रयोजन इस बात का आकलन करना होता है कि क्या ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है । यदि आयात कीमत में गिरावट आती है तो घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत घटाने के लिए बाध्य होगा । यदि आयात कीमत बढ़ती है परंतु वह उत्पादन लागत में वृद्धि के बराबर नहीं पहुंचती है तो घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमत में वृद्धि करने से वंचित हो सकता है । पाटनरेधी नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या आयातों के कारण घरेलू कीमत में कटौती हो रही है । अथवा क्या आयातों के प्रभाव से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में अन्यथा ह्रास या न्यूनीकरण हुआ है । इस प्रकार नियमों में कीमत कटौती, कीमत ह्रास या कीमत न्यूनीकरण की पुष्टि करने का स्पष्ट प्रावधान है । बहरहाल सकारात्मक कटौती के अभाव का तात्पर्य क्षति न होने से नहीं है ।

74. घरेलू उद्योग ने पी वी सी सस्पेंशन रेंजिन मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों का भी हवाला दिया है जिनमें संबद्ध देशों से संचयी रूप से कीमत कटौती नकारात्मक थी । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निम्नानुसार माना था :-

286. यह भी देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत लगभग उसी स्तर पर है जिस स्तर पर संबद्ध देशों से आयातों के भारित औसत पहुंच मूल्य है । अतः समग्र स्तर पर कीमत कटौती मामूली तौर पर नकारात्मक है । यद्यपि, कुछ देशों में पर्याप्त सकारात्मक कीमत कटौती हुई है तथापि, घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक ह्रास हुआ है क्योंकि घरेलू

उद्योग ने स्पष्टतः अपना बाजार हिस्सा बचाने के लिए कीमतें कम रखी हैं और इसलिए कीमत कटौती से कीमत प्रभाव की सही स्थिति का पता नहीं चलेगा ।

75. पॉलीप्रोपीलीन के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निम्नानुसार माना था -

181. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों का पहुंच मूल्य 100 (आधार वर्ष 2005-06) से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 131 हो गया था । घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भी इसी प्रकार बढ़ोत्तरी का रुख देखा गया । संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमतों से सदैव अधिक रहे, अतः आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कीमत कटौती नहीं हुई । संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान कीमत में प्रतिकूल कटौती देखी गई है । इस संदर्भ में घरेलू उद्योग ने यह कहा है कि भारत औसत बिक्री मूल्य के साथ भारत औसत पहुंच मूल्य की तुलना से इस दृष्टि से सही स्थिति सामने नहीं आती कि भारत में इस कीमत पर आने वाले माल के आधार पर घरेलू कीमतें लगाई गई हैं । इसके अतिरिक्त, संबंधित देशों से निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा बुक किए गए आदेशों तथा इन सामानों के भारत में पहुंचने के समय में अंतर है । यह मानते हुए कि जांच अवधि के दौरान संबंधित सामानों की कीमतों में पर्याप्त उतार चढ़ाव आया है, भारत औसत आधार पर कोई तुलना करने से भ्रामक स्थिति सामने आने की संभावना है । घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने बिक्री कीमतों में वृद्धि लागतों में वृद्धि के अनुसार नहीं हो सकती । तथापि, बिक्री कीमतों में तदनुरूपी वृद्धि की तुलना में लागतों में वृद्धि की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को कीमत संबंधी दबाव झेलना पड़ा है ।

झ. बिक्री में निम्नलिखित कारण से गिरावट आई है अर्थात् उपभोक्ता वैश्विक मंदी के कारण खरीद नहीं कर रहा है, वैश्विक मांग के कारण वस्त्र निर्यातों में तेजी से गिरावट आई है, संतुलित घरेलू मांग, स्फीतिकारी दबाव के साथ वैश्विक मंदी, मूल श्रृंखला में मालसूचियों का परिसमापन

76. यह नोट करना अत्यंत रोचक है कि हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट हेतु कारण रेखांकित किए हैं परंतु उन्होंने इस तथ्य की अनदेखी की है कि इन कारणों से आयात में भी गिरावट आनी चाहिए थी परंतु आयातों में और अधिक वृद्धि हुई है । अनुरोध है कि ऐसी स्थिति में जहां (क) उपभोक्ता घरेलू स्रोत से खरीद सीमित कर रहे हैं परंतु आयातों के जरिए खरीद बढ़ा रहे हैं, और (ख) आयात कीमत के कारण घरेलू कीमत में गिरावट से इस बात की पुष्टि होती है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है ।

ज. घरेलू उद्योग द्वारा रिबेटों के रूप में माने गए निर्यातों पर अपनी आपूर्तियों के लिए प्रोत्साहन की पेशकश कर रहा है । माने गए निर्यातों पर आपूर्तियों के लिए प्रभारित कीमतें घरेलू बिक्री के लिए प्रभारित कीमत से काफी कम हैं ।

77. घरेलू उद्योग एक सुनिर्धारित कीमत नीति अपनाता है । घरेलू उद्योग "कीमत सूची" के अनुसार, उत्पाद की घोषणा और बिक्री करता है । प्रत्येक बिक्री सौदे के लिए कीमत का मोलभाव नहीं किया जाता है । घरेलू उद्योग व्यापार पूछताछों का उत्तर देने, भाव दरें देने, कीमत तय करने, खरीद और ऑर्डर पूरा करने की प्रणाली नहीं अपनाता है । घरेलू उद्योग "कीमत सूची"

घोषित करता है और उसके बाद घोषित कीमत सूची के आधार पर सामग्री की बिक्री करता है । आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर कंपनी द्वारा की गई समस्त बिक्री कीमत सूची के अनुसार की जाती है जिसमें कीमतों में संशोधन करने के लिए विपणन कार्यकारियों के प्रचालन स्तर तक छिटपुट या कोई विवेकाधिकार नहीं होता है ।

78. घरेलू उद्योग की कीमत सूची का उपयोग आयातित उत्पाद की कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की कीमत के साथ करने के लिए किया जाना चाहिए । ऐसी स्थिति में जहां कंपनी अलग-अलग कीमतों पर अलग-अलग ग्राहकों को सामग्री की बिक्री करती है, हर बार कीमतें तय करती है जो एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक के लिए अलग-अलग होते हैं, वहां संगत अवधि के दौरान बेची गई मात्राओं के लिए भारित औसत बिक्री कीमत निर्धारित करना संगत और उचित होना चाहिए । तथापि, ऐसी स्थिति में, जहां कंपनी पूर्व निर्धारित, घोषित सार्वजनिक कीमत सूचियों पर अपने उत्पाद की बिक्री करती है और जहां ऐसी कीमत सूचियों की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार करने के बाद की जाती है, वहां आयातित और घरेलू उत्पाद के बीच उचित तुलना ऐसी कीमत सूचियों के आधार पर की जानी चाहिए । घरेलू उद्योग ने यह दोहराया है कि बिक्री कीमतें ग्राहकों के अनुसार अलग-अलग नहीं होती हैं और इसलिए किसी खास अवधि में बेची गई मात्राओं की भारित औसत बिक्री कीमत निर्धारित करने की कोई जरूरत नहीं है ।

79. कीमत एक वैज्ञानिक और पारदर्शी ढंग से निर्धारित की जाती है । कीमत निर्धारित करने का आधार प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमत होता होता है । प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए जिसमें अलग-अलग देशों में विद्यमान अंतरों (अर्थात् विनियम दर, सीमाशुल्क आदि) को ध्यान में रखा जाना चाहिए, कंपनी अपनी मूल कीमत तय करती है ।

ट. क्षति विश्लेषण हेतु घरेलू उद्योग द्वारा ज्ञात निर्यात बिक्री को शामिल करना पाटनरोधी नियमावली एवं विनियमों के असंगत है ।

80. अनुरोध है कि कंपनी ने बिक्री की कुल श्रेणियों को "माने गए निर्यात" कहा है । उन्हें विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के साथ इस बात पर कोई असहमति नहीं है कि माने गए निर्यात घरेलू बिक्री का भाग नहीं होने चाहिए । तथापि, मात्र इस वजह से कि कंपनी ने कुछ बिक्रियों को माने गए निर्यात कहा है, इसलिए ये माने गए निर्यात बन जाएंगे ।

81. माने गए निर्यातों को विदेश व्यापार नीति में परिभाषित किया गया है । माने गए निर्यात बिक्री के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :-

"प्रमुख/उप ठेकेदारों द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति की निम्नलिखित श्रेणियों में एफटी पी के अंतर्गत "माने गए निर्यात" माना जाता है बशर्ते वस्तु का विनिर्माण भारत में किया गया हो :-

- (क) अग्रिम प्राधिकार/वार्षिक जरूरत/डी एफ आई ए के लिए अग्रिम प्राधिकार पर वस्तु की आपूर्ति;
- (ख) ई ओ यू या एस टी पी या ई एच टी पी या बी टी पी को वस्तुओं की आपूर्ति;
- (ग) ई पी सी जी स्कीम के अंतर्गत प्राधिकार धारकों को पूंजीगत वस्तु की आपूर्ति
- (घ) बहुराष्ट्रीय या द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित/आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अधिसूचित निधियों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आई सी बी) के अंतर्गत एम ओ एफ द्वारा उन एजेंसियों/निधियों की प्रक्रियाओं के अनुसार वित्तपोषित परियोजनाओं को वस्तुओं की आपूर्ति जहां सीमाशुल्क को शामिल किए बिना निविदा मूल्यांकन हेतु विधि करार होते हैं;
- (ङ) बहुराष्ट्रीय या द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित/आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अधिसूचित निधियों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आई सी बी) के अंतर्गत एम ओ एफ द्वारा उन एजेंसियों/निधियों की प्रक्रियाओं के अनुसार वित्तपोषित परियोजनाओं को वस्तुओं तथा उपकरणों की आपूर्ति एवं उनकी स्थापना (आद्योपांत संविदाओं की एकल जिम्मेवारी) जिनमें विदेश में निर्मित वस्तुओं के लिए डिलीवर्ड ड्यूटी पेड (डी डी पी) कीमतों के 38 आधार पर बोलियां आमंत्रित की गई हों और उनका मूल्यांकन किया गया हो ।"
- (च) असंयोजित/विसंयोजित स्थिति सहित पूंजीगत वस्तुओं तथा संयंत्रों, मशीनों, सहायक सामग्री, औजारों, डाइयों और ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति जिनका उपयोग वाणिज्यिक उत्पादन के चरण तक स्थापना के प्रयोजन हेतु किया जाता है और उर्वरक संयंत्रों को एफ ओ आर मूल्य के 10% तक कलपुर्जों की आपूर्ति ।
- (छ) किसी परियोजना या प्रयोजन को वस्तुओं की आपूर्ति जिनके संबंध में वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना द्वारा शून्य सीमाशुल्क पर ऐसी वस्तुओं के आयात की अनुमति दी हो ।
- (ज) विद्युत परियोजनाओं और शोधनशालाओं को वस्तुओं की आपूर्ति जो उपर्युक्त (च) में शामिल नहीं हैं ।
- (झ) 100% ई ओ यू (डोमेस्टिक फ्रेट कंटेनर विनिर्माता) द्वारा समुद्री फ्रेट कंटेनरों की आपूर्ति बशर्ते भारत से बाहर उक्त कंटेनरों को 6 माह के भीतर या सीमाशुल्क द्वारा अनुमत ऐसी अन्य अवधि के भीतर निर्यात कर दिया गया है ।
- (ञ) यू एन एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को आपूर्ति; और
- (ट) आई सी बी के विपरीत प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं को वस्तुओं की आपूर्ति ।"

82. चूंकि भारत सरकार माने गए निर्यात बिक्रियों को निर्यात बिक्री मानती है और चूंकि क्षति निर्धारण घरेलू बिक्री के लिए किया जाना चाहिए इसलिए विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने यह सही दावा किया है कि माने गए निर्यात बिक्री को घरेलू बिक्री में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

83. घरेलू उद्योग द्वारा की गई घरेलू बिक्री माने गए निर्यात बिक्री के रूप में पात्र नहीं है । यद्यपि, वह बाजार में माने गए निर्यातों की शब्दावली का प्रयोग कर रहा है । वस्तुतः उपभोक्ता उसके द्वारा किए गए निर्यातों पर निर्यात दावों का दावा करता है और घरेलू उद्योग "माने गए निर्यात" नाम का प्रयोग केवल इस वजह से करता है कि फाइबर की खपत एक ऐसे उत्पाद में की गई है जिसका निर्यात किया गया है तथापि, समस्त निर्यात लाभ उपभोक्ता द्वारा लिए गए हैं न कि घरेलू उद्योग द्वारा । यदि ये माने गए निर्यात बिक्री होते तो घरेलू उद्योग भी विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत प्रदत्त विभिन्न लाभों का पात्र होता ।

84. अतः यह अनुरोध है कि ये बिक्रियां माने गए निर्यात बिक्रियां नहीं हैं जैसा कि विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने समझा है बल्कि ये केवल घरेलू बिक्रियां हैं । अतः इन बिक्रियों को "घरेलू बिक्री" शीर्ष के अंतर्गत सही ढंग से शामिल किया गया है ।

ठ. आवेदक द्वारा अपने संबद्ध पक्षकारों को की गई आपूर्तियों के बारे में सूचना का अगोपनीय रूपांतरण प्रदान किया जाए ।

85. याचिकाकर्ता ने अपने संबद्ध पक्षकारों को कोई आपूर्ति नहीं की है ।

ठ. निष्कर्ष:

86. विरोधी पक्षकार द्वारा दिए गए तर्क किसी तथ्यात्मक और विधिक आधार के बिना कोरे अनुमान हों । इसके अलावा, दावों की पुष्टि नहीं की गई है और यह वर्तमान जांच के तथ्यों की उचित जानकारी के बिना किए गए हैं ।

87. प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन उत्पाद के बारे में की गई वर्तमान जांच पर विचार करते हुए यह स्पष्ट होता है कि -

क. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वर्तमान जांच सही तरीके से शुरू की है ।

ख. याचिकाकर्ता कंपनी घरेलू उद्योग है भले ही उसका एक इंडोनेशियाई उत्पादक से संबंध है । इंडोनेशियाई उत्पादक ने भारत को काफी कम मात्रा में निर्यात किया है और वह भी अग्रिम लाइसेंस पर ।

ग. यद्यपि, याचिकाकर्ता ने जांच की शुरुआत में संबंध को स्वीकार किया था, तथापि, याचिकाकर्ता का अब निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि कृपया इसकी जांच की जाए क्योंकि सर्कुलर वीविंग मशीन के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह सिद्धांत निर्धारित किया गया है कि क्या सभी याचिकाकर्ताओं को पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर इंडोनेशियाई उत्पादक से संबद्ध कंपनी माना जाना चाहिए ।

घ. संबद्ध देशों से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात उसकी संबंधित सामान्य कीमत से कम पर किया गया है ।

ङ घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद के संबंध में वास्तविक क्षति हुई है ।

च. यह वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है ।

छ. भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना अपेक्षित है ।

पी टी साउथ पैसिफिक विस्कोस, इंडोनेशिया; इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन्स और राजस्थान टैक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन की ओर से दायर उत्तर संबंधी अनुरोध

प्रारंभिक आपत्तियां

88. कृपया स्मरण करें कि हमारे मूल अनुरोधों में भी हमने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष दायर आंकड़े, सूचना और साक्ष्य की मांग की थी । वर्तमान मौखिक सुनवाई का अवसर आने से पूर्व इन्हें हमें उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए था । वर्तमान नियमों में पूर्ण सूचना, आंकड़े और साक्ष्य उपलब्ध कराना अनिवार्य है । ऐसे किसी मामले में ऐसी कोई नीति प्राकृतिक न्याय एवं उचित अवसर के सिद्धांत के प्रतिकूल है और हमें भागीदार हितबद्ध पक्षकार के रूप में मामले के सभी पहलुओं पर उचित टिप्पणियां देने से वंचित किया गया है । इस सीमा तक उक्त पक्षकारों के हित के साथ गंभीर भेदभाव हुआ है जिसकी ओर से वर्तमान उत्तर दायर किया जा रहा है ।

89. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए पुनरावृत्ति के जोखिम पर हम यह उल्लेख करने के लिए बाध्य हैं कि हम पूर्ण और सार्थक उत्तर संबंधी अनुरोध दायर करने में पूर्णतः असमर्थ हैं । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई कड़ी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम आवेदक उद्योग के लिखित अनुरोधों के आधार पर सीमित उत्तर संबंधी अनुरोध दायर करने के लिए बाध्य हैं । प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की यह मांग है कि प्रदत्त अवसर प्रभावी होना चाहिए और इस प्रकार हमारा अनुरोध है कि सूचना/दस्तावेज/आंकड़े उपलब्ध कराए जाने चाहिए और तभी हम से उन पर पूर्ण टिप्पणियां दायर करने के लिए कहा जाए ।

90 लिखित अनुरोध व्यापार सूचना के प्रतिकूल हैं:- हम यह अनुरोध करना चाहेंगे कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर लिखित अनुरोधों में व्यापार सूचना 1/2007, दिनांक 22.10.2007 में निहित

विशिष्ट निर्देशों के प्रतिकूल प्रत्येक पैराग्राफ को उचित पैराग्राफ नं. नहीं दिए गए हैं । आप इस बात से सहमत होंगे कि लगातार क्रम संख्यांकित पैराग्राफों के अभाव में किसी हितबद्ध पक्षकार के लिए उक्त व्यापार सूचना के पैरा 3(i) के अनुसार अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करना नितांत असंभव है । हमारा अनुरोध है कि आपकी जानकारी में हम यह मुद्दा इस वजह से ला रहे हैं क्योंकि व्यापार सूचना की अपेक्षाओं का अधिकार और व्यवहार के रूप में उल्लंघन किया जा रहा है । हमने विगत में भी पैरावार उत्तर दायर करने के लिए अन्य पक्षकारों को हो रही कठिनाइयों का उल्लेख किया है परंतु यह परंपरा अभी भी जारी है । ऐसी प्रक्रिया का पालन न करने पर हमें बताया गया है कि अनुरोधों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा अनुरोध है कि इन अनुरोधों को रिकॉर्ड में न लिया जाए ।

91. कृपया यह नोट किया जाए कि इंडोनेशिया के एक अन्य निर्यातक अर्थात् पी टी इंडो भारत रेयन की ओर से कोई लिखित अनुरोध नहीं किया गया है । यद्यपि, उक्त निर्यातक के लिए रिकॉर्ड में प्रतिनिधि आवेदक का प्रतिनिधि ही प्रतीत होता है ।

92. पैराग्राफ वार (संभव सीमा तक) उत्तर संबंधी अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

93. आवेदक के लिखित अनुरोधों के संख्या रहित पैरा 1 की विषय वस्तु पर कोई उत्तर जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें किसी अनुरोध के बिना कुछेक तथ्यों को दोहराया गया है ।

94. आवेदक के लिखित अनुरोधों संख्या रहित पैरा 2 की विषय वस्तु में यह कहा गया है कि उन्होंने निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष पूर्व में दायर पूर्ववर्ती अनुरोधों में निहित सभी तथ्य, तर्क, अभिकथन और विवरण दोहराए हैं और उन्होंने निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि उन्हें लिखित अनुरोधों के भाग के रूप में तदनुसार माना जाए । आवेदक से उन तारीखों के साथ जिनको ये दायर किए गए थे, ऐसे अनुरोधों की तारीख के संदर्भ में ऐसे अनुरोधों की सूची मांगी जाए । यदि ऐसे दस्तावेजों का अगोपनीय रूपांतरण गोपनीय रूपांतरण के साथ दायर नहीं किया गया था तो उस पर विचार न किया जाए क्योंकि ये नियम 7 की अपेक्षाओं के प्रतिकूल हैं । हम अपना यह अनुरोध दोहराते हैं कि सार्वजनिक फाइल की सूची प्रदान की जाए ताकि हम इस बात की प्रति जांच कर सकें कि क्या ये रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं । बहरहाल हमारा अनुरोध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी आंकड़ों/सूचना या साक्ष्य के साथ आवेदक द्वारा किए गए सभी अनुरोधों की प्रति उपलब्ध कराएं । विगत में किए गए बार-बार अनुरोधों के बावजूद भी हमें आवश्यक दस्तावेजों से इंकार किया गया है जिनका प्रयोग अंतिम जांच परिणाम निकालने में किया जा रहा है ।

95. आवेदक के लिखित अनुरोधों के पैरा 1 की विषय वस्तु पर कोई उत्तर जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें किसी अनुरोध के बिना कुछेक तथ्यों को दोहराया गया है ।

96. आवेदक के लिखित अनुरोधों के पैरा 2 की विषय वस्तु पर कोई उत्तर जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें किसी अनुरोध के बिना कुछेक तथ्यों को दोहराया गया है ।

97. लिखित अनुरोधों के पैरा 3 की विषय वस्तु को तब तक रिकॉर्ड में नहीं लिया जा सकता जब तक कि प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत समस्त सूचना का अगोपनीय रूपांतरण सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान न कर दिया जाए । सभी हितबद्ध पक्षकारों को पूर्ण अगोपनीय रूपांतरण प्रदान किए बिना इन पर विचार किया जाना नियम 7 की अपेक्षा के प्रतिकूल होगा । पत्रों की तारीखों का हवाला दिए बिना जिनको ये अनुरोध दायर किए गए थे, अनुरोध दोहराए नहीं जा सकते ।

98. आवेदक के लिखित अनुरोधों के पैरा 4 की विषय वस्तु पर कोई उत्तर जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें किसी अनुरोध के बिना कुछेक तथ्यों को दोहराया गया है ।

99. पैरा 5 की विषय वस्तु गलत है और इससे इंकार किया जाता है । ग्रासिक इंड लि. नियम 5(3) के अनुसार आधार की अपेक्षा को पूरा नहीं करता है और न ही वह नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग बनने की पात्रता रखता है ।

100. पैरा 5(क) की विषय वस्तु पर कोई उत्तर अपेक्षित नहीं है क्योंकि यह किसी अनुरोध के बिना नियम 5(3) की पुनरावृत्ति है ।

101. पैरा 5(ख) से (ट) की विषय वस्तु गलत है और इससे इंकार किया जाता है । सिवाय इस बात के कि इसमें कानून को पुनः उद्धृत किया गया है । इस बारे में विस्तृत अनुरोध किए जा चुके हैं कि देश में एकमात्र उत्पादक को किस प्रकार नियम 2(ख) के अनुसार, पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है क्योंकि वर्तमान मामले में यह एक स्वीकृत तथ्य है कि ग्रासिक इंड लि. चीन और इंडोनेशिया के निर्यातकों से संबंधित है और इसीलिए यह अपवर्जित श्रेणी में आता है । चूंकि उत्पादक एक ही है इसलिए उसके पास नियम 5(3) के अनुसार आधार रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है । बहरहाल सेंटगोबेन ग्लास इंडिया लि. बनाम भारत संघ मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय से इस मुद्दे का अब समाधान हो गया है कि जिसमें यह निर्णय दिया गया है कि संशोधित नियम 2(ख) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास "घरेलू उद्योग" की परिभाषा में अपवर्जित श्रेणी पर विचार करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है । अनुरोध है कि उक्त निर्णय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कदाचित ही लागू किया गया है और यह निर्दिष्ट प्राधिकारी पर बाध्यकारी है ।

102. घरेलू उद्योग ने आगे यह अनुरोध किया है कि उक्त नियम 2(ख) में परिवर्तन किया गया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए सर्वप्रथम यह तय करना अपेक्षित है कि ऐसी परिस्थितियों में कौन सा नियम लागू होगा । इस संदर्भ में अनुरोध है कि घरेलू उद्योग ने इस बारे में कोई अनुरोध नहीं किया है । किसी पूर्वाग्रह के बिना अनुरोध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उन नियमों से अपनी शक्ति ग्रहण करता है जो उस समय प्रचलित थे जब ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया गया था । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसे पुराने नियम के अंतर्गत कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है जो कानून की दृष्टि में मौजूद नहीं है तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि यह मुद्दा "घरेलू उद्योग" के क्षेत्र और परिभाषा से अधिक संबंध रखता है जिसका निर्धारण उस समय करना होता है जब अंतिम

जांच परिणाम दिए जाते हैं । जांच की शुरुआत के समय "घरेलू उद्योग" का कोई महत्व नहीं होता है क्योंकि इससे जांच की समूची प्रक्रिया निरर्थक बन जाएगी ।

103. पैरा 5(1) की विषय वस्तु गलत है और इससे इंकार किया जाता है कि सार्वजनिक सुनवाई के दौरान हमने यह उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता ने प्रश्नों के निर्धारित सैटों से महत्वपूर्ण प्रश्न जानबूझ कर हटा दिया है ताकि इंडोनेशिया के साथ संबंध की प्रगति का बचाव किया जा सके । हितबद्ध पक्षकारों को प्रदत्त आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण में अथवा प्राधिकारी द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के दस्तावेजों में याचिकाकर्ता के दावे के समर्थन में आज की तारीख तक ऐसी कोई सूचना, दस्तावेज या साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं । निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे कृपया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से गौर करें और इसका समुचित समाधान निकालें ।

104. पैरा 5 (ड और ढ) की विषय वस्तु गलत है और इससे इंकार किया जाता है । अनुरोध है कि याचिकाकर्ता ने निर्णयों के केवल कुछ उद्धरण उपलब्ध कराए हैं और इनमें से अधिकांश उद्धरण इस मामले के लिए प्रासंगिक नहीं हैं और इनमें से कुछ के द्वारा याचिकाकर्ता के दावे का विरोध होता है क्योंकि प्राधिकारी ने ऐसी कंपनी को सामुदायिक उद्योग के क्षेत्र से बाहर रखने के अपने निर्णय की पुष्टि की है । हम यह समझने में असमर्थ हैं कि ऐसे मामलों से आवेदकों का मामला किस ढंग से आगे बढ़ता है । इसके अलावा, अनुरोध है कि ऐसे जांच परिणाम के अंशों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता । आवेदकों के लिए ऐसे निर्णयों पर भरोसा करते समय इनकी सभी प्रतियां उपलब्ध कराना अनिवार्य है । संपूर्ण निर्णय और संपूर्ण तथ्यों को समझे बिना हम संपूर्ण और सार्थक टिप्पणियां देने में असमर्थ हैं । उपर्युक्त के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोधों में इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि उनके द्वारा प्रस्तुत अभिकथन ऐसी स्थिति से संबंधित नहीं है जिसमें आवेदक निर्यातकों से संबंधित है अपितु केवल उस स्थिति से संबंधित हैं जहां आवेदक संबद्ध वस्तु का आयातक है । हम इस बात से इंकार करते हैं कि आयातकों के मामले से संबंधित उक्त निर्णय ऐसी स्थिति पर स्वयं लागू होते हैं जहां आवेदक और विदेशी निर्यातक के बीच संबंध का मुद्दा होता है । आवेदक द्वारा उल्लिखित पाठ्यपुस्तकों में भी दोनों स्थितियां अलग-अलग हैं । इसके अलावा घरेलू उद्योग ने ऐसा एक भी निर्णय नहीं बताया है जिसमें नियम 2(ख) के अंतर्गत अपवर्जित श्रेणी के बारे में विवेकाधिकार की मौजूदगी के मुद्दे पर सवाल उठाया गया हो । इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उल्लेखित दृष्टांत उनके खुद के कानून और न्यायशास्त्र के संदर्भ में कुछेक क्षेत्राधिकार में प्रचलित कुछेक पद्धतियों के संकेत के सिवाय कुछ नहीं है । बहरहाल उपर्युक्त निर्णय में मद्रास उच्च न्यायालय ने भी यह निर्णय दिया है कि "भारतीय नियम को दूसरे देशों की परिभाषा की सहायता से या ऐसे उपबंधों जिनकी भाषा हमारे उपबंध के समान नहीं है, पर आधारित निर्णय की सहायता से नहीं समझा जा सकता या उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती ।"

105. पैरा 5(ण) और उप पैरा (I से iv) की विषय वस्तु गलत है और इससे इंकार किया जाता है । यह दोहराया जाता है कि माननीय प्राधिकारी से संबंध छिपाने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रपत्र को जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया है । यह भी स्मरणीय है कि सार्वजनिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के प्रतिनिधियों ने पहली बार संबंध के स्वरूप को उपलब्ध कराकर वैकल्पिक सिद्धांत का सुझाव दिया । जहां तक संबंध के स्वरूप के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी के दंडित प्रश्न के उत्तर में आवेदक की जानबूझ कर गलत बयानी का संबंध है, आवेदक ने लिखित अनुरोधों में पूर्णतः असंतोषजनक उत्तर दिया है । यह उल्लेख किया गया है कि "संबंध को स्थापित करने वाली सूचना उन्हीं स्थितियों में संगत होती है जहां कोई पक्षकार ऐसे संबंध की मौजूदगी का खंडन करता है" । आवेदक का ऐसा कोई उत्तर न केवल गलत है अपितु पूर्णतः आनुमानिक है । यह आवेदक द्वारा नितान्त गलत घोषणा करने के तरीके से ध्यान हटाने का स्पष्ट प्रयास है । संगत प्रश्न के सामान्य पाठन से यह पता चलता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी संबंध की उस प्रकृति की मांग कर रहे हैं जिसका उत्तर देना जरूरी है यदि संबंध की मौजूदगी स्वीकार की जाती है । अब यह एकदम स्पष्ट हो गया है कि घरेलू उद्योग ने स्वयं प्रश्नावली में परिवर्तन कर इस महत्वपूर्ण सूचना को जानबूझ कर छिपाया है क्योंकि जांच के उस चरण पर पूर्ण और निष्पक्ष सूचना से जांच की शुरुआत ही नहीं हो सकती थी । यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक ने इस चरण पर भी सामान्य निदेशकों के मुद्दे के बारे में गोपनीयता का दावा किया है । इस बारे में गोपनीयता का दावा करने का कोई कारण नहीं बताया गया है । हम यह दोहराते हैं कि "संबंध" की सच्चाई स्वीकार करने के बाद भी संबंध की पूर्ण प्रकृति प्रासंगिक बन जाती है । ऐसा इस वजह से है कि ऐसी सूचना के अभाव में प्राधिकारी नियम 2(ख) के अंतर्गत शामिल करने या बाहर रखने के लिए अपनाए जाने वाले विशिष्ट मानदंड का निर्णय करने की स्थिति में नहीं होंगे । इन परिस्थितियों में यह सच है कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र में परिवर्तन किया गया है जिसकी माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनदेखी नहीं की जा सकती क्योंकि यह न्यायशास्त्र के सिद्धांत के सर्वथा खिलाफ है । पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा भरे जाने की आशा की जाती है के संगत पृष्ठों की प्रति अनुबंध-1 में संलग्न है ।

106. पैरा 6 की विषय वस्तु पर कोई उत्तर अपेक्षित नहीं है क्योंकि यह पूर्ववर्ती अनुरोधों में प्रदत्त सूचना की मात्र पुनरावृत्ति है ।

107. पैरा 7 के उत्तर में यह अनुरोध किया जाता है कि आज भी याचिकाकर्ता निदेशकों के नामों और संबंधित कंपनियों के साथ संबंध को गोपनीय रखे हुए है । कृपया इस बात को समझें कि हम तब तक इस मुद्दे पर टिप्पणी देने में समर्थ नहीं हैं जब तक हमें पूर्ण और सार्थक सूचना प्रदान नहीं की जाती है । वांछित सूचना मिल जाने पर हम विस्तृत टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ।

108. पैरा 8 की विषय वस्तु गलत है और इससे इंकार किया जाता है । अनुरोध है कि डी जी ए डी ने विशिष्ट सूचना (इस मामले में संबंध के स्वरूप के बारे में) मांगने के लिए विशिष्ट प्रपत्र निर्धारित किए हैं ।
109. पैरा 9 की विषय वस्तु गलत है और पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित कारणों से इससे इंकार किया जाता है ।
110. पैरा 10 की विषय वस्तु गलत है और पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित कारणों से इससे इंकार किया जाता है ।
111. पैरा 10 (क-घ) की विषय वस्तु पर कोई उत्तर अपेक्षित नहीं है क्योंकि यह पूर्ववर्ती अनुरोधों में प्रदत्त सूचना की मात्र पुनरावृत्ति है जिन पर उचित कार्रवाई की गई है ।
112. पैरा 10 (ड-घ) की विषय वस्तु गलत है और पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित कारणों से इससे इंकार किया जाता है ।
113. जहां तक नियम 2(ख) में 1 दिसंबर, 2011 को किए गए संशोधन का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि इस संशोधन द्वारा एकमात्र "केवल" शब्द हटाया गया है अनुरोध है कि इस परिवर्तन का कोई महत्व नहीं है क्योंकि "केवल" शब्द हटाए जाने से निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध विवेकाधिकार के क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है ।
114. किसी पूर्वाग्रह कि बिना हम यह उल्लेख करना चाहते हैं कि शेष देशों द्वारा अपनाई जा रही पद्धति डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार तैयार होने से पूर्व की उनकी संविधि में निर्धारित पद्धति और/अथवा प्रयुक्त विशिष्ट भाषा से उत्पन्न होती है । उदाहरणार्थ अमरीकी कानून द्वारा प्रयुक्त भाषा में प्राधिकारी में विशिष्ट रूप से विशेषाधिकार निहित है । कनाडा में आवेदन के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की परिभाषा अलग है और क्षति एवं कारणात्मक संबंध के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विश्लेषण के प्रयोजनार्थ परिभाषा अलग है । ई यू उन पद्धतियों को अपना रहा है जो डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार से पूर्व प्रचलित थीं । मात्र इसलिए कि इन पद्धतियों को चुनौती नहीं दी गई है, यह नहीं माना जा सकता कि ये ऐसी पद्धतियां बेहतर कानून हैं और डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार के अंतर्गत दायित्वों के अनुरूप हैं । बहरहाल भरोसेमंद कोई भी जांच परिणाम या निर्णय वर्तमान कार्यवाही में हमारे द्वारा दिए गए उस तर्क का समाधान नहीं करता है कि वर्तमान संशोधित नियम 2(ख) और अनुच्छेद 4 में "सकता है" शब्द शेष उत्पादकों के संदर्भ में है न कि अपात्र उत्पादकों के संदर्भ में । स्पष्टतः इनमें भेद किया जा सकता है और यह अनुच्छेद 4 की साधारण भाषा और यहां तक कि उनके संबंधित विधानों को ध्यान में रखते हुए बेहतर नहीं है ।
115. उप पैरा 10 च (क और ख) की विषय वस्तु गलत है और इससे इंकार किया जाता है । यह दोहराया जाता है कि विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई पद्धतियों का उस स्थिति में कोई बाध्यकारी नजीरगत महत्व नहीं होता है जब निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने कानून द्वारा बंधे होते हैं । इस मुद्दे का समुचित समाधान माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्याय उद्घोषणा के संग्रह में किया है

कि भारत में न्यायालय और प्राधिकरण स्वदेशी कानून से बंधे हुए हैं। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय (2011 की डब्ल्यू पी सं. 23515 इस मामले में प्रासंगिक है)। इसके अलावा, ऐसे सभी देशों या क्षेत्रों द्वारा प्रयुक्त भाषा भारतीय कानून के समनुरूप नहीं है। बहरहाल न्यायाधिकरण ने भी यह माना है कि विवाद निपटान निकाय के निर्णय अर्थात् पैनल रिपोर्टें या अपीलीय निकाय की रिपोर्टें कोई बाध्यकारी महत्व नहीं रखती हैं। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि किसी देश द्वारा अपनाई गई पद्धति भारतीय कानून की साधारण भाषा लागू करते समय कोई महत्व रखेगी। उक्त धारा की विषय वस्तु की व्याख्या गलत है और इससे इंकार किया जाता है। पूर्ववर्ती अनुरोधों और रिमांड पश्चात् अनुरोधों में हमने नियम 2(ख) पर विस्तार से चर्चा की है। संक्षिप्तता की वजह से इन्हें दोहराया नहीं जा रहा है। उक्त अनुरोधों को आवेदकों के अनुरोधों के उत्तर में समाविष्ट किया गया माना जाए।

116. अनुरोध है कि आवेदक द्वारा उल्लिखित ई सी और भारतीय निर्णय कोई महत्व नहीं रखते हैं क्योंकि वे वर्तमान मुद्दे से पूर्णतः असंबद्ध हैं। आवेदक द्वारा उल्लिखित सभी मामलों में प्राधिकरण इस स्थिति से सहमत थे जिसमें घरेलू उत्पादक स्वयं संबद्ध वस्तु का आयातक होता है। अनुरोध है कि पाठ्य पुस्तकों से उपलब्ध न्याय सिद्धांत का अत्यंत कम या कोई अनुकरणीय महत्व नहीं है क्योंकि अन्य क्षेत्राधिकारों द्वारा अपनाई गई पद्धति खासकर तब कोई अनुकरणीय महत्व नहीं रखती है जब भारतीय कानून की भाषा डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार या विदेशी कानूनों की भाषा से नितांत अलग हो।

117. जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, यह अनुरोध किया जाता है कि सोडा ऐश मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि संशोधित नियम 2(ख) के अंतर्गत अपवर्जित श्रेणियों में आने वाले घरेलू उत्पादकों को शामिल करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है।

118. आवेदक द्वारा उल्लिखित जांच परिणामों के विभिन्न उद्धरणों पर टिप्पणियां : आवेदक द्वारा निर्णयों की अस्वीकार्यता के बारे में हमारे मूल अनुरोध के प्रति पूर्वाग्रह के बिना हम निम्नानुसार अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करते हैं।

119. इस जांच परिणाम के क्रम सं. 1 में श्रेणी-1 के अंतर्गत शामिल किए जाने की अपेक्षा की गई है जो संबंधित निर्यातकों से स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा किए आयातों से संबंधित है। श्रेणी-1 के मामले संगत नहीं हैं क्योंकि आवेदकों ने अपनी संबंधित कंपनी से स्वयं संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। तथापि, किसी पूर्वाग्रह के बिना यह उल्लेखनीय है कि जांच परिणाम की क्रम सं. 1 यथापरिभाषित किसी समर्थक के संदर्भ में है न कि याचिकाकर्ता (सामुदायिक उद्योग) के संदर्भ में। अतः यह मामला श्रेणी-1 के भीतर ही नहीं आता है जैसा कि आवेदकों ने इसे बनाया है। इसके अलावा, टोकाईसीकी, घरेलू उत्पादक द्वारा स्वयं आयातों के कारण प्राधिकारी ने ऐसी कंपनी को सामुदायिक उद्योग के दायरे से बाहर रखने के अपने निर्णय की पुष्टि की थी। इसके अलावा,

टोकाईसीकी से संबंधित क्षति के आंकड़ों पर क्षति संबंधी जांच परिणाम हेतु विचार नहीं किया गया है। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि इस मामले से आवेदकों का मामला किस ढंग से आगे बढ़ रहा है।

120. इस जांच परिणाम के क्रम सं. 2 में श्रेणी-I के अंतर्गत शामिल किए जाने की अपेक्षा की गई है जो संबंधित निर्यातकों से स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा किए आयातों से संबंधित है। श्रेणी-I के मामले संगत नहीं हैं क्योंकि आवेदकों ने अपनी संबंधित कंपनी से स्वयं संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, जिस जांच परिणाम पर भरोसा किया गया है वह अंतिम जांच परिणाम है। जिसका कल्पना में भी कोई अनुकरणीय महत्व नहीं हो सकता। हमें इस बात का आश्चर्य है कि आवेदकों ने अंतिम जांच परिणाम पर भरोसा नहीं किया है क्योंकि यह अवधि 1995 की है और जांच परिणाम या तो उसी वर्ष में या अगले वर्ष में निकाले जाने चाहिए थे। उल्लिखित मामले में उत्पादक को अलग न रखने का मुख्य कारण यह था कि उसी उद्योग के लगभग सभी उत्पादक फिटिंग पाइपों का आयात कर रहे हैं जो उनके विनिर्माण की योजनाओं से बाहर हैं और उत्पादकों को पाटित आयातों से सुरक्षा नहीं दी जा सकती।

121. इस जांच परिणाम के क्रम सं. 3 में श्रेणी-I के अंतर्गत शामिल किए जाने की अपेक्षा की गई है जो संबंधित निर्यातकों से स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा किए आयातों से संबंधित है। श्रेणी-I के मामले संगत नहीं हैं क्योंकि आवेदकों ने अपनी संबंधित कंपनी से स्वयं संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि इस जांच परिणाम से आवेदकों के मामले को किस प्रकार समर्थन मिलता है क्योंकि कोई आयात लगाए गए आरोपों के अनुसार किया गया नहीं पाया गया है। स्पष्ट तौर पर इन मामलों का उल्लेख कार्यनीतिक दावा करने और इस बात पर विश्वास करने के लिए प्राधिकारी को भ्रम में डालने के लिए किया गया है कि संबंध के बावजूद उसे शामिल किया गया था।

122. इस जांच परिणाम के क्रम सं. 4 में श्रेणी-I के अंतर्गत शामिल किए जाने की अपेक्षा की गई है जो संबंधित निर्यातकों से स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा किए आयातों से संबंधित है। श्रेणी-I के मामले संगत नहीं हैं क्योंकि आवेदकों ने अपनी संबंधित कंपनी से स्वयं संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, जिस जांच परिणाम पर भरोसा किया गया है वह अंतिम जांच परिणाम है। जिसका कल्पना में भी कोई अनुकरणीय महत्व नहीं हो सकता। हमें इस बात का आश्चर्य है कि आवेदकों ने अंतिम जांच परिणाम पर भरोसा नहीं किया है क्योंकि यह अवधि 1995 की है और जांच परिणाम या तो उसी वर्ष में या अगले वर्ष में निकाले जाने चाहिए थे।

123. इस जांच परिणाम के क्रम सं. 5 में श्रेणी-I के अंतर्गत शामिल किए जाने की अपेक्षा की गई है जो संबंधित निर्यातकों से स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा किए आयातों से संबंधित है। श्रेणी-I के मामले संगत नहीं हैं क्योंकि आवेदकों ने अपनी संबंधित कंपनी से स्वयं संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, यह मामला वर्तमान कार्यवाई में हमारे द्वारा दिए गए तर्कों का निपटान नहीं करता है। "सकता है" शब्द की व्याख्या को यह आरोप लगाते हुए कभी चुनौती नहीं दी गई

थी कि यह शेष उत्पादकों के संदर्भ में है न कि अपात्र उत्पादकों के संदर्भ में । अतः न्यायशास्त्र भेदमूलक बन जाता है ।

124. इस जांच परिणाम के क्रम सं. 6 में श्रेणी-I के अंतर्गत शामिल किए जाने की अपेक्षा की गई है जो संबंधित निर्यातकों से स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा किए आयातों से संबंधित है । श्रेणी-I के मामले संगत नहीं हैं क्योंकि आवेदकों ने अपनी संबंधित कंपनी से स्वयं संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है । इसके अलावा, जिस जांच परिणाम पर भरोसा किया गया है वह अनंतिम जांच परिणाम है । जिसका कल्पना में भी कोई अनुकरणीय महत्व नहीं हो सकता । हमें इस बात का आश्चर्य है कि आवेदकों ने अंतिम जांच परिणाम पर भरोसा नहीं किया है क्योंकि यह अवधि 1998 की है और जांच परिणाम या तो उसी वर्ष में या अगले वर्ष में निकाले जाने चाहिए थे । इसके अलावा, सीमेंस को अपनी संबंधित कंपनी से आयात किए जाने के कारण अलग किया गया था । फिलिप्स के लिए यह पाया गया था कि इसने संघटकों का आयात किया है और इनका प्रयोग ई यू में फिलिप्स द्वारा संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने के लिए किया गया था । जांच अवधि के दौरान अमरीकन फिलिप्स द्वारा कोई निर्यात नहीं किया गया था । इस संदर्भ में ही प्राधिकारी ने ऐसा कोई निष्कर्ष निकाला था । इस जांच परिणाम से आवेदकों के मामले को कोई सहायता नहीं मिलती है ।

125. इस जांच परिणाम की क्रम.सं. 7 वर्तमान मामले में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम 22 फरवरी, 2000 को जारी किए थे । यह 2010 के बाद की स्थिति पर लागू नहीं होता है क्योंकि इसे 1999 के बाद और 2010 से पूर्व नियम 2(ख) में किए गए संशोधन के संदर्भ में दर्ज किया गया था । इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वर्ष 1999 के संशोधन के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी को कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया था । यही वजह है कि आवेदकों ने कार्यनीतिक ढंग से जांच परिणाम की तारीख का उल्लेख नहीं किया है ।

126. इस जांच परिणाम की क्रम.सं. 8 वर्तमान मामले में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम 2 फरवरी, 2006 को जारी किए थे । यह 2010 के बाद की स्थिति पर लागू नहीं होता है क्योंकि इसे 1999 के बाद और 2010 से पूर्व नियम 2(ख) में किए गए संशोधन के संदर्भ में दर्ज किया गया था । इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वर्ष 1999 के संशोधन के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी को कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया था । यही वजह है कि आवेदकों ने कार्यनीतिक ढंग से जांच परिणाम की तारीख का उल्लेख नहीं किया है ।

127. इस जांच परिणाम की क्रम.सं. 9 वर्तमान मामले में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम 24 दिसंबर, 2009 को जारी किए थे । यह 2010 के बाद की स्थिति पर लागू नहीं होता है क्योंकि इसे 1999 के बाद और 2010 से पूर्व नियम 2(ख) में किए गए संशोधन के संदर्भ में दर्ज किया गया था । इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वर्ष 1999 के संशोधन के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी को कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया था । यही वजह है कि आवेदकों ने कार्यनीतिक ढंग से जांच परिणाम की तारीख का उल्लेख नहीं किया है ।

128. इस जांच परिणाम की क्रम सं. 10 में इस आवेदक से अपने मामले के समर्थन में भरोसा किए जाने की अपेक्षा की गई है । भरोसा किया गया जांच परिणाम अनंतिम जांच परिणाम है जिसका कल्पनातीत ढंग से कोई अनुकरणीय महत्व नहीं हो सकता । हम आश्चर्यचकित हैं कि आवेदकों ने अंतिम जांच परिणाम पर कोई भरोसा नहीं किया है क्योंकि जिस अवधि से यह संबंधित है वह अवधि पुरानी अवधि है । अंतिम आदेश और निष्कर्ष के संदर्भ के बिना अंतरित आदेशों का हवाला देना किसी अनुकरणीय महत्व के लिए भी किसी अनुरोध का आधार नहीं बन सकता । इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा उल्लिखित उद्धरण से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता ।

129. इस जांच परिणाम की क्रम सं. 11 में इस आवेदक से अपने मामले के समर्थन में भरोसा किए जाने की अपेक्षा की गई है । भरोसा किया गया जांच परिणाम अनंतिम जांच परिणाम है जिसका कल्पनातीत ढंग से कोई अनुकरणीय महत्व नहीं हो सकता । हम आश्चर्यचकित हैं कि आवेदकों ने अंतिम जांच परिणाम पर कोई भरोसा नहीं किया है क्योंकि जिस अवधि से यह संबंधित है वह अवधि पुरानी अवधि है । अंतिम आदेश और निष्कर्ष के संदर्भ के बिना अंतरित आदेशों का हवाला देना किसी अनुकरणीय महत्व के लिए भी किसी अनुरोध का आधार नहीं बन सकता । इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा उल्लिखित उद्धरण से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता । इसके अलावा, एक उत्पादक ने प्रपत्र में मांगी गई सूचना प्रदान नहीं की है और जिसे आयोग ने असहयोगी माना है और इस प्रकार यह सामुदायिक उद्योग का भाग नहीं है । इस प्रकार यह मामला हमारे तर्कों जैसा है । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह मामला तुरंत समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ग्रासिम संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है ।

130. इस जांच परिणाम की क्रम सं. 12 में इस आवेदक से अपने मामले के समर्थन में भरोसा किए जाने की अपेक्षा की गई है । भरोसा किया गया जांच परिणाम अनंतिम जांच परिणाम है जिसका कल्पनातीत ढंग से कोई अनुकरणीय महत्व नहीं हो सकता । हम आश्चर्यचकित हैं कि आवेदकों ने अंतिम जांच परिणाम पर कोई भरोसा नहीं किया है क्योंकि जिस अवधि से यह संबंधित है वह अवधि बिक्री अवधि है । अंतिम आदेश और निष्कर्ष के संदर्भ के बिना अंतरित आदेशों का हवाला देना किसी अनुकरणीय महत्व के लिए भी किसी अनुरोध का आधार नहीं बन सकता । इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा उल्लिखित उद्धरण से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता । इसके अलावा, प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा जापान के यूरो प्रिंट सदस्यों को शामिल किया जा रहा है ।

131. इस जांच परिणाम की क्रम सं. 13 से 17 में इस आवेदक से अपने मामले के समर्थन में भरोसा किए जाने की अपेक्षा की गई है । भरोसा किया गया जांच परिणाम अनंतिम जांच परिणाम है जिसका कल्पनातीत ढंग से कोई अनुकरणीय महत्व नहीं हो सकता । हम आश्चर्यचकित हैं कि आवेदकों ने अंतिम जांच परिणाम पर कोई भरोसा नहीं किया है क्योंकि जिस अवधि से यह संबंधित है वह अवधि पुरानी अवधि है । अंतिम आदेश और निष्कर्ष के संदर्भ के बिना अंतरित आदेशों का हवाला देना किसी अनुकरणीय महत्व के लिए भी किसी अनुरोध का आधार नहीं बन सकता ।

132. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच परिणाम की क्रम सं. 18 और 19 की वर्ष 2010 के बाद कोई प्रयोज्यता नहीं है क्योंकि इसे 1999 के बाद और 2010 से पूर्व नियम 2(ख) में किए गए संशोधन के संदर्भ में दर्ज किया गया था। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 1999 में किए गए संशोधन के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान किया गया था। ऐसा इस वजह से है कि आवेदकों ने अंतिम जांच परिणाम की तारीख का उल्लेख करने के लिए कार्यानीतिक ढंग से इसका विलोपन किया था।

133. जांच परिणाम की क्रम सं. 20 वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है क्योंकि समुदाय द्वारा किए गए आयात संबद्ध देश से नहीं किए गए थे।

134. जांच परिणाम की क्रम सं. 21 पर अपने मामले के समर्थन में आवेदक द्वारा भरोसा किए जाने की मांग की गई है। भरोसा किया गया जांच परिणाम अनंतिम जांच परिणाम है जिसका कल्पनातीत ढंग से कोई अनुकरणीय महत्व नहीं हो सकता। हम आश्चर्यचकित हैं कि आवेदकों ने अंतिम जांच परिणाम पर कोई भरोसा नहीं किया है क्योंकि जिस अवधि से यह संबंधित है वह अवधि 1999 की है और अंतिम जांच परिणाम जांच अवधि के 18 माह के भीतर दर्ज किए गए थे। अंतिम आदेश और निष्कर्ष के संदर्भ के बिना अंतरित आदेशों का हवाला देना किसी अनुकरणीय महत्व के लिए भी किसी अनुरोध का आधार नहीं बन सकता।

135. जांच परिणाम की क्र. सं. 22 को ऐसी श्रेणी में शामिल करने की मांग की जाती है जो असंबद्ध निर्यातकों से स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयातों से संबंधित है। उपर्युक्त श्रेणी संगत नहीं है क्योंकि आवेदकों ने असंबद्ध कंपनी से संबद्ध वस्तु का स्वयं आयात नहीं किया है। इसके अलावा, यह मामला वर्तमान कार्यवाही में हमारे द्वारा दिए गए तर्क से संबंधित नहीं है। "सकता है" शब्द की व्याख्या को यह आरोप लगाते हुए कभी चुनौती नहीं दी गई है कि यह शेष उत्पादकों के संदर्भ में है न कि अपात्र उत्पादकों के संदर्भ में। अतः न्यायशास्त्र भेदमूलक है।

136. जांच परिणाम की क्र.सं. 23 में आवेदक द्वारा अपने मामले के समर्थन में भरोसा किए जाने की मांग की है। भरोसा किया गया जांच परिणाम अनंतिम जांच परिणाम है जिसका कल्पनातीत ढंग से कोई अनुकरणीय महत्व नहीं हो सकता। हम आश्चर्यचकित हैं कि आवेदकों ने अंतिम जांच परिणाम पर कोई भरोसा नहीं किया है क्योंकि जिस अवधि से यह संबंधित है वह अवधि वर्ष 2000 की है और अंतिम जांच परिणाम जांच शुरुआत के 18 माह के भीतर दर्ज किए गए थे। अंतिम आदेश और निष्कर्ष के संदर्भ के बिना अंतरित आदेशों का हवाला देना किसी अनुकरणीय महत्व के लिए भी किसी अनुरोध का आधार नहीं बन सकता।

137. जांच परिणाम की क्र.सं. 24 में आवेदक द्वारा अपने मामले के समर्थन में भरोसा किए जाने की मांग की है। भरोसा किया गया अंतिम जांच परिणाम का कल्पनातीत ढंग से कोई अनुकरणीय महत्व नहीं है क्योंकि यह मामला ऐसे उत्पादक को बाहर रखे जाने से संबंधित है जिसने स्वयं के बारे में जानकारी नहीं दी है और जिसे निर्यातकों से संबंधित पाया गया था। इसके अलावा, फिलिप्स उपभोक्ता को यथापरिभाषित "सामुदायिक उद्योग" नहीं माना गया था क्योंकि बी सी

संघटकों का एक बड़ा हिस्सा था और यह मामला केवल उनकी सूचना के आधार पर बनाया गया था । किया गया भरोसा पूर्णतः भ्रामक और कपटपूर्ण है ।

138. इस जांच परिणाम की क्रम सं. 25 में इस आवेदक से अपने मामले के समर्थन में भरोसा किए जाने की अपेक्षा की गई है । भरोसा किया गया जांच परिणाम अनंतिम जांच परिणाम है जिसका कल्पनातीत ढंग से कोई अनुकरणीय महत्व नहीं हो सकता । हम आश्चर्यचकित हैं कि आवेदकों ने अंतिम जांच परिणाम पर कोई भरोसा नहीं किया है क्योंकि जिस अवधि से यह संबंधित है वह अवधि वर्ष 2000 की है और अंतिम जांच परिणाम जांच की शुरुआत के 18 माह के भीतर शुरू किए गए थे। अंतिम आदेश और निष्कर्ष के संदर्भ के बिना अंतरित आदेशों का हवाला देना किसी अनुकरणीय महत्व के लिए भी किसी अनुरोध का आधार नहीं बन सकता ।

139. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच परिणाम की क्रम सं. 18 और 19 की वर्ष 2010 के बाद कोई प्रयोज्यता नहीं है क्योंकि इसे 1999 के बाद और 2010 से पूर्व नियम 2(ख) में किए गए संशोधन के संदर्भ में दर्ज किया गया था । इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 1999 में किए गए संशोधन के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान किया गया था । ऐसा इस वजह से है कि आवेदकों ने अंतिम जांच परिणाम की तारीख का उल्लेख करने के लिए कार्यनीतिक ढंग से इसका विलोपन किया था ।

140. जांच परिणाम की क्र. सं. 27 वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है क्योंकि उक्त मामले में प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपवर्जन के बाद भी शेष उद्योग का हिस्सा कुल घरेलू उत्पादन के 60% से अधिक बनता है ।

141. जांच परिणाम की क्र. सं. 28 वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है क्योंकि उक्त मामले में प्राधिकारी उक्त मामले में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सामुदायिक उत्पादकों को क्षति हुई है भले ही संबंध रखने वाले उत्पादकों को शामिल किया गया हो । निकाले गए निष्कर्ष खासकर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में थे । उपर्युक्त के प्रति किसी भेदभाव के बिना "सकता है" के संदर्भ में वर्तमान जांच में दिए गए तर्क उसमें नहीं उठाए गए हैं । अतः इस मुद्दे का निर्णय रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार किए जाने की जरूरत है ।

142. उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि समझौते में विधिक प्रासंगिकता अथवा तथ्यात्मक विषय वस्तु की जांच किए बिना कई निर्णयों का मात्र उल्लेख किया गया है । वस्तुतः "घरेलू उत्पादक से संबंधित निर्यातकों" की श्रेणी से जुड़े केवल दो निर्णयों से इस बात की पुष्टि होती है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में परिकल्पित दूसरी स्थिति के लिए आयातों की मात्रा का कोई महत्व नहीं है ।

143. पैरा 6 और 7 की विषय वस्तु गलत है और इससे इंकार किया जाता है । यह दोहराया जाता है कि वर्तमान मामले में आवेदक ने 6 माह की जांच अवधि का अनुरोध किया था और प्राधिकारी ने किसी ठोस आधार या तर्क के बिना पद्धति और दिशा निर्देशों के अपवाद करते हुए

इसेक स्वीकार किया था । माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस बात को नहीं समझा है कि आवेदक ने रणनीतिक ढंग से केवल 6 माह की क्षति का दावा किया और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए विशिष्ट दिशा निर्देशों और पद्धति के प्रतिकूल ऐसे दावों के आधार पर नियम 5 की पूर्व शर्तों की जांच का अनुरोध किया । 6 माह की जांच अवधि का चयन पाटनरोधी व्यवहार सम्मिलित दिशा निर्देशों के भी प्रतिकूल है । डी जी ए डी की यह संगत परंपरा रही है कि अत्यधिक वांछित जांच अवधि एक वित्त वर्ष की होती है । कई मामलों में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस मामले पर जोर दिया है कि सूचना आवश्यक रूप से कम से कम एक वर्ष की होनी चाहिए । अनुरोध है कि लिखित अनुरोधों में भी आवेदक ने अपने पक्ष में किए गए अपवाद का कोई व्यावहारिक कारण नहीं दिया है । विधित स्थिति सभी को पता है । अतः यह माना जा सकता है कि न तो आवेदक और न ही निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास जांच अवधि को 6 माह तक सीमित रखने का कोई आधार है जैसा कि हमारे लिखित अनुरोधों में बताया गया है कि 5% को अत्यधिक पाटन नहीं कहा जा सकता जो जांच अवधि को 6 माह लेने का एकमात्र आधार है । अतः यह कानूनन या तथ्यानुसार कोई उचित मापदंड नहीं है । आवेदक ने अत्यधिक पाटन के मुद्दे को उत्पादन लागत से जोड़ने का प्रयास किया है जो समग्र से परे है । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कम पाटन मार्जिन की जांच किए जाने का यह तर्क नहीं निकाला जा सकता कि अत्यधिक पाटन (जो अपेक्षाकृत कम जांच अवधि का एकमात्र औचित्य है) घरेलू उद्योग द्वारा अंतरित रहता है ।

144. पैरा 8 और 9 के उत्तर में यह अनुरोध किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने पाटन और क्षति तथा कारणात्मक संबंध के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष दायर पूर्ववर्ती अनुरोधों में प्रस्तुत क्रमशः सभी तथ्यों, तर्कों अभिकथनों और विवरणों को दोहराया है और उन पर भरोसा किया है और उन्होंने निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि उन्हें लिखित अनुरोधों के भाग के रूप में तदनुसार माना जाए । यह दोहराया जाता है कि आवेदक से उन तारीखों के साथ जिनको ये दायर किए गए थे, ऐसे अनुरोधों की तारीख के संदर्भ में ऐसे अनुरोधों की सूची मांगी जाए । यदि ऐसे दस्तावेजों का अगोपनीय रूपांतरण गोपनीय रूपांतरण के साथ दायर नहीं किया गया था तो उस पर विचार न किया जाए क्योंकि ये नियम 7 की अपेक्षाओं के प्रतिकूल हैं । हम अपना यह अनुरोध दोहराते हैं कि सार्वजनिक फाइल की सूची प्रदान की जाए ताकि हम इस बात की प्रति जांच कर सकें कि क्या ये रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं ।

145. पैराग्राफ 10 की विषय वस्तु गलत है और इससे इंकार किया जाता है । यह दोहराया जाता है कि आवेदक ने मांग में कमी के तथ्य को मामूली रूप से बढ़े हुए आयातों के साथ जोड़ने का प्रयास किया है । अनुरोध है कि यहां मुद्दा यह है कि क्या मांग में कोई कमी आई है या नहीं और यदि कमी आई है तो उससे घरेलू उद्योग का निष्पादन किस प्रकार प्रभावित हुआ है । आगे यह दोहराया जाता है कि 6 माह की अल्पावधि में आयातों में वृद्धि कोई महत्व नहीं रखती है क्योंकि जांच अवधि के दौरान निष्पादनाधीन ऑर्डरों और निकासी को रोका नहीं जा सकता । बहरहाल मांग में कमी कारणात्मक संबंध का एक मुद्दा है जिसे उपर्युक्त कारणों से सवर्धित आयातों के साथ तर्क सम्मत और विधिसम्मत ढंग से जोड़ा नहीं जा सकता है ।

146. ई सी के निर्णय के उद्धरणों के उत्तर में यह अनुरोध किया जाता है कि तीन जांच परिणामों में से दो परिणामों पर अनंतिम जांच परिणामों के रूप में भरोसा किया गया है जो अनुकरणीय महत्व के नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त मानदंड (परिषद विनियम (ई सी) सं. 2080/2001, 23 अक्टूबर, 2001 जिसमें जापान के मूल की साईकलों के लिए आंतरिक गेयर हबों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है) हमारे विचारों का समर्थन करते हैं और याचिकाकर्ता के दावों का खंडन करते हैं उल्लिखित मामले में मांग में % गिरावट 8% की थी जबकि सामुदायिक उद्योग के बाजार हिस्से में कमी 9% की आई थी। अतः बाजार हिस्से में कमी मांग में गिरावट के % की तुलना में कम थी। वर्तमान जांच में मांग में गिरावट 51.98% की है जबकि बाजार हिस्से में कमी 5.81% की आई है। अतः इस मापदंड से घरेलू उद्योग के दावे को समर्थन नहीं मिलता है। इसके विपरीत यह घरेलू उद्योग के दावे के प्रतिकूल है।

147. पैरा 11 (क) की विषय वस्तु गलत है और इससे इंकार किया जाता है। अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त पक्षकारों से घरेलू उद्योग की ओर से कभी भी कोई गोपनीय सूचना की मांग नहीं की गई थी। हमने केवल यह अनुरोध किया था कि गोपनीय रूपांतरण में दी गई सूचना को उसके अगोपनीय रूपांतरण में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए ताकि हम उन पर सकारात्मक टिप्पणियां दे सकें। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों ने उचित समय पर और प्राधिकारी की अपेक्षानुसार आवश्यक सूचना प्रदान की थी।

148. पैरा 10(ख) की विषय वस्तु गलत है और इससे इंकार किया जाता है। पाटन और पाटन मार्जिन निकालने के बारे में याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त कार्य प्रणाली सभी को ज्ञात है।

149. पैरा 10(ग) की विषय वस्तु गलत है और इससे इंकार किया जाता है। पाटन और पाटन मार्जिन निकालने के बारे में याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त कार्य प्रणाली सभी को ज्ञात है। हमने पाटन के अंतिम आंकड़े के लिए कार्य प्रणाली के बारे में कभी कोई तर्क नहीं दिया है। हमने प्राधिकारी के निष्कर्ष के बारे में आपत्तियां की हैं कि अत्यधिक पाटन के रूप में 6% पाटन और वह भी 6 माह की अल्पावधि के दौरान विचार किया जाना उचित नहीं है क्योंकि यह जांच अवधि के रूप में केवल 6 माह की अल्प अवधि का चयन करने के लिए न्यायोचित नहीं है। याचिकाकर्ता और उसके प्रतिनिधि को इस आपत्ति के बारे में पूरी जानकारी है। चूंकि आवेदक की ओर से औचित्य प्रस्तुत नहीं किया जा सकता इसलिए वे असंगत और भ्रामक अनुरोध कर मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास कर रहे हैं।

150. पैरा 10(घ) की विषय वस्तु गलत है और इससे इंकार किया जाता है। याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में "कीमत प्रभाव" शीर्षक के अंतर्गत यह तथ्य स्वीकार किया है कि ग्रे और डायड के बीच कीमत में भारी अंतर था। अतः ग्रे और डायड के ऐसे संयुक्त आंकड़ों के आधार पर पाटन मार्जिन और क्षति का कोई विश्लेषण निरर्थक है। अतः यह कहना कि हितबद्ध पक्षकार केवल यह आरोप लगा रहे हैं कि पर्याप्त अंतर गलत है और यह आवेदन में याचिकाकर्ता के अनुरोधों के प्रतिकूल है।

151. पैरा 10(ड) की विषय वस्तु गलत है और इससे इंकार किया जाता है । अनुरोध है कि अधिनियम और नियमावली की वर्तमान स्कीम के अंतर्गत यदि ऐसा पाटन हुआ है जिससे आवेदक को परिणामी क्षति हुई है तो अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए आयातों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता है । दूसरे शब्दों में उस स्थिति में कोई संरक्षण हासिल नहीं किया जा सकता है जब आयात पाटित कीमत पर किए जाते हैं क्योंकि वे निर्यात प्रयोजन के लिए होते हैं । ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अग्रिम लाइसेंस अंतर्गत विश्लेषण शुल्क की सिफारिश करने के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण था । इसके अलावा, हमने गलत ढंग से यह तर्क दिया है कि अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए आयातों का वर्तमान जांच पर भारी प्रभाव पड़ा है और घरेलू उद्योग को हुई कोई क्षति अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए आयातों के कारण हो सकती है ।

152. पैरा 10(च) की विषय वस्तु गलत है और इससे इंकार किया जाता है । हमने ऐसा कभी कोई तर्क नहीं दिया है कि प्राधिकारी ने अनुबंध-1 का पैरा 7 लागू नहीं किया है । यह दोहराया जाता है कि याचिकाकर्ता उन तर्कों को प्रस्तुत कर प्राधिकारी को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है जो हमने कभी उठाए ही नहीं थे ।

153. पैरा 10(छ) की विषय वस्तु गलत है और इससे इंकार किया जाता है । अनुरोध है कि हमने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने अपने संबद्ध पक्षकार की पूर्ण और सही सूचना प्रदान नहीं की । हमने याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा के बारे में कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया है । यद्यपि, वर्तमान आवेदन के संबंध में आचरण संदिग्ध हो सकता है । 10(छ) में याचिकाकर्ता का अनुरोध आश्चर्यजनक है ।

154. पैरा 10(ज) की विषय वस्तु गलत है और इससे इंकार किया जाता है । अनुरोध है कि याचिकाकर्ता ने इंडोनेशियाई सहायक कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति के बारे में सूचना सही समय पर प्रकट नहीं की है जिसकी घोषणा डी जी ए डी द्वारा निर्धारित प्रपत्र के प्रश्न 6 में जांच की शुरुआत के समय की गई थी ।

155. पैरा 10(झ) की विषय वस्तु गलत है और इससे इंकार किया जाता है । तथापि, आवेदक द्वारा की गई तुलना भी इस बात के मद्देनजर उचित नहीं है कि 6% पाटन मार्जिन को अत्यधिक पाटन माना जा सकता है ।

156. पैरा 10(ञ) की विषय वस्तु गलत है और इससे इंकार किया जाता है । हम इस बात को समझने में असमर्थ हैं कि विरोधाभासी हित रखने वाले घरेलू उद्योग और निर्यातक द्वारा समान परामर्शदाता कैसे रखे जा सकते हैं । इस संदर्भ में प्राधिकारी का ध्यान ए टी एम ए बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें यह माना गया है कि पाटनरोधी मामलों में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के बीच संबंध होता है । जब पक्षकारों के बीच संबंध होता है तो हित का टकराव अंतरनिहित होता है । अतः यह सुझाव देना आधारहीन है कि याचिकाकर्ता और किसी प्रतिवादी दोनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है । यह स्पष्ट है कि आवेदक ने अपने संबद्ध पक्षकार के साथ किसी

असाधारण शुल्क की सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रणाली के साथ छोड़छाड़ की है। अनुरोध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया यह निष्कर्ष निकालने के आधार के रूप में केवल इस तथ्य पर विचार करें कि याचिकाकर्ता प्राधिकारी के समक्ष निर्दोष रूप में उपस्थित नहीं हुआ है।

157. पैरा 10(ट) की विषय वस्तु गलत है और इससे इंकार किया जाता है। अनुरोध है कि आवेदक अपनी उस स्थिति और तथ्यों में परिवर्तन नहीं कर सकता जो जांच की शुरुआत, रिमांड कार्रवाई और अंतिम जांच परिणाम में आधार थे। इसके अलावा, यदि पक्षकार संबंधित नहीं है तो इस बात की जानकारी लेने की उत्सुकता रहती है कि एक ही वकील समान कार्यवाही में दो असंबद्ध परंतु विरोधाभासी पक्षकारों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। बहरहाल आवेदन ने ऐसा कोई आधार या तर्क प्रस्तुत नहीं किया है कि वह चीनी और इंडोनेशियाई कंपनियों से किस प्रकार संबंधित नहीं है।

158. पैरा 10(झ) की विषय वस्तु गलत है और इससे इंकार किया जाता है। हम यह दोहराते हैं कि सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन को गोपनीय नहीं रखा जा सकता क्योंकि इनकी गणना उद्यमोत्तर विशिष्ट आंकड़ों के आधार पर की जाती है।

159. उपर्युक्त आधार पर आवेदकों के "निष्कर्ष और अनुरोध" दोषपूर्ण हैं और भ्रामक आंकड़ों तथा सूचना पर आधारित हैं। पाटनरोधी संबंधी वर्तमान कानून और पद्धति के अनुसार ऐसी परिस्थितियों में अधिनियम और नियमावली के अंतर्गत कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती। यह ऐसा उचित मामला है जिसमें कार्यवाही तुरंत समाप्त कर दी जाए।

160. हम यह भी निवेदन करते हैं कि आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से और उनके लिए दायर किए गए उत्तर संबंधी अनुरोधों की प्रति न्याय और उचित प्रतिस्पर्धा के हित में हमें उपलब्ध कराई जाए। उपर्युक्त के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना हम प्राधिकारी से यह भी अनुरोध करते हैं कि वह कृपया आगे कार्रवाई करने से पूर्व जांच के बारे में आवेदकों के साथ आदान-प्रदान किए गए अगोपनीय रूपांतरण सहित समस्त पत्राचार की प्रतियां उपलब्ध कराएं ताकि प्रत्येक पत्राचार पर हम उचित टिप्पणियां दायर कर सकें। प्राधिकारी से हमारा अनुरोध है कि वह ऐसे किसी उत्तर पर विचार न करें जिसके बारे में अगोपनीय रूपांतरण दायर नहीं किया गया है और जिसकी प्रतियां हमें प्रदान नहीं की गई हैं। प्राधिकारी को समस्त आंकड़ों और दायर की गई सूचना पर टिप्पणी देने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को वंचित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इसका कार्यवाही के परिणाम पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

161. उपर्युक्त के प्रति किसी भेदभाव के बिना अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्यवाही एस जी जी आई बनाम भारत संघ (उपर्युक्त) के मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अधिकारातीत है और इसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि आवेदक ने लंबे समय से अवैध पाटनरोधी शुल्क के संरक्षण का लाभ उठाया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

162. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी के पास वर्तमान जांच की शुरुआत के समय ऐसी कोई सूचना दायर नहीं की गई थी कि मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज के चीन जन.गण. और इंडोनेशिया में संबद्ध पक्षकार हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तर्क तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि प्राधिकारी को इस बात की जानकारी थी कि मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज की जांच की शुरुआत के चरण पर चीन जन.गण. और इंडोनेशिया दोनों में संबद्ध कंपनियां हैं जैसा कि इस विषय पर 19 मार्च, 2009 की जांच शुरुआत संबंधी पैरा से भी स्पष्ट हो जाएगा ।

163. जहां तक इस तर्क का संबंध है, कि उन्होंने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी के समक्ष दायर आंकड़ों, सूचना और साक्ष्य की मांग की थी और वर्तमान मौखिक सुनवाई का अवसर देने से पूर्व उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए था । प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस विषय पर पाटनरोधी नियम और विनियम में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी के समक्ष दायर किए गए आंकड़े सूचना और साक्ष्य उपलब्ध कराए । पाटनरोधीनियमावली में केवल इस बात की अपेक्षा की गई है कि प्राधिकारी नियम 5 के उप नियम (1) में उल्लिखित आवेदन की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों या ऐसी एसोसिएशन जिसके निर्यातक सदस्य काफी अधिक हैं और निर्यातक देशों की सरकारों को उपलब्ध कराएंगे और यह कि प्राधिकारी ऐसे अन्य हितबद्ध पक्षकार को आवेदन की प्रति भी उपलब्ध कराएंगे जो लिखित में इसके लिए अनुरोध करता है । पाटनरोधी नियमावली में आगे यह अपेक्षा की गई है कि प्राधिकारी जांच में भाग लेने वाले एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य को दूसरे हितबद्ध पक्षकार को उपलब्ध कराएंगे । इस प्रयोजनार्थ एक मानक पद्धति के रूप में प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारों की ओर से दायर सूचना/आंकड़ों/ साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण की एक सार्वजनिक फाइल रखी जाती है । हितबद्ध पक्षकारों का ध्यान स्वयं जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के जरिए इस तथ्य की ओर आकर्षित भी किया गया है । अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों सहित किसी नियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और इन हितबद्ध पक्षकारों के पास इस जांच की समूची कार्यवाही के दौरान अपने हितों की रक्षा करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना/आंकड़ों/साक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध थे; अतः यह तर्क दोषपूर्ण है ।

164. जहां तक इस तर्क का संबंध है, कि लिखित अनुरोध 22.10.2007 की व्यापार सूचना 1/2007 के प्रतिकूल है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त व्यापार सूचना पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच को सुकर बनाने के लिए जारी की गई थी और इसलिए हितबद्ध पक्षकारों को सामान्यतः उसमें सुझाए गए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए था ।

165. जहां तक इस तर्क का संबंध है, कि मै. ग्रासिम इंड लि. नियम 5(3) के अनुसार "आधार" की अपेक्षा को पूरा नहीं करता है और न ही वह नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग बनने

की पात्रता रखता है क्योंकि यह वर्तमान मामले में एक स्वीकृत तथ्य है कि ग्रासिम इंड लि. चीन और इंडोनेशिया के निर्यातकों से संबंधित है और इसलिए वह अपवर्जित श्रेणी में आता है। चूंकि यह एकमात्र उत्पादक है इसलिए नियम 5(3) के अनुसार आधार रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है और यह कि इस मुद्दे का समाधान अब सेंटगोवेन ग्लास इंडिया लि. बनाम भारत संघ के मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने कर लिया है जिसमें यह माना गया है कि संशोधित नियम 2(ख) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास "घरेलू उद्योग" की परिभाषा में अपवर्जित श्रेणी पर विचार करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है; प्राधिकारी ने समय-समय पर लागू कानून के संदर्भ में इस विषय पर संबंधित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की सावधानीपूर्वक जांच की है।

166. शुरुआत में यह उल्लेख करना उचित होगा कि नियम 2(ख) में 1 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना सं. 86/2011-सी.शु. (एन टी) के तहत पुनः संशोधन किया गया है जिसमें पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) से "केवल" शब्द हटा दिया गया है। आगे यह नोट किया जाता है कि इस संशोधन को सेंटगोवेन ग्लास इंडिया लि. बनाम भारत संघ के मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया है जैसा कि निर्णय के पैरा से स्पष्ट हो जाएगा।

167. नियम 2(ख) अब निम्नानुसार है।

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थशेष उत्पादकों के उल्लेख के रूप में निकाला जाएगा।"

168. जहां तक इस बात का संबंध है कि ऐसी परिस्थितियों में कौन सा नियम लागू होगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच की शुरुआत के समय नियम 2(ख) पर विचार करते हुए अथवा आज की तारीख के अनुसार नियम 2(ख) पर विचार करते हुए प्राधिकारी के पास दोनों ही स्थिति में इस विषय पर विवेकाधिकार है जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट हो जाएगा।

169. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में यह उपबंध है कि कुछेक स्थितियों में घरेलू उद्योग का निर्धारण करते समय ऐसे घरेलू उत्पादकों को अलग रखा जाए जो आरोपित पाटित वस्तुओं के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हैं अथवा जो स्वयं उसके आयातक हैं। प्राधिकारी का यह सुविचारित मंतव्य है कि नियम 2(ख) "जाए" शब्द के प्रयोग से यह संकेत मिलता है कि संदर्भाधीन उत्पादकों के दोनों प्रकारों अर्थात् संबंधित उत्पादकों और पाटित उत्पाद का आयात करने वाले उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग होने से स्वतः अपवर्जित नहीं किया जाता है। इसके विपरीत जांच प्राधिकारियों की यह सुसंगत पद्धति रही है कि ऐसे उत्पादकों के अपवर्जन का निर्णय उचित और समान आधारों पर एवं समस्त कानूनी और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामला दर मामला आधार पर लिया जाना चाहिए।

170. किसी घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल करने या बाहर रखने का मुद्दा कोई खास महत्व नहीं रखता है, क्योंकि प्रश्न यह उठता है कि क्या वे वास्तव में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) की भावना के अनुसार घरेलू उद्योग का भाग हैं जिसका असर आवेदन के "आधार" पर पड़ता है अर्थात् क्या उनका उत्पादन पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित प्रतिनिधित्व के आवश्यक स्तर पर है या नहीं (घरेलू उत्पादक जिन्होंने आवेदन दायर किया है या उसका समर्थन किया है), क्योंकि निर्यातकों या आयातकों के साथ संबंध के कारण घरेलू उद्योग की परिभाषा से अपवर्जित घरेलू उत्पादकों के उत्पादन अथवा उनके खुद के पाटित आयातों के कारण उत्पादन पर कुल घरेलू उत्पादन की गणना करने और इस बात का निर्धारण करते समय विचार नहीं किया जाएगा कि क्या समर्थनकर्ता घरेलू उत्पादकों के साथ साथ आवेदकों का उत्पादन ऐसे उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है।

171. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(ख) में कई बार संशोधन किया गया है। यह नोट किया जाता है कि 1.1.95 की स्थिति के अनुसार नियम 2(ख) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास ऐसी स्थितियों में कोई विवेकाधिकार नहीं था जहां एक या अधिक घरेलू उत्पादकों ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया था अथवा वह विचाराधीन उत्पाद के आयातक या निर्यातक से संबंधित था।

172. तथापि, डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार और अन्य जांचकर्ता प्राधिकरणों के स्वदेशी कानूनों में ऐसी स्थितियों में जांचकर्ता प्राधिकारियों को विवेकाधिकार दिया गया है जिन्हें मामला दर मामला आधार पर लागू करना था। अतः नियम 2(ख) में 15 जुलाई, 1999 की सी.शु. अधिसूचना सं. 44/1999 (एन टी) के तहत संशोधन किया गया था जिसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी स्थितियों में विवेकाधिकार प्रदान किया गया था जिसका प्रयोग मामला दर मामला आधार पर किया जा सकता था। नियम 2(ख) में वर्ष 2010 में पुनः निम्नानुसार संशोधन किया गया था।

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थशेष उत्पादकों के उल्लेख के रूप में निकाला जाएगा।"

173. तथापि, 1 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना सं. 86/2011-सी.शु. (एन टी) के तहत "केवल" शब्द को हटा दिया गया है। जैसा कि उल्लेख किया गया है कि नियम 2(ख) में "सकता है" शब्द के उपयोग का यह संकेत मिलता है कि संदर्भाधीन उत्पादकों के दोनों प्रकारों अर्थात् संबंधित उत्पादकों और पाटित उत्पाद का आयात करने वाले उत्पादकों को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में स्वतः अपवर्जित नहीं किया जाता है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी में इस प्रयोजनार्थ इस प्रकार से निहित विवेकाधिकार से निम्नलिखित स्थितियों के समाधान में मदद मिलती है :-

(क) कुछ घरेलू उत्पादक शायद केवल इसलिए आवेदन का समर्थन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वे स्वयं उत्पाद का आयात कर रहे हों अथवा वे उत्पाद के आयातक या निर्यातक से संबंधित हों । ऐसे घरेलू उत्पादक पाटन की अनुचित प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए अन्य घरेलू उत्पादकों को उत्पादन बंद करने के लिए बाध्य कर सकते हैं । अधिकारी को स्वविवेक का अधिकार दिए जाने का एक कारण ऐसी संबंधित सत्ताओं को जांच से बाहर रखना है जो शेष घरेलू उत्पादकों द्वारा पाटनरोधी आवेदन करके और पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रिया के विरुद्ध उपयुक्त राहत की मांग करके उन्हें हुई क्षति की क्षतिपूर्ति की मांग करने के प्रयास को बाधित कर सकते हों । यदि ऐसा नहीं है तो शेष घरेलू उत्पादक पाटनरोधी आवेदन दायर करने और पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रिया के विरुद्ध उपयुक्त उपचार की मांग करने के लिए कानून में यथाप्रदत्त "योग्यता संबंधी अपेक्षा" को पूरा नहीं कर पाएंगे । संक्षेप में घरेलू उद्योग के दायरे से कतिपय कंपनियों को बाहर रखे जाने की जरूरत थी ताकि प्राधिकारी देश में क्षतिकारी पाटन का समाधान कर सकें ।

(ख) एक या उससे अधिक घरेलू उत्पादकों ने संभवतः विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है अथवा उनकी संबंधित कंपनी ने एक या उससे अधिक सकारात्मक कारणों से विचाराधीन उत्पाद का आयात अथवा निर्यात किया है । इनमें से कुछ कारण नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं :

- (i) आयात अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए ताकि उत्तरवर्ती उत्पाद के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की जा सके ।
- (ii) आयात उत्पादन के अस्थायी निलंबन के समय किए गए हैं (जो अनेक वास्तविक कारणों जैसे आग लगने, हड़ताल होने, प्राकृतिक आपदा आदि के चलते हो सकता है) ।
- (iii) आयात किसी विशेष किस्म के आयात के द्वारा उत्पाद की व्यवस्था को पूरा करने के लिए किए गए हैं जिसका उत्पादन शायद आवेदक न कर रहा हो और जो उसके कुल व्यावसायिक प्रचालनों का महज एक छोटा सा हिस्सा हो ।
- (iv) आयात परीक्षण, अनुसंधान और विकास, बीज विपणन के प्रयोगों के लिए किए गए हों (घरेले उत्पादकों द्वारा कम कीमत के आयातों का सामना करते समय उत्पाद की गुणवत्ता और अन्य मापदंडों की जांच के लिए आयात किया जाना एक आम समस्या है) ।
- (v) उत्पाद के किसी हिस्से का आयात उस उत्पाद के विनिर्माण में मुख्य कार्यकलाप नहीं होता है ।

174. स्वतः ही कुछ सदाशयी घरेलू उत्पादकों को केवल पूर्ववर्ती नियम 2(ख) के तहत अनिवार्य रूप से बाहर रखने की शर्त के कारण घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखना उचित नहीं होगा ।

अतः प्राधिकारी का यह विचार है कि संशोधित नियम में प्राधिकारी को उपर्युक्त स्थितियों में विदेकाधिकार प्रदान किया गया है । दूसरे शब्दों में पाटनरोधी नियमावली को निर्दिष्ट प्राधिकारी को स्व-विवेक प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है ताकि कतिपय स्थितियों में किसी घरेलू उत्पादक को शामिल किया जा सके या कतिपय स्थिति में किसी घरेलू उत्पादक को जांच से बाहर किया जा सके ।

175. किसी घरेलू उत्पादक को शामिल करने अथवा बाहर रखने के संबंध में पर्याप्त न्यायिक व्यवस्थाएं मौजूद हैं, जो निम्नानुसार संकेत करती हैं :

(क) इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कारक विनिर्माण और आयात के बीच घरेलू उत्पादक के व्यापार संतुलन है । यदि वह कंपनी अधिकांशतः भारत में उत्पाद का विनिर्माण करती है तो उसे शामिल किया जाना चाहिए । तथापि, यदि घरेलू उत्पादक उत्पादन बंद कर देता है या उसे घटा देता है और बजाए इसके उस उत्पाद का आयात करता है या व्यापार का सामान्य ध्यान उत्पादन से हटकर आयातों की ओर चला जाता है तो उसे बाहर रखा जाना चाहिए ।

(ख) यदि किसी घरेलू उत्पादक ने किसी संबंधित पक्षकार से आयात अथवा निर्यात का सहारा लेकर पाटन के प्रभाव से स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है, तो उस कंपनी को बाहर रखा जाना चाहिए ।

(ग) यदि किसी घरेलू उत्पादक ने किसी प्रकार से पाटन प्रक्रियाओं में भाग लिया है या अन्यथा अनुपयुक्त ढंग से उससे लाभान्वित हुआ है तो उसे बाहर रखा जाए ।

(घ) यदि किसी घरेलू उत्पादक को शामिल करने से क्षति संबंधी निष्कर्ष में गड़बड़ी आ जाएगी तो उसे बाहर रखा जाए ।

(ङ) यदि कोई घरेलू उत्पादक प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं करता है तो प्राधिकारी ऐसे घरेलू उत्पादक को अयोग्य मान सकते हैं ।

176. प्राधिकारी ने मै. जाको द्वारा लिखित पाठ्य पुस्तक ह्यूमैन एंड मिरांडा का भी संदर्भ लिया है; जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी स्थिति में अन्य डब्ल्यू टी ओ सदस्यों द्वारा अपनाए जाने वाले मापदंडों का उल्लेख है जो निम्नानुसार है :

(क) विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादन का प्रतिशत जिसे संबंधित उत्पादकों द्वारा लेखांकित किया गया है ।

(ख) क्या संबंधित उत्पादकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के आयातों से उन्हें लाभ हुआ है या पाटन के प्रभावों से उनका संरक्षण हुआ है ।

(ग) क्या संबंधित पक्षकारों को बाहर रखने से उद्योग के शेष सदस्यों के आंकड़ों में अनुचित विकृति आ जाएगी ।

(घ) घरेलू उत्पादन के लिए उत्पादक द्वारा दर्शायी गई वचनबद्धता का स्तर या दीर्घावधिक प्रकृति जो आयात संबंधी कार्यकलापों के विरुद्ध हो ।

(ङ) संबंधित उत्पादकों के लिए घरेलू उत्पादन हेतु आयात संबंधी पोतलदानों का अनुपात ।

177. कतिपय घरेलू उत्पादकों को शामिल करने अथवा बाहर रखने संबंधी स्वविवेक का प्रयोजन संगत घरेलू उद्योग से ऐसे घरेलू उत्पादकों, जिन्होंने क्षतिकारी पाटन में भाग लिया है को बाहर रखकर भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभावों के संबंध में वस्तुनिष्ठ और विशुद्ध निर्धारण करने में प्राधिकारी को सक्षम बनाना है । जांचकर्ता प्राधिकारी किसी संबंधित उत्पादक को बाहर रख सकते हैं जहां संबंधित पक्षकार ने

(क) बाजार पर कीमतों में गिरावट को उत्पन्न किया है या उसमें योगदान दिया है ।

(ख) उसके प्रभावों से स्वयं को संरक्षित किया है या

(ग) वे उससे अनुचित रूप से लाभान्वित हुए हैं ।

178. प्रथम श्रेणी अर्थात् पाटन की प्रथाओं में भागीदारी करने के संबंध में अनेक विशिष्ट स्थितियों में विभेद किया जा सकता है । एक ओर ऐसी स्थिति में बाहर रखना वस्तुतः उचित है जहां किसी घरेलू उद्योग की क्षति स्व-आरोपित है क्योंकि पाटित उत्पादकों से हुए आयातों ने घरेलू उत्पादक की अपनी क्षमता के प्रयोग को घटा दिया है या जिनके परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादक को अपने स्वयं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तैयार की गई परियोजनाओं को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा है । दूसरी ओर किसी घरेलू उत्पादक को बाहर रखना प्रथम दृष्टया उचित नहीं है यदि पाटन में उसकी भागीदारी आत्मरक्षा का एक कार्य था । अतः ऐसे घरेलू उत्पादक को संगत घरेलू उद्योग को परिभाषित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

179. ऐसे घरेलू उत्पादकों, जो पाटित उत्पाद का आयात करते हैं या जिनका संबंधित निर्यातक पाटित उत्पाद का निर्यात करता है या जिनका संबंधित उत्पादक पाटित आयात का उत्पाद करता है और जो पाटन की प्रक्रिया से अनुचित रूप से लाभान्वित नहीं होते हैं । यदि ऐसे आयात उनकी बिक्रियों या बाजार के आकार के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व नहीं करते हों। वस्तुतः ऐसे घरेलू उत्पादकों को बाजार में अन्य आपूर्तिकर्ताओं से प्रतिस्पर्धा के कारण इसका कोई लाभ नहीं मिलता । जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस बात का निर्णय लेने के लिए कि क्या किसी घरेलू उत्पादक को बाहर रखा जाए, बनाया गया एक अन्य तरीका यह है कि क्या घरेलू उत्पादक कुछ पाटित आयातों के द्वारा अपने घरेलू उत्पादन की पूर्ति कर रहा है अथवा क्या वह प्राथमिक रूप से सीमित उत्पादन करने वाला कोई आयातक है । दूसरे मामले में ऐसी कंपनी को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए । एक अन्य तत्व जिस पर विचार किया जा सकता है, यह है कि क्या जांचाधीन घरेलू उत्पादक को आयात के देश में उत्पादन के लिए वचनबद्ध कंपनी के रूप में समझा जा सकता है अथवा नहीं ।

180. मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. के घरेलू उद्योग होने के दावे पर प्रश्न उठाते हुए प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकार ने यह तर्क दिया है कि मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. को घरेलू उद्योग बनने का हकदार नहीं माना जाना चाहिए ।

181. मामले के विधिक प्रावधानों और तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्य मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. को घरेलू उद्योग नहीं माने जाने को न्यायोचित नहीं ठहराते हैं । प्रतिवादी पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा संदर्भित मामले वर्तमान स्थितियों से संगत नहीं हैं तथापि, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा अपनाए गए मामले उन स्थितियों तक सीमित नहीं हैं जहां आवेदक कंपनी

(कंपनियों) ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया हो । आवेदक ने कुछ निर्णयों का हवाला दिया है जिनमें एक घरेलू उत्पादक संबद्ध अथवा असंबद्ध देश के निर्यातक से संबंधित था और जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा यह पाया गया था कि ऐसे घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग की श्रेणी में शामिल किया जाना न्यायसंगत है । प्रतिवादी पक्षकारों का यह तर्क कि घरेलू उद्योग को साधारणतया बाहर रखा जाए, न तो कानून के सामान्य पठन से सिद्ध होता है या न ही इस विषय संबंधी न्यायशास्त्र से सिद्ध होता है ।

182. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को परिभाषित करने वाले संगत प्रावधान प्राधिकारी को किसी संबंधित घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग का हिस्सा मानने अथवा नहीं मानने का विवेक प्रदान करते हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां आवेदक निर्यातक देश में किसी उत्पादक से संबंधित है, वहां ऐसे संबंध के तथ्य मात्र से उस उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे और कार्यक्षेत्र से स्वतः बाहर रखा जाना संभव नहीं है । वस्तुतः ऐसे मामलों में प्राधिकारी को स्व-विवेक मामला दर मामला आधार पर आगे जांच करने के लिए और इस बात की जांच करने के लिए प्रदान किया गया है कि क्या ऐसे संबंधित उत्पादक को घरेलू उद्योग में शामिल किए जाने का पात्र अथवा अपात्र समझा जाए । स्वयं सिद्ध ढंग से इस मामले के तथ्यों पर संबंध के प्रभाव पर इस प्रयोजनार्थ ध्यान देने की जरूरत है । इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर विचार किया है :

(क) क्या संबंधित पक्षकारों का व्यवहार असंबंधित पक्षकारों की तुलना में अलग और भिन्न है ।

(ख) क्या यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य है कि ऐसे संबंधित उत्पादक ने भारतीय बाजार में पाटन शुरू किया अथवा उसे तेज किया ।

(ग) क्या संबंधित घरेलू उत्पादक पाटन के प्रभाव से सुरक्षित रहा या उससे अनुचित ढंग से लाभान्वित हुआ ।

(घ) क्या संबंधित घरेलू उत्पादक ने भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने का प्रयास किया ।

(ड) क्या यह एक स्वयं आरोपित क्षति का मामला है ?

183. एक संबंधित पक्षकार होने के अलावा, वर्तमान मामले में संबंधित पक्षकार द्वारा किए गए निर्यातों यदि कोई हो, के प्रभाव का मूल्यांकन करना भी संगत है कि क्या ऐसे संबंधित पक्षकार ने इस अवधि के दौरान भारत को उत्पाद का निर्यात किया था । यदि हां तो क्षति के दावों पर उनका प्रभाव क्या है ? यदि नहीं, तो क्या ऐसा कोई अन्य आधार है जो अब भी बाहर रखे जाने को न्यायोचित ठहराता हो । यदि संबंधित पक्षकार ने भी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है तो निम्नलिखित की भी जांच किया जाना अपेक्षित है ।

- ऐसे संबंधित पक्षकार द्वारा किए गए निर्यात की मात्रा
- संबंधित पक्षकार द्वारा किए गए ऐसे निर्यातों का प्रयोजन
- क्या यह बात दर्शाने वाला कोई साक्ष्य है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबंधित पक्षकार द्वारा ऐसे निर्यातों के कारण हुई थी ।
- क्या संबंधित घरेलू उत्पादक का सामान्य ध्यान संबद्ध वस्तु के उत्पादन पर था अथवा सामान्य ध्यान धीरे-धीरे अथवा निरंतर आयातों की ओर स्थानांतरित हुआ है ।
- क्या ऐसे संबंधित पक्षकार द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा इतनी रही थी कि संबंधित निर्यातक धीरे-धीरे अथवा निरंतर असंबंधित घरेलू उत्पादकों के बाजार के प्रतिस्थापित कर रहा था ।
- कोई अन्य कारक जिसे कार्यवाही की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संभवतः प्राधिकारी के ध्यान में लाया गया हो ।

184. पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि उन्हें पी टी इंडो भारत रेयान द्वारा पाटन का सहारा लेने के लिए बाध्य किया गया है अर्थात् उन्होंने पाटन के रूप में अनुचित प्रतिस्पर्धा का सहारा इसलिए लिया क्योंकि अन्य पक्षकार पाटन कर रहा था । तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन के कारण कानून के अंतर्गत पूर्णतः असंगत हैं और केवल पाटन का तथ्य संगत है । पाटनरोधी कार्रवाई में केवल पाटन की मौजूदगी और मात्रा संगत हैं और ऐसा पाटन किए जाने के कारण कोई महत्व नहीं रखते हैं । यदि एक या उससे अधिक विदेशी उत्पादकों (एक ही या भिन्न-भिन्न देशों के) को एक या उससे अधिक अन्य विदेशी उत्पादकों द्वारा पाटन का सहारा लेने के लिए बाध्य किया गया हो, तो कानून इसकी अनदेखी नहीं करता है । इसके अलावा, इस मामले के तथ्यों के आधार पर इस आरोप को गलत पाया गया था क्योंकि पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस ने पी टी इंडो भारत रेयान द्वारा निर्याति पोतलदानों से काफी पहले संबद्ध वस्तु का निर्यात किया था । इसके अलावा, पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा पी टी इंडो भारत द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा से काफी अधिक

रही है । पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस को उसके घरेलू बाजार में भी संबंधित उत्पाद की घाटे पर बिक्री करते हुए पाया गया था और इसलिए यह आरोप कि उन्होंने अन्य पक्षकार द्वारा पाटन किए जाने के कारण पाटन किया है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है और इसमें कोई दम नहीं है ।

185. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि भारत में "एकमात्र एकाधिकारी उत्पादक" द्वारा पाटनरोधी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि "पाटन" एक अनुचित व्यापार प्रक्रिया है और यदि इससे घरेलू उद्योग को क्षति साबित होती है तो इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, चाहे केवल एक घरेलू उत्पादक ही हो; क्योंकि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का समाधान करना ही है । शुल्क लगाए जाने से भारतीय बाजार में अपाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करने के विदेशी उत्पादकों के अधिकार प्रतिबंधित नहीं होंगे । प्रतिस्पर्धारोधी व्यवहार के निवारण की मांग इसके निवारण हेतु उचित कार्रवाई चलाकर ऐसे व्यवहार से प्रभावित किसी कंपनी द्वारा की जा सकती है ।

186. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि न तो भारतीय कानून और न ही डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार में यह व्यवस्था है कि प्राधिकारी को केवल इसलिए किसी घरेलू उत्पादक को अयोग्य मान लेना चाहिए यदि वह विदेशी उत्पादक से संबंधित हो, यदि ऐसा संबंधित विदेशी उत्पादक जांच में भाग लेता हो और उसके निर्यातों के संबंध में सकारात्मक पाटन मार्जिन सिद्ध हुआ हो । इसके अलावा, प्रत्येक ज्ञात निर्यातक के संबंध में अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाना अपेक्षित है और यह अधिनियम अथवा पाटनरोधी नियमावली इस संबंध में किसी संबंधित और असंबंधित निर्यातक के बीच कोई भेद नहीं करती है । जहां तक नियम 2(ख) के अंतर्गत मान्यता संबंधी भ्रम का संबंध है, उसमें भी ऐसे मामले में स्पष्ट रूप से प्राधिकारी को स्वविवेक प्रदान किया गया था । तथापि, ऐसे स्व-विवेक का प्रयोग निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ ढंग से किया जाना चाहिए ।

187. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क देते समय गलती की है कि आयातों की मात्रा पर आधारित मापदंड कोई तर्कसंगत मापदंड नहीं है । चूंकि वर्तमान मुद्दा किसी संबंधित निर्यातक द्वारा किए गए "निर्यात" का है, इसलिए प्राधिकारी मानते हैं कि आयातों की मात्रा वस्तुतः संबंधित घरेलू उत्पादक को बाहर रखने संबंधी निर्णय लेने के लिए एक प्रमुख कारक है । इसके अलावा यह अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का आकलन करने में एक कारक होगा कि क्या दावा की गई क्षति स्वआरोपित क्षति है अन्यथा कुछ और है ।

188. वर्तमान मामले में मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. के पास इंडोनेशिया और चीन जन.गण में संबद्ध कंपनियां हैं जो संबंधित उत्पाद का उत्पादन और बिक्र करती हैं, जिनके नाम हैं बिरला

जिंगवाई फाइबर्स कं. लि., चीन जन.गण. और पी टी इंडो भारत रेयान, इंडोनेशिया है। पी टी इंडो भारत रेयान-इंडोनेशिया ने भेजी गई प्रश्नावली का अपना विस्तृत उत्तर भी दिया है जिसका सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया गया है और इन जांच परिणामों के संगत खंडों में उचित ढंग से उन पर विचार किया गया है। पी टी इंडो भारत रेयान मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. की सहायक कंपनी नहीं है। यह नोट किया जाता है कि मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. की पी टी इंडो भारत रेयान इंडोनेशिया में केवल ***% की शेयरधारिता और बिरला जिंगवाई फाइबर्स कं. लि., चीन जन.गण. में ***% की शेयरधारिता है। मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और उसने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण क्षति का दावा किया है।

189. इस बात पर जोर दिया जाना महत्वपूर्ण है कि एक संबंधित पक्षकार होने के बावजूद प्राधिकारी की जानकारी में उनके व्यवहार में ऐसा कोई अंतर नहीं आया है जिनसे ऐसा लगता हो कि वह कोई संबंधित पक्षकार है। मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. द्वारा प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने या वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क का आवेदन करके कोई अन्य अनावश्यक लाभ लेने के संबंध में प्राधिकारी को कोई साक्ष्य नहीं मिला है।

190. इसके अलावा, पी टी इंडो भारत रेयान द्वारा की गई निर्यातों की मात्रा काफी कम है और छिन्न-भिन्न प्रकृति की है; ये आयात शुल्क छूट श्रेणी के अंतर्गत असंबंधित आयातकों के द्वारा किए गए हैं। मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. ने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां अधिकांश निर्यात असंबंधित इंडोनेशियाई निर्यातक द्वारा किए गए हैं और जहां पी टी इंडो भारत रेयान और भारतीय आयातक/उपभोक्ता के बीच केवल 3 बिक्री संबंधी सौदे (जांच अवधि के दौरान) हुए हैं, और वह भी शुल्क छूट योजना के अंतर्गत सामग्री के आयात के लिए, तो यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि इन पक्षकारों ने अन्य प्रतिस्पर्धियों को भारत से बाहर निकालने के लिए संधि की थी। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि पी टी इंडो भारत रेयान से किए गए आयात शुल्क छूट योजना के अंतर्गत किए गए हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया है कि इन दोनों पक्षकारों ने कोई मिलीभगत की है। इसके अलावा, यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि असंबंधित इंडोनेशियाई उत्पादक को पी टी इंडो भारत रेयान द्वारा उद्धरित कथित कम कीमतों के कारण कीमतों को कम करना पड़ा था। पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ लगाये गये इस आरोप कि पी टी इंडो भारत रेयान-इंडोनेशिया द्वारा पाटन उत्पन्न और शुरू किया गया है की इन दोनों कंपनियों के सत्यापन के दौरान जांच की गई थी और इसे निराधार और गलत पाया गया था। यह विचार इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तु के आयातों के विश्लेषण द्वारा और भी सुदृढ़ हो जाता है, जैसा कि निम्नांकित तालिका से देखा जा सकता है।

	आयात मी.ट. में		कुल आयात	का हिस्सा	का हिस्सा
	पी इंडो भारत रेयान एक्सपोर्ट्स	पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस एक्सपोर्ट्स	इंडोनेशिया से	पी इंडो भारत रेयान	पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस
2006	-	***	***	0.00%	100.00%
2007	***	***	***	5.51%	94.49%
2008 जन.-जून	-	***	***	0.00%	100.00%
जांच अवधि	***	***	***	2.29%	97.71%

191. प्राधिकारी ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में इंडोनेशिया के हिस्से की जांच भी की है। यह पाया गया था कि यद्यपि, वर्ष 2006-07 में इंडोनेशिया से हुए आयात भारत में हुए कुल आयातों का केवल लगभग 38% रहे थे, परंतु 2007-08 में ये बढ़कर 74% हो गए, अप्रैल-जून, 2008 में 93% और जांच अवधि के दौरान 84% हो गए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इंडोनेशियाई आयातों के हिस्से में भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों की दृष्टि से निरंतर वृद्धि हुई है। इसके अलावा पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस का हिस्सा इंडोनेशिया से इन आयातों में काफी अधिक रहा था जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है :

	भारत में कुल आयात	इंडोनेशिया से आयात	सकल आयातों में इंडोनेशिया का हिस्सा	पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस द्वारा निर्यात	कुल आयातों में पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस का हिस्सा
2006-07	6,774	2,554	37.70%	***	29.02%
2007-08	6,842	5,069	74.09%	***	71.67%
अप्रैल-जून 08	1,890	1,757	92.95%	***	92.95%

जांच अवधि	6,329	5,305	83.82%	***	81.90%
-----------	-------	-------	--------	-----	--------

192. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संदर्भित डब्ल्यू टी ओ के निर्णय के संबंध में प्राधिकारी ने नोट किया है कि उस मामले का मुद्दा वर्तमान मामले में संगत नहीं है। उस मामले में मुद्दा यह था कि क्या संबद्ध पक्षकारों के बीच हुए सौदों को सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ व्यापार के सामान्य प्रक्रिया में हुए सौदे माना जा सकता है। इस प्रकार यद्यपि, उस मामले में मुद्दा सामान्य मूल्य और संबंधित पक्षकारों के बीच हुए सौदों के संदर्भ में उठाया गया था; वर्तमान मामले में विचाराधीन मुद्दा यह है कि क्या मै. ग्रासिक इंडस्ट्रीज लि. को संबद्ध देशों में उनकी संबद्ध कंपनियों के साथ उनके संबंधों के मद्देनजर नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग माने जाने हेतु अपात्र समझा जाना चाहिए। यह भी नोट करना संगत है कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में भी; संबंधित पक्षकारों के बीच सभी सौदों को विश्वसनीय अथवा अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार उनकी जांच प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर की जा सकती है। यद्यपि वर्तमान मामले में सौदे ऐसे संबंधित पक्षकारों के बीच भी नहीं हुए हैं अपितु पी टी इंडो भारत और असंबंधित भारतीय उपभोक्ताओं के बीच हुए हैं।

193. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग और पी टी इंडो भारत रेयान का उद्देश्य भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को अवरुद्ध करना है। तथापि, वर्तमान मामले में सिद्ध सकारात्मक पाटन मार्जिन को देखते हुए यह स्पष्ट है कि असंबंधित इंडोनेशियाई उत्पादक ने पाटन नहीं किया है, जिसे उकसाया गया नहीं पाया गया है और वह पी टी इंडो भारत रेयान द्वारा की गई 3 छोटी पोतलदानों के कारण ही सिद्ध नहीं होता है। पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस द्वारा पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु का भारी मात्रा में निर्यात किया गया है। जांच करने पर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को "क्षति" हुई है जैसा कि इन जांच परिणामों के संगत खंडों में देखा जा सकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि छोटे और छिटपुट निर्यात इस क्षति के खास कारक नहीं रहे हैं। इसके अलावा, मै. ग्रासिक इंडस्ट्रीज लि. का मुख्य ध्यान संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिक्री करने पर रहा है। इस प्रकार यह स्व आरोपित क्षति का मामला प्रतीत नहीं होता है। प्राधिकारी ने ऐसे पाटनरोधी मामलों को भी नोट किया है जिनमें यद्यपि आयात संबंधित घरेलू उत्पादकों द्वारा अपनी संबद्ध कंपनियों से किए गए थे, तब भी जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा उन्हें घरेलू उद्योग का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के दायरे और कार्यक्षेत्र से मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज को बाहर रखे जाने का कोई न्यायसंगत कारण दिखाई नहीं दिया है।

194. अतः प्राधिकारी इस बात को दोहराते हैं कि आवेदक को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा जाना अपेक्षित नहीं है । इस प्रकार, एसोसिएशन ऑफ मेनमेड फाइबर इंडस्ट्रीज आफ इंडिया द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से आवेदन दायर किया गया है । आवेदक के इस दावे कि भारत में समान वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है, पर किसी हितबद्ध पक्षकार ने प्रश्न नहीं उठाया है । रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. का उत्पादन संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है । मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. का उत्पादन भारती उत्पादन का 50% से अधिक है ।

195. इस प्रकार प्राधिकारी अपने इस विचार को दोहराते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. को घरेलू उद्योग मानना उचित है । तदनुसार प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है ।

196. जहां तक इस मुद्दे का संबंध है कि याचिकाकर्ता ने प्रश्नों के निर्धारित सैटों से महत्वपूर्ण प्रश्न जानबूझकर हटा दिया है ताकि इंडोनेशिया से संबंध के स्वरूप का बचाव किया जा सके ।

जांच अवधि

197. जहां तक इस मामले में अपनाई गई 6 माह की जांच अवधि का संबंध है, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नोट किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार अथवा पाटनरोधी नियमावली दोनों में जांच की निश्चित अवधि के बारे में कोई निर्धारण नहीं है । जांच प्राधिकारियों ने 6 माह से लेकर 18 माह तक जांच अवधि को अपनाया है । जहां तक सी ए डी पी की सिफारिशों का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ये केवल सिफारिशें हैं और इन सिफारिशों में भी यह स्वीकार किया गया है कि जांच अवधि 12 माह की अवधि से कम हो सकती है । 6 माह की जांच अवधि अपनाने को माननीय सेस्टेट द्वारा भी बरचाऊ लेबरोटरीज लि. बनाम वित्त मंत्रालय के मामले में बरकरार रखा गया है ।

198. प्राधिकारी ने पहले ही दर्ज किया है कि वर्तमान मामले में जांच अवधि का समुचित चयन मामले के तथ्यों को देखते हुए किया गया था जिसमें इस विषय पर नवीनतम उपलब्ध आंकड़े भी शामिल हैं । इसके अलावा, विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने भी यह स्वीकार किया है कि जांच अवधि के रूप में 6 माह की अवधि निर्धारित करना अवैध नहीं है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कहना गलत है कि डी जी ए डी की परंपरा जांच अवधि के रूप में 12 माह की अवधि को लेने की रही है, वस्तुतः प्राधिकारी ने 6 माह की अवधि से लेकर 18 माह की अवधि को जांच अवधि के रूप में लिया है ।

199. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने कई मामलों में 6 माह के रूप में जांच अवधि को लिया है । जैसा कि उल्लेख किया गया है, हितबद्ध पक्षकार भी इस बात से सहमत हैं कि जांच अवधि

के रूप में 6 माह पर विचार करना अवैध नहीं है। सी ए डी पी दिशानिर्देशों को अनिवार्य निर्धारण के रूप में नहीं माना जा सकता। बहरहाल ये दिशा-निर्देश सभी स्थितियों में लागू नहीं हो सकते भले ही मामले के तथ्य कुछ भी हों। वित्तीय रिपोर्टिंग जैसे तथ्यों पर ही विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये केवल एक अवधि को जांच अवधि मानने अर्थात् अप्रैल-मार्च को मानने पर लागू होंगे। जांच अवधि के रूप में 6 माह की अवधि मानने के कारणों के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह प्रारंभिक जांच परिणामों में उल्लिखित है। इस तर्क के संबंध में कि 6 माह की जांच अवधि में मंदी की 4 माह की अवधि शामिल है, प्राधिकारी का मानना है कि मंदी के तथ्य का सामान्य मूल्य में कम निर्यात मूल्य के समान में इच्छानुसार तर्क नहीं दिया जा सकता क्योंकि मंदी का तथ्य सामान्य मूल्य के लिए भी समान रूप से लागू होगा। तथापि, यह नोट किया गया कि इंडोनेशिया में संबंधित समान के घरेलू मूल्य भारत को निर्यात किए गए मूल्य से वस्तुतः अधिक थे। अतः वैश्विक बाजार में मंदी को जांच अवधि निर्धारित करने में विचार करने हेतु औचित्यपरक कारण नहीं माना जा सकता।

200. जहां तक मांग में कमी का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में कमी से घरेलू उद्योग तथा आयात समान रूप से प्रभावित हुआ होगा। तथापि, ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि मांग में कमी आई हो लेकिन संबंधित देशों से निर्यात की मात्रा में वृद्धि हुई हो। प्राधिकारी का यह मानना है कि 6 माह की जांच अवधि आयात मूल्यों में काफी गिरावट तथा घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण ह्रास को देखते हुए न्यायोचित थी।

201. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद बांस के फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर है। विचाराधीन उत्पाद के लिए सीमाशुल्क वर्गीकरण में बांस के फाइबर को अलग नहीं रखा गया है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त सूचना पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें विचाराधीन उत्पाद से भिन्न उत्पाद के आयात शामिल हो सकते हैं। घरेलू उद्योग ने टिप्स द्वारा प्रदत्त सूचना प्रस्तुत की है जिसे जांच की शुरुआत के समय स्वीकार किया गया था।

202. घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 5504 9090 के अंतर्गत भारी मात्रा में आयात होने की सूचना दी गई है। प्राधिकारी ने सीमाशुल्क वर्गीकरण सं. 55041000 तथा 55049090 के लिए आयात की सूचना हेतु डीजीसीआईएंडएस के कार्यालय से अनुरोध किया था जिसे प्राप्त कर उसका विश्लेषण किया गया था। तदनुसार संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा का निर्धारण किया गया है। आवेदक द्वारा टिप्स के आंकड़ों और डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार दावा किए गए आयातों की तुलना से निम्नानुसार पता चलता है:

	टिप्स आंकड़े		डी जी सी आई एंड एस आंकड़े	
	मात्रा किग्रा.	रू./किग्रा.	मात्रा किग्रा.	रू./किग्रा.
चीन जन.गण.	907252	96.03	1023971	94.13
इंडोनेशिया	4533741	98.44	4689364	98.47

203. रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री से यह देखा गया है कि संबद्ध देशों को छोड़कर किसी अन्य देश से संबद्ध वस्तु का कोई अयात नहीं हुआ है। डी जी सी आई एंड एस और टिप्स के अनुसार मात्रा एवं कीमत मोटे तौर पर तुलनीय है।

204. जहां तक चीन जन.गण. के बारे में सामान्य मूल्य के निर्धारण का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा जारी जांच शुरुआत संबंधी सूचना के बाद चीन के किसी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन नहीं किया है। जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में ही प्राधिकारी ने यह संकेत दिया था कि आवेदक ने उचित प्रतिनिधि देश के रूप में इंडोनेशिया का सुझाव दिया है। हितबद्ध पार्टियों ने इस संबंध में अनुरोध करने का निवेदन किया था। तथापि, चीन जन.गण. के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने उत्तर नहीं दिया है और इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है। अतः प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या इंडोनेशिया को चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन से एक उचित प्रतिनिधि बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने इंडोनेशिया के विकास के स्तर और कथित सामानों को ध्यान में रखा। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी नोट किया कि ये इंडोनेशिया में कथित सामान के दो प्रमुख उत्पादक हैं और संयोग से दोनों ने ही इस जांच में सहयोग किया है। साथ ही यह भी नोट किया गया है कि इन उत्पादकों द्वारा इंडोनेशिया के घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण घरेलू बिक्री की गई है। अतः प्राधिकारी इस बात पर विचार करते हैं कि इंडोनेशिया को इस मामले विशेष में एक उचित प्रतिनिधि देश के रूप में मानना उचित होगा। अतः इंडोनेशिया को चीन जन.गण. के लिए एक उचित प्रतिनिधि देश मानकर प्राधिकारी ने इंडोनेशिया के औसतन सामान्य मूल्य को महत्व दिया है जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के संगत उपबंधों के अनुसार चीन जन.गण. के लिए निर्धारित है।

205. प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है जिनमें घरेलू उद्योग का यह तर्क भी शामिल है कि उन्होंने तथाकथित "माने गए निर्यातों" के लिए विदेश व्यापार नीति

के अंतर्गत कोई लाभ नहीं लिया है । अतः ऐसी बिक्रियों को घरेलू बिक्री माना जाना चाहिए । तथापि, इन दावों और प्रतिदावों की प्रति जांच आगे की जाने वाली जांच और मौके पर सत्यापन की कार्यवाही के दौरान की जाएगी ।

206. पाटनरोधी नियमों के अनुबंध II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और ; (ख) पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातकों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।"

207. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) निम्नानुसार उल्लेख है :

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट, सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा ।"

208. प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों और दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की तथ्यपरक जांच की है । चूंकि वर्तमान जांच में शामिल देश एक से अधिक हैं, इसलिए प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या संचयी निर्धारण हेतु शर्तों की प्रथम दृष्टया पूर्ति होती है या नहीं । प्राधिकारी ने यह पाया है कि :

- i. प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन निर्धारित सीमाओं से अधिक है;
- ii. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है;
- iii. आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से हुए निर्यात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं । ऐसा इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि

घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद निम्नलिखित आधार पर समान वस्तुएं हैं :- प्रत्येक संबद्ध देश से हुए आयात काफी अधिक रहे हैं; भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु में प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा है; सामान्य पार्टियां आयातित सामग्री और घरेलू सामग्री का उपयोग कर रही हैं; भारतीय उत्पादक/ग्राहक घरेलू सामग्री तथा आयातित सामग्री का उपयोग कर रहे हैं ; संबद्ध देशों के निर्यातकों और आवेदक ने एक ही श्रेणी के ग्राहकों को एक समान अवधि में एक समान उत्पाद की बिक्री की है आदि ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी निर्धारण करना उचित होगा ।

मांग एवं बाजार हिस्सा:-

209. देश में उत्पाद की मांग का निर्धारण घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से हुए आयातों की मात्रा के रूप में किया गया है ।

मी. ट. में

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जून 08	जुलाई-दिसं. 08 (जांच अवधि)	अप्रैल-जून 08	जांच अवधि वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग की बिक्री	223,147	226,178	237,395	49,784	100,925	199,136	201,850
सूचीबद्ध	100	101	106	89	90	8	90
भारत में आयात	198	6,774	6,842	1,890	6,329	7,561	12,658
सूचीबद्ध	100	3,421	3,456	3,818	6,392	3,818	6,392
मांग	223,345	232,952	244,237	51,674	107,254	206,697	214,508
सूचीबद्ध	100	104	109	93	96	9	96
मांग में बाजार हिस्सा							
संबद्ध देश	0.06%	1.34%	2.78%	3.66%	5.90%	3.66%	5.90%
अन्य देश	0.03%	1.57%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

घरेलू उद्योग	99.91%	97.09%	97.20%	96.34%	94.10%	96.34%	94.10%
--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

- i. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में वर्ष 2007-08 तक वृद्धि हो रही थी । तथापि, उसमें अप्रैल-जून, 08 की अवधि और जांच अवधि के दौरान गिरावट (आनुपातिक आधार पर) आई है ।
- ii. यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट देखी गई है, तथापि मात्रा में पर्याप्त वृद्धि (आनुपातिक आधार पर हुई है) । कुछेक हितबद्ध पार्टियों ने यह तर्क दिया है कि भारत में उत्पाद की मांग में गिरावट आई है और इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, आरोपित आयातों के कारण नहीं हुई है । तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मांग में गिरावट के प्रभाव के परिणामस्वरूप आयातों में (आनुपातिक आधार पर) गिरावट आई होगी ।
- iii. विरोधी पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि भारत में उत्पाद की मांग में गिरावट आई है और इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति यदि कोई हुई हो, तो वह आरोपित आयातों के कारण हुई है । तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में गिरावट के प्रभाव के कारण आयातों में गिरावट के साथ-साथ उनमें आनुपातिक आधार पर गिरावट आई है । परंतु यह देखा जाता है कि संबद्ध वस्तु के पाटित कीमतों पर आयात बढ़े हैं ।
- iv. जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पाटित आयातों का बाजार हिस्सा काफी अधिक रहा है ।

आयात की मात्रा और बाजार हिस्सा

210. संबद्ध वस्तु के आयातों और बाजार हिस्सों का ब्योरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जून 08	जुलाई- दिसं. 08 (जांच अवधि)	अप्रैल-जून 08	जांच अवधि वार्षिकीकृत
संबद्ध देशों से आयात	125	3,121	6,779	1,890	6,329	7,561	12,658
अन्य देशों से आयात	73	3,653	62	-	-	-	-

आयात							
कुल आयात	198	6,774	6,841	1,890	6,329	7,561	12,658
निम्न के संबंध में पाटित आयात -							
- भारतीय उत्पादन	0.05%	1.26%	2.44%	3.27%	10.05%	3.27%	10.05%
- भारतीय खपत	0.06%	1.34%	2.78%	3.66%	5.90%	3.66%	5.90%
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	99.91%	97.09%	97.20%	96.34%	94.10%	96.34%	94.10%

यह देखा गया है कि:-

- i. आयातों में समग्र रूप में पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित हुई है ।
- ii. आयातों में भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है ।
- iii. जहां संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, वहीं घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है ।
- iv. इस तर्क के संबंध में कि बाजार हिस्से में गिरावट विशेष रूप से बृहत आर्थिक समस्याओं को देखते हुए कोई खास नहीं है, प्राधिकारी मानते हैं कि उस मात्रा के संबंध में कोई विधिक निर्धारण नहीं है जहां तक संकेतक इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए विकृति दर्शाएं कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अथवा क्षति नहीं हुई है । विधिक प्रावधानों के अनुसार न तो पाटनरोधी नियमावली और न ही डब्ल्यू टी ओ के पाटनरोधी करार में मांग में बाजार हिस्से के आधार पर कोई निर्धारित न्यूनतम सीमा संबंधी मापदंड है । कुछ प्राधिकारी आयातों के 1% बाजार हिस्से को अधिक हिस्सा मानते हैं । यदि किसी देश विशेष से आयातों का 1% बाजार हिस्सा "काफी अधिक" माना जा सकता है तो बाजार हिस्से में 2.3% की गिरावट को कम नहीं माना जा सकता है ।
- v. तथापि, बृहत आर्थिक समस्याओं (हितबद्ध पक्षकार स्पष्ट रूप से वैश्विक मंदी का हवाला दे रहे हैं) के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे कारकों की मौजूदगी पाटन को उचित नहीं ठहराती है और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति का समाधान करने का निवारण नहीं करती है । ऐसी स्थिति में जहां उत्पाद की घरेलू मांग में गिरावट आई है, वहां आयातों में वृद्धि से क्षति में वृद्धि ही होगी ।

आयातों का कीमत प्रभाव

211. निम्नलिखित तालिका से यह देखा जाता है कि कीमत में मामूली ऋणात्मक कटौती हुई है ।

रु./किग्रा.	चीन जन.गण.	इंडोनेशिया
सीआईएफ निर्यात कीमत	94.13	95.39
पहुंच कीमत	99.03	100.35
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	98.72	98.72
कीमत कटौती	(0.31)	(0.31)
कीमत कटौती % रेंज	-1% से 1%	-2% से 2%

212. तथापि, घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि वह विचाराधीन उत्पाद के पहुंच मूल्य के अनुसार संबद्ध वस्तु की कीमत तय करता है और यह तुलना निवल बिक्री कीमत में उस कारोबार छूट को शामिल करने के बाद की जानी चाहिए जो वह अपने ग्राहकों को प्रदान करता है, जो कि प्राप्त कारोबार के लिए प्रत्यक्ष प्रासंगिक होता है ; और यदि इस कारोबारी छूट को औसत बिक्री कीमत में शामिल किया जाएगा तो कीमत कटौती अत्यधिक सकारात्मक होगी ।

213. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव प्रतिकूल रहा है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है :-

प्राधिकारी ने उत्पादन लागत तथा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ-साथ आयातों की पहुंच कीमत की आगे तुलना की है जो निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गयी है :

रु /किग्रा.	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जून 08	जलाई-दिसं. 08 (जांच अवधि)
उत्पादन की लागत	60.54	64.28	71.09	90.99	88.677
सूचीबद्ध	100	106	117	150	146
बिक्री कीमत	72.94	84.89	102.62	108.60	98.72
सूचीबद्ध	100	116	141	149	135
पहुंच कीमत चीन जन.गण.	138.02	86.59	112.66	110.79	99.03
सूचीबद्ध	100	63	82	80	72
पहुंच कीमत इंडोनेशिया	77.28	87.58	99.47	107.78	100.35
सूचीबद्ध	100	113	129	139	130
संबद्ध देशों से औसत पहुंच कीमत	77.77	87.40	102.80	108.07	100.14
सूचीबद्ध	100.00	112.39	132.19	138.97	128.77

214 यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत आधार वर्ष में 100 से बढ़कर जांच अवधि में 135 हो गई है। तथापि, इसकी उत्पादन लागत आधार वर्ष में 100 से बढ़कर जांच अवधि में 146 हो गई है। स्पष्टतः घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी बिक्री कीमत में बढ़ोत्तरी नहीं कर सका; जिससे यह पता चलता है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में अत्यधिक ह्रास हो रहा था।

215 प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की कम कीमत पर बिक्री की भी जांच की है और यह नोट किया है कि संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से काफी कम रहा है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है।

रु./किग्रा.	एनआईपी (ग्रे फाइबर)	पहुंच कीमत	कम कीमत पर बिक्री	कम कीमत पर बिक्री % रेंज
चीन जन.गण.	107.97	99.03	8.94	5 से 15
इंडोनेशिया	107.97	100.35	7.62	5 से 15
संबद्ध देश	107.97	100.14	7.83	5 से 15

स्पष्टतः घरेलू उद्योग पाटित आयातकों की मौजूदगी के कारण क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर संबद्ध वस्तु की बिक्री करने के लिए बाध्य हुआ है ।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

216. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन उत्पादों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री में वास्तविक एवं संभावित गिरावट, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में गिरावट; घरेलू कीमत, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक; नकद प्रभाव, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित ऋणात्मक प्रभावों सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों की तथ्यपरक और निष्पक्ष जांच शामिल होनी चाहिए । घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है । घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है :-

बिक्री मात्रा

217. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा निम्नलिखित तालिका में दी गई है :-

मी.ट. में	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जून 08	जुलाई- दिसं. 08 (जांच अवधि)	अप्रैल-जून 08	जांच अवधि वार्षिकीकृत
बिक्री मात्रा	223,147	226,178	237,395	49,784	100,925	199,136	201,850
प्रवृत्ति सूचीबद्ध	100	101	106	89	90	89	90

218 यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री में वर्ष 2007-08 तक बिक्री हुई थी और उसके बाद अप्रैल-जून, 08 की अवधि तथा जांच अवधि में गिरावट आई थी। यद्यपि, मांग में गिरावट आई है तथापि, मांग में गिरावट आने के कारण आयातों में आनुपातिक रूप से गिरावट नहीं आई है, अपितु उनमें वास्तविक वृद्धि हुई है।

219. इस तर्क के संबंध में कि बिक्री मात्राओं में गिरावट उपभोक्ताओं के खरीद कम करने और वस्त्र उत्पादों के निर्यातों में तेजी से गिरावट के कारण आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति जहां (क) उपभोक्ता घरेलू स्रोत से खरीद को सीमित कर रहे हैं परंतु आयातों के जरिए खरीद बढ़ा रहे हैं; और (ख) आयात कीमतों के कारण घरेलू कीमतों में गिरावट आई है। वस्तुतः यह सिद्ध करती है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है।

उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग

220 उत्पादन, क्षमता एवं क्षमता उपयोग से संबंधित सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

मी.ट. में	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जून 08	जुलाई- दिसं. 08 (जांच अवधि)	अप्रैल-जून 08 वार्षिकीकृत	जांच अवधि वार्षिकीकृत
क्षमता	253,450	266,450	266,450	82,355	166,520	329,420	333,040
सूचीबद्ध	100	105	105	130	131	130	131
उत्पादन	228,981	246,832	277,818	57,829	114,314	231,317	228,628
सूचीबद्ध	100	108	121	101	100	101	100
क्षमता उपयोग	90.35%	92.64%	104.27%	70.22%	68.65%	70.22%	68.65%
सूचीबद्ध	100	103	115	78	76	78	76

221. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वर्ष 2007-08 तक सुधार हो रहा था जिसमें अप्रैल-जून, 08 की अवधि और जांच अवधि में गिरावट आई। कुछेक हितबद्ध पार्टियों ने यह आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग ने मार्च, 2008 में अपनी क्षमता में वृद्धि की थी और किसी नई क्षमता द्वारा पुरानी क्षमता के बराबर कार्य निष्पादन नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी ने क्षमता के उसी स्तर पर जो विस्तार से पूर्व विद्यमान था, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच की है और यह नोट किया है कि क्षमता के एक समान स्तर होने के बाद भी क्षमता उपयोग वर्ष 2007-08 में 104.27% से घटकर जांच अवधि में 85.8% हो गया।

लाभ/हानि, निवेश पर आय और नकद लाभ

222. लाभ/हानि, निवेश पर आय और नकद लाभ से संबंधित सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है:-

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जून 08	जुलाई- दिसं. 08 (जांच अवधि)	अप्रैल-जून 08 वार्षिकीकृत	जांच अवधि वार्षिकीकृत
करपूर्व लाभ लाख रुपए	27,670	46,615	7485	8767	10143	35068	20286
सूचीबद्ध	100	168	27	127	73	127	73
करपूर्व लाभ रु. किग्रा	12	21	32	18	10	18	10
सूचीबद्ध	100	166	25	142	81	142	81
पीबीआईटी लाख रुपए	30,990	50474	7968	1068	149272	42756	298555
सूचीबद्ध	100	163	25	138	96	138	9
पीबीआईटी लाख रुपए	14	22	34	21	15	21	15
सूचीबद्ध	100	161	24	155	107	155	10
नकद लाभ लाख रुपए	31083	50703	79269	10169	130555	40676	2610909
सूचीबद्ध	100	163	25	131	84	131	8
नकद लाभ रु. किग्रा.	14	22	33	20	13	20	13
सूचीबद्ध	100	161	24	147	93	147	93
निवेश पर आय - जीएफए आधार	23.55%	34.97%	43.54	23.4	14.69%	23.46	14.69
सूचीबद्ध	100	149	18	100	62	100	6
आरओआई- एनएफए आधार	37.44%	55.64%	63.90	32.4	21.16%	32.42	21.16
सूचीबद्ध	100	149	17	8	57	87	57

223 प्राधिकारी नोट करते हैं कि लाभप्रदता में वर्ष 2007-08 तक सुधार हो रहा था जिसमें तत्पश्चात पर्याप्त गिरावट आई थी। निवेश पर आय एवं नकद लाभ में भी लाभप्रदता के समान प्रवृत्ति देखी गई है। यह नोट किया जाता है कि यद्यपि जांच अवधि के दौरान निवेश पर औसत आय सकारात्मक थी, तथापि क्षति अवधि के दौरान इसमें भारी गिरावट आई। प्राधिकारी ने जांच अवधि के भीतर तिमाही आधार पर घरेलू उद्योग के लाभ एवं आरओआई स्थिति की आगे जांच की थी। आगे यह नोट किया गया है कि जांच अवधि की दूसरी तिमाही में घरेलू उद्योग के निष्पादन में भारी गिरावट आई है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है

	जुलाई-सितं. 08	अक्टू-दिसं. 08	जुलाई-दिसं. 08 (जांच अवधि)
आरओआई - जीएफए आधार	20.04%	9.19%	14.69%
सूचीबद्ध	100	46	73
आरओआई - एनएफए आधार	28.21%	13.13%	21.16%
सूचीबद्ध	100	47	75

मालसूची:

224. घरेलू उद्योग की मालसूची का स्तर निम्नानुसार रहा है:

मी.ट. में	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जून 08	जुलाई-दिसं. 08 (जांच अवधि)
मालसूची	13,654	5236	8233	13587	13539
मालसूची-दैनिक बिक्रियों की संख्या के बराबर	20	7	11	21	20

यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की मालसूची में वर्ष 2006-07 में गिरावट आई जिसमें वर्ष 2007-08 में पुनः वृद्धि हुई । अप्रैल-जून, 08 की अवधि एवं जांच अवधि के दौरान वर्ष 2007-08 की अवधि की तुलना में मालसूची में पुनः वृद्धि हुई ।

रोजगार, मजदूरी एवं उत्पादकता

225. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी एवं उत्पादकता से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जून 08	जुलाई-दिसं. 08 (जांच अवधि)	जुलाई-दिसं. 08 (जांच अवधि वार्षिकीकृत)
रोजगार	4813	4683	4640	4552	4563	4563
सूचीबद्ध	100	97	96	95	95	95
मजदूरी लाख रु.	5037	5893	6292	1719	3088	6176
सूचीबद्ध	100	117	125	137	123	123
प्रति दिवस उत्पादकता	654	705	794	661	653	653
सूचीबद्ध	100	108	121	101	100	100
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	48	53	60	51	50	50
सूचीबद्ध	100	111	126	107	105	105

यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तर में गिरावट आई थी ।

226. तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह गिरावट न केवल जांच अवधि में देखी गई है अपितु यह जांच अवधि से पूर्व भी विद्यमान थी । घरेलू उद्योग की मजदूरी में सामान्य वृद्धि प्रदर्शित होती है । जहां तक प्रति कर्मचारी उत्पादकता का संबंध है, इसमें वर्ष 2007-08 तक वृद्धि हुई और अप्रैल-जून, 08 की अवधि और जांच अवधि के दौरान गिरावट आई ।

पाटन मार्जिन:

227. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से हुए निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन सकारात्मक और निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है ।

वृद्धि

228. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्री (आधार वर्ष से 9.54% और वर्ष 2007-08 से 16% की गिरावट) उत्पादन (आधार वर्ष से 0.15% और 2007-08 से 21.46%) और क्षमता उपयोग (आधार वर्ष से लगभग 24% और वर्ष 2007-08 से 39.42% की गिरावट) जैसे मात्रात्मक मापदंडों के रूप में घरेलू उद्योग की वृद्धि ऋणात्मक रही है । कीमत संबंधी मापदंडों में वृद्धि भी ऋणात्मक देखी गई है । जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का कर पूर्व लाभ (आधार वर्ष से 26.69% और वर्ष 2007-08 से 197% की गिरावट) तथा निदेश पर आय (आधार वर्ष से 43.49% और वर्ष 2007-08 से 114.13% की गिरावट) में भी भारी कमी आई है ।

वास्तविक क्षति का खतरा

229. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की अधिशेष क्षमताओं की उपलब्धता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है । रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों में क्षमताओं में भारी वृद्धि हुई है जबकि क्षमता उपयोग में भारी गिरावट आई है जिससे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की अधिशेष क्षमताओं का संकेत मिलता है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान पाटित आयातों की वृद्धि दर अत्यधिक है जिससे अत्यधिक संवर्धित आयात की संभावना का पता चलता है । इंडोनेशिया से सहयोगी निर्यातकों के आंकड़ों से उनकी मालसूची के स्तरों में भारी वृद्धि प्रदर्शित होती है । भारी मात्रा में कम कीमत पर बिक्री और भारी मूल्य ह्रास हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे का संकेत मिलता है । यदि जांच अवधि के तुरंत बाद की तिमाही के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पहुंच मूल्य को देखा जाता तो यह मत और भी दृढ़ हो जाएगा । यह नोट किया जाता है कि पहुंच मूल्य में 7.81% तक की गिरावट आई है जैसा कि इंडोनेशिया से आयातों के मामले में निम्नांकित तालिका से देखा जा सकता है । जहां तक जांच अवधि के दौरान चीन जन.गण. से आयातों का संबंध है, यह देखा गया है कि पहुंच मूल्य में 18.03% तक की गिरावट आई है । संचयी रूप से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पहुंच मूल्य में जांच अवधि के दौरान 7.97% की गिरावट आई है ।

रु./किग्रा.	जुलाई-दिसं.08 (जांच अवधि)	जन-मार्च 09 (जांच अवधि के बाद की तिमाही)
पहुंच मूल्य - चीन जन.गण.	99.03	81.17
पहुंच मूल्य -इंडोनेशिया	100.35	92.51

संबद्ध देशों से औसत पहुंच कीमत	100.02	92.05
--------------------------------	--------	-------

कारणात्मक संबंध

घरेलू उद्योग के विचार

230 प्राधिकारी ने सभी अन्य ज्ञात कारकों की पहले ही जांच कर ली है। मांग में गिरावट के कारण क्षति के संबंध में प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणामों में इसकी जांच की गई है। जहां तक वैश्विक मंदी का संबंध है, यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि वैश्विक मंदी के कारण लाभप्रदता में वास्तव में गिरावट आनी चाहिए। जहां तक निविष्टि लागत में वृद्धि का संबंध है, इसे नियमावली के अंतर्गत विशिष्ट रूप से शामिल किया जाता है।

231. जहां तक भारतीय रूपए के कमजोर होने का संबंध है, तो यह बात घरेलू उद्योग के विरुद्ध होने के बजाए घरेलू उद्योग के लाभ की ओर जानी चाहिए। यद्यपि, आवेदक केवल आयातित बुद्धि पर निर्भर करता है और उस पर इसके कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था क्योंकि आयातित लुग्दी की पहुंच कीमत काफी बढ़ गई थी।

232. जहां तक क्षमता विस्तार का संबंध है, यह पूर्ववर्ती निर्णयों का परिणाम होता है। किसी भी तरह से घरेलू उद्योग से केवल पाटन के कारण अपनी विस्तार योजनाओं को समाप्त करने की आशा नहीं की जा सकती है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

233. प्राधिकारी को ऐसे अन्य कारकों की जांच करनी चाहिए जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

234. अपनी वार्षिक रिपोर्ट में घरेलू उद्योग ने बताया है कि उत्पादन और बिक्रियों और लाभों में कमी (1) कम मांग (2) वैश्विक मंदी (3) निविष्टि लागत में तेजी से वृद्धि और भारतीय रूपए के कमजोर पड़ने के कारण हुई है। इस प्रकार कथित पाटन के कारण क्षति होना मिथ्या आरोप है और कोरी कल्पना है।

235. कीमतों में कटौतियों का कथित पाटन से कोई लेना देना नहीं है (इस संबंध में वर्ष 2007-08 की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है)

236. कम लाभप्रदता निविष्टि लागतों में वृद्धि, कम मात्राओं और कम मार्जिनों के कारण है। ब्याज और मूल्यहास की लागत काफी अधिक प्रतीत होती है (वर्ष 2007-08 की वार्षिक रिपोर्ट, कारपोरेट प्रस्तुतिकरण, वित्त वर्ष 09 की दूसरी तिमाही का प्रस्तुतिकरण और वित्त वर्ष 09 की तीसरी तिमाही के प्रस्तुतिकरण का संदर्भ दिया गया है)।

237. मंदी की स्थिति के बावजूद घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है।

238. बिक्रियों में गिरावट (1) उपभोक्ताओं के खरीद नहीं करने (2) वस्त्र निर्यातों में गिरावट के कारण मांग में कमी आने (3) स्थितिकारी दबाव के साथ वैश्विक मंदी (4) मूल्य श्रृंखला में मालसूची के परिसमापन के कारण आई है ।

239. क्षमता में विस्तार हुआ है, इस प्रकार क्षमता में वृद्धि /विस्तार की क्षमता के कारण कोई क्षति नहीं हुई है । (वर्ष 2007-08 की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है)

240. तीसरी तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार कम मांग के कारण उत्पादन को घटाया गया था । भिन्न-भिन्न मंचों के समक्ष घरेलू उद्योग द्वारा भिन्न-भिन्न विवरण दिया गया है ।

241. डेप्ट 09-एच1 के कार्य निष्पादन में पानी की कमी के कारण 48 दिनों तक एनएजीडीए संयंत्र के बंद रहने के बावजूद उत्पादन में 15% तक की वृद्धि हुई । बिक्रियों में 19% की वृद्धि, नई प्रभागीय आय में 17% तक और पी बी आई डी टी में 35% तक की वृद्धि हुई ।

242. घरेलू उद्योग गुजरात के विलायत में 80,000 मी.ट. की एक परियोजना में निवेश करने की योजना बना रहा है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

243. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या अन्य मापदंडों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी । इस संबंध में निम्नलिखित मापदंडों का विश्लेषण किया गया है : -

(क) तीसरे देशों से आयात:- प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से संबद्ध वस्तु के आयात के सौदेवार आंकड़े एकत्र किए हैं । रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान किसी अन्य देश से संबद्ध वस्तु का कोई आयात नहीं हुआ है ।

(ख) मांग में कमी:- प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु की मांग में 2007-08 तक पर्याप्त सुधार प्रदर्शित हुआ है और तत्पश्चात जांच अवधि में गिरावट देखी गई है तथापि, मांग की तुलना में आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई है जो सामान्यतः मांग में गिरावट के कारण नहीं होनी चाहिए थी । यह नोट किया जाता है कि उपलब्ध मांग के भीतर घरेलू उद्योग ने अपना बाजार हिस्सा गंवाया है । स्पष्टतः घरेलू उद्योग को पहले ही घटती हुई मांग की समस्या का सामना करना पड़ रहा था परंतु पाटित आयातों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया ।

(ग) खपत की प्रवृत्ति : खपत की प्रवृत्ति में किसी खास परिवर्तन को नोट नहीं किया गया है । स्पष्टतः घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित सामग्री से सीधे प्रतिस्पर्धा कर रहा है ।

(घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ : रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई हो ।

(ङ) प्रौद्योगिकी में विकास : रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार क्षति अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो ।

(च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन : घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन को घरेलू बिक्रियों और निर्यात बिक्रियों के लिए पृथक-पृथक किया गया है और घरेलू उद्योग की क्षति का आकलन करते समय घरेलू उद्योग के केवल घरेलू कार्य निष्पादन पर विचार किया गया है ।

244. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण विकृति आई है । यह बात निम्नलिखित तथ्यों से सिद्ध होती है:-

245. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में भारी वृद्धि हुई है । यह नोट किया जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है परंतु संबद्ध देशों से आयातों के हिस्से में वृद्धि हुई है ।

246. कीमतों पर दबाव रहा है क्योंकि घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं कर पाया है । पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत ह्रास के कारण घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । इसके परिणामस्वरूप लाभ और नकद प्रवाह में भारी गिरावट आई है ।

247. संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य के साथ घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत की तुलना से यह पता चलता है कि कम कीमत पर बिक्री का भी मामला बनता है ।

248. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि उत्पादन, बिक्री और लाभप्रदता में गिरावट कम मांग, प्रचलित वैश्विक मंदी, निविष्टि लागतों में तेजी से वृद्धि और भारतीय रूपए के कमजोर होने के कारण आई है ; प्राधिकारी नोट करते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट में इन सार्वजनिक विवरणों से इस निष्कर्ष में कोई बदलाव नहीं आया है कि इस उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को

क्षति उठानी पड़ी है । सर्वप्रथम हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गलत ढंग से यह मान लिया गया है कि उत्पाद का पाटन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एकमात्र कारण होना चाहिए । यद्यपि, मांग में गिरावट के कारण निश्चित रूप से उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई है परंतु संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण भी घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है । लाभप्रदता के संबंध में घरेलू उद्योग आयात कीमतों के आधार पर अपनी कीमतें तय करता है; इसलिए बाजार में कम कीमत पर पाटित आयातों की उपलब्धता के कारण स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग को ऐसी कीमतों की पेशकश करने पर बाध्य होना पड़ा है जिनसे निविष्टियों की लागत में हुई वृद्धि की वसूली नहीं हो सकती थी ।

249. जहां तक निविष्टि लागतों में तेजी से वृद्धि से संबंधित मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के अनुक्रम में अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है तो यह स्पष्ट रूप से कीमत न्यूनीकरण का मामला है जो क्षति का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है । भारतीय रूपए के कमजोर पड़ने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इससे आयातों से होने वाली क्षति में कमी आनी चाहिए क्योंकि भारतीय रूपए के कमजोर होने से आयातों के कम आकर्षक होने का प्रभाव पड़ता है ।

क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

रु./किग्रा.

	इंडोनेशिया			चीन जन.गण.
	पी टी इंडो भारत रेयन	पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस	अन्य	
एनआईपी	107.97	107.97	107.97	107.97
पहुंच मूल्य	97.30	100.42	77.94	99.03
क्षति मार्जिन	10.67	7.55	30.03	8.94

क्षति मार्जिन %	9.88%	6.99%	27.81%	8.28%
क्षति मार्जिन रेंज(%)	5-15	5-15	25-35	5-15

प्रकटन विवरण पर हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध:

250. मै. पी टी साउथ पैसिफिक विस्कोस, इंडोनेशिया; मै. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन ऑफ मै. राजस्थान टैक्सटाइल्स मिल्स एसो. की ओर से संक्षेप में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- प्रारंभिक आपत्ति: यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान कार्रवाई अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा 13.8.2011 को जारी रिमांड निर्देशों के अनुसरण में की जा रही है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने विशेष रूप से यह निर्देश दिया था कि सीमाशुल्क अधिसूचना में कोई उपांतरण करने की प्रक्रिया अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश की तारीख से 6 माह के भीतर पूरी की जाएगी। 6 माह की उक्त अवधि 12.2.2012 को समाप्त हो गई। उक्त अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें अपीलीय न्यायाधिकरण का ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है कि उपांतरण, यदि कोई हो, करने के लिए 6 माह की उक्त अवधि कितने समय तक बढ़ाई गई है और यह कि निर्दिष्ट प्राधिकारी अपीलीय न्यायाधिकरण से समय विस्तार की मांग नहीं कर सकता क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उक्त आदेश को स्वीकार नहीं किया है और कई अन्य मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय में कई अपीलें दायर की हैं।
- चूंकि कार्यवाही अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित 6 माह की अवधि के भीतर पूरी नहीं हुई है, इसलिए संबद्ध कार्यवाही में रिमांड निर्देश के पालन में आगे कोई कदम नहीं उठाया जा सकता।
- व्यापार सूचना सं. 1/2007 का अनुपालन न किया जाना : प्रकटन विवरण के पैरा 164 में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि व्यापार सूचना को केवल उठाए गए मुद्दों की जांच को सुकर बनाने के लिए जारी किया जाता है और इसलिए हितबद्ध पक्षकारों के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसमें सुझाए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए।
- सामान्य निदेशक : अनुरोध है कि प्रकटन विवरण से पहली बार हमें यह पता चला कि ग्रासिक इंड लि., बिरला जिंगवाई फाइबर्स कंपनी लि., चीन तथा पी टी इंडो भारत रेयन, इंडोनेशिया के सामान्य निदेशक हैं। जांच के उचित चरण पर संगत तथ्यों का प्रकटन न कर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्राकृतिक न्याया के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।
- याचिकाकर्ता का आधार : प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 86/2011-सी.शु. (एन टी) द्वारा दिसंबर, 2011 के संशोधन पर अत्यधिक भरोसा किया है जिसके परिणामस्वरूप पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत "घरेलू उद्योग" की परिभाषा से

"केवल" शब्द हटाया गया है। इसके परिणामस्वरूप विवेकाधिकार "शेष उत्पादकों" से हटकर "अपवर्जित श्रेणी के उत्पादकों" पर लागू नहीं होता है। अतः अनुरोध है कि दिसंबर, 2011 के संशोधन का विवाद के मुद्दे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसका हवाला देने की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल निर्दिष्ट प्राधिकारी उस कानून को अपनाने के लिए विधिक रूप से बाध्य हैं जो नियम 17 के अंतर्गत निर्धारित 18 माह की अवधि के दौरान प्रवृत्त था और न कि उसके बाद। इस संबंध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष सोडा ऐश के मामले में नियम 2(ख) की व्याख्या के बारे में वित्त मंत्रालय के विचारों का हवाला दिया गया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह तर्क दिया गया है कि "केवल" शब्द को हटाए जाने का मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और याचिकाकर्ता के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग हेतु पात्र है। याचिकाकर्ता ने निर्णयों के केवल कुछ उद्धरण उपलब्ध कराए हैं और इनमें से अधिकांश उद्धरण इस मामले के लिए प्रासंगिक नहीं हैं और उनमें से कुछ याचिकाकर्ता के दावे के विरोधाभासी हैं। पैरा 186 में प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध तथा असंबद्ध निर्यातक के बीच पाटनरोधी नियमों में कोई भेद उपलब्ध नहीं है। इस संदर्भ में यह तर्क दिया गया है कि संबद्ध पक्षकार अपने निर्यातों की योजना बना सकता है क्योंकि पाटनरोधी जांच की शुरुआत से संबद्ध पक्षकार के लिए कोई चौकाने वाला तत्व उत्पन्न नहीं होता है अतः संबद्ध और असंबद्ध दोनों उत्पादकों को समान मानना गलत है। यह तर्क दिया गया है कि चीन की कंपनी के मामले में आंकड़ों और सूचना की जांच और उनका सत्यापन किए बिना ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि चीन की कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई निर्यात नहीं किया गया था।

- सार्वजनिक फाइल में दस्तावेज: हमारे अनुरोध के बावजूद सार्वजनिक फाइल के दस्तावेज कभी भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे। अतः यह उल्लेख पर्याप्त नहीं है कि प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियम के अनुसार सार्वजनिक फाइल रखी है।
- निर्यातों की मात्रा: बिक्री प्रस्ताव से ही बाजार में विकृति आ सकती है और ये बाजार में प्रचलित कीमतों में घटबढ़ के लिए पर्याप्त होते हैं। पी टी इंडो भारत रेयन ने अल्प मात्रा में निर्यात किया है और इस अल्प और विछिन्न निर्यात के कारण पी टी साउथ पैसिफिक विस्कोस ने कीमत पर नियंत्रण रखा। अतः हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वह कृपया निर्यातों के प्रयोजन का मूल्यांकन करें न कि संबद्ध निर्यातक द्वारा किए गए पोतलदानों की मात्रा और संख्या का। इस संबंध में हम यह भी अनुरोध करना चाहते हैं कि अल्प निर्यातों में भी पी टी इंडो भारत रेयन सकारात्मक पाटन मार्जिन के योग्य है। यह कारक आवेदक को घरेलू उद्योग के रूप में अपात्र मानने के लिए अकेले ही काफी है।

- अल्प जांच अवधि : हमने यह कभी तर्क नहीं दिया है कि प्राधिकारी जांच अवधि के रूप में 6 माह नहीं ले सकते हैं। इस संबंध में हमने केवल यह उल्लेख किया गया है कि 5% के पाटन मार्जिन को अत्यधिक पाटन नहीं कहा जा सकता जो 6 माह को जांच अवधि के रूप में लेने का एकमात्र आधार है। अतः कानून या तथ्यों के अनुसार यह कोई उचित मानदंड नहीं है। आवेदक ने अत्यधिक पाटन के मुद्दे को उत्पादन लागत से जोड़ने का प्रयास किया है जो समझ से परे है। हमारा यह तर्क कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन के कारण यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अत्यधिक पाटन हुआ है (जो कि अल्प जांच अवधि के लिए एकमात्र औचित्य है), प्राधिकारी द्वारा अनुत्तरित रहता है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए वर्तमान जांच अवधि के बारे में की गई कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड में कोई स्पष्ट कारण नहीं है।
- क्षति: माने गए निर्यातों को घरेलू बिक्री नहीं माना जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ता वे लाभ प्राप्त कर रहा है जो केवल निर्यात बिक्रियों के लिए उपलब्ध है और साथ ही साथ वह इन बिक्रियों को सामान्य घरेलू बिक्री में जोड़कर लाभ प्राप्त करना चाहता है। याचिकाकर्ता के लाभ में केवल 2008-09 में गिरावट आई थी और वह भी केवल विश्वव्यापी आर्थिक संकट के कारण। उक्त अवधि को छोड़कर याचिकाकर्ता आपवादिक रूप से बेहतर कर रहा है। 10 वर्ष के वित्तीय निष्पादन का हवाला देने के बारे में यह तर्क दिया गया है कि 2008-09 में याचिकाकर्ता का लाभ पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 16% घटा है जबकि अगले वर्ष अर्थात् 2009-10 में लाभ में 2008-09 की तुलना में 41% और 2007-08 की तुलना में 19% की वृद्धि हुई है। इस तथ्य से इस बात की स्पष्ट पुष्टि होती है कि घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, निश्चित तौर पर वैश्विक मंदी के कारण हुई है।

घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

251. घरेलू उद्योग ने संक्षेप में ये तर्क दिए हैं कि :

- नियमों में यह विनिर्दिष्ट नहीं है कि प्राधिकारी एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दूसरे हितबद्ध पक्षकार को "प्रदान" करेंगे। नियमों में यह उपबंध है कि प्राधिकारी प्रदत्त साक्ष्य "उपलब्ध कराएंगे"। प्राधिकारी ने ऐसा सार्वजनिक फाइल के जरिए किया है। वह "ऐसी फाइलें" "निरीक्षण और नोट करने" के लिए उपलब्ध करेंगे। वस्तुतः यह कानून के अंतर्गत अपेक्षा है। कानून में यह बंदिश नहीं है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की जाएंगी। अतः इसे कानूनी अधिकार के रूप में नहीं उठाया जा सकता।

- अनुरोधों को रिकॉर्ड में न लिया जाए क्योंकि आवेदकों द्वारा दायर लिखित अनुरोध पैराग्राफ संख्याओं से रहित हैं: यह तर्क कानून से परे है और इसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए । यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्दिष्ट प्राधिकारी को बाध्य नहीं कर सकते, पैराग्राफ संख्यांकन जैसी चीजें कोई महत्व ही नहीं रखती हैं ।
- "आधार" के मुद्दे के बारे में सेंटगोबेन में दिए गए निर्णय पर माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्थगनादेश जारी किया है और इसलिए इसे वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ उद्धृत नहीं किया जा सकता ।
- यह तर्क दिया गया है कि जांच की शुरुआत के समय प्रचलित और अब जांच परिणाम दर्ज करने के समय प्रचलित नियम लागू होगा । किसी पूर्वाग्रह के बिना 2010 के संशोधन से भी प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्राप्त है ।
- जहां तक संबंध का प्रश्न है समस्त संगत सूचना प्राधिकारी के रिकॉर्ड में है । यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि उसका संबद्ध देशों में उत्पादन संरचनाएं हैं । चूंकि याचिकाकर्ता ने स्वयं इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि ये कंपनियां संबद्ध हैं इसलिए जिस आधार पर ये कंपनियां संबद्ध हैं, वह अप्रासंगिक बन जाता है । संबंध की पुष्टि करने वाली सूचना उन स्थितियों में ही प्रासंगिक होती है जहां कोई पक्षकार ऐसे संबंध की मौजूदगी का खंडन करता है ।
- उल्लिखित सभी मामले इस बात का निर्धारण करने में प्रासंगिक हैं कि क्या प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्राप्त है ।
- अल्प जांच अवधि के बारे में यह तर्क दिया गया है कि अत्यधिक पाटन जांच अवधि के भीतर हुआ था । यदि जांच अवधि के आंकड़ों पर माह दर माह आधार पर विचार किया जाए तो इससे अत्यधिक पाटन की स्पष्ट पुष्टि हो जाएगी । जनवरी-मार्च, 09 की अवधि में हुए आयात की सूचना से यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से कीमत में आगे और भारी गिरावट हुई थी । वस्तुतः ये वे ऑर्डर थे जो जांच अवधि के अंत में बुक किए गए थे और इसलिए इन्हें प्रतिवादी निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तर में शामिल किया गया है ।
- क्षति एवं कारणत्मक संबंध के बारे में यह तर्क दिया गया है कि हालांकि मांग में गिरावट आई है तथापि, यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एकमात्र या मुख्य कारक नहीं है । प्रथमतः मांग में गिरावट का घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादकों पर समान प्रभाव पड़ना चाहिए था । तथापि, जहां विदेशी उत्पादकों ने अत्यधिक बाजार हिस्सा हासिल किया वहीं घरेलू उद्योग ने इसे गंवाया है । द्वितीयतः विदेशी उत्पादकों ने अपनी कीमत में भारी कमी की है । परिणामतः घरेलू उद्योग भी कीमतों पर भारी

कटौती करने के लिए बाध्य हुआ था। कीमत मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट पाटित आयातों के कारण आई है।

- आवेदक को अपनी स्थिति और उन तथ्यों में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो रिमांड कार्रवाई में जांच की शुरुआत, प्रारंभिक जांच परिणाम और अंतिम जांच परिणाम के आधार हैं। इसके अलावा यदि पक्षकार संबंधित नहीं हैं तो यह अत्यंत उत्सुकतापूर्ण है कि एक ही वकील एक ही कार्रवाई में दो असंबद्ध परंतु विरोधी पक्षकारों का प्रतिनिधित्व कर रहा है—एक वकील ने कई बार एक से अधिक संबद्ध पक्षकार का प्रतिनिधित्व किया है। क्या इसका तात्पर्य यह है कि वे सभी विदेशी उत्पादक संबंधित थे? उदाहरणार्थ अलग-अलग देशों के विदेशी उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ही वकील का कोई संबंध नहीं हो सकता है। क्या प्रतिनिधित्व करने वाला यह साझा वकील उन्हें संबद्ध बना देता है? वर्तमान मामले में वही वकील विदेशी उत्पादक और भारतीय उपभोक्ता एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्या इससे विदेशी उत्पादक और भारतीय उपभोक्ता एसोसिएशन संबद्ध बन जाते हैं?
- क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोध दोहराए हैं। घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुष्टि होती है क्योंकि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में भारी वृद्धि हुई है। जहां घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है वहीं संबद्ध देशों से हुए आयातों में वृद्धि हुई है। कीमत ह्रास हुआ है क्योंकि घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमत बढ़ाने में असमर्थ रहा है। अत्यधिक कीमत ह्रास पाटित आयातों के कारण हुआ है जिसका घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप लाभ और नकद प्रवाह में अत्यधिक गिरावट आई है। संबद्ध वस्तु के पहुंच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत के साथ किए जाने पर यह पता चलता है कि यह मामला कम कीमत पर बिक्री का भी बनता है।
- यह तर्क दिया गया है कि शुल्क को पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा के रूप में और डॉलर आधार पर ही लगाया जाए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

252. हितबद्ध पक्षकारों के ऐसे अनुरोधों, जिन्हें इस जांच के लिए संगत माना गया था, की जांच निम्नानुसार की गई है :

- जहां तक प्रारंभिक आपत्ति का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने अपीलीय न्यायाधिकरण से समय विस्तार मांगने के लिए उचित कदम उठाए हैं। इसके अलावा,

प्राधिकारी इस मत से सहमत नहीं हैं चूंकि उसने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलें दायर की हैं इसलिए संबद्ध कार्यवाही में रिमांड निर्देश के अनुपालन में आगे कोई कदम नहीं उठाया जा सकता ।

- जहां तक व्यापार सूचना संख्या 1/2007 का अनुपालन न किए जाने का संबंध है, प्राधिकारी अपने इस मत को दोहराते हैं कि उक्त व्यापार सूचना पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच को सुकर बनाने के लिए जारी की गई थी और इसलिए हितबद्ध पक्षकारों को सामान्यतः उसमें सुझाए गए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए था ।
- जहां तक सामान्य निदेशकों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना/आंकड़े सार्वजनिक फाइल में रखे गए थे जो पाटनरोधी नियमों के अनुसार जांच में भागीदार सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध थीं ।
- "याचिकाकर्ता के आधार" के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे की विस्तार से जांच की है और वे यह दोहराते हैं कि उसके पास नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग हेतु योग्य बनने के लिए किसी घरेलू उत्पादक को बाहर रखने या शामिल रखने का विवेकाधिकार है और वे इस मुद्दे पर अपने जांच परिणाम को दोहराते हैं ।
- सार्वजनिक फाइल में दस्तावेजों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना/आंकड़े सार्वजनिक फाइल में रखे गए थे जो पाटनरोधी नियमों के अनुसार जांच में भागीदार सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध थीं ।
- जहां तक मै. पी टी इंडो भारत रेयन द्वारा निर्यातों की मात्रा का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे की जांच की है और वे रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस विषय से संबंधित अपने जांच परिणामों को दोहराते हैं ।
- जहां तक जांच अवधि का संबंध है, प्राधिकारी इस विषय पर अपने जांच परिणाम दोहराते हैं । इसके अलावा, पाटित कीमतों पर बेची गई संबद्ध वस्तु की मात्रा की तुलना में अत्यधिक पाटन के मुद्दे पर भी गौर किए जाने की जरूरत है ।
- क्षति के बारे में प्राधिकारी 17 मई, 2010 के अंतिम जांच परिणाम में समुचित रूप से विचार किए गए समस्त संगत मुद्दों को नोट करते हैं और इसलिए उनकी पुष्टि की जाती है ।
- जहां तक शुल्क के स्वरूप का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क की पहले ही संस्तुति निर्धारित आधार पर की गई है और उसमें संशोधन करने का कोई कारण नहीं बनता है ।

निष्कर्ष:

253. माननीय सेस्टेट के आदेशों के अनुसार समस्त पक्षकारों को मौखिक और लिखित अनुरोध करने का अवसर प्रदान करने के बाद प्राधिकारी ने इनकी जांच उपर्युक्त पैराग्राफों में की है। समस्त पक्षकारों के अनुरोधों की जांच करने के बाद प्राधिकारी पूर्व में निकाले गए निष्कर्षों और 17 मई, 2010 के अंतिम जांच परिणामों में उल्लिखित निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

254. अतः प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना की तारीख से संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश की एतद्वारा पुष्टि करते हैं। प्राधिकारी आगे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की संगत अधिसूचना में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2012

Final Findings

Subject : Post-Decisional Oral hearing on Anti-dumping investigation concerning imports of 'Viscose Staple Fibre excluding Bamboo fibre' originating in or exported from China PR and Indonesia-Final Findings.

Order No. 14/6/2009-DGAD.—In pursuance of the Hon'ble Tribunal (CESTAT's) Final order No. AD/31-51/2011-AD dated 11th August, 2011, a Post-decisional hearing was held on 14th December,

2011 on the captioned subject, wherein the interested parties that had participated in the instant investigation were requested to participate.

2. Upon conclusion of the said hearing, the interested parties that had made their oral submissions were advised to file the written submissions within the stipulated time as per the AD Rules. They were also advised to file the rejoinders thereafter.

3. The written submissions and rejoinders filed by the interested parties, to the extent considered relevant, have been duly considered in this order. Submissions made by interested parties have been examined by the Authority as follows:

Written Submissions made on behalf of the domestic industry

4. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry:

Product under consideration and like article

5. *The product under consideration is "Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre". Viscose Staple Fibre is described as "Viscose rayon staple fibre not carded/combed" under the Customs Tariff and is also known as "Rayon Fibre" in some markets. The product under consideration is classified under Custom Headings 5504.10.00. The Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.*

6. *With regard to like article, Rule 2(d) of the AD rules provides as under:*

"like article " means an article, which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article that although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation.

7. *The information made available to the Authority makes it amply clear that there is no material difference in the domestic like article and imported subject goods. Subject goods produced by domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market & tariff classification of the goods. None of the opposing interested parties have raised any objection in this regard. Thus, subject goods*

produced by the domestic industry should be treated as like article to the subject goods imported from subject countries in accordance with the AD rules for the purpose of the present investigation.

Standing & Scope of Domestic Industry

8. *It has been argued that the petitioner does not satisfy the requirement of standing and Grasim does not constitute domestic industry within the meaning of the law.*

9. *Domestic industry submits that Grasim Industries Ltd. satisfies the requirement of standing and constitutes domestic industry within the meaning of the rules. Followings are relevant in this regard.*

a. *Rule 5 (3) in its relevant part provides as follows.*

(3) The designated Authority shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub-rule (1) unless -

(a) it determines, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to the application expressed by domestic producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry :

Provided that no investigation shall be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than twenty five per cent of the total production of the like article by the domestic industry, and

(b) it examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies itself that there is sufficient evidence regarding -

(i) dumping,

(ii) injury, where applicable; and

(iii) where applicable, a causal link between such dumped imports and the alleged injury.

to justify the initiation of an investigation.

Explanation. - For the purpose of this rule the application shall be deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry, if it is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty per cent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition, as the case may be, to the application.

b. *It would be seen that the Authority is justified in initiating the investigations if domestic producers supporting the petition account for more than 25% of production, provided the application is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty percent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing*

either support for or opposition, as the case may be, to the application. In the present case, admittedly, the petitioner is the sole producer of the product in the Country and therefore requirements of Rule 5(3) are fully met. The only issue that remains to be considered is whether the relationship of the petitioner with foreign producers is such as to disentitle the petitioner from being considered as domestic industry. Followings are relevant in this regard.

c. Rule 2(b) as it stood at the time of initiation was as follows.

(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case [such producers may be deemed] not to form part of domestic industry :

d. The rule 2(b) was amended after the preliminary findings and before final findings. The amended rule is as follows –

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' **may be construed as referring to the rest of the producers only**"

e. The Rules have been further amended on 1st Dec., 2011. The present rule is as follows–

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' **may be construed as referring to the rest of the producers**"

f. Thus, in a situation where the definition under Rule 2(b) was different at the time of initiation, final findings and at present, the Authority is required to first consider whether Rule 2(b) as amended in Budget 2010 will at all apply to

investigations initiated prior to such amendment, particularly when the rules have now been further amended. Rule prevailing at the time of final findings is not the rule that was prevailing either at the time of initiation or now when the Designated Authority shall record the findings.

- g. Admittedly, Rule 2(b) as applicable at the time of initiation clearly provided a discretion to the Designated Authority to consider a domestic producer as eligible or ineligible in certain situations. The ordinary rule under 2(b) is that the Designated Authority shall consider domestic producers as a whole as the domestic industry. It is only under certain situations mentioned under the rule 2(b) that the Designated Authority is required to consider whether such domestic producers who are themselves importers of the product or are related to exporters or importers of the product should be considered as ineligible domestic industry.*
- h. Assuming though not admitting that the Authority is required to apply rule 2(b) as amended during Budget 2010 in the present case, the domestic industry submits that considering either rules, Grasim Industries should be considered as eligible domestic industry.*
- i. Two kinds of exclusions have been provided under Rule 2(b) wherein the Designated Authority is required to consider whether such domestic producers should be considered as eligible or ineligible domestic producers. The two situations are -*
 - i. Domestic producer itself is an importer of the product under consideration;*
 - ii. Domestic producer is related to an exporter or an importer of the dumped product.*
- j. Undisputedly, Grasim Industries has not imported the product and therefore the first situation is not applicable in the present case.*
- k. As regards second situation, petitioner submits that the Rule 2(b) does not differentiate or distinguish domestic producers that may be related to exporters with the domestic producers who may be related to importers. Much emphasis was placed at the time of hearing stating that the decisions referred by the domestic industry does not pertain to a situation of relationship with an exporter and all cases referred by the domestic industry concerns situations where domestic producers are related to importers. Petitioner submits that the rules have not distinguished and have not placed differently situations of domestic producers who may be related to exporters from a situation of domestic producers who may be related to importers. Such being the case, decisions wherein domestic producers may be related to importers are equally relevant and applicable for the present case.*
- l. The petitioner admitted relationship at the time of initiation of investigations. The petitioner, in alternate to the submissions earlier made, submits that the Authority may consider whether at all petitioner is related to the exporter. It was emphasized at the time of hearing that had the nature of relationship between the*

foreign producers and domestic industry was fully known to the Authority, the Authority would not have even initiated the investigations. The domestic industry, however, points out that the fact that Authority has even after an elaborate finding on this issue itself established that the situation in any case could not have been different at the time of initiation. In any case, full relevant factual information is on record of the Authority and the same is relied upon.

- m. **The parameters adopted for exercise of discretion** – It has been argued that the parameters adopted by the Authority for exercising discretion are without any legal basis and are contrary to the settled law on the subject. The petitioner strongly disputes and disagrees. As far as the alleged "settled law" on the subject is concerned, no such material has been placed before the Authority. The interested parties are trying to base their cases on mere statements. As far as the parameters adopted by the Authority are concerned, petitioner has provided elaborate material covering relevant extracts from a number of leading text books on anti-dumping, number of decisions of the European Commission and a number of decisions of the Designated Authority. The petitioner has provided a large number of cases relating to those situations where petitioner was related to an exporter or an importer or itself was an importer of the product concerned.
- n. The emerging jurisprudence is summarized below.
- i. Is the behaviour of the related parties distinct and different as compared to unrelated parties;
 - ii. Whether there is some evidence to show that such related producer triggered or intensified dumping in the Indian market;
 - iii. Is the related domestic producer shielded from effects of dumping or unduly benefited from it;
 - iv. Is the related domestic producer seeking to stifle the competition in the Indian market;
 - v. Is there a case of self-inflicted injury?
 - vi. the impact of the exports, if any, made by the related party in a given case. Whether such related party had exported the product to India during the period, if so, what is the impact thereof on the claims of injury. If not, whether there is any other ground still justifying its exclusion. In case the related party has also exported the subject goods, then the following also need to be evaluated:
 - The volume of exports made by such related party;
 - The purpose of such exports made by the related party;
 - Whether there is any evidence to show that injury to the domestic industry was attributable to such exports by the related party;
 - Whether the general emphasis of the related domestic producer was on the production of the subject goods or whether the general emphasis gradually or steadily shifted to imports;
 - Whether the volume of exports by such related parties were such that the related exporter is gradually or steadily substituting the unrelated domestic producers' market;
 - Any other factor which might have been brought to the notice of the Authority by the interested parties during the course of the proceedings.

- o. Exports by the Chinese related producers – It has been alleged that the Designated Authority failed to appreciate that one of the reasons of limiting POI to 6 months could be that the related party may have more than negligible exports to India prior to July 2008. Petitioner however submits that –*
- i. No such certification in fact has been prescribed under the application proforma. Much has been argued with regard to the form and manner prescribed by the Authority and yet it has been argued that no certificate has been provided by the Chinese related producers, even when there is no such prescribed requirement.*
 - ii. The applicant is required to provide relevant information, which has been provided and its accuracy has been certified. It is now for the interested party to establish that the claims made by the domestic industry are incorrect.*
 - iii. A certificate has in fact been provided from the Chinese producers only to remove the unnecessary doubt attempted to have been created.*
 - iv. Petitioner submits that it is a mere imagination that the six months investigation period has been proposed by the petitioner for this reason. The exporter's questionnaire prescribed by the Authority requires information not only for the period of investigation but also for the preceding years. The information filed by the exporter, which has also been verified by the Authority, clearly establishes that the exports made by the related party prior to the period of investigation were not more than negligible.*
- 10. The application was filed by the Association of Man Made Fibre Industry of India on behalf of the domestic industry. M/s Grasim Industries Ltd. is the sole producer of the Like Article in India and has provided the relevant information concerning the injury and costing in this regard. There is no other producer of the like article in India. Authority has rightly held in the finding that the production of M/s Grasim Industries Ltd. accounts for a major proportion of the domestic production as the production of M/s Grasim Industries Ltd. is more than 50% of Indian production.*
- 11. The petitioner stated that it has affiliated companies in Indonesia and China producing & selling the product, namely Birla Jingwai Fibres Company Limited, China and PT Indo Bharat Rayon, Indonesia. The relationship between these entities is given in the table below:*

SN	Name of the entity	Common directors
1	Grasim Industries Ltd	Mr. Kumar Manglam Birla Ms. Rajshree Birla Mr. S K Jain
2	Birla Jingwai Fibres Company Limited, China	Mr. S K Jain

3	PT Indo Bharat Rayon, Indonesia	Mr. Kumar Manglam Birla Ms. Rajshree Birla Mr. S K Jain
---	------------------------------------	---

12. Since petitioner itself had stated that these entities are related producers in the subject countries, the basis on which these companies are related became irrelevant. Further, the rules require information with regard to "exporters" and not merely with regard to "producers". These producers are largely selling their products either in the respective domestic markets or exporting to third countries. In general, there are no exports to India. In particular, the Chinese company has not exported the product to India, whereas the Indonesian Company has exported small quantity to India, which is less than 3% of imports and negligible with reference to Indian production. The exports have been made because some customers of the petitioner required imported material under duty exemption schemes. Relevant evidence has been provided to the Designated Authority on confidential basis¹. Since the volumes of these imports are quite small, hence the Authority has rightly considered that the petitioner should not be considered ineligible under the Rules.

13. It is rightly held by the Authority that the application satisfied the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules and therefore, M/s Grasim Industries Ltd. is being treated as 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules.

14. An issue that arises for consideration and determination in the present case is in a situation where a producer is related to an exporter in one of the exporting countries, should that producer be considered as eligible domestic industry. In other words, whether the Designated Authority has discretion under the Rule 2(b), and if so, how the discretion is required to be applied. Even when the Designated Authority has issued a preliminary findings and final findings after due consideration of facts and law, in view of challenge on this account, petitioner has done detailed research on this issue by referring to various text books, practices of other investigating Authorities and decisions taken by other investigating Authorities. These have been discussed herein below.

a. It would be recalled that the anti dumping rules were amended in 1999, wherein one of the amendments related to the definition of domestic industry. The Rule (2(b)) prior to this amendment was as follows:

2(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the

¹ In fact, other parties to the investigations concede that the imports of VSF are almost 90% under advance licence category

alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry:

b. *The rule after the amendment is as follows:*

2(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case *[such producers may be deemed]* not to form part of domestic industry :

c. *The rule 2(b) was amended after the preliminary findings and before final findings. The amended rule is as follows –*

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers only"

d. *The Rules have been further amended on 1st Dec., 2011. The present rule is as follows—*

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

e. *It is evident that the rule was amended with a view to provide a discretion to the Designated Authority to decide on merits whether a company who is importing the product under consideration or which is related to an exporter or importer should be included or excluded for the determination of the domestic industry.*

f. *Not all kinds of imports are condemned under Rule 2(b). Thus, Rule 2(b) has been amended with the sole objective of providing a discretion to the Designated Authority to decide whether to include or exclude a company who has itself imported the alleged dumped product, or who is related to an exporter or importer of the subject goods. Such a discretion has been exercised in an even manner by the Designated Authority in the instant case. Following are relevant in this regard*

(A) Emerging jurisprudence as clarified in the text books:-

- (a) Extracts from 'DUMPING AND SUBSIDIES-The Law and Procedures Governing the Imposition of Anti-dumping and Countervailing Duties in the European Community – by M/s. Clive Stanbrook and Philip Bentley, Kumer Law International, 3rd Edition

5.1.3 Community producers who are related to exporters/ importers or are importers of the product.

Community producers may not wish to support a complaint because they are related to the exporters or importers, or are themselves importers of the allegedly dumped or subsidized product. In such cases, it is considered that the remaining Community producers should not be prevented from making a complaint just because they cannot raise the necessary proportion of support. Thus the rule is modified so that the Community Authorities may treat the Community industry as meaning those producers who are not related to exporters or importers and are not importers themselves of the offending product. The Community Authorities retain discretion in this matter, it would seem that the 50% and the 25% rules still apply to the producers left after the exclusion of those who are related to exporters etc. It would make nonsense to say otherwise, as the following example shows. If 51% of Community production was related to the exporters they would voice their opposition and it would be impossible for the unrelated producers ever to bring an anti-dumping or anti-subsidy complaint. Unlike Regulation (EEC) No.2423/88, Regulation (EC) No.384/96 and Regulation (EC) No.3284/94 provide a definition of "related"...

....

It would appear that provided that the reason for importing the product is essentially defensive, the Community Authorities will not exclude the producer. There are many cases where the Community Authorities have held that the producer was importing the allegedly offending product simply to try to defend a position in market increasingly affected by dumping or subsidies. For example, in Copper Sulphate from Yugoslavia, the Community Authorities found that –

...

The Community Authorities consider it to be a legitimate act of commercial self protection for Community producers to make purchases to "stay on the market with as" full a range of models as possible or even to protect market niches which would have disappeared without sales of the models in question.

.....One of the factors that will be important in this respect will be the balance of the business of the company as between manufacturing and importing. If the company is predominantly in manufacturing and assembly in the Community market with some supplemental business importing products then it is likely to be included. On the other hand, if a Community producer closes down its production and imports instead or the general emphasis of his

business is on imports, he will be excluded. Exclusion will be likely if, on examination it appears that by importing products, a company has "shielded" itself from the effects of dumping. This will also be likely if it appears that producers have in some way participated in the dumping practice or unduly benefited from it. To include such companies would lead to a distorting effect on injury findings.

It appears to be the Community Authorities practice to exclude a Community producer who imports the product subject to investigation but does not cooperate because in such circumstances, the Community Authorities cannot determine whether the Community producer was acting defensively or for some other reason.

- (b) ***Extracts from –A Handbook on Anti-dumping Investigations – by Judith Czako, Johann Human and Jorge Miranda, Cambridge University Press, page 234***

Exclusion of related producers

... ..

The AD Agreement does not list any specific test or criteria to be applied in determining whether related producers or importers should be excluded from the definition of the domestic industry. Investigating Authorities generally address the related party issue on a case-by-case basis. Among the criteria that have been considered by Members in deciding whether to exclude related parties are –

- *The percentage of domestic production of the product in question that is accounted for by the related producers;*
- *Whether imports of the product in question by the related producers allow them to benefit, or serve to shield them, from the effects of dumping;*
- *Whether exclusion of the related parties would unduly skew the data for the remaining members of the industry;*
- *The level or long-term nature of the commitment shown by the producer to domestic production, as opposed to importing activities*
- *The ratio of import shipments to domestic production for the related producers.*

- (c) ***Extracts from Appendix-F, Antidumping and Countervailing Duty Handbook – Publication 3482, 9th Edition, United States International Trade Commission, page App. F-33:***

..... Thus, for example, if a US producer is related to a foreign exporter and the foreign exporter directs its exports to the United States so as not to compete with the related US producer, the Commission may determine that appropriate circumstances exist to exclude the related US producer from the domestic industry.

The Commission has examined the following factors in determining whether appropriate circumstances exist to exclude a related party:

- (i) the percentage of domestic production attributable to the related producer;
- (ii) the reason the related producer has decided to import the article under investigation, i.e. to benefit from the unfair trade practice or to enable it to continue production and compete in the domestic market; and
- (iii) the position of the related producer vis-à-vis the rest of the industry, i.e. whether inclusion or exclusion of the related party will show the data for the rest of the industry.

(B) Various decisions of the investigating authorities

Domestic industry also refers to and relies on European Commission practice. The paper book presented at the time of oral hearing may kindly be referred in this regard. European Commission considers following parameters while deciding when to include a community producer who has itself imported the subject goods.

(a) The 'core business' test

To decide whether Community producers-importers should be given the status of producers or importers, the Commission considers in particular whether the companies operating in the Community supplemented their Community production or assembly activity with an additional activity based on imports or whether the companies were acting as importers with relatively limited additional production activity in the Community.

- (b) Importers are merely a defensive action against low-priced imports -The commission considers whether the imports were made for merely a defensive action against low priced imports.*

Petitioner has categorize the import made by a producer in following categories

- I. Imports by petitioner itself-from related exporter
- II. Imports by petitioner itself-from unrelated exporter
- III. Imports by petitioner itself-from Other than Subject country
- IV. Imports by affiliated company in India from related exporter
- V. Imports by affiliated company in India from unrelated exporter
- VI. Relationship with exporter exported during POI
- VII. Relationship with exporter no exports during POI

• Imports by petitioner itself-from related exporter

1. Council Regulation (EC) No 423/97 of 3 March 1997 amending Regulation (EEC) No 3433/91 in respect of imports originating in Thailand and imposing definitive anti-dumping duties on imports of gas-fuelled, non- refillable pocket flint lighters originating in Thailand, the Philippines and Mexico. Official Journal L 065, 06/03/1997 P. 0001 – 0016.

D. COMMUNITY INDUSTRY

- a) *The investigation confirmed that the complainant Community producers, either represented by the EFLM (on whose behalf the request for an interim review in respect of Thai imports had been lodged) or acting separately in two distinct groups (one having lodged the complaint concerning imports originating in the Philippines and the other one the complaint concerning imports originating in Mexico), accounted in all cases for a major proportion of total Community production of the like product.*
- b) *During the course of the investigation carried out in respect of the above companies, it became apparent that two producers or groups of producers, namely Tokai Seiki GmbH, together with one of its sales subsidiary in the Community, and the companies belonging to the Swedish Match Group, were related respectively to the sole Mexican exporter and one Filipino exporter and were also importing the dumped product from the countries concerned.*

In these circumstances, the Commission examined whether, in the light of the provisions of Article 4 (1) (a) of the basic anti-dumping Regulation, these companies should be excluded from 'the Community industry'. In this respect, it should be recalled that Article 4 (1) (a) does not provide for the automatic exclusion of producers who are related to exporters and/or themselves importing the dumped products, but rather obliges the Commission to examine on a case-by-case basis whether the exclusion of any producer in this situation is warranted.

As far as Tokai Seiki GmbH is concerned, it has firstly to be noted that this company had made it clear that it only supported the action against the Philippines and Thailand and that its cooperation as a potential Community producer was restricted to the investigations in respect of these two countries. Secondly, the investigation showed that this producer was not only related to the sole Mexican exporter but also responsible for a very large proportion of the total imports into the Community of disposable flint lighters declared as originating in Mexico.

In this respect, it should be recalled that the investigations concerning Mexican and Filipino imports were carried out in the framework of a single proceeding (see recital 5) and that a cumulative assessment of the effect of the dumped imports from Thailand, the Philippines and Mexico was found to be warranted (see recitals 40 to 44). In this context, it was considered that taking into account the situation of Tokai Seiki GmbH in the overall injury assessment was not appropriate since, given the importance of the Mexican imports concerned, it would have led to unreliable results. Accordingly, it was considered appropriate to exclude Tokai Seiki GmbH from 'the Community industry'.

As regards the companies belonging to the Swedish Match Group, which are related to the Filipino exporter Swedish Match Philippines, Inc., it appeared appropriate to determine whether those companies (which were complainants in all three cases and fully cooperated in all three investigations) were primarily producers with an additional activity based on imports and merely supplementing their Community production, or whether they were importers with relatively limited additional production in the Community.

The investigation revealed that the import activity of the companies belonging to the Swedish Match Group in respect of the product concerned originating in the Philippines was extremely limited, thus underlining that the core of their operations relating to the product concerned firmly remained in the Community. Accordingly, it was considered appropriate to maintain the companies concerned within 'the Community industry'.

The injury findings set out below are therefore based on the information submitted by the cooperating companies other than Tokai Seiki GmbH, namely the producers belonging to the BIC Group and to the Swedish Match Group, and the Spanish company Flamagas.

2. COMMISSION REGULATION (EC) No 2318/95 of 27 September 1995 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain tube or pipe fittings, of iron or steel, originating in the People's Republic of China, Croatia and Thailand and terminating the anti-dumping proceeding in respect of imports of these fittings, originating in the Slovak Republic and Taiwan. Official Journal L 234, 03/10/1995 P.0004- 0015.

D. COMMUNITY INDUSTRY

(37) *Since not all producers established in the Community participated in the investigation and one Community producer was found to manufacture special tube or pipe fittings not subject to the proceeding, the Commission had to examine whether the complainants constitute a major proportion of the total Community production of the like product. It also had to take into consideration the fact that one of the complainant Community producers in the United Kingdom imported the allegedly dumped products from an exporter in Thailand which, in addition, is a related party.*

(38) *With regard to the imports of the complainant UK producer, the examination of the facts showed that almost all producers in this particular branch of the industry rely to a certain degree on the purchase of fitting types which are outside their manufacturing programme. In fact, fittings producers have to offer a complete range of product types in order to satisfy the requirements of the customers and thus to compete in the market.*

It was indeed established that the complainant UK producer in question imported during the investigation period the product under investigation from a related exporter in Thailand for which dumping was found. The level of these imports, however, was found not to exceed 2 % of the total sales made by the UK producer on the Community market. In addition, the imported quantities consisted mainly of product types not manufactured by this producer to complement its range of products and were imported solely to defend its market position. It is therefore considered that, although they are related parties, such a low level of imports could not have shielded the UK producer from the effects of dumping nor have been any substantial benefit to it, and that there are no reasonable grounds for excluding this producer from the definition 'Community industry'.

In the course of the investigation, one of the complainant Italian producers withdrew from the complaint on the grounds that the products it manufactured were not exported by the exporting countries concerned.

As to the determination of the share of the output of the producers represented in complaint, the Commission used the information submitted together with further data provided during the on-the-spot investigation by the complainant producers which by far are the largest producers established in the Community. The Commission also used reliable market research data.

On the basis of the above considerations, the share of the total Community production held by the complainant producers during the investigation period was calculated at 85 %, thus amounting to a major proportion of total Community production.

3. ***Council Regulation (EC) No 2022/95 of 16 August 1995 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ammonium nitrate originating in Russia Official Journal L 198, 23/08/1995 P.0001-0014***

C. COMMUNITY INDUSTRY

The complainant producers account for 94 % of the Community production of ammonium nitrate and therefore constitute the Community industry in accordance with Article 4 (5) of Regulation (EEC) No 2423/88.

EFIA, representing the Community importers, alleged that Hydro Fertilizers Ltd (UK) should be excluded from the Community industry because it allegedly imported ammonium nitrate from Russia and Lithuania through Fertrachem UK, a related company. However, it was established that no such imports were made during the investigation period by Fertrachem. It was also alleged that BASF, another complainant producer, should be excluded on the same grounds, since it allegedly imported Russian and Lithuanian ammonium nitrate into the Community through a related company, Kali (UK) Ltd. It was established that Kali (UK) Ltd did import ammonium nitrate from Lithuania and Russia during the investigation period, and had no agreement with any company related to BASF, either directly or through a subsidiary during this period, and had no agreement with any company related to BASF as regards purchases of ammonium nitrate.

There is consequently no justification for considering the exclusion of either Hydro Fertilizers Ltd (UK) or BASF from the Community industry.

4. ***COMMISSION REGULATION (EC) No 823/95 of 10 April 1995 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of disodium carbonate originating in the United States of America Official Journal L 083, 13/04/1995 P. 0008 – 0018***

D. COMMUNITY INDUSTRY

Some United States exporters and the representatives of the major processing industry in the Community, the glass industry, argued that two of the complainant companies were related to United States exporters, had themselves imported American soda ash during the period of investigation and should therefore not be considered as part of the Community industry in the light of Article 4 (5) of the Basic Regulation.

In this respect, it should be recalled that Article 4 (5) does not provide for the automatic exclusion of producers related to the exporters or producers who are

themselves importing the allegedly dumped product, but rather imposes on the Community institutions the obligation to examine on a case-by-case basis whether the exclusion of any producer in this situation is warranted.

Accordingly, the Commission considered whether those two Community producers, were merely supplementing their Community production with an additional activity based on imports, or whether they were importers with relatively limited additional production in the Community. This approach is consistent with the recent case-law of the Court of Justice regarding the definition of 'Community industry'.

The Commission examined the relationship between the quantities produced in the Community and the quantities imported. On the basis of the facts established in the investigation, it was found that the two Community producers which are related to exporters and are themselves importing from the United States, import relatively low quantities (in one case these imports represented 10 % of the Community producer's production sold in the Community and in the other case less than 1 %). Furthermore, for one Community producer who had bought a United States producer in 1992, existing contracts had to be honoured; imports from this company ceased in 1993. The other producer mainly imports for its captive consumption.

In these circumstances, it can be concluded that the two Community producers concerned, with corporate headquarters located in the Community, where their commercial policy is formulated and foreign investments planned as a normal business extension of their commercial activities, did not principally act as importers but continued to retain the manufacture of soda ash as their main activity. Given the relatively low quantities imported, these producers cannot be considered to have been shielded against the effects of dumping because of imports.

In the light of the above, it was considered that there were no grounds for the exclusion of any of the complainant producers from the definition of the Community industry.

5. Council Regulation (EC) No 2025/97 of 15 October 1997 imposing a definitive anti-dumping duty on imports into the Community of advertising matches originating in Japan and collecting definitively the provisional duty imposed Official Journal L 284, 16/10/1997 P. 0057 – 0067

E. COMMUNITY INDUSTRY

(33) *The large majority of the Community producers of advertising matches are members of FEFA (Fédération Européenne des Fabricants d'allumettes), the European association who lodged the complaint on behalf of its members. These producers, located in France, Spain, Italy, Belgium, Portugal and United Kingdom are usually small and medium-sized enterprises with limited resources. Consequently, even though they all supported the complaint, only the main producers, representing 78 % of the total Community output of the product concerned and thus, clearly meeting the criteria set forth in Article 4 (5) of the basic Regulation, have actively cooperated with the Commission in this investigation.*

(34) *A Japanese exporter questioned the exclusion from the published provisional determinations of a Community producer located in France, who replied to the Commission questionnaire.*

(35) This situation is explained by the fact that this producer, although supporting the complaint, was not in a position to comply with the requirements of the Commission for the on-the-spot investigation due to important internal difficulties. Therefore it was decided that this producer could not be considered as actively cooperating in the proceeding and was not included in the definition of the Community industry.

(36) This decision is reflected in the contents of recital 25 of the provisional duty Regulation which indicates that the term 'Community industry' should be interpreted as referring to those Community producers of the like product whose collective output constitutes a major proportion of the total Community production who supported the complaint and who actively cooperated in the proceeding.

(37) Despite the explanation provided in recital 26 of the provisional duty Regulation, one importer of Japanese advertising matches in the Community claimed that the main complainant Community producer should not be considered as part of the Community industry on the grounds that he imported directly or via its related companies dumped advertising matches from Japan in volumes representing far more than 4 % of its own production. In support of its claim a list of the subsidiaries of the above complainant which allegedly imported the advertising matches from Japan was supplied.

(38) The Commission re-examined the level of imports made by this Community producer and confirmed its provisional finding, namely that the quantities imported by this producer represented around 4 % of its own total production of advertising matches.

(39) Another exporter claimed that two of the complaining Community producers were no longer producing advertising matches. Even though this exporter is referring to events which allegedly happened after the investigation period, which therefore should normally not be taken into account, it has to be noted that no indication exists that any of the complaining Community producers stopped manufacturing the product covered by this investigation.

(40) In conclusion, the definition of the Community industry for the purposes of the present proceeding and the provisional findings made by the Commission in this respect are hereby confirmed.

6. COMMISSION REGULATION (EC) No 1845/98 of 27 August 1998 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain large electrolytic aluminium capacitors originating in the United States of America and in Thailand

D. COMMUNITY INDUSTRY

Community production

(39) Four large producers of LAECs, i.e. Philips, BHC Aerovox Ltd (United Kingdom), Vishay Roederstein GmbH (Germany) and Siemens-Matsushita Components GmbH & Co., KG (Germany), as well as some small to medium-sized producers are established in the Community.

(40) One of the large producers, Siemens-Matsushita Components GmbH & Co., KG (Munich, Germany) is a joint venture between a German company and a Japanese company and is related to one of the exporting producers in the USA. Therefore, this producer was excluded from the Community industry, in accordance with Article 4(1) of the Basic Regulation on the grounds that through its relationship this producer was

shielded from the injurious effects of dumped imports. It should be noted that this producer was also excluded from the Community industry in the two previous proceedings concerning LAECs.

(41) Some producers/exporters claimed that one of the complaining Community producers, Philips, could not be considered as part of the Community industry, on the grounds that another company within the Philips group, namely Philips Consumer Electronics BV, had been importing LAECs from the USA during the investigation period.

The investigation revealed that Philips Consumer Electronics BV, which bought around 40% of Philip's output and was its biggest traditional customer, had imported LAECs from the USA during the investigation period, as components for its own production of electronic products. It was noted that the LAECs imported were used by Philips Consumer Electronics BV exclusively as components for its own production of electronic products and that the imported LAEC were never resold on the Community market.

The choice of Philips Consumer Electronics BV to be partly supplied by US exporters was made possible by the structuring of the Philips Group in different profit centres, which are all independent and free to source their materials from any producers which can give the best market conditions. This choice did not presuppose that the primary interest of Philips went from producing to importing.

For these reasons, it was considered that the imports made by Philips Consumer Electronics BV, can be viewed as a perfectly legitimate business decision, since it imported the dumped products only to a limited extent, continuing to rely on its parent company for a majority of its requirements. These imports were considered as a necessary commercial measure until the time when fair conditions of competition were restored in the Community market.

It was therefore concluded that no reasonable grounds existed to exclude Philips from the Community industry. It should be noted that the same conclusion was reached in recitals (10) to (12) of Commission Regulation (EEC) No 1451/92 imposing provisional anti-dumping measures on imports of LAECs originating in Japan².

(42) One of the exporting producers further argued that Philips should be excluded from the definition of the Community industry, since it is related to a producer in the USA, North American Philips, which is active in the production of LAECs.

Information made available to the Commission indicated that North American Philips only produced for the North American market and that this producer did not export LAECs to the Community during the investigation period.

Therefore, the Commission concluded that Philips should not be excluded from the Community production.

(43) Based on the above, the Community production consisted of all companies producing LAECs in the Community, with the exception of Siemens-Matsushita

² OJ L 152, 4. 6. 1992, p. 22.

Components GmbH & Co., KG (Germany). These companies are hereinafter referred to as 'the Community producers'.

Community industry

(44) *As mentioned above, two Community producers actively supported the complaint. However, one of these two complainant producers, BHC Aerovox Ltd, could not submit the information requested within the deadlines set and was, therefore, excluded from the scope of the Community industry.*

(45) *Another large Community producer, Vishay Roederstein GmbH (Germany), expressed support for the complaint but did not complete the questionnaire of the Commission.*

(46) *One small to medium-sized Community producer, Trobo SA (Spain), expressed support for the complaint, but did not provide full information to the Commission. All other small to medium-sized Community producers remained silent.*

(47) *In these circumstances, the situation of the sole co-operating complainant Community producer, Philips, was considered. It accounted for 41% of the total estimated Community production of the product subject to investigation in the Community and thus constituted a major proportion of Community production pursuant to Article 5(4) of the Basic Regulation. Consequently, this producer will hereinafter be referred to as the 'Community industry' within the meaning of Article 4(1) of the Basic Regulation.*

7. *Designated Authority's Final Findings Anti-Dumping investigation concerning imports of Nylon Tyre Cord Fabric- (NTCF) from Indonesia, South Korea, Thailand and Taiwan.*

E. DOMESTIC INDUSTRY

8. (i) *The present petition for Anti-Dumping investigation has been filed by the Association of Synthetic Fibre Industry (ASFI) on behalf of domestic producers i.e. M/s. SRF Ltd., M/s. Nirlon Ltd., M/s. Century Enka Ltd and M/s. NRC Ltd. The petition has been supported by other domestic producer M/s Baroda Rayon Ltd. It has been claimed by petitioners that the four petitioner companies and the other supporting company M/s Baroda Rayon Ltd. are the only producers of NTCF in India and hence the petition has support of all the domestic manufacturers of NTCF in India and fulfils the requirement of requisite standing as required under the Rules.*

(ii) *It has been argued by the exporters and other interested parties that M/s SRF Ltd. have imported the subject goods during the period of investigation through a related company M/s SRF Overseas Ltd. They being related to the importers cannot file petition for Anti-Dumping investigation. Similarly M/s Baroda Rayons Ltd are related to one of the exporters M/s. Thai Baroda Industries Ltd which is an exporter under investigation. Therefore, both these companies cannot be the petitioners in Anti-Dumping investigation. Both these companies accounts for majority of domestic production of NTCF in India and therefore, the petition lacks requisite support from domestic industry as required under the Rules.*

(iii) In the Preliminary Findings, the Authority held that imports by M/s SRF Ltd represented 0.24% of the total imports from subject countries during the POI Besides; the imports by M/s SRF Ltd. represented only 0.08% of total production of NTCF of domestic industry during the POI. There is no evidence of any other imports by M/s SRF Ltd. from its related company M/s SRF Overseas Ltd during the POI. The Authority notes that the quantum of imports by M/s SRF Ltd from its related company M/s SRF Overseas Ltd., Dubai were in very insignificant quantities and would not justify the exclusion of M/s SRF Ltd from the scope of domestic industry. As regards, M/s Baroda Rayon Ltd., the Authority noted that M/s Baroda Rayon Ltd. was related to M/s Thai Baroda Industries Ltd who themselves were exporters of the subject goods and are subject to investigation in the present case. However, the present petition has been filed by four producers representing the domestic industry. M/s Baroda Rayon Ltd have merely supported the petition filed by other producers representing the domestic industry and as such M/s Baroda Rayon Ltd. is not an active applicant in the present petition.

F. The interested parties have made the following arguments on preliminary findings with regards to the standing of Domestic Industry. -

9. ARGUMENTS BY PETITIONER

- i. M/s. SRF Limited. M/s. Nirlon Limited, M/s Century Enka Limitd and M/s NRC Limited constitute the domestic industry in the present case. The imports by M/s. SRF from M/s. SRF Dubai does not amount to imports of allegedly dumped articles and consequently the question of excluding M/s. SRF from the scope of domestic industry does not arise. This position would apply keeping in view the definition of the domestic industry as it existed prior to the amendment in July, 1999.
- ii. Without going into the question whether the July, 1999 amendment is retrospective or prospective, in either case there is no warrant to exclude M/s. SRF from the domestic industry.
- iii. The argument that if M/s. SRF and M/s Baroda Rayon Corporation are eliminated, the remaining producers will account for less than 50% of the domestic production of NTCF and hence they cannot maintain an application is also incorrect. In such case, the remaining producers would constitute 100% of the eligible domestic production and would be entitled to maintain the application in their own right.

10. ARGUMENT BY EXPORTERS

- i. The Designated Authority ought to have applied the non amended definition of domestic industry which was applicable at the time of initiation of present investigation. As per these Rules there is mandatory exclusion from domestic industry of certain domestic producers. The Authority has arrived its provisional findings that M/s. SRF is related M/s. SRF Overseas Limited, a known exporter of subject goods and also the it has imported the subject goods during the period of investigation from its related company. The exclusion of M/s. SRF from the scope of domestic industry is mandatory and not discretionary. The import of subject goods irrespective of its quantity is enough to invoke exclusion of M/s. SRF Limited from the scope of domestic industry.

- ii. Besides, M/s. SRF, M/s. Baroda Rayon Corp. are also related to M/s Thai Baroda Industries Limited. The exclusion of M/s. SRF and M/s Baroda Rayon Corporation, would have the significance of eliminating domestic producers together accounting for more than 50% of Indian domestic production of subject goods from the purview of domestic industry. As such the balance domestic producers together account for less than 50% of Indian domestic production and they cannot constitute domestic industry for the purpose of Rule 2(b) As such the application filed on behalf of domestic producers other than M/s. SRF and M/s Baroda Rayon Corporation cannot be an application on behalf of domestic industry. Therefore, the present investigation is not maintainable and must be terminated.

11. EXAMINATION BY AUTHORITY

- i. The issue with regard to the standing of the petitioner has been examined by Designated Authority. Rule 2(b) and Rule 5(3)(a) of the Anti-Dumping Rules are relevant in this regard.
- ii. The Anti Dumping Investigations in the matter were initiated by the Designates Authority on 26.2.99 The petition has been filed by four of the domestic producers of NTCF in India, i.e. M/s SRF Ltd., M/s Nirlon Ltd., M/s Century Enka Ltd. and M/s NRC Ltd Further, the petition has been supported by another domestic producer of NTCF M/s Baroda Rayon Carp.
- iii. Thus, based on the evidence available on record, the petition was filed by four of the domestic manufacturers and was supported by one other manufacturer. None of the domestic manufacturers of the subject goods had opposed the petition. Hence, the petition had requisite support of domestic industry for initiation of investigation as required under Rule 5(3) (a) of the Anti-Dumping Rules as were prevalent on 26.02.1999.
- iv. During the course of investigation, it was brought to the notice of Designated Authority that M/s SRF Ltd., one of the petitioners in present investigation had imported on insignificant quantity of NTCF from M/s SRF Overseas Ltd. a related company It was further brought to the notice of Designated Authority that M/s Baroda Rayon Ltd., one of the domestic producers are related to M/s Thai Baroda Industries Ltd, against whom the investigation have been initiated.
- v. The Anti Dumping Rules (Rule 2(b) had been amended on 15th July, 1999 inter-alia with regards to the status of the domestic industry. Hence at the point of time of examining these facts that was brought to the notice of the Designated Authority. The Authority observed in its preliminary findings that since the imports by M/s SRF Ltd represent only 0.24% of the total imports from the subject countries during the Period of Investigation (POI), under the revised Rule 2(b), such insignificant quantum of imports would not justify exclusion of M/s SRF Ltd. from the scope of domestic industry.
- vi. The issue with regard to the standing of the domestic industry was also examined by the Authority with reference to the Rules as it existed prior to 15th July, 1999. The Rule 2(b) provides that the domestic industry shall be deemed to exclude such domestic producers who are related to the exporters or importers of the alleged dumped articles or are themselves importers thereof These provisions have to be read with provisions of Rule 5(3) (a) of the relevant Rules. Even, considering that M/s SRF Ltd and M/s Baroda Rayan Ltd are related to the importers or are

themselves importers, as per Rule 2(b) of the Rules, as existing prior to 15th July, 1999, the domestic industry would be represented by only M/s Nirlon Ltd., M/s Century Enka Ltd. and M/s NRC Ltd. In such an eventuality the petition had the support of 100% of the domestic producers of NTCF.

- vii. Thus, the domestic producers had the requisite standing to represent the domestic industry as required under the Rules even prior to the amendment in the Anti Dumping Rules on 15th July, 1999.
- viii. In view of the foregoing, Authority holds that the Petitioners had requisite standing to file the petition, as required under the rules and the present petition has been filed on behalf of domestic industry.

12. Anti-Dumping Investigation concerning imports of Pentaerythritol originating in or exported from China PR and Sweden.

6. The applicant has submitted that product being sold by Perstorp in India is Technical Pentaerythritol 95%, which is nothing but mixture of Pentaerythritol of two different purities, i.e. Technical Pentaerythritol 88% (30%) and Pentaerythritol Mono Grade 98% (70%). They have further argued that different customers require Pentaerythritol of different purities, ingredients and melting points to suit their process requirements and the product of required parameters is being supplied to the customers by mixing the product. Pentaerythritol Technical Grade, which contains Monopentaerythritol 89% is used in the manufacture of the same products as that are manufactured from Pentaerythritol (Mono) Grade containing Monopentaerythritol 98%. The purity of Pentaerythritol (mostly defined in terms of Monopenta) and other ingredients varies depending upon the molar ratio used for manufacture of the product and other process conditions. The purity of Pentaerythritol varies from min. 92% to max. 98%. Pentaerythritol of different purity are nothing but one like product and are within the scope of the present investigations. The Perstorp has submitted that they are one of the major domestic producer of the subject goods in India and manufacturer of technical Penta 95% and imports its raw materials such as mono penta 98% and technical penta 89 – 90% from Sweden. They have also argued that all these three Penta are of different grades can not be considered as like product.

7. On examination of the submissions filed by the interested party, it is noted that the claim of Perstorp Aegis that the imported raw materials are further processed to manufacture the subject goods under investigation was not substantiated with evidence and during the on the spot verification visit at their unit, it was found that different purities of Penta ranging from 89%-98% were supplied to the paint industry. In addition to various material provided by interested parties, the Authority relies upon verification conducted at the premises of Perstorp Aegis. It was found that the company had undertaken blending and re-bagging of Pentaerythritol of two different purities of the subject goods under consideration. It was also found that in the process of blending the imported products neither the essential product characteristics underwent a significant change nor the company employed a significant plant & equipment, investment therein, manufacturing process, and production activities. The technical literature available on the

product distinguishes Pentaerythritol and Dipentaerythritol as two different products. However, sufficient evidence was not been brought by Perstorp Aegis to establish their claim that monopenta and technical penta are two different products, having different product properties, production process, functions & uses, differ significantly in terms of pricing. On the contrary, investigations revealed that the two types have essential similar product properties, produced using same production process, similar functions & uses and fall under the same customs classification. The domestic industry has placed the SION norms for Penta (all grades) which implies the various grades of Penta are one like product and it was supplemented by the response of the user industry also. The technical literature available on this subject distinguishes Pentaerythritol and Dipentaerythritol as two different products not between monopenta and technical penta and none of the interested parties produced any evidence on monopenta and technical penta as two different products. The Authority notes that Pentaerythritol can be of two grades known as technical grade (TG) or nitration grade (NG), however there is no material difference found between these two grades and both the grades are produced out of same process. During the course of verification of costing and sales information of the domestic industry it was established from their sales and excise register that Paint Industry is using different purities of Penta in their manufacturing setup. During the verification visit, the domestic industry had shown that during the production process less than 2% of entire production of Penta results into the production of nitration grade whereas more than 97% constitutes as technical grade and they are the like product within the meaning of AD Rules. On the basis of information made available before Authority, it is noted that merely changes in the purity along with name (which varies between 92%-98%), the imported product does not become different from product under consideration, i.e., Pentaerythritol. It is also noted, even though the product resold by Perstorp Aegis may be different from imported product and may have been processed before selling, the resold product remains Pentaerythritol only and no verifiable evidence was placed by Perstorp Aegis which could establish that the imported product and resold products are not like products within the meaning of the AD Rules.

8. Rule 2(d) of the AD Rules specifies that "Like Articles" means an article which is identical or alike in all respects to the product under investigation or in the absence of such an article, another article, having characteristics closely resembling those of the articles under examination. In this context of this Rules, no significant/material evidence were provided to establish the difference between the subject goods manufactured by the domestic industry and the imported product from subject countries. The subject goods produced by the applicant is found comparable to the imported product in terms of a number of parameters which includes product properties, production process, functions & uses, pricing, customs classification. The domestic product is found commercially and technically substitutable to the imported product. On the basis of the evidence brought before the Designated Authority, the Authority holds that the goods produced by the domestic industry are like articles to the goods imported from the subject countries.

9. The Authority conducted an on-the-spot verification at the plant of M/s Perstorp Aegis in order to verify the claims of the company. It was found that the Unit-II (where the imported product is blended) at Silvassa is not in operation. The company was asked to explain in detail the production activities carried out by them and also provide information with regard to the following:-

- Production technology
- Plant & equipment installed
- Investment
- Production process
- List of raw materials consumed and details of consumption as per format A of the costing information and per unit consumption as per format B of the costing information
- Specifications of the "raw materials" consumed / the "finished product" produced
- Various functions & uses of the penta imported/ penta sold in the domestic market

10. The company did not provide full information. It was found that the production process is mere a blending of penta of two different purity which results in penta of a different purity. It could neither be established by Perstorp that the imported product and resold product was significantly different nor they could establish that the process employed by them resulted in a different product. The company was also asked to provide separate details of cost of production of the Pentaerythritol produced at two different plants. However, no such information regarding the cost of production was provided. In view of the above, it could not be established that imported Pentaerythritol and Pentaerythritol produced and sold by the company at two different units and Pentaerythritol supplied by the domestic industry are not like products.

11. The Authority notes that even though the company claimed that it is also a domestic industry, they did not provide any information with regard to injury to the domestic industry. The company could neither able to establish that the goods imported by them are not like product to the goods sold by them nor the company could establish that the goods imported by them and goods produced and sold by the domestic industry (Kanoria Chemicals) are not like products.

15. On examination the submissions of the interested parties regarding their claim that goods imported by Perstorp Aegis are raw materials and not the subject goods under investigation, the Authority found that the goods imported by Perstorp Aegis were nothing but Pentaerythritol of various grades. The Authority further notes that Perstorp Aegis, an importer of the subject goods and related to an exporter of the subject goods, in itself is sufficient to exclude them from the constituent of the domestic industry. Therefore, the Authority considers that exclusion of the company is justified since they have imported significant quantity of subject goods from their related company and did not provide any costing or injury information for their claim of being treated as domestic industry inspite of requests made by the Designated Authority. Asian Paints is another producer, producing the product substantially for its own captive requirements. The

applicant has submitted that the production of Asian Paints should be excluded since the production of Asian Paints may not compete in merchant market and they may not have experienced injury from such dumping of subject goods in Indian market. On examination of the arguments of the applicant, the Authority has found appropriate to include production of Asian Paints for determining standing of the applicant. The Authority notes that Perstorp, Sweden and Perstorp Aegis, India are related to each other in view of Rule 2(b) of AD Rules. Since Perstorp, India is a subsidiary of Perstorp, Sweden and therefore the later is in a position to control the former hence it was found appropriate to exclude as a constituent of the domestic industry. In view of the above, the Authority holds that the applicant fulfils the requisite criteria to satisfy standing and constitutes domestic industry, as required under Rule 5(a) and (b) and Rule 2(b) of AD Rules.

13. Designated Authority's Final Findings in the matter of Anti-Dumping Investigations concerning imports of 'Carbon Black used in rubber applications' originating in or exported from Australia, China PR, Iran, Malaysia, Russia and Thailand.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

16. Rule 2(b) of the AD Rules defines domestic industry as under:-

"Domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers may be deemed not to form part of domestic industry".

17. The Application has been filed by Association of Carbon Black Manufacturers on behalf of the domestic industry. M/s. Phillips Carbon Black Limited and M/s. Hi-Tech Carbon have provided injury information, whereas M/s. Continental Carbon India Limited has supported the application.

Issue raised by the Interested Parties

18. M/s Jiangxi Black Cat Carbon Black Co., Ltd ("Black Cat") has, inter alia, contended that the applicant does not have standing in view of relationship of M/s Hi-Tech carbon India with M/s Liaoning Birla Co. Ltd (China) and M/s Thai Carbon Black Public Company Ltd. (Thailand). Further, Phillips Carbon is also ineligible in view of imports made by M/s Ceat Ltd., which is their related company.

Views of the Domestic Industry

19. The Domestic Industry has submitted that Rule 2(b) had been amended for the reason that a discretion was required to be provided to the Designated Authority

to include or exclude a company who is found to be related to a foreign supplier or an Indian importer or who itself imported the material. Since the fact of imports or relationship does not automatically imply exclusion and further since the ordinary/general rule is to include all parties, it is required to be established by the interested parties seeking exclusion that such exclusion is indeed necessary in the facts and circumstances of the present case. However, barring mere claim, no factual material has been provided by the interested parties justifying exclusion of these two companies. M/s Ceat Ltd. and M/s Phillips Carbon Black Ltd. are not related companies. The Applicant has further submitted that even though the interested parties have not justified the need for exclusion, facts of the case do not justify exclusion of either company. The applicant has made reference to text books on anti-dumping and practices of other investigating authorities in this regard and has contended that there is no justification whatsoever for exclusion of either companies. The two companies have not reduced their production and have not turned to trading. In fact, in case of M/s Hi-Tech Carbon, the related Thai company has exported the entire material only under advance licence (whereas there is no import from the Chinese related company). In case of M/s Ceat Ltd. also, majority of the imports are under advance licence. The Applicant has also claimed that the volume of exports made from Thailand by related company of Hi Tech Carbon is significantly low in terms of total imports and consumption of the product in India. Similarly, the imports made by M/s Ceat Ltd. constituted a very small proportion in its total sales.

Examination by the Authority

20. The Authority notes that M/s Hi Tech Carbon is related to M/s Thai Carbon Black Public Company and M/s Liaoning Birla Co. Ltd. M/s Hi Tech Carbon has claimed that M/s Liaoning Birla Co. has not exported carbon black in Indian market. Even though M/s Thai Carbon Black Public Company Ltd. has exported the subject goods to India, the entire volume of exports is only 2178 MT, out of total of 515350 MT in POI. Some interested parties have reiterated their argument regarding inclusion of M/s Hi Tech in view of exports by their related entity. The Authority, however, notes that the exports made by the Thai related company are not so significant and not under such condition to take a view that M/s Hi Tech should be considered ineligible to be considered as a part of the domestic industry. The Authority notes that the Hi Tech Carbon has not turned to importing and trading. The focus of the company remains substantially on production. Further, there is no evidence on record to show that M/s Phillips Carbon Black Ltd. and M/s Ceat Ltd. are related companies. Even though ATMA has participated in the present investigations as an interested party and M/s Ceat Ltd. is their member, there is no evidence on record to show that M/s Ceat Ltd. has imported significant volumes of the product under consideration from the subject countries after payment of customs duties.

21. The Authority notes that the volume of exports made by M/s Thai Carbon Black is too insignificant in relation to production and consumption in India. Besides, it has not been established that M/s Hi Tech Carbon should be excluded from the purview of domestic industry because of exports made by the related company. The Authority considers it appropriate to include M/s Hi Tech Carbon within the scope of the domestic industry. With regard to eligibility of M/s Phillips

Carbon, the Authority notes that the interested parties have not provided sufficient evidence to justify its exclusion.

22. *As per the evidence available on record, production of M/s Phillips Carbon Black Ltd. and Hi-Tech Carbon account for a major proportion of the domestic production of like article, being significantly more than 50% of Indian production. Further, the petition is supported by M/s Continental Carbon. The application thus satisfied the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules. Further, M/s Phillips Carbon Black Ltd. and M/s Hi-Tech Carbon are being treated as "domestic industry" within the meaning of Rule 2(b) read along with Rule 2(d) of the AD Rules for the present purpose.*

Imports by petitioner itself-from unrelated exporter

14. *Commission Decision No 307/2000/ECSC of 10 February 2000 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain hot-rolled flat products of non-alloy steel originating in the People's Republic of China, India and Romania. Official Journal L 036, 11/02/2000 P. 0004 -- 0019*

1. Definition of the Community industry

1.1. Total Community production

(39) Within the Community, the product concerned is manufactured by:

- 12 producers which lodged the complaint,*
- five Community producers supporting the complaint, and*
- one Community producer which did not support the complaint.*

(40) Some exporting producers argued that certain complaining Community producers had imported hot-rolled flat products of non-alloy steel from the countries concerned by the proceeding during the "investigation period". The Commission therefore examined whether any of them should be excluded from the definition of the Community production.

It was found that none of the producers cited had itself imported the product in question. One trading company belonging to the same corporate group as a complaining Community producer had, however, made such imports during the investigation period. This company which purchased steel throughout the world, including from the producer belonging to the same group, and sold mainly in third countries on its own account was found to act independently. In fact, the structure of the grouping to which both companies, belong is such that each maintains its own financial accounts, submits separate annual reports, and has no profit and loss transfer agreement with the holding company. Furthermore, separate income tax returns are filed, each has its own board of directors, and business relations with other companies in the group are carried out at arms length on identical terms to those applicable to other companies where no legal relationship exists. These purchases could not, therefore, affect the status of the producer concerned, and it was considered that there were no grounds for excluding any producer of hot-rolled flat products of non-alloy steel from the definition of the Community production.

(41) The 18 Community producers of hot-rolled flat products of non-alloy steel mentioned above, therefore, constitute the Community production within the meaning of Article 4(1) of the basic Decision.

1.2. Community industry

(42) Of the 12 producers who lodged the complaint, ten replied to the Commission's questionnaires, allowed on-spot investigations and provided the Commission with additional information when requested; they were therefore considered as cooperating in the investigation.

These 10 Community producers are: Aceralia (Spain), British Steel (United Kingdom), Dillinger (Germany), GTS (France), ILVA (Italy), Palini and Bertoli (Italy), Salzgitter (Germany), Thyssen (Germany), Tramelal (Italy), Voest Alpine (Austria). These companies accounted for more than 75 % of total Community production in the IP, and thus represented a major proportion of the Community production within the meaning of Article 5(4) of the basic Decision, and are hereinafter referred to as "the Community industry".

(43) Eight of these companies are fully integrated, i.e. they produce or buy within the group they belong to, the steel slabs used for rolling the product concerned. The two remaining companies are so-called re-rollers, which buy steel slabs on the free market for manufacturing the product concerned.

For the purpose of the provisional findings, on-spot investigations were carried out at the premises of seven complaining producers. The total production of these seven companies represented about 80 % of the total output of the Community industry.

1.3. Other Community producers

(44) The two remaining complainant producers, with production accounting for less than 2 % of the total output of the 12 complaining producers, did not reply to the Commission's questionnaires; they were therefore considered not to be cooperating in the framework of the current investigation and thus not part of the Community industry.

Of the six other producers, one supporter replied partially to the Commission's questionnaires and in principle allowed on-spot investigations, while the other five companies did not reply at all to the Commission's questionnaires.

These eight companies are referred to hereinafter as "other Community producers".

15. Commission Regulation (EC) No 1497/2001 of 20 July 2001 imposing provisional anti-dumping duties on imports of urea originating in Belarus, Bulgaria, Croatia, Estonia, Libya, Lithuania, Romania and the Ukraine, accepting an undertaking offered by the exporting producer in Bulgaria and terminating the proceeding as regards imports of urea originating from Egypt and Poland. Official Journal L 197, 21/07/2001 P. 0004 - 0027

1. Definition of the Community industry

(154) Of the ten complainant Community producers, one (Kemira Agro Rozenburg BV) did not cooperate with the Commission, and was, therefore, not regarded as being part of the Community industry. Another Community producer (Irish Fertiliser Industries Ltd) did not provide the information requested in the format required and is considered not to have cooperated with the Commission, thus likewise not forming part of the Community industry.

(155) A number of exporting producers claimed that, as some Community producers also purchased and imported urea from the countries concerned, these producers should be excluded from the definition of the Community industry.

(156) The investigation established that some of the complainant Community producers purchased the product concerned from sources both inside and outside the Community, including from the countries concerned. However, in the most part these purchases were small in volume, and were made to cover shortfalls in supply due to maintenance. One company did make more substantial purchases during the IP, equivalent to 20 % of its production. These purchases were made to supplement their own product range, were not sufficient to consider the company as anything other than a Community producer of urea. For these reasons, it is provisionally determined that all eight companies can be included in the Community production.

(157) As these eight complainant cooperating Community producers represent more than 76 % of the Community production of urea they constitute the Community industry within the meaning of Article 4(1) and Article 5(4) of the basic Regulation.

16. Commission Regulation (EEC) No 1418/88 of 17 May 1988 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of serial-impact dot-matrix printers originating in Japan. Official Journal L 130, 26/05/1988 P. 0012 – 0033

G. COMMUNITY INDUSTRY

(60) There are eight producers of SIDM printers in the Community. The investigation has shown that during the period under investigation the four Europrint members manufactured about 65 % of the total Community output of SIDM printers, hence a major proportion of the total Community production of the like product within the meaning of Article 4 (5) of Regulation (EEC) No 2176/84.

(61) The Commission also found that three of the Europrint members, i. e. Mannesmann-Tally, Hisi and Philips, imported, during the investigation period, SIDM printers from Japan in quantities which amounted respectively to 51 %, 42 % and 11 % by volume of the total sales of these Community producers (under the assumption that all imported printers are also sold).

(62) In this respect, CJPRINT submitted that a complainant should be excluded if its imports cannot be regarded as interim defensive measures and if it is simply using its resources as a multinational corporation to import products from those sources which it concludes can provide the best products at the lowest price irrespective of where in the world the source may be located. Consequently, the three importing Community producers should, according to CJPRINT, be excluded because their imports cannot be considered to be an interim defensive measure as the imported products amount to substantial quantities, are resold under their own brand name at a substantial profit and have led to increasing market shares.

(63) With regard to these arguments, the Commission noted that Article 4 (5) of Regulation (EEC) No 2176/84 leaves a certain discretion to the Community institutions as to whether or not they exclude certain importing Community producers. When exercising this discretion, the Commission considered that it is normal for large firms engaged in international business to buy part of their range of models from other producers. The mere fact that a Community producer has imported goods of a kind for which dumping has been found and has resold them with a reasonable profit margin, does not, in itself, prevent it from complaining about dumping or having its injury taken into account. In deciding whether to exclude a Community producer from consideration, the Commission took into account whether the importing of the dumped products and their sale on the Community market should, due to the reasons behind this, the volume of such imports or any other

circumstances, be considered as part of normal and sound business practice on the part of a producer. In this respect, it is particularly important to what extent these imports can be considered as having been made in self defence.

(64) As far as the reasons for these imports are concerned, the Commission has found that all printer models imported by the Community producers belong to the low end segment of the SIDM printer market. Before 1983, all three companies were represented in this market segment with their own manufactured printers. The decisions to replace their existing printer models by printers of Japanese origin were, in the first place, based on the general consideration that, for defending their position on the market, it is necessary for an SIDM printer manufacturer to offer a full range of printers and to be represented in all market segments. Indeed, without offering a full range, the three companies would have run the risk of also losing sales and customers in the other market segments and, consequently, be totally driven out of the printer market. Secondly, because of the low price level on the Community printer market caused by imports from Japan, the costs of development and production of a new printer model would not have been recovered within a reasonable time. The prices which the Japanese manufacturers offered were so low that, even at the low level of resale prices on the Community market, the imported products could be resold at a reasonable profit.

(65) As far as the volume and other circumstances of these imports are concerned, the Commission considered that the quantities concerned were not so high as to make it necessary to exclude the three companies concerned. The value of imports represented a substantially smaller proportion of the three companies' total net sales than the volume of imports. This is because all the imports were of relatively low-priced printers.

(66) Moreover, the number of printers imported represents a modest proportion of total sales in the Community in the lower end of the market. In 1983, imports from Japan by Community producers represented 4 460 units, i. e. 0,5 % of Community consumption. In 1986, imports by Community producers represented 91 138 units, i. e. about 4,3 % of total Community consumption.

(67) As far as the profit margins on the sales of these imported printers are concerned, the investigation has shown that they were not more than 5 % (as a percentage of return on sales) higher than the return on sales of the Community producers' printers.

(68) In the light of these circumstances, the Commission is of the opinion that both the reasons which led the three companies to import SIDM printers from Japan as well as the other circumstances can be considered as a reasonable measure of self-defence necessary to stay in the market. Since the market conditions have worsened for the Community producers since 1983, the fact that these imports are not a temporary measure cannot be considered as decisive in these proceedings. Thus, the Commission has come to the conclusion that, for the purposes of the preliminary findings, the three Europrint members who have imported dumped SIDM printers from Japan should not be excluded from the Community producers representing the Community industry.

(69) The Commission therefore interpreted the term 'Community industry' as referring to the four Community producers that are members of Europrint.

17. Commission Regulation (EC) No 165/97 of 28 January 1997 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain footwear with textile uppers originating in the People's Republic of China and Indonesia. Official Journal L 029, 31/01/1997 P. 0003 – 0018

D. COMMUNITY INDUSTRY

1. The complainant producers

(54) The investigation confirmed that the determination set out in recital (3) was correct and, accordingly, the Commission considers that, for the purposes of this proceeding, the complainant companies constitute the Community industry within the meaning of Article 4 (1) and Article 5 (4) of the Basic Regulation.

2. Application of Article 4 (1) (a): Definition of the 'Community industry'

(55) During the course of the investigation it became apparent that a Community producer in the first group, as defined in (6), was also importing the dumped product from the countries subject to the present proceeding. In those circumstances, the Commission examined whether, in the light of Article 4 (1) (a) of the Basic Regulation, that company should be excluded from the definition of the Community industry.

In this respect it should be recalled that Article 4 (1) (a) does not provide for the automatic exclusion of producers which themselves import the dumped product, but rather obliges the Community institutions to examine on a case-by-case basis whether the exclusion of any producer in such a situation is warranted.

For the purpose of carrying out that examination, it appeared appropriate to determine whether that company was primarily a producer with an additional activity based on imports, merely supplementing its Community production, or whether it was an importer with relatively limited additional production in the Community. Such an approach seemed to be both reasonable and consistent with the practice of the Community and the case-law of the Court of Justice (5).

The investigation showed that the imports of dumped products from the countries concerned accounted for less than 25 % of the turnover of the company in question. It is therefore the opinion of the Commission that the main core of business for the company was production of footwear in the Community and that it was not shielded from the dumping practices. Therefore, for the purposes of Article 4 (1) and Article 5 (4) of the Basic Regulation, that company was considered, along with the other cooperating producers, as forming the Community industry.

18. Commission Regulation (EC) No 1069/97 of 12 June 1997 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of cotton-type bed linen originating in Egypt, India and Pakistan. Official Journal L-156, 13/06/1997 P. 0011–0033

E. COMMUNITY INDUSTRY

1. Definition of the Community industry

(52) After elimination from the list of companies included in the complaint of seven of them found not to be complainants, the Commission found that the remaining companies represented a major proportion of Community production of bed linen and satisfied the requirements of Article 5 (4) of the basic Regulation.

After initiation of the proceeding, a number of organizations representing exporters and importers of bed linen from the countries concerned alleged that several of the producers which made up the Community industry were also importing the dumped product from the countries subject to the proceeding. In these circumstances, the Commission re-examined whether, in the light of the provisions of Article 4 (1) (a) of the basic Regulation, these companies should be excluded from 'the Community industry'.

(53) For the purposes of carrying out this reexamination, and in accordance with consistent practice of the Community institutions, it appeared appropriate to determine whether those companies were primarily producers in the Community with an additional activity based on imports and merely supplementing their Community production, in order to be able to offer a complete range of products, or whether they were importers with relatively limited additional production in the Community.

(54) In all but one case, companies alleged to be importing bed linen from the countries concerned were among those selected in the sample of Community producers (see recitals (58) to (61)). The Commission was therefore able to examine the extent of these imports during the course of its on-the-spot verification visits. For all but one of these sampled companies, the investigation showed that the imports of dumped products from the countries concerned had accounted for less than 10 % of the turnover of the companies in question in the period examined. It is therefore the opinion of the Commission that these companies were not shielded from the effects of dumped imports and that for the purposes of Article 4 of the basic Regulation these companies may be considered along with the other cooperating producers, as belonging to the Community industry.

In the case of the one other sampled company, it was found that a higher proportion of its bed linen sales in the investigation period were of Pakistani origin and also that only a minor part of its sales were of its own production. It appeared in addition that the company's future activity was likely to be further focused on imports. This company, whose core interests were deemed clearly not to be in the production of bed linen within the Community, was therefore eliminated from the Community industry.

(55) Since all but one of the sampled companies alleged to be importing bed linen from the countries concerned were found, on examination, not to be doing so in quantities sufficient to warrant exclusion, it has been considered that the allegations made by the exporters in this regard were excessive and unreliable. Consequently, on the basis of the findings concerning the sample, no exclusion of the one non-sampled company is warranted. This company should, therefore, be retained in the definition of the Community industry. In any event, this issue has no substantial influence on the question of the representativity of the Community industry.

(56) Three other companies were eliminated. In one case the company was found no longer to produce bed linen. In two other cases the companies did not respond to the requests for information which were addressed, via Eurocoton and the national associations, to those complainants which were not selected in the sample of Community producers, in order to obtain information on the Community industry as a whole.

(57) The remaining 35 companies, which cooperated with the enquiry and are located in France, Germany, Italy, Spain, Portugal, Austria and Finland, represented a major proportion of total Community production in the investigation period. These

companies were therefore deemed to make up the Community industry under the terms of Article 4 (1) of the basic Regulation.

2. Sampling

(58) Because of the number of companies in the Community industry it was decided to resort to sampling, in accordance with Article 17 of the basic Regulation.

(59) 27 of the 35 companies, representing 96,7 % of Community industry production and 32,5 % of total Community production in 1995, (the latest figures available at the time of sample selection) were situated in Germany, Italy, France and Portugal.

(60) As a general rule, Community producers sell a large proportion of their bed linen production in their own Member State, in part because of differences between Member States in standard products and sizes. This is true of Germany, France and Italy which are both the largest producers of bed linen in the Community and very important importers. The producers in these Member States were therefore clear candidates for assessing the impact of the imports on the Community industry.

Producers in Portugal, for their part, sell a large proportion of their production in other Member States and represent about one third of the production of complainant companies. Even though Portugal is not a significant importer, therefore, it was decided that the effect of the imports on the producers there should be assessed and that Portugal should be represented in the sample.

(61) In consultation with the complainant Eurocoton an initial list of 19 companies was arrived at (eight from France, six from Germany, four from Italy and one from Portugal).

In the course of the enquiry one of these companies was eliminated from the sample for failing to cooperate with the enquiry. As a result of this exclusion, and of the exclusion of the other company under Article 4 (1) (a) of the basic Regulation (see recital (54)), in the following injury analysis information given for 'sampled producers' is based on information supplied by the remaining 17 producers which represented 20,7 % of total Community production and 61,6 % of the production of the Community industry. They included the largest Community industry companies in Germany, Italy and Portugal, and also smaller producers. The Commission therefore considered this sample to be representative of the Community industry.

19. Commission Regulation (EC) No 1023/97 of 6 June 1997 imposing a provisional anti-dumping duty on certain imports of flat pallets of wood originating in Poland and accepting undertakings offered from certain exporters in connection with those imports. Official Journal L 150, 07/06/1997 P. 0004 – 0017.

D. COMMUNITY INDUSTRY

1. Definition

(32) The Community producers who supported the complaint in this proceeding constituted a major proportion of the total Community production of the product concerned, in accordance with Article 4 (1) and 5 (4) of the Basic Regulation.

One importer claimed that several producers in the Community were importing the allegedly dumped pallets from Poland. The investigation has nevertheless shown that the quantities of pallets imported from Poland by some Community producers were relatively small in relation to the production volume of such producers whose core

interests clearly remained in the production of pallets in the Community. The limited imports in question were a defensive reaction to low-priced imports from Poland.

Consequently, it would not be warranted to exclude producers importing pallets from Poland from the assessment of Community industry. Thus, the Community producers who supported the complaint represent the Community industry within the meaning of Article 4 (1) of the Basic Regulation.

20. Commission Regulation (EC) No 255/2001 of 7 February 2001 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of integrated electronic compact fluorescent lamps (CFL-i) originating in the People's Republic of China. Official Journal L 038, 08/02/2001 P. 0008 – 0021

1. Definition of the Community industry

(49) In the course of the proceeding Philips Lighting BV informed the Commission that it no longer wished to be treated as a member of the group of complainants. Therefore, data relating to Philips Lighting BV were not taken into account for the purpose of determining the Community industry and injury to the Community industry. It should be noted that the provisional conclusions concerning injury and causal link would not have been different had the data relating to Philips Lighting BV been taken into consideration.

(50) The two remaining cooperating Community producers account for more than 85 % of the Community production of CFL-i during the IP.

(51) Several exporting producers submitted that the complainants are themselves importing the product concerned from the PRC. In this respect, it emerged that the two remaining co-operating Community producers had indeed imported CFL-i from the country concerned and resold those imports. According to Article 4(1)(a) of the basic Regulation "[...] when producers are related to the exporters or importers or are themselves importers of the allegedly dumped product, the term 'the Community industry' may be interpreted as referring to the rest of the producers". During the IP, on average 14,6 % of the total sales of CFL-i by these producers in the Community originated in the country concerned. However, despite these sales of imported CFL-i, the primary activity of these companies remained in the Community. Furthermore, the sales are explained by the need for the complainants to complete their product range so as to be able to satisfy demand, as well as by the attempt to defend themselves against low priced imports due to dumping. Consequently, the described trading activity of these producers did not affect their status as Community producers.

(52) The two remaining Community producers are therefore deemed to constitute the Community industry within the meaning of Article 4(1) and Article 5(4) of the basic Regulation.

(53) As the Community industry is thus constituted of only two producers, all figures relating to the latter had to be indexed for confidentiality reasons.

2. Community consumption

(54) Community consumption was established on the basis of the sales volumes of the Community industry and of Philips Lighting BV on the Community market, Eurostat import figures concerning the volume of imports from the country concerned and from other third countries, duly adjusted where appropriate.

(55) In this respect it was found that, as mentioned above, not only CFL-i are imported into the Community under CN code 85393190, but other products as well. As a consequence, an estimate of the percentage of CFL-i in all products imported under this code was made for each country exporting CFL-i to the Community. These estimates were based on the questionnaire replies by cooperating importers that were found to trade the totality of the imports of CFL-i from certain countries, information provided by the complainant as well as by the Chinese exporting producers as verified by the Commission.

(56) On this basis, Community consumption increased by 117 % between 1996 and the IP from 56,9 million units to 123,3 million units. Steep increases occurred in particular between 1997 and 1998 and between 1998 and 1999/IP.

21. Commission Regulation (EC) No 1833/98 of 25 August 1998 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of bicycles originating in Taiwan. Official Journal L 238, 26/08/1998 P. 0010 - 0026

F. COMMUNITY INDUSTRY

1. Representativeness

(43) Before the initiation of the investigation and in order to confirm the necessary support for the complaint, the Commission requested all known producers in the Community to submit basic information as to their respective production volume and to clarify their position with regard to the complaint lodged. Community producers representing around 60 % of the total Community production expressly supported this complaint.

(44) By virtue of Article 4(1) of the Basic Regulation, the Commission investigated whether or not producers supporting the complaint, who themselves imported some of the allegedly dumped bicycles from Taiwan, should be excluded from the determination of Community production.

It was found that those imports were relatively small in relation to the total production in the Community of the said producers and that their core interests were thus considered to be in the Community. It was established that the limited imports made by the said producers were a defensive reaction against low priced imports from Taiwan and not made because these producers were not able to produce the types of bicycles imported. On this basis, it was decided that such producers should not be excluded in determining the Community production. Data relating to these imports were disregarded when the injury factors pertinent to the situation of the Community industry were established.

(45) It follows that in accordance with Articles 4(1) and 5(4) of the Basic Regulation the Community producers supporting the complaint constitute the Community industry as their collective output represents a major proportion of total Community production (hereinafter referred to as the 'Community industry').

22. Designated Authority's Final Findings in the matter of Anti-Dumping (Sunset Review) investigations Metronidazole originating in or exported from China PR

D. DOMESTIC INDUSTRY

6. In the original investigation the application for anti-dumping investigation was filed by M/s. Aarti Drugs Ltd., Mumbai and M/s Aarey Drugs & Pharmaceuticals, Mumbai on behalf of the domestic industry. In the present sunset review the information/data has been provided by M/s Aarti Drugs Ltd., Mumbai M/s Unichem Laboratories Ltd., Mumbai and M/s J B Chemicals Ltd., Mumbai. The data and information submitted by M/s Aarti Drugs Ltd and M/s Unichem Laboratories Ltd. has been considered for analyzing the injury to the domestic industry. The data provided by M/s J B Chemicals has been disregarded for injury analysis as the domestic sales of this company during POI was only 1 MT whereas rest of the production had been exported.

7. In this case, during POI domestic industry had imported approximately 50% of the total imports of subject goods from China PR in which M/s Aarti Drugs Ltd. account for 40%, M/s Unichem Laboratories Ltd. account 3.07% and M/s J B Chemicals account for 7.15% of total imports. It has been contended that imports were made under Advance Licenses of Duty Exemption Scheme for manufacture of Metronidazole Benzoate for export purpose only and did not enter into commerce of the country, therefore, applicants cannot be excluded from purview of domestic industry.

8. This issue has been examined in terms of Rule 2(b) of Anti Dumping Rules and Article 4.1(i) of the Anti-Dumping Agreement. As per Anti-Dumping Agreement 'when producers are related to exporters or importers or are themselves importers of the allegedly dumped product, the term 'domestic industry' may be interpreted as referring to the rest of producers'. As per Rule 2(b) of the Rules, 'domestic industry' means the domestic producer as a whole engaged in manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major production of total domestic production of that article except when such producers are related to exporters or importers of the alleged dumped articles or are themselves importers thereof in which case such producer may be deemed not to form part of domestic industry'.

9. The Authority examined the issue on imports made under Advance Licenses by the applicants. As per Foreign Trade Policy of India, the inputs imported for export production cannot be sold in India. Inputs imported under Advance Licenses after processing/manufacturing necessarily have to be exported. Therefore, the Authority is of the view that inputs imported under Duty Free Advance Licenses when used for export purpose only will not disqualify the producers from domestic industry under Rule 2(b) of AD Rules.

10. The domestic industry has also raised the issue that J B Chemicals should be treated as domestic industry as per definition in Rule 2(b) of AD Rules as Rules refer to producers as a whole engaged in manufacturing of like article. The Authority has examined this issue and is of the view that M/s J B Chemicals is a part of domestic industry as per Rule 2(b), however, its data has not been used for injury analysis as injury to the domestic industry is analysed with reference to its sales in the domestic market. In this case M/s J B Chemicals had sold only 1 MT of its production in the domestic market during POI whereas rest of its

production had been exported. As sale of 1 MT by M/s J B Chemicals would be insignificant for its impact on the injury to the domestic industry, therefore, the data of this company has been disregarded for the purpose of injury analysis.

23. Designated Authority's Final Findings in the matter of Anti-Dumping investigations concerning import of Seamless Tubes from Austria, Czech Republic, Russia, Romania and Ukraine.

6. On Standing: Argument raised by Domestic Industry:

The petition was filed by Association of Seamless Tubes Manufacturers on behalf of the three participating companies viz. MSL, KSTL and ISMT. There are six companies in India who have created capacities for Seamless Tubes production. TISCO, Remi Metals and BHEL are the other three companies who have the capacity for production of the subject goods. The petition is supported by Remi Metals. The Designated Authority has determined the locus as follows:

- i. Remi Metals and BHEL have been considered as importing the subject goods and thus have been excluded.*
- ii. MSL has been considered as related to Jindal Drilling and Industries Ltd. that has important large volumes of the subject goods from the named countries.*
- iii. The production of TISCO has been considered for determining the locus.*

2. Domestic Industry comments as follows:

- i. Imports from Remi Metals and BHEL : Domestic Industry agrees with the findings of the Designated Authority that these companies have imported the subject goods and therefore should be excluded from the scope of the present investigation. BHEL is largely a captive consumer of the subject goods. Production of BHEL is required to be excluded from the eligible production.*
- ii. The Designated Authority has -considered the production of TISCO in the eligible production. Though there is no implication with regard to the standing of the petitioners to file the present petition whether TISCO is considered within the eligible production, as the standing conditions are satisfied in any event, it is submitted that while initially TISCO conveyed verbally that they would be supporting the petition it was later considered more appropriate by them to remain neutral as they were not at present producing the subject goods. TISCO may therefore be excluded.*
- iii. It is submitted that MSL cannot be treated as related to an importer and cannot be excluded from the scope of the present investigation. A discretion has been provided to the Designated Authority in the amendment of the Anti-Dumping Rules dated 15.7.1999 to decide whether or not a producer who is related to an importer, exporter or itself is an importer of the alleged dumped goods should be included in the investigations. The Designated Authority in the case of PSF, held that though Reliance Industry itself had imported the subject goods it qualified to be included within the scope of domestic industry. Similarly, in case of Nylon Tyre Cord Fabric, the DA held that SRF qualified to be included*

within the scope of domestic industry inspite of the fact that it was related to an importer. In the instant case the petitioner company has itself not imported any volume's and the injury assessment would not have got biased in any way. It is submitted in this connection that

- a. *JDIL and MSL are public limited companies and are not related under any provision of the Company's Act, 1956. None of them is either a related company or a subsidiary of the other one in terms of Section 4 of the Companies Act, 1956. They were neither under the same management in terms of Section 370 (1B) of the Companies Act, 1956 nor were in the same group in terms of Section 372 (11) of the Companies Act, 1956.*
- b. *The main business carried on by MSL and JDIL are different. MSL is engaged in manufacture of Seamless Pipes whereas JDIL is mainly engaged in off-shore oil well drilling. It is also engaged in a limited extent in threading, end-finishing, cold pilger, heat treatment, etc. of seamless pipes. Jindal has imported all the material from Volzhsky Pipe Plant who has cooperated with the Authority. The volumes imported by the company are in the region of * * * MT, which constitute an insignificant proportion of the Indian demand.*
- c. *The day-to-day functioning of JDIL is conducted by the Whole time Director subject to the control of the Board of Directors of the company. Likewise, the day-to-day functioning of MSL is conducted by the Managing Director subject to the control of the Board of Directors of the company. Both the companies have their own professional Board of Directors. It is evident from the constitution of the Board of Directors of the two companies that there is only one common Director in the Board of the two companies who is Shri D.P.Jindal. The board cannot take any decision unless the decision is approved by a minimum of two directors in MSL as is also the case with JDIL. It is submitted that the common Director cannot in any situation influence the decision as he lacks necessary quorum.*
- d. *Public Limited companies like MSL and JDIL are basically run by the Board of Directors who control all aspects of business. Since there is only one common director in the board of the two companies, there is no way one company can exercise direction or restraint over the other. One of the important facts to note is that JDIL has imported the sizes which are not produced by MSL.*

7: Arguments raised by ONGCL and Volszkhy:

The investigation in this case was initiated on 21.5.1999 and on that day the un-amended rule 2 (b) was in force. This rule did not give any discretion to the Designated Authority and every domestic producer who is related to the exporter or importer or who has imported the alleged dumped article had to be excluded from the purview of the term "domestic industry". The fact that Maharashtra Seamless Ltd. is related to an importer of the alleged dumped article was brought to the notice of the Authority by ONGCL & Volszkhy. The European Council Regulation on antidumping, in addition to defining the term "related" specifies a company which holds more than 5% of the shares in another, as related to the

other. The definition of the term "related" as used by the European Commission is extracted below:

"For the purpose of completing this questionnaire, a company should be considered to be related if it holds directly or indirectly more than 5% of your capital or otherwise has controlled over your company or if your company holds more than 5% of its share capital or you otherwise control it. Furthermore, companies under the same holding are considered to be related". In fact the supply by the JDIL of pipes imported from the countries under investigation compete in the same market as the pipes supplied by MSL and hence MSL has to be excluded.

9. DOMESTIC INDUSTRY:-

The petition has been filed by the Association of Seamless Tubes Manufacturers on behalf of M/s Maharashtra Seamless Ltd., M/s Kalyani Seamless Tubes Ltd., and M/s Indian Seamless Metal Tubes Ltd. Other domestic manufacturers of the subject goods are Tisco, Remi Metals and BHEL.

The above mentioned six companies have created capacity for production of seamless tubes. BHEL has created capacity primarily for captive consumption. It is noted that Remi Metals has imported 7884.79MT of the subject goods from the subject countries during the period of investigation. BHEL has also imported the subject goods but from sources other than the listed countries. After careful consideration of the above, it was decided by the Authority to exclude Remi Metals and BHEL from the scope of domestic industry in view of captive consumption by BHEL and the substantial imports made by Remi Metals of the subject goods from the named sources. Tisco has suspended production and is not a supporter of the present petition.

As stated at para 8 of these final findings, the domestic industry is constituted of M/s Maharashtra Seamless Ltd., M/s Kalyani Seamless Ltd., and M/s Indian Seamless Metal Tubes Ltd., who account for 100% of the total eligible domestic production of the subject goods and thereby have the required standing to file the petition under the Rules.

Imports by petitioner itself from Other than Subject country

24. Council Regulation (EC) No 769/2002 of 7 May 2002 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of coumarin originating in the People's Republic of China. Official Journal L 123, 09/05/2002 P. 0001 – 0009

DEFINITION OF THE COMMUNITY INDUSTRY

(39) The company represented by the applicant was the only producer of coumarin in the Community during the investigation period.

(40) During the IP, the Community producer imported coumarin from a country other than the PRC. The purpose of such imports was to compensate shortages of the product concerned from the producer's Community production due to technical reasons. These imports represented a minor part of the total sales volume by the producer in the Community. Thus, despite these sales of imported coumarin, the primary activity of the company remained in the Community and the import of this producer did not affect its status as Community producer. This Community producer

is therefore deemed to constitute the Community industry within the meaning of Article 4(1) and Article 5(4) of the basic Regulation.

Imports by affiliated company in India from related exporter

25. *Commission Regulation (EC) No 362/1999 of 18 February 1999 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of steel ropes and cables originating in the People's Republic of China, India, Mexico, South Africa and the Ukraine and accepting undertakings offered by certain exporters in Hungary and Poland Official Journal L 045, 19/02/1999 P. 0008 - 0025*

D. COMMUNITY INDUSTRY

1. Community production

(34) A number of exporting producers alleged that one complainant Community producer should be excluded from the definition of Community industry as it was related to an importer and a chain of distribution/trading companies which had imported the product concerned into the Community from the countries under investigation during the period examined pursuant to Article 4(1)(a) and (2) of the Basic Regulation.

It should be noted that the complainant Community producer in question had not itself made any imports during the period investigated.

As regards imports by the trading companies in the group, the Commission established that the complainant Community producer in question was indeed part of a group of companies that included an importer and distribution companies, and that these had imported SWR from the countries concerned during the investigation period. The structure of the group was found to have changed between 1994 and the IP. However, throughout the whole period investigated, the complainant Community producer in question and both the importer and the distribution companies had had common holdings and were therefore considered to be related companies.

The Commission examined the nature of the group structure and found that it could not be excluded that a certain degree of control may have existed between the related companies either directly or through the common holding company. The Commission established that the volume of dumped imports made by the related companies in the IP represented 2 % of Community consumption, 6 % of total third country imports and only 11 % of the complainant Community producer's volume of production. The principal activity of this complainant Community producer was therefore the production of SWR.

As concerns the behaviour of the complainant Community producer concerned on the Community market, the Commission found that despite the possible existence of any such control, the complainant Community producer in question was suffering the same injurious effects of the dumped imports as the other complainant Community producers investigated in the course of the current proceeding. It should be noted in this respect that the company concerned did not adopt commercial behaviour on the Community market that was significantly different from that of the other complainant Community producers as a result of the imports in question. The complainant Community producer in question was found to have suffered consistent and significant undercutting by the imports originating in the countries concerned during the IP (a weighted average undercutting of 75,8 % was found). It was therefore

considered that the complainant Community producer in question did not benefit unduly from the imports concerned and it had not been shielded from the injurious effects of the dumping.

In view of the above the Commission considered that there were no grounds to exclude the complainant Community producer in question from the total Community production.

(35) The Commission found that during the investigation period certain complainant Community producers had purchased SWR from various sources outside the Community, including the countries concerned. However, the volume of these imports represented a negligible share of total production (i.e. less than 1 % of the complainant Community producers' total production of SWR). The Commission therefore considered that these purchases were in accordance with the standard commercial practice of producers who had to supplement their own range of products with a small proportion of imports. These imports were necessary in order to be able to offer a full range of products and be able to compete on the Community market.

(36) Based on the above, the Commission considered Community production to consist of all companies producing SWR in the Community at the time of the investigation. These companies are hereinafter referred to as the 'Community producers'.

2. Community industry

(37) A number of small producers that supported the complaint did not provide responses to the Commission's questionnaires. In accordance with Article 4(1) the scope of the Community industry was defined as the remaining cooperating producers.

(38) On this basis the following 20 complainant Community producers made up the 'Community industry', i.e. Bremer Drahtseilerei Lüling GmbH (Germany), Bridon International Limited (United Kingdom), BTS Drahtseile GmbH (Germany), Cables Y Alambres Especiales Sa. (Spain), Casar Drahtseilwerk Saar GmbH (Germany), Cordoaria Oliveira SA (Portugal), Drahtseilerei Gustav Kocks GmbH (Germany), Holding Ficadi (France), Iscar Funi Metalliche (Italy), D. Koronakis SA (Greece), Metalcalvi Wire Ropes (Italy), Midland Wire Cordage Co., Ltd (United Kingdom), Randers Rebslageri (Denmark), Redaelli Tecnacordati SpA (Italy), Trefileurope (France), Trenzas Y Cables SL (Spain), Vereinigte Drahtseilwerke GmbH (Germany), Voest-Alpine Austria Draht GmbH (Austria), Vornbäumen-Stahlseile GmbH and Wadra GmbH (both Germany).

(39) The Community industry accounted for 97 % of the total estimated Community production and thus constituted a major proportion of Community production pursuant to Article 5(4) of the Basic Regulation.

Imports by affiliated company in India from unrelated exporter

26. *Council Regulation (EC) No 2320/97 of 17 November 1997 imposing definitive anti-dumping duties on imports of certain seamless pipes and tubes of iron or non-alloy steel originating in Hungary, Poland, Russia, the Czech Republic, Romania and the Slovak Republic, repealing Regulation (EEC) No 1189/93 and terminating the proceeding in respect of such imports originating in the Republic of Croatia Official Journal L 322, 25/11/1997 P. 0001-0024*

D. COMMUNITY INDUSTRY

(42) *The same Community producers cooperated in the two investigations (see recital (8)). These companies represented more than 90 % of the total Community production of the product subject to the investigation, and constituted, therefore, a major proportion of the total production of the product concerned in the Community.*

(43) *A number of exporters alleged that their products were purchased and imported by certain complainant Community producers. They claimed that these producers should be excluded from the determination of the Community industry for the purpose of the injury assessment pursuant to Article 4 (1) (a) of the basic Regulation.*

No substantiating evidence to support this assertion was provided. In addition, the investigation carried out by the Commission has shown that none of the Community producers imported the products concerned and that certain importers, related to such Community producers, imported small quantities of the products concerned during the investigation period. These imports were resold in the Community market exclusively by these related importers, which were found to have acted independently and even to have operated in competition with the sale departments of their related producers. In any event, the examination of the facts revealed that the volume of these imports accounted for less than 3 % of the total sales volume of these products on the Community market for each of the Community producers.

It is, therefore, considered that such a low level of imports could not have led to any injury to the Community producers and consequently there are no grounds for excluding these producers.

Consequently the producers mentioned in recital (8) will be referred to hereinafter as the 'Community industry' within the meaning of Article 4 (1) of the basic Regulation.

Relationship with Exporter exported during POI

27. COMMISSION REGULATION (EC) No 1742/2000 of 4 August 2000 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain polyethylene terephthalate (PET) originating in India, Indonesia, Malaysia, the Republic of Korea, Taiwan and Thailand

C. COMMUNITY INDUSTRY

(87) *The following 9 Community producers co-operated in the investigation, i.e. replied to the Commission's questionnaires, allowed on-spot verifications and provided the Commission with additional information when requested:*

- Du Pont Polyesters Ltd (UK);
- Eastman Chemicals BV (NL);
- INCA International SpA (I);
- Italtel Preforme SpA (I);
- KOSA GmbH(D);
- Shell Chemicals Ltd (UK);
- Wellman PET Resins Europe (NL);
- Aussapol SpA (I);
- CEP-Tergal Fibre (F).

(88) It should be noted that, although Aussapol SpA and CEP - Tergal fibres were not among the companies on whose behalf the complaint was lodged, these companies supported the complaint and co-operated in the investigation.

(89) It should also be noted that, although it operates a plant in Malaysia, Eastman has been considered part of the Community industry because its affiliated company has exported only insignificant quantities of PET to Eastman itself. No other co-operating companies did import PET from the countries concerned during the IP.

(90) None of the three other European producers replied to the Commission's questionnaires or expressed opposition to the proceeding.

(91) The cumulated production of the nine co-operating producers during the investigation period was 1 042 350 tonnes out of an estimated total Community production of 1 220 000 tonnes, i.e. 85 % of the Community production.

(92) The Commission, therefore, considers that the nine cooperating producers constitute the 'Community industry' within the meaning of Article 4(1) and Article 5(4) of the Basic Regulation.

28. COUNCIL REGULATION (EC) No 173/2000 of 24 January 2000 terminating the anti-dumping proceedings concerning imports of certain large aluminium electrolytic capacitors originating in Japan, the Republic of Korea and Taiwan

D. COMMUNITY INDUSTRY

1. Composition of the Community industry

(60) The two reviews cover the same product and are based on data largely pertaining to the same time periods. Therefore, it is considered appropriate to investigate them simultaneously. Consequently, the same producers in the Community constitute the Community production and the Community industry in both reviews.

(61) Four large producers of LAECs, i.e. BC Components, BHC Aerovox Ltd (United Kingdom), Vishay Roederstein GmbH (Germany) and Siemens-Matsushita Components GmbH & Co. KG (Germany), as well as some small to medium-sized producers, were established in the Community.

Three producers supported the request for review on Japan: BC Components, BHC Aerovox Ltd and Vishay Roederstein GmbH. However, the two latter producers did not cooperate with the Commission and were, therefore, not considered part of the Community industry.

(62) As indicated above, BC Components is a new company, incorporated after the end of the IP. It has, notably, taken over the activities of Philips components BV in the manufacturing and sales of LAECs. This takeover was made on a going concern basis, in particular as regards the manufacturing and sales of LAECs in

the Community. Moreover, BC Components BV, expressed its support for both reviews.

(63) Siemens-Matsushita Components GmbH & Co. KG (hereinafter 'Siemens-Matsushita') and the other small and medium-sized producers were not among the producers which requested the review on Japan. Moreover, these companies did not make themselves known after the publication of the notices announcing the initiation of the reviews. Therefore, in accordance with Article 5(4) of the Basic Regulation, these producers could not be considered part of the Community industry.

(64) One Japanese producer/exporter contested the fact that Siemens-Matsushita was not contacted by the Commission and the fact that this company was excluded from the Community industry. These claims could not be accepted because, as stated above, further to the publication of the above notices, Siemens-Matsushita did not make itself known as an interested party and did not express any interest in cooperating. Also, it did not oppose its exclusion from the Community industry.

In addition, available information indicated that Siemens-Matsushita is a joint venture owned in equal parts by Siemens AG (Germany) and the Matsushita Electric Industrial Ltd Group (Japan), a non cooperating Japanese producer/exporter. Siemens AG holds control of the corporate management and holds the casting vote in the event of a tied vote. Siemens-Matsushita was reported not to have imported any LAECs originating in the countries concerned and to sell its own production of LAECs on the Community market under its own brand. However, through its 50 % shareholding, the Matsushita Electric Industrial Ltd Group is clearly in a position to exert control or restraint on Siemens-Matsushita. Available information also indicated that Siemens-Matsushita benefited from the shared know-how of its two shareholders. These two companies are therefore related within the meaning of Article 4(2) of the Basic Regulation.

(65) The important shareholding of Matsushita Electric Industrial Ltd in Siemens-Matsushita and the abovementioned shared know-how lead to the conclusion that Siemens-Matsushita is in a fundamentally different position as compared to that of BC Components. Therefore, in accordance with Article 4(1)(a) of the Basic Regulation, it was considered appropriate to exclude Siemens-Matsushita from the definition of the Community industry.

(66) It should finally be underlined that Siemens-Matsushita was already excluded from the definition of the Community industry in the original investigations concerning imports from Japan and imports from the Republic of Korea and Taiwan. This approach has not been disputed in either of these two investigations.

(67) A number of Japanese producers/exporters claimed that BC Components should be excluded from the Community industry because, until the end of the IP, companies which were related to it at that time, in particular Philips Consumer Electronics BV, imported significant quantities of LAECs from Japan.

(68) The Commission examined whether the fact that Philips Consumer Electronics BV imported LAECs from Japan was a sufficient reason to exclude BC components, at that time the only LAECs manufacturer within the Philips Group, from the Community industry.

It was found that almost all imports made by the Philips Group were not destined for further resale, but were incorporated by Philips Consumer Electronics BV in its own production of electronic products. Moreover, the investigation revealed that the majority of these imports (more than 85 %) were of 'radial' products either not yet produced by BC Components or still in a start-up phase of production. In these circumstances, Philips Consumer Electronics BV had no other choice but to be supplied by producers/exporters in the countries concerned.

Philips Consumer Electronics BV were products directly competing with BC Components' production and represented an insignificant share of the total imports into the Community. It was also noted that Philips Consumer Electronics BV, despite the above imports, was the biggest traditional customer of BC Components, since it represented approximately 40 % of its total sales in the IP. The choice of Philips Consumer Electronics BV to be partly supplied by producers/exporters in the countries concerned was made possible by the structuring of the Philips Group into different profit centres which are all independent and free to choose their suppliers, notably when it is necessary to complete or supplement the range of products offered within the Philips Group (as in the case of the 'radial' LAECs).

(69) For the above reasons, the imports made by Philips Consumer Electronics BV were considered as normal commercial behaviour until such time as fair conditions of competition would be restored on the Community market.

(70) BC Components, represented a major proportion (41 %) of the total estimated Community production.

(71) Based on Article 4(1)(a) of the Basic Regulation, the estimated production of Siemens Matsushita was not taken into account in the determination of the total Community production, for the purposes of the assessment of the representativity of the Community industry.

One cooperating Japanese producer/exporter claimed that, had the estimated production of Siemens-

Matsushita been taken into account, BC Components would not have had sufficient standing to be representative of the total Community production.

However, it was found that even if the production of Siemens-Matsushita, as established on the basis of the information submitted by the cooperating parties had been included in the determination of the total Community production, the Community industry would still have represented a major proportion of this production, pursuant to Article 5(4) of the Basic Regulation.

(72) It was therefore confirmed that BC Components constituted the Community industry in both reviews, within the meaning of Article 4(1) of the Basic Regulation.

29. Commission Regulation (EC) No 1472/2000 of 6 July 2000 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of Polyester Staple Fibres originating in India and the Republic of Korea Official Journal L 166, 06/07/2000 P. 0001- 0013

E. DEFINITION OF THE COMMUNITY INDUSTRY

(60) Both complaints were lodged on behalf of 8 of the 14 Community producers known to produce PSF in the Community. One of these complainant producers withdrew from cooperation and another had to be considered as non-cooperating as it did not provide a sufficient questionnaire response.

(61) The share of total Community production of PSF held by the six cooperating Community producers during the IP was 71.5 %. On this basis, these six complainant producers constitute the Community industry within the meaning of Article 4(1) of the basic Regulation. They are referred to as the "Community industry" hereafter.

(62) It was argued that two of the six complainant producers should not be included in the Community industry as they were related to an exporting producer from Indonesia. This country was involved in both an anti-dumping and an anti-subsidy investigation involving PSF.

(63) It should be recalled that the current proceeding investigates a complaint against imports originating in the Republic of Korea and India. It is further recalled that producers related to exporters may be excluded from the definition of the Community industry if the relationship leads to a behaviour which is different to that of unrelated Community producers because such related producers are shielded from the effects of dumping, unduly benefiting from the dumping practices or are even participating in the dumping practices. No evidence was found during the investigation that the two Community producers related to the Indonesian exporters would fall under any of the three aforementioned categories. In particular, it was not found that the information relating to the various injury indicators for these two companies was significantly different to other complainants. This shows that the two companies were not shielded from the effects of dumping, unduly benefiting from the dumping practices or are even participating in such practices. Consequently, these two Community producers have not been excluded from the definition of the Community industry.

30. Final Findings in the matter of Anti-dumping investigation concerning import of Para Cresol originating in or exported from People's Republic of China.

7. Domestic Industry

The Authority recalls the preliminary findings on the issue of domestic industry. The petition has been filed by M/s Atul Limited (Aromatics Division), Dist. Valsad, Gujarat. The petitioner company is the sole producer of Para Cresol in India. Therefore they claim to represent the 100% domestic production of the subject goods. The petitioner had informed in the petition regarding imports of 32 MT of Para Cresol made during POI under Advance Licence for fulfilling export obligation. It has been argued by some of the importers that since the petitioner has made imports during the POI they may not be treated as part of the eligible domestic industry. The Authority had noted that the imports of 32 MT made by

M/s Atul Limited during POI were meant for export production and these imports were necessitated due to a planned stoppage of their Para Cresol plant. The Authority did not consider these small quantity imports for export production to make the petitioner as ineligible to be treated as 'Domestic Industry' within the meaning of Rule 2(b) supra. The petitioner was, therefore, considered to represent the domestic industry.

Arguments have been made on behalf of importers viz. M/s Blackrose Exports Pvt. Ltd., Metrochem Industries Ltd., Nandolia Organic Chemicals Pvt. Ltd. and Universal Chemical Industries Ltd. stating that the petitioner lacks the standing to file the petition as they have made imports of subject goods. Further, it has been argued that the following three reasons considered by the Authority while treating M/s Atul Limited as domestic industry are not sufficient:

- i. Imports made by the petitioner are insignificant.*
- ii. Imports made under advance licence,*
- iii. Imports have been made at a time of temporary shut down of production facilities.*

It has been argued that imports made by the petitioner constituted more than 5% of imports whereas under WTO rules, 3% volume of imports is a quantity considered as significant. Further, these imports made by the petitioner were more than 1% of demand of the product. With regard to second reason regarding imports made by the petitioner under advance licence, it has been argued by the importers that it is the practice of the Designated Authority to exclude all such producers from the eligible domestic industry. It has been argued that in the case of imports of Metronidazole from China, three producers were excluded from the purview of domestic industry even though these companies made imports under advance licence. As regards the third reason given by petitioner to have made imports under advance licence in the condition of temporary shut down, it has been argued by the importer that the reasoning defies all logic as at one place, domestic industry claimed that imports were necessitated due to its own requirement for exports and at the same time, it has been stated that imports had to be made due to temporary shut down of the plant. In response to the Disclosures, the importers have reiterated their above stand.

The domestic industry has drawn attention to the legal position on definition of domestic industry as per Rule 2 (b). They have argued that the word 'shall' existing in the said Rule was amended to read as 'may' by virtue of the Amendment No.44/99-CUS dated 15.7.1999. Thus specific discretionary powers were vested in the Designated Authority to decide whether in a particular case, the importing domestic industry may be considered not forming a part of the domestic industry under Rule 2(b). In the instant case, the Designated Authority was satisfied that the petitioner should be considered as the eligible domestic industry despite the fact that they have imported the said product. Imports in the instant case were made by the petitioner against advance licence which are totally exempt from the incidence of custom duty and also the anti dumping duty. This exemption is based on the fact that such imports do not enter in the mainstream commerce of the country. Exclusion of producers who imported the product under consideration has to be decided by the Designated Authority on a case by case basis, on reasonable and equitable ground, and by taking into consideration all

the legal and economic aspects involved. The purpose of the provisions on the exclusion of certain producers is to obtain an objective and undistorted view of the effects of the dumped imports. It is pertinent to note that the present petitioner has not in any way participated in dumping practices or shielded from its effects or in any way benefited unduly from them. The contention of the importers that the importing domestic industry is ordinarily to be excluded, is not borne out either from a plain reading of the law or from the jurisprudence on the subject. The petitioner has also cited the excerpts from the book titled "EC Anti Dumping Law, A Commentary on Regulation 384/96 by Nicholas Khan" which contains the practices followed by EC in this regard.

It has been further argued by the petitioner that the preliminary findings on the issue of 'domestic industry' have been misinterpreted and distorted in the submissions made by the importers. The said findings make it amply clear that the imports by the domestic industry have been ignored for determining the standing of the domestic industry because the imports were necessitated to fulfill the export commitments and not for the reasons cited in the submissions of importers / consumers. The reasons in support of questioning the decision of the Designated Authority are based on an erroneous interpretation of the preliminary findings and hence needs to be rejected ab initio. The criteria of 3% volume of imports mentioned by importers has no connection or linkage with the status of the domestic industry to file a petition. The reliance placed by the importers on the Phenol case is also totally mischievous and misleading.

The Authority has examined the arguments made by the importers on the preliminary findings on the issue of 'domestic industry' and the arguments made by the petitioner. The Authority is of the view that Rule 2(b) gives the discretion to the Authority in determining as to whether a domestic producer who has made imports of subject goods can be considered as part of the domestic industry or to be excluded. In the instant case, the petitioner, who is the sole producer of the subject goods in India, had made imports of 32 MT during the POI. These imports were made for export production and these had been necessitated due to a planned stoppage of their Para Cresol plant. The Authority has not considered these imports as very significant, particularly, when these were meant for export production. The reference to the criteria of 3% volume of imports in the context of the determination of standing of domestic industry has no relevance, as these provisions relate to determination of de minimus volume of imports. The facts and circumstances of other cases cited by the importers in support of their arguments are different from the instant case. The Authority therefore, reiterates and confirms its preliminary findings on the issue of 'domestic industry'.

Relationship with exporter no exports during POI

31. Council Regulation (EC) No 771/98 of 7 April 1998 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of tungsten carbide and fused tungsten carbide originating in the People's Republic of China Official Journal L 111, 09/04/1998 P. 0001 - 0009

D. COMMUNITY INDUSTRY

(22) A number of claims were made by the Chinese exporters/producers and some users concerning the definition of the Community industry and the standing of the producers supporting the review request.

(23) The Chinese exporters/producers claimed that one of the producers supporting the review request was related to one importer of Chinese carbide and should therefore be excluded from the definition of the Community industry pursuant to Article 4(1)(a) and (2) of the Basic Regulation.

It was established during the investigation that the two companies concerned although related had no control over each other. Moreover, these companies had conflicting interests regarding the imposition of the anti-dumping measures. One company was producing carbide whereas the other company was importing the product concerned. It was found that the two companies were acting autonomously when defining and pursuing their business strategy. Overall, it was concluded that their relationship did not influence the behaviour nor did it distort the analysis of the economic situation of the Community producer in question as regards the product concerned and there was therefore no reason to exclude this producer from the definition of the Community industry.

(24) As mentioned in recital (2), the request for review was submitted by producers representing almost the totality of the production of carbide intended for sales on the open market and, accordingly, they constituted the Community industry.

This was contested by a number of integrated producers of tungsten end-products in the Community (tools, hard metals), producing small quantities of carbide exclusively for internal consumption. Specifically, they argued that the representativity of the producers supporting the review should be assessed by reference to the totality of the Community production of the product concerned (including their own captive production) and that, on this basis, the producers supporting the review were not representative of the Community industry.

(25) This issue was examined but it was concluded that the argument was incorrect. Indeed, even if the output of the companies which only produce for captive use was taken into account, the producers supporting the review request would still account for 60 % of the overall Community production of the product concerned, thus fulfilling the criteria of Article 5(4) of the Basic Regulation. In addition, it was confirmed that the producers supporting the review accounted for almost all Community production of carbide intended for sales in the open market.

(26) Given the above, the producers supporting the review request constitute the Community industry within the meaning of Articles 4(1) and 5(4) of the Basic Regulation. For the remainder of this Regulation, the term "Community industry" will be used to refer to the companies supporting the review.

32. Council Regulation (EEC) No 535/87 of 23 February 1987 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of plain paper photocopiers originating in Japan Official Journal L 054, 24/02/1987 P. 0012 - 0035

iii) Definition of Community industry in the context of the proceeding

In this case the Commission has been obliged to take into consideration the fact that all Community producers concerned with this proceeding have links of either a corporate or commercial nature with Japanese exporters. This has given rise to complex questions regarding the definition of Community industry under Article 4 (5)

of Regulation (EEC) No 2176/84 and has necessitated a detailed examination of the position of each of the complainant companies based on the specific facts pertaining to each company's situation.

(a) Position of Rank Xerox

(50) In Regulation (EEC) No 2640/86 the question of whether Rank Xerox, in view of its corporate relationship with its Japanese supplier, Fuji Xerox, should be included as part of the Community industry for the purposes of assessing injury within the context of the proceeding was essentially left open since the Commission concluded that there was injury to Community producers irrespective of whether Rank Xerox's production of low-volume copiers was included in the term 'Community industry' or not. However, since the duty required to remove the injury was calculated to be at a lower level when Rank Xerox was included in Community industry for the assessment of injury than if it had been excluded, for the purposes of the provisional findings, the Commission decided to consider Rank Xerox as part of the industry.

(51) In order to come to a definitive decision on the position of Rank Xerox in the proceeding, the Commission re-examined all matters relevant to the assessment of whether the Community industry, as defined in Article 4 (5) of Regulation (EEC) No 2176/84, should include Rank Xerox. As a starting point the Commission reviewed the relative importance of Rank Xerox's operations with its affiliate Fuji Xerox compared with the company's other operations in the photocopier industry in the Community.

(52) The facts as finally established show that Rank Xerox's imports from Fuji Xerox of PPCs which were sold in the Community represented about 7 % of the company's total sales and rentals in the Community of new machines in segments 1 to 5 over the period 1981 to the end of the reference period. With the exception of the imports of the 1055 mid-volume model from Fuji Xerox in 1984, these imports were all segment 1 and 2 copiers and represented approximately 8 % of Rank Xerox's segment 1 and 2 machine sales and rentals in the Community of these machines in the same period. In terms of sales and rentals of new machines in segments 1 to 5 inclusive on the Community market by all producers over the period 1981 to July 1985, Rank Xerox's resales of Fuji Xerox imports represented less than 1 % of the total.

(53) The findings in Regulation (EEC) No 2640/86 (recital 74) regarding Rank Xerox's reasons for importing principally in advance of the setting-up of manufacture of the equivalent model in the Community, and regarding the resale prices of the Fuji Xerox imports being the same as those of models manufactured in the Community are confirmed, no contrary evidence having been produced.

(54) With regard to Rank Xerox's sales of segment 1 and 2 copiers not supplied in complete units by Fuji Xerox over the period 1981 until the end of the reference period, it was alleged that these were produced in the Community from parts supplied in large measure to Rank Xerox by Fuji Xerox. Following these allegations, the Commission investigated the production of all photocopiers manufactured by Rank Xerox in the Community. In this context the Commission visited the manufacturing plants of Rank Xerox in the United Kingdom (low-volume machines) and the Netherlands (mid-volume machines) and examined the nature of the manufacturing operations carried out in each plant.

(55) In the Netherlands it was found that integrated manufacturing operations were carried out by, or on behalf of, Rank Xerox in the Community. The value added within

the Community in these manufacturing operations exceeds 70 %. The photocopiers produced by Rank Xerox in the Netherlands have Community origin.

In the United Kingdom, Rank Xerox's products were manufactured on the basis of parts originating predominantly in Japan and to a lesser degree in the Community. However, Rank Xerox had already set in motion concrete plans to replace certain key components of Japanese origin with parts produced in the Community. These plans have materialized in the meantime, leading to a substantial increase in value added within the Community for these low-volume products.

As regards the type of operations carried out in the United Kingdom, these consist of the construction of sub-assemblies for the production line, including the fusers, modules, develop boxes, cassettes, semi-automatic document handlers, optics and other minor assemblies. These operations are completed by the frame assembly and the final mainline assembly of sub-assemblies and components. The manufacturing process is completed by testing and packing of the photocopiers. Overall, in the reference period, the value added in the Community in the production of Rank Xerox's low-volume copiers was between 20 % and 35 %.

(56) The Commission has examined whether, in view of these facts, Rank Xerox can be considered as a Community producer of segment 1 and 2 copiers within the meaning of Article 4 (5) of Regulation (EEC) No 2176/84. The Commission has noted that the Regulation does not lay down precise guidelines in this context. In particular, no threshold has been specified in either Community legislation or in previous cases for the minimum value added that must be respected in order for a producer to qualify as part of Community industry. Therefore the Commission has been obliged to look at the particularities of the present case.

(57) The first point to note is that the company is a manufacturer of photocopiers in the Community of long standing and one of the largest companies in the market.

Whilst the production operations of Rank Xerox in the United Kingdom were more limited than the activities undertaken at its plant in the Netherlands during the reference period, the company did nonetheless undertake a multiplicity of manufacturing operations necessary in order to produce copiers for the market. In addition, Rank Xerox has been actively engaged in the process of replacing parts from Japan with other key components either of its own manufacture or from subcontractors within the Community.

The investigation showed that, if no protective measures covering segment 1/2 copiers were taken, then the process actively engaged in by Rank Xerox of replacing key parts sourced from Japan with Community-produced supplies would be jeopardized. Article 4 (1) of Regulation (EEC) No 2176/84 authorizes protective measures in the case of the retardation of the establishment of an industry. If no anti-dumping measures were to be taken in this case, there would be a setback not only to Rank Xerox's future plans on sourcing products from the Community, which are already well established, but also a threat to the process already begun in this area. This might lead to a rupture in the process of building up Rank Xerox's production of low-volume copiers based on parts manufactured in the Community.

(58) In any event, since the like product in the proceeding has been defined to be all photocopiers from personal copiers up to and including machines classified in Dataquest segment 5, it would be inappropriate to analyse whether a Community producer should be part of Community industry just in terms of its production of one

model or a limited range of models. This is the case even if, looked at in isolation, there were doubts as to whether Rank Xerox's manufacturing operations in the United Kingdom were sufficient to confer upon it the status of a Community producer in the sense of Article 4 (5) of Regulation (EEC) No 2176/84, for segment 1/2 copiers. The weighted average value added in the Community for all PPCs manufactured by Rank Xerox in the range segment 1 to segment 4 was in excess of 50 % in the reference period. Also the company has a policy of obtaining an increasing proportion of its components from within the Community.

(59) In any case, even if Rank Xerox's production in the United Kingdom was not regarded as part of Community industry for the purpose of these proceedings, there would remain Community production of PPCs in the same segments of the market as Japanese products, or in adjoining segments. The rates of duty appropriate to protect that Community production in accordance with the criteria used in this Regulation would be unaffected.

(60) The Commission also examined the issue of whether Rank Xerox should be excluded in whole or in part from the definition of Community industry by virtue of the benefits it derives from dumped imports from Fuji Xerox. In addition, an investigation was made of the question whether, in purchasing from Fuji Xerox, Rank Xerox inflicted injury upon itself and whether its motivation in importing was not one of acting primarily out of self-defence but more one of profit maximization within the context of its parent's, Xerox Corporation's, worldwide rationalization of copier production.

(61) With respect to the benefits that Rank Xerox derives from its corporate relationship with Fuji Xerox, it is evident that there are gains arising from the supply of cheap machines prior to start-up of production in the Community. These benefits, however, are short-lived and limited in scope. Furthermore, when account is taken of the volumes of imports concerned it is evident that the benefits are insignificant when assessed against injury being caused to Rank Xerox through dumping by other Japanese exporters.

(62) As regards the possibility that Rank Xerox may have inflicted injury upon itself by provoking or contributing to a fall in prices on the market, there is no evidence to suggest this. In the first place, Rank Xerox's resale prices for segment 1 and 2 products imported from Fuji Xerox were the same as for the corresponding Rank Xerox Community-produced machines and these prices were generally undercut by the prices of Japanese subsidiary companies on the Community market. This fact demonstrates that Rank Xerox cannot be considered to have inflicted injury upon itself through its purchase and resale of machines from Fuji Xerox.

(63) With respect to the possibility that injury was caused by Rank Xerox to other Community producers through the resale of photocopiers supplied by Fuji Xerox at dumped prices, the evidence showed that when account is taken of the different features of these models and the comparable Community-produced model, the Rank Xerox resale prices were in general below those of the Community producer concerned and must therefore be considered to be injurious to that producer. It follows, therefore, that the effect of these imports should be taken into account in assessing the injury to other Community producers.

(64) Finally, on the question of whether Rank Xerox acted in order to protect itself against low-priced competition from Japanese producers, the Commission reviewed

the evidence supplied by interested parties, including that submitted by Rank Xerox itself. Whilst the company maintained that a major factor in its decision to purchase low-volume photocopiers from its affiliate in Japan from 1978 onwards was the low price prevailing on the Community market which had been set by Japanese exporters, no convincing evidence was advanced in support of this statement. Independent sources suggest, on the contrary, that the decision may have been due more to internal difficulties which the Xerox Corporation as a whole experienced in producing new low-volume products. Faced with this situation, Rank Xerox turned to Fuji Xerox which had developed a low-volume model (2202) for sale in Japan and imported this product into the Community. This model replaced Rank Xerox's former Community-produced model (660) but was not itself produced in the Community.

(65) This initial supply link with Fuji Xerox was short-lived and was superseded in 1979 by the pattern of supply arrangements described in recital 53. The purpose of such supply arrangements has evidently been to enable Rank Xerox to prepare for and to accelerate the marketing of new products in advance of their manufacture in the Community as Community products. While it cannot be said that Rank Xerox was obliged to purchase machines from Fuji Xerox for self-defensive purposes, it is clear that in current circumstances in which the low-volume end of the market is dominated by Japanese suppliers, the ability to bring to the market a product more quickly than by waiting for Community production to come on-stream has enabled the company better to defend its overall position.

(66) Even if the company's activities in importing were not considered to be self-defensive, the low volume of supplies from Fuji Xerox in terms of Rank Xerox's total range of photocopiers in the Community is a decisive factor in favour of the view that there are no reasonable grounds for excluding the company's production of low-volume copiers from the definition of Community industry in the proceeding by virtue of its purchase of complete PPCs from Fuji Xerox.

(67) In summary, and having taken account of the particular circumstances of the case, the Commission considers that under Article 4 (5) of Regulation (EEC) No 2176/84, Rank Xerox should be considered to be a Community producer of photocopiers for the purposes of this proceeding.

(b) Position of Tetras

(68) In November 1986, Tetras, a member of CECOM and producer of a personal copier in the Community, established a relationship with Canon, a Japanese exporter, whereby Canon took a 19 % shareholding in Tetras with an option to purchase an additional 30 % of the company's stock from other investors within a pre-set time limit. The minority shareholding relationship with Canon has not affected Tetras' position either as a Community producer or as a complainant and consequently Tetras remains part of the Community industry for the purposes of this proceeding.

(c) Position of Océ and Olivetti

(69) As regards the position of Océ and Olivetti, representations were made by a number of exporters and OEMs to the effect that these companies should be excluded from the scope of Community industry in the proceeding under Article 4 (5) of Regulation (EEC) No 2176/84 on the basis of their links with Japanese suppliers. It was argued, in essence, that the scale and long tradition of these companies' links with Japanese suppliers precluded them from being considered as Community producers in the proceeding.

(70) With respect to the relative importance of these companies' links with Japanese suppliers, the data show that for Océ and Olivetti, sales in the Community of imported machines represented between 35 and 40 % of each company's sales and rentals of new machines placed in the market over the period 1981 to July 1985. Models imported from Japan by Océ for resale have been segment 1 and 2 copiers with lower prices than those of Océ's own-produced machines. Olivetti has imported predominantly segment 1 copiers over the period 1981 to July 1985, but since 1984 has also purchased personal copiers from Canon.

(71) The question of whether Olivetti and Océ could have caused injury to themselves through actions in importing dumped PPCs was dealt with extensively in Regulation (EEC) No 2640/86. The Council confirms these findings and considers that these companies should be included in the definition of Community industry for the following reasons:

- Both companies attempted, at various times, to develop and market a fuller range of models but were thwarted in their attempts to do so because of depressed market prices set by Japanese imports. This is evidenced by management evaluations of projects and full documentation in one case of a prototype model scheduled for introduction to the market.

- The companies' resort to distribution of Japanese-manufactured machines on an OEM basis was a response to the need to offer a full range of models to their customers. By doing so, the companies were clearly protecting customer bases against competition from other suppliers who were able to offer a full model range.

- Over the period 1981 to the end of the reference period, the companies sold and rented far more units of their own manufactured products than those of imported PPCs.

- The prices at which the two companies resold the imports on an OEM basis were in general higher than those of the same machine sold by their suppliers on the Community market, thereby discounting the possibility that Océ and Olivetti could have inflicted injury upon themselves via their pricing policy, and supporting the argument that these OEM sales were subsidiary to and aimed at facilitating the placement of their own-manufactured machines.

- The very small volume of Océ's and Olivetti's OEM imports in relation to total imports of all Japanese-produced machines (average of 4 % over the period 1981 to 1985), and the fact that they were sold at higher prices than those sold by their suppliers, demonstrates that these limited imports could not have had detrimental effects on the prices of their own and other Community producers' own-manufactured PPCs. In conclusion, the Council confirms that within the context of this proceeding Océ and Olivetti did not injure themselves in importing low-cost PPCs from Japan for distribution on an OEM basis.

(72) Finally, the Commission's argument in recital 73 of Regulation (EEC) No 2640/86 that Océ and Olivetti could be considered to have done nothing which caused them to suffer losses greater than they would have suffered if they had attempted to base their own PPC business on the marketing of a more limited range of models was challenged on grounds of the lack of evidence justifying this conclusion. In response the Council points to the difficulties experienced by companies past and present to

base their photocopying business on the marketing of a limited range of models and the need, emphasized by nearly all successful producers, to be in a position to respond to a customer's total copying needs. These considerations support the conclusions of the Commission.

(73) In conclusion, the Council confirms that Océ and Olivetti should be included in the definition of Community industry for the purposes of the proceeding.

(d) Position of Develop

(74) Develop, a Community producer of photocopiers, was effectively taken over in May 1986 by Minolta, a Japanese exporter, and subsequently withdrew its support for the complaint. While Develop continues to be a producer the question arises whether it should be considered as part of Community industry for the purposes of injury assessment. In the view of CECOM, Develop should be included since, during the reference period and before, the company was injured by the dumping practices of Japanese exporters.

(75) The Commission takes the view that, since it withdrew its support for the petition, Develop should no longer be considered part of the Community industry for the purposes of this proceeding. As to the argument that injury allegedly suffered by Develop in the reference period and before should be taken into account, the Council confirms the Commission's position that remedies to counter dumping practices can only be applied to offset injury caused to those producers defined as constituting the Community industry in the proceeding. It follows, therefore, that it would be illogical in determining the measures to be applied to take account of injury allegedly suffered by a producer not considered as part of the industry. Consequently Develop is not considered part of the Community industry for the purposes of this proceeding.

(e) Position of Canon

(76) Representations were made to the Commission by Canon that the Community industry should be defined to include not just the complainants but also Canon Giessen and Canon Bretagne - producers of photocopiers in the Community - but which do not support the complaint. The Commission considers that since the complainants form a major proportion of the industry, irrespective of whether Canon's subsidiaries are included or not, then it is sufficient in the proceeding to assess whether injury has been caused to this major proportion of the industry.

(f) Conclusion

(77) In summary, the Community industry for the purposes of this proceeding is defined to be the Community producers, Rank Xerox, Olivetti, Océ and Tetras, who manufacture photocopiers in the Community.

g. Having regard to the above, petitioner submits that the Authority has rightly noted the submissions made regarding exports made by related exporter and eligibility of the petitioner company as a domestic industry.

E. Selection of POI

33. Another issue that has been raised by the interested parties' concerns period of investigation selected in the present case. The Applicant domestic industry has submitted as follows:

- a. *petition contained sufficient reasons for choosing 6 months as the POI;*
 - b. *the notice of initiation issued by the Designated Authority contains reasons for choosing 6 months as the POI,*
 - c. *decision to take six-months period as POI has been upheld by the Hon'ble Tribunal in the matter of Virchow Laboratories Ltd. v/s Ministry of Finance, wherein CESTAT has held as under:*
34. *It is contended on behalf of the Designated Authority that there is no rule mandating the Authority to take a period of 12 months for determination of dumping. The Designated Authority has observed that there was significant drop in the import price of HAS from the subject countries during six months. The price had dropped by over 50% and the landed price of the imports had been continuously declining in the last four years. There was no allegation of malafides made against the Authority in the matter of choice of the period by any one of the parties during the investigation proceedings.*
35. *There are no rules during the period of investigation as twelve months as contended by the appellant. On the other hand, the footnote to Part I Article 2.2.1 of Agreement on implementation of Article VI of the General Agreement on Tariff and Trade, 1994 would give a different indication. Article 2.2.1 provides that while determining normal value, the Authority shall take into consideration sales, which are made in an extended period of time in substantial quantities. Footnote to this clause explains that the extended period of time should normally be one year but shall in no case be less than six months. This would show that choice of a period of six months is not barred.*
36. *While rejecting a similar contention in Final Order No. 22/2000-AD, dated 2-2-2000 [2000 (119) E.L.T. 157 (T)] the Tribunal has observed as follows :-*

"We are not convinced with the arguments advanced on behalf of the appellants that assessment is arbitrary since the D.A. has chosen only 6 months i.e. October, 1994 to March, 1995 as period of investigation for the purpose of assessment. The D.A. is right in observing that there are no specific provisions in the Rules to suggest the period of investigation. There are, however, indirect references available to suggest that the period of investigations should not be less than six months. Our anti-dumping law is based upon agreement on implementation of Article VI of the General Agreement on Tariff and Trade (W.T.O. Agreement). Annexure 1.2(1) suggests and Note for of WTO (Article 2.2.1) suggests that the period of investigation should not be less than six months. In the absence of prescription or restriction with reference to the period of investigation in the respective provisions of anti-dumping law, we do not find any flaw in the order in the course adopted by D.A. taking six months as period of investigation."

We, therefore, hold that the discretion exercised by the Designated Authority in choosing a period of six months is not in any manner vitiated.

- d. even when the WTO Agreement contains no legal provision with regard to choice of POI, the Committee on Anti Dumping practices has stated as follows –

(i) Recommendation by the Committee on Anti-Dumping Practices

20. At its meeting of 4–5 May 2000, regarding appropriate periods of data collection, the Committee on Anti-Dumping Practices recommended with respect to original investigations to determine the existence of dumping and consequent injury:

“1. As a general rule:

(a) the period of data collection for dumping investigations normally should be twelve months, and in any case no less than six months, ending as close to the date of initiation as is practicable;

(b) the period of data collection for investigating sales below cost, and the period of data collection for dumping investigations, normally should coincide in a particular investigation;

(c) the period of data collection for injury investigations normally should be at least three years, unless a party from whom data is being gathered has existed for a lesser period, and should include the entirety of the period of data collection for the dumping investigation;

(d) In all cases the investigating authorities should set and make known in advance to interested parties the periods of time covered by the data collection, and may also set dates certain for completing collection and/or submission of data. If such dates are set, they should be made known to interested parties.

2. In establishing the specific periods of data collection in a particular investigation, investigating authorities may, if possible, consider practices of firms from which data will be sought concerning financial reporting and the effect this may have on the availability of accounting data. Other factors that may be considered include the characteristics of the product in question, including seasonality and cyclicity, and the existence of special order or customized sales.

3. In order to increase transparency of proceedings, investigating authorities should include in public notices or in the separate reports provided pursuant to Article 12.2 of the Agreement, an explanation of the reason for the selection of a particular period for data collection if it differs from that provided for in: paragraph 1 of this recommendation, national legislation, regulation, or established national guidelines.”

21. *Having regard to the above, petitioner submits that 6 months POI considered in the present case is fully justified. The petition contained sufficient reasons. The Designated Authority gave reasons in the notice of initiation.*
22. Dumping - *The domestic industry had earlier made elaborate submissions on various aspects relating to dumping. The previous submissions made by the domestic industry before are referred to and relied upon. Further, the information provided by the domestic industry and other submissions made by the domestic industry during the course of the present investigations may kindly be considered as part and parcel of the present submissions. These are not being repeated for sake of brevity. However, all these submissions may kindly be deemed to be included in the present submissions.*
23. Injury & causal link - *The domestic industry had earlier made elaborate submissions on various aspects relating to injury and causal link. The previous submissions made by the domestic industry before are referred to and relied upon. Further, the information provided by the domestic industry and other submissions made by the domestic industry during the course of the present investigations may kindly be considered as part and parcel of the present submissions. These are not being repeated for sake of brevity. However, all these submissions may kindly be deemed to be included in the present submissions.*
24. Contraction in demand - *It has been argued that the contraction in demand has caused injury to the domestic industry. Followings are relevant in this regard –*
- a. *The demand of the product under consideration has not registered negative growth, except some reduction during the investigation period. With regard to demand in the investigation period, petitioner submits that while there is decline in demand, the same is not the sole or principal cause of injury to the domestic industry. Firstly, decline in demand should have equally impacted the domestic industry and Foreign Producers. However, whereas the Foreign Producers gained significant market share, the domestic industry lost the same. Secondly, the Foreign Producers have reduced the prices too significantly. Resultantly, the domestic industry was forced to undertake too significant price cuts. Deterioration in the performance of the domestic industry in respect of price parameters is due to dumped imports.*
 - b. *The interested parties have argued that the reduction in demand has not been appropriately examined by the Authority with regard to casual link analysis. Petitioner disputes and submits that the Authority has adequately examined the issue of contraction in demand in its impact on the injury to the domestic industry. In fact, any contraction in demand should have affected all parties equally. However, whereas imports have gone up with the decline in demand, sales of domestic industry have disproportionately*

declined. While it is appreciated that the domestic industry would have faced some loss of sales due to decline in demand, a higher degree of decline in sales vis-à-vis decline in demand on one hand and increase in imports in absolute terms and relative to production & consumption on the other hand clearly establishes that injury to the domestic industry is because of imports. Further, followings are relevant.

- c. It is true that the demand for the product had declined as a result of economic recession. This is also true that to such an extent injury to the domestic industry is caused by contraction in demand. However, the fact that imports have increased in a situation where demand has declined, at the least, establishes intensified injury to the domestic industry because of increased imports. While the industry was already facing lack of demand, the difficulties of domestic industry have been compounded by increase in imports. Further, while the decline in the sales volumes (and consequently production & capacity utilization) can be partly seen in decline in demand, the same does not justify the substantial decline in profitability.*
- d. It is also relevant to point out that the volume of dumped imports would have further increased but for contraction in demand. Had the market for the product continued to grow, the dumped import volumes would have increased further. Given the price advantage, it is quite likely that even other consumers would have switched to imports, had the domestic industry not immediately corrected its prices.*
- e. We also refer to the decision of the E.C. in the following cases, relevant extracts of which are given below –*

COUNCIL REGULATION (EC) No 2080/2001 of 23 October 2001 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of internal gear hubs for bicycles originating in Japan

(b) Fall in consumption in 1999 and market development

(92) It has been examined whether the fall in consumption in 1999 was a major factor contributing to the injury suffered by the Community industry. Given the presence of basically two major operators on the Community market, it was considered that the possible impact of the fall in consumption and the subsequent market development should be examined in the light of the performances of both operators.

(93) In 1999, as compared with 1998, the Community industry's sales volume decreased by around 18 %, whereas demand decreased by 8 %, i.e. to a much lesser degree. The Community industry also lost around 9 % of market share. During the same period, the exporting producer was able to increase its sales volume by 17 % and its market share by 30 %.

(94) During the IP, by comparison to 1999, the Community industry increased its sales volume by 4 % but its market share dropped by 4 %. In

the meantime, the exporting producer was able to further increase its sales volume (22 %) and market share (11 %), namely to a much larger extent than the recovery of the market (8 %).

(95) *Based on the above facts, it is clear that the deterioration of the Community industry's position in 1999 was more dramatic than any reduction in consumption. Similarly, when the market recovered during the IP, the performance of the Community industry was far below the market development. In the meantime, the dumped imports substantially improved their position on the Community market. Consequently, unlike dumped imports it is considered that the fall in consumption did not play any significant role in the injurious situation of the Community industry.*

Conclusion on causation

(102) *The substantially dumped imports which increased materially during the period considered, the price undercutting and the price depression found, all had significant negative consequences on the economic situation of the Community industry, notably in terms of sales prices and sales volumes, which in turn had an effect on market share and profitability. The impact of the dumped imports was such that it caused material injury to the Community industry. Based on the above facts and considerations, it is also concluded that any other factors which may have contributed to the injury suffered by the Community industry were not such as to break the causal link between the injury established and the impact of the dumped imports concerned.*

COMMISSION REGULATION (EC) No 1629/2000 of 25 July 2000 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of ammonium nitrate originating in Poland and Ukraine

(b) Decrease in apparent consumption

(47) *As to the development of demand, apparent consumption of AN fell by 950 000 tonnes between 1995 and the (annualised) IP, i.e. by 16,7 %. The fall was particularly marked between 1998 and the annualised IP. As stated above, the AN market is characterized by a distinct seasonal pattern. The major part of the sales take place between October and March of each year (high season), while during the rest of the year demand is relatively subdued (low season). As the investigation period of 18 months contains two low seasons and only one high season, the annualised apparent consumption would be understated. In addition, it cannot be excluded that the decrease in demand (even if statistically overstated in the IP) is the consequence of certain substitution effects amongst different nitrogen fertilisers. It has been established in a recent case concerning UAN solutions that apparent consumption of UAN solutions increased in recent years (see Commission Regulation (EC) No 617/2000 (1)). This trend continued in the second half of 1999. However, while the decline in demand certainly contributed to increased competition and exerted a certain downward pressure on prices, thereby contributing*

to the injury suffered by the Community industry, the latter did anticipate a fall in demand and is adapting to it, which may be seen in the recent announcement of different plant closures. Also, in the absence of the price pressure from the dumped imports the decline in prices and profitability of the Community industry would have been much less marked.

Conclusion on causation

(49) In view of the above, it is provisionally concluded that while the decline in apparent consumption or certain third country imports certainly may have contributed to the injury suffered by the Community industry, in particular in terms of a reduction in production and sales volume, the dumped imports remain a significant factor especially as far as the price and profit development of the Community industry is concerned. In view of the coincidence in time between, on the one hand, the price decrease and undercutting established for the imports concerned, the significant market share gained by the dumped imports originating in the countries concerned and, on the other hand, the decline in sales suffered by the Community industry, as well as the reduction of its sales prices and the decline of its profitability, it is provisionally concluded that the dumped imports originating in the countries concerned have caused the material injury suffered by the Community industry. Thus, it was also concluded that the effect of factors other than the dumped imports were not such as to break the causal link between the dumped imports and the material injury suffered by the Community industry therefrom.

COMMISSION REGULATION (EC) No 1845/98 of 27 August 1998 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain large electrolytic aluminium capacitors originating in the United States of America and in Thailand.

Community consumption

(90) One of the cooperating producers/exporters claimed that the decline in sales suffered by the Community industry after 1995 was due to a general downturn in the economic cycle of the LAECs market. It should be noted that the Community consumption declined by 8% between 1995 and the investigation period and that, during the same period, the sales of the Community industry decreased by 25 %, i.e. a far larger decrease than the Community consumption. Moreover, between 1995 and the investigation period, despite the decline in consumption, the cumulated dumped imports originating in the USA and Thailand remained stable in volume terms at the high level of 1995 but increased their market share.

Conclusion

(98) Although it cannot be excluded that some of the imports from other third countries and the recent reduction of Community consumption may have contributed to the loss in market share and the disadvantageous situation of the Community industry, the investigation has also shown that these factors were not such as to break the causal link between the imports subject to the investigation and the material injury suffered by the Community industry. This conclusion is drawn in particular given the

decline in sales and the loss of market share of the Community industry, over a period during which demand in the Community increased globally, which coincided with a notable increase in the volume of imports originating in the USA and Thailand, at prices which undercut those of the Community industry. Consequently, in a period where the Community industry was trying to recover from past dumping practises from other third countries it was unable to benefit from the increased demand on the Community market, but it was also unable to benefit from the economies of scale which would have resulted from an increased sales volume, if the Community industry could have maintained its market share. Moreover, as a result of this decline in sales, the average profitability of the Community industry was again on the decline after 1995 and so were employment levels and investments. Therefore, it is concluded that dumped imports from the countries concerned caused material injury to the Community industry during the period considered.

25. Other major issues raised by the interested parties at the time of oral hearing or in the writ petition

- a. Confidentiality – The petitioner has claimed such information as confidential which is by nature confidential because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information. Petitioner provided sufficient reasons for claiming confidentiality and the same were considered by the Authority. It is, therefore, not a situation that the Authority has accepted confidentiality claims on mere claims made by the parties. As regards confidentiality claims on Chlore Alkali and similar other information, petitioner submits that the confidentiality claims are fully consistent in this regard. In any case, no prejudice has been established by the parties. It is also relevant to point out that the Designated Authority's hands are not tied up to the mere claims made by the petitioner domestic industry or foreign producers. It is fully open to an exporter or association/importer/user to provide relevant information to the Authority. In particular, it was open to these parties to provide relevant information with regard to prevailing prices of inputs etc. in fact, Rule 6 in its relevant part provides opportunities to the importers and consumers to provide relevant information to the Designated Authority. The relevant rule is extracted below.

(5) The designated Authority shall also provide opportunity to the industrial users of the article under investigation, and to representative consumer organisations in cases where the article is commonly sold at the retail level, to furnish information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury where applicable, and causality.

No information whatsoever has however been provided by the consumers or their association. Petitioner requests the Authority to specifically

record in the findings that no factual information has been provided by the association or any of its members/ consumers.

- b. **Plant wise analysis** -- *It has been argued that no proper plant-wise analysis has been done to reach appropriate conclusions on injury. Petitioner submits that the argument is illegal and should not be accepted. Under the rules, the Designated Authority is required to determine injury in respect of domestic industry. The relevant rule is extracted below.*

11. Determination of injury. - (1) *In the case of imports from specified countries, the designated Authority shall record a further finding that import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry in India or materially retards the establishment of any industry in India.*

(2) *The designated Authority shall determine the injury to domestic industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to establishment of domestic industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out in Annexure II to these rules.*

26. *It would be seen that the Designated Authority is required to determine injury in respect of "domestic industry". In fact, in a situation where domestic industry comprises of more than one producer, it is established position that the Designated Authority is required to consider domestic industry as a whole for its determination. The Designated Authority cannot consider individual company performances for injury analysis. Such being the case, the information, in any case, cannot be broken into plant wise analysis. In any case, any such analysis would be highly misleading/distorted for the reason that it is company as a whole whose performance can be examined and not plant specific performances. It may not even be feasible to determine plant wise performances under the law for the reason that a company is required to maintain its financial performance consolidated for all the plants/operations. Plant wise financial records are required to be maintained only to the extent that these are relevant for the purposes of consolidation into company's account. It is quite possible that some of the income and expenses are not charged/booked in the relevant plant operations (there is no such statutory requirement. In fact, it is quite possible to book all production expenses at the plant level and all other expenses and income at some other plant or office). In fact, the rules provides as follows with regard to the assessment of injury.*

(vi) *The effect of the dumped imports shall be assessed in relation to the domestic production of the like article when available data permit the separate identification of that production on the basis of such criteria as*

the production process, producers' sales and profits. If such separate identification of that production is not possible, the effects of the dumped imports shall be assessed by the examination of the production of the narrowest group or range of products, which includes the like product, for which the necessary information can be provided.

27. *It would be seen that the rules in fact authorize the Authority to consider information which might even include other products. Such being the case, plant wise performance, in any case, cannot be envisaged.*

- a. No intensified dumping – *It has been argued that DA has been failed to appreciate that decrease in landed value was a function of cost of production and does not necessarily result in a conclusion that there was increased dumping margin.*

It is submitted that the dumping margin is not directly related to cost of production. It is only in a situation where the cost of production is above the selling price that the cost of production becomes relevant. Otherwise, dumping margin being the difference between domestic price and export price, it is immaterial that the cost of production might have undergone a change. The decline in landed price at a first instance clearly implies increased dumping.

- b. Grey and dyed fiber comparison – *It has been argued that the data of grey and dyed has been combined. Petitioner submits that it is for the importers, foreign producers and consumers to provide relevant information and make appropriate claims. The interested parties cannot confine themselves to mere arguments. If the consumers or foreign producers considered that there were significant differences in grey and dyed cost and price and the same required separate assessment, the relevant data should have been provided to the Authority and claims should have been made within the time limits set out in the notice of initiation. Such high questions of fact cannot be brought before the Authority at such a belated stage of the proceedings.*

28. *Without prejudice, it is submitted that it has not been established that in fact data of grey and dyed has been combined. The import data does not show significant imports of dyed fiber. Thus, in any case, the issue is totally irrelevant.*

29. Majority imports were in advance license – *Petitioner submits that no factual information has been provided by the association. The Designated Authority cannot consider such factual argument without relevant information on record. The Designated Authority is required to satisfy itself with regard to accuracy of the claims which can only be done if an interested party has provided relevant information to the Designated Authority. In the present case, however, the association and its members have preferred non cooperation with the Authority and therefore it remains to be established that the imports were only in advance license. In fact, by their own arguments, they are contending that majority of the imports were under advance license. Majority could mean even just above 50%. It*

is possible that the imports were entirely under advance license in the earlier years and only 50% or so imports were under license in the period of investigation. If so, this clearly establishes that the consumers moved to imports of the product under consideration on duty paid basis as well.

30. Without prejudice, even if it is argued that entity of imports were under advance license, the same could have still caused injury to the domestic industry. As submitted extensively and repeatedly during the course of the investigations, the pricing of the domestic industry has been based on the import prices. Further, consumers are in a position to decide their sources based on relative price offered by different suppliers. The imports are admittedly not under negative list of DGFT. A price quoted by foreign producers can very well be converted into the price at which the consumer can import the material for its domestic consumption – only difference between advance license imports and duty paid import being the element of customs duty. Once the customs duty is added to the price offers given by the foreign producers, the consumers know precisely the price at which they are in a position to import the material. Thus, there is no legal and factual basis or the argument that import under advance license have no relevance to the present purposes and could not have caused injury to the domestic industry.

31. Determination of Normal Value – It has been argued that Para 7 of Annexure-I has not been applied by the Authority. The petitioner disagrees and submits that the Designated Authority has in fact applied Para 7. Followings are relevant in this regard. According to Para-7, the normal value in China can be determined on any of the following basis: -

- a) the price in a market economy third country,
- b) constructed value in a market economy third country,
- c) the price from such a third country to other country, including India,
- d) the price actually paid in India, adjusted to include a reasonable profit margin.
- e) the price actually payable in India, adjusted to include a reasonable profit margin.

Normal Value could not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available. It is relevant to mention here that such Normal Value must be "comparable price in the ordinary course of trade for the like article when meant for consumption in such market economy third country". In order to arrive at Normal Value on this basis, the Designated Authority requires complete & exhaustive verifiable information on all domestic sales made by a cooperating producer in such third country, along with its cost of production and all other associated information and evidences (including all information in the ordinary course of trade). Principles of fair comparison as laid down under Article 2.4 of the Anti dumping Agreement are also relevant in this respect.

Petitioner submits that India is an appropriate surrogate country for Chinese producers. Not only consideration of India as a surrogate country has resulted in access to accurate and adequate information, there is no factual basis to consider that India is not a proper surrogate country. India has been considered as an appropriate surrogate country by other Investigating Authorities too.

The normal value in China can be determined on any of the above-mentioned basis. The normal value in China can thus be determined on the basis of (a) price in India, and (b) cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and profit.

Without prejudice, petitioner submits that the interested parties could have provided relevant information to the Designated Authority in accordance with the provisions of Para-7 and could have requested the Designated Authority to consider the same. However, no such factual information has been provided by any interested party. The obligation of the Designated Authority under the Rules is with regard to information made available to the Designated Authority by various interested parties.

32. Malafide petition – *It has been argued that the proceedings of the applicant are malafide & with an intention to avoid competition as the applicant has deliberately manipulated the figures of the balance sheet & records of the public disclosure. Petitioner strongly refutes and submits that such a wild statement is without any legal and factual basis. Petitioner is one of the most respected business houses in the Country. No data has been distorted at all and there has been no manipulation of the figures in the Balance Sheet or in the records of the public disclosures. Such statements are clearly imaginary.*

33. Other issues relating to standing of the petitioner : *Question 6 is not answered fully*

Followings are relevant –

- a. *All relevant information is on the record of the Designated Authority.*
- b. *Petitioner clearly stated that it has production set ups in the subject countries.*
- c. *Since petitioner itself had agreed that these entities are related, the basis on which these companies are related becomes irrelevant. Information establishing relationship is relevant only in those situations where a party disputes existence of such relationship.*
- d. *The petitioner has affiliated companies in Indonesia and China producing & selling the product. The companies are Birla Jingwai Fibres Company Limited, China and PT Indo Bharat Rayon, Indonesia. The relationship between these entities is given in the table below:*

S N	Name of the entity	Common directors
1	Grasim Industries Ltd	Mr. Kumar Manglam Birla Ms. Rajshree Birla Mr. S K Jain
2	Birla Jingwai Fibres Company Limited, China	Mr. S K Jain
3	PT Indo Bharat Rayon, Indonesia	Mr. Kumar Manglam Birla Ms. Rajshree Birla Mr. S K Jain

34. Without prejudice to petitioner's primary argument that full information is on record of the Designated Authority and the Designated Authority has rightly exercised discretion, as an alternative to the submissions made before, petitioner submits that the Designated Authority has in the meantime issued final findings in the matter of circular weaving machines, wherein the Designated Authority has laid down the governing principle for relationship. Petitioner submits that if the test applied in circular weaving machines are applied to the present case, it would be seen that the petitioner is not even related to the Indonesian company. Therefore, given the repeated arguments of the opposing parties on this account, petitioner submits that the Designated Authority may revisit the previous determination and consider whether at all the petitioner should be treated as related company.
35. It may be argued that the Designated Authority has initiated the investigations based on relationship and once the petitioner itself has agreed existence of relationship, the same cannot be revisited either by the petitioner or by the Authority. Petitioner however submits that the Authority has to reach its own determination, independent of the claims by the parties. If the Designated Authority has laid down some principles for relationship in some other case, the same are equally applicable to the petitioner's case as well. Chinese company is 100% subsidiary of Aditya Birla Group. This relationship is wholly irrelevant for the present purposes. Under the Rule 2(b), relationship is relevant only with "exporters" or "importers". Relationship with foreign producers is wholly immaterial and does not lead to disqualification of such domestic producer. No information on relationship with Indonesian company is given. The relevant information is on record of the Authority.
36. The petitioner got the investigation initiated on the basis of truncated information and now claiming that there is no relationship: Even the facts gathered during the course of the investigations establish that initiation was valid.
37. 6% cannot be said to be an intensified dumping: The intensified dumping was within the investigation period. If the data for the investigation period is considered on month by month basis, the same shall clearly establish intensified dumping.

Export Price USD per KG

	July 08	Aug 08	Sept 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08
China	2.02	2.02	2.10	2.28	2.09	1.78
Indones ia	2.28	2.17	2.17	2.18	2.24	2.05

Information of imports in Jan.-March, 09 period shows that there was further significant decline in prices from subject countries.

Jan-Mar 09	USD KG
China	1.57
Indonesia	1.79

There is further decline in export price from subject countries in Jan-March, 2009. In fact, these are the orders booked at the end of POI and must therefore have been included in the questionnaire responses of the responding exporters.

38. There is unison of interest. The counsel representing domestic industry is also representing the related exporter. There is no legal prohibition. Neither the petitioner nor the Indonesian company has something to hide from the Designated Authority.
39. In the light of the statement that domestic industry is not related to either Chinese or Indonesian company, the initiation, preliminary findings and final findings is non est. The argument must be rejected for the following reasons – (a) the argument has been advanced as an alternate to the argument that there is no justification for treating the petitioner company as eligible domestic producer; (b) should the parties agree with the petitioner that it is not related to the exporters, the entire argument must fail. Should the Designated Authority find no merit in the argument of the petitioner, the primary argument remains; (c) had it been the other way, i.e., a situation where the petitioner had claimed no relationship and the Authority finds such relationship, possible illegality of the investigation could be true. However, where the petitioner established that such relationship does not render the petitioner as ineligible, subsequent claim that the petitioner is not related will not vitiate the legal position.
40. Normal value is based on generality of data and still kept confidential. The Designated Authority cannot disclose such export price and dumping margin, as the same will lead to disclosure of normal value.
41. To sum up, the domestic industry has submitted that:
 - (a) The present investigations have been rightly initiated by the Designated Authority.
 - (b) The petitioner company constitutes domestic industry, notwithstanding its relationship with one of the Indonesian producer. The Indonesian producer has had very small volume of exports to India, that too under Advance Licence.
 - (c) Even when the petitioner had admitted relationship at the time of initiation, petitioner now requests the Designated Authority to kindly examine, more so because of the jurisprudence laid down by the Designated Authority in the matter of Circular Weaving Machine whether at all the petitioner should be treated as related company to the Indonesian producer within the meaning of anti dumping rules.

- (d) *The product under consideration has been exported to India from the subject countries below associated Normal values.*
- (e) *The domestic industry has suffered material injury in respect of the product under consideration.*
- (f) *The material injury has been caused by the dumped imports from the subject countries.*
- (g) *Definitive anti dumping duties are required to be imposed on imports of the product under consideration in India.*

Written Submissions made on behalf of PT South Pacific Viscose, Indonesia; Indian Spinners Association and Rajasthan Textiles Mills Association

42. The following submissions have been made on behalf of these interested parties:

43. Preliminary Objections: *the initiation of investigation in this case is without jurisdiction for the following reasons:*

- a. *It is submitted that domestic industry has intentionally and mischievously changed the format as prescribed by the Authority in the application Proforma. Part 'b' of the question 6, which is important because it gives the information about relationship of applicant with exporter or importer of the alleged dumped article. This question of nature of such relationship and comes from the Rule 2(b) which must necessarily be answered prior to the initiation itself. It was stated by the representative of the Domestic industry that they had provided the required information even though the question might have changed. It is respectfully submitted that the Domestic Industry is making a futile attempt to obfuscate the Authority. The non-confidential version which is supposed to be a replica of the confidential version is a testimony to the fact that no information was provided by the Domestic Industry with regard to their relationships with producer/exporter in the country under investigation. This is reinforced by the fact that no such mention about relationship has been indicated in the initiation notification also. Clearly, it is only after the interested parties raised a serious objection that the Domestic Industry made an attempt to cover up an issue which in our opinion is fatal to the case.*
- b. *In view of the amended definition of Rule 2(b), the sole producer in India ceases to be an eligible Domestic Industry in terms of the specific provisions of law. Rule 2(b) reads as follows:-*

"Rule 2(b): "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof [in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers only]

Provided that in exceptional circumstances referred to in sub-rule (3) of Rule 11, the domestic industry in relation to the article in question shall be deemed to comprise two or more competitive markets and the producers within each of such market a separate industry, if—

- (i) *the producers within such a market sell all or almost all of their production of the article in question in that market; and*
- (ii) *the demand in the market is not in any substantial degree supplied by producers of the said article located elsewhere in the territory;*

c. *Scope of Rule 2(b) post-amendment in February 2010 can be analyzed through the Table below:*

	Rule 2(b) Prior to 27.2.2010	Rule 2(b) with effect from 27.2.2010
d. A		
Main Definition	"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article	"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article
Exclusions	except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof	except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof
Scope of Discretion	in which case such producers [shall] may be deemed not to form part of domestic industry:	in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers only:
Implications	Discretion in respect of Category B	Discretion in respect of Category A + C only

Table above goes to show that there is no change in Rule 2(b) in relation to the "main definition" and "exclusions". The change brought about is only in relation to the "scope of discretion". It is submitted that after having determined the eligibility of the domestic producers strictly in terms of the express language of the Rule, the DA has to apply the "major proportion" test to use its discretion whether or not to consider the eligible domestic producers as the eligible "Domestic Industry". With respect, this is the only discretion available to the Designated Authority under the amended rule.

- d. *It is clear from the above table that subsequent to the amendment in Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules vide Notification No. 18/2010-Customs (NT) dated 27.02.2010, the Authority was left with no discretion with regard to the inclusion of the domestic producers who are either related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers of the Product under Consideration. It is important to note that prior to the said amendment, the Rule specifically empowered the Designated Authority to exercise its discretion with regard to the above-referred category of domestic producers whereas the erstwhile discretion has specifically been taken away by the said amendment. It is pertinent to note that the word "may" in the amended Rule 2(b) gives discretion limited and restricted to the "rest of the producers" and not for the excluded category. Thus, any exercise of the discretion by Designated Authority to treat applicants within the definition of "Domestic Industry" under the amended Rule 2(b) would be without jurisdiction and without the authority of law.*
- e. *It is important to note that in the instant case the Rule 2(b) prior to the amendment dated 1.12.2011 is applicable because this amendment in the Rule 2(b) is effective from the date of its publication in the Official Gazette.*

Standing of the Applicant: *On behalf of the interested parties, we submit that the applicant is not eligible to file the present application under the Rules and the jurisprudence on the subject. In this context, we submit as under:*

- f. *Rule 2(b) contemplates that, the Designated Authority may not treat domestic producers as Domestic Industry if such producers are related to exporters or importers or are themselves importers of the allegedly dumped product. Admittedly in the subject case, M/s. Grasim has related entities in China and Indonesia. It is also admitted that PT Indo Bharat Rayon, Indonesia is wholly 100% held by the applicant in question and has not only exported subject goods to India but has been found to be resorting to dumping.*
- g. *Final findings record that PT Indo Bharat Rayon, Indonesia (100% subsidiary of the sole domestic producer) resorted to unfair price behaviour and was adjudged with the maximum anti-dumping duty of 0.164 % whereas the dumping margin from the other cooperating exporter is only 0.103%. Under the circumstances, it is apparent that the injury to the sole domestic producer is, at best, a self-inflicted injury which ought not to be protected by way of anti-dumping duty.*
- h. *It is obvious that the cause of the injury, if any, is attributable to the dumped imports from the related entity. It goes without saying the non-related exporters have no choice but to match the prices being offered by the other cooperating exporter from Indonesia which happens to be a 100% group company of the sole Indian producer. Under the circumstances, it is clear that the Indian producer and its subsidiary in Indonesia have colluded to ensure that the other competitors are first forced to lower their prices and then the Indian arm brings an anti-dumping investigation with the sole objective of blocking fair competition in the Indian market. It is submitted that the process*

of anti-dumping investigations should not be allowed to be so brazenly abused by the sole monopoly producer in India.

- i. It may also be placed on record that the fact that PT Indo Bharat Rayon was a fully owned subsidiary of the applicant was withheld from all the stakeholders in this investigation. In fact, even today, the true nature of the relationship has been withheld from all other interested parties except the applicant and its related exporter from Indonesia, who are both represented through the same representative. Hence, parties were prevented from raising objections on standing.*
- j. Without prejudice to the above, it is apparent that the related entity of applicant is seeking determination of individual dumping margin. This goes against the object and purpose of introduction of deeming fiction in Rule 2(b) which contemplates exclusion of such producers who are related to the exporters if the Designated Authority deems it fit. Exercise of discretion in favour of Domestic Industry would be an antithesis to the object and purpose of introduction of deeming fiction in Rule 2(b).*
- k. As regards the reasoning adopted in the Final Findings that the quantum of imports by the related party was less than 3%, we submit that such an approach is not valid for the reasons in the following paragraphs:*
 - (i) There is no indication in law or theory that the quantum of imports can be a decisive factor for the purpose of exercise of discretion under Rule 2(b). It is important to note that wherever the legislature wanted to give numerical criteria in the law, the same has been done specifically. For instance, 2% as de minimis dumping margin, 3% and 7% as de minimis volume from each country have been specifically mentioned in the WTO Agreement on Anti-dumping as the Indian Anti-dumping Rules. No such numerical criteria have been laid down for the use of discretion under Rule 2(b) or its corresponding Article in the Anti-dumping Agreement.*
 - (ii) There are good reasons for not providing for numerical criterion for Rule 2(b) as the important issue is the nature of relationship and the possibility of abuse by a collusive behaviour.*
 - (iii) It is important to note that the Designated Authority himself in the prescribed application proforma seeks information with regard to the nature of relationship and NOT on the quantum of imports by the related a party.*
- l. The entire issue of related party transactions goes by the doctrine of "Single Economic Enterprise". In the US Hot Rolled Steel, paragraphs 141-158; Ref. WT/DS-184/AB/R, the Appellate Body has held that "There are many reasons relating to corporate law and strategy, and to fiscal law, which may lead to resources being allocated, in these ways, within a single economic enterprise".*

m. Under the EC jurisprudence and academic literature, the authorities exclude the domestic producer from the definition of "Domestic Industry" if they find

- (i) That the related exporter had participated in the dumping practices, or*
- (ii) That the related exporter provoked or contributed to a fall in prices in the market.*

n. In the instant case, based on the Final Findings of the Designated Authority himself, it is clear that:

- (i) The Indian applicant is related to the major producer and exporter from Indonesia.*
- (ii) The related exporter from Indonesia has exported to India at dumped prices. The dumping margin for the related exporter is almost twice that of the other cooperating exporter [Criterion (h) (i) above]. Thus, it is clear that the injury, if any, is self-inflicted, a situation in which no anti-dumping authority ever imposes duties.*
- (iii) A detailed analysis would indicate that the related exporter himself had provoked the price fall by offering material at prices lower than that of the other exporters. Thus, the related exporter from Indonesia viz. PT Indo Bharat Rayon has not only contributed but provoked price fall in the Indian market [Criterion (h) (ii) above].*
- (iv) It goes without saying the non-related exporters have no choice but to match the prices being offered by the other cooperating exporter from Indonesia, which is admittedly a related company of the Applicant. Under the circumstances, it is clear that the Indian producer and its group company in Indonesia have colluded to ensure that the other competitors are first forced to lower their prices and then strategically the Applicant brings an anti-dumping investigation with the sole objective of blocking fair competition in the Indian market.*
- (v) Going by the EC jurisprudence also, related produces which fulfil any of the above criteria, would have to be excluded from the definition of Domestic Industry.*

44. Short & Inappropriate Period of Investigation: It is submitted that in the instant case, the applicant had requested for a six month period of investigation which was accepted by the Authority by making an exception to the practice and guidelines without any sound basis or reasoning. The Hon'ble Designated Authority has not appreciated that the Applicant strategically claimed injury only for 6 months and requested for examination of pre-conditions of Rule 5 based on such claims contrary to the specific guidelines and practice followed by the Designated Authority. The selection of 6 month period of investigation is also contrary to guidelines of the Committee on Anti-Dumping Practices. It has been the consistent stand of the DGAD that the most desirable period of investigation is a financial year. In several cases, the Designated Authority has insisted that the

information should necessarily be of a minimum of one year. None of the factors like financial reporting having an effect on availability of data, characteristics of the product in question, including seasonality and cyclicity, etc. has been taken into account while fixing the period of investigation for minimum period of 6 months.

- a. While accepting such 6 month period as period of investigation the DA recorded in the impugned preliminary findings as under:

"5.3 The Authority has noted the submissions made by the interested parties regarding period of investigation and is of the view that the period of investigation chosen in the instant matter has been appropriately chosen considering the facts of the case, which also covers the most recent available data on the subject. Besides, the decision to take six-month period as POI has also been upheld by the Hon'ble tribunal in the matter of Virchow laboratories Ltd. v/s Ministry of Finance."

- b. It can be seen that the Designated Authority has in the Final Findings merely stated that "is of the view that the period of investigation chosen in the instant matter has been appropriately chosen considering the facts of the case, which also covers the most recent available data on the subject". It is respectfully submitted that this is just a statement which cannot be put under the category of a reasoned exercise of discretion based on cogent reasoning. In the initiation notification, intensified dumping has been stated to be intensified dumping in July-Dec., 2008. This is without any basis in law or logic for choosing an exceptional period of six months as the POI. In fact, the practice of normally taking a year as the period of investigation is precisely to ensure that no anti-dumping investigations are initiated due to short-term fluctuations in prices. Moreover the Authority is fully aware that the shortest permissible POI of six months covers about four months when the entire world was passing through an unprecedented economic and financial crisis in which the fabric and consequently the yarn and the fibre industry suffered considerably. It is an admitted fact that there was a substantial fall in demand in an otherwise growing market and, therefore, the Designated Authority ought not to have taken a period craftily selected by the Domestic Industry even if the same is legally permissible. It may be clarified that the issue here is not about the legality of selecting a six month POI but the propriety and appropriateness of the same. In support of the above, kind attention is drawn to following from extract guidelines from Committee on Anti-Dumping Practices:

"1. As a general rule:

- 1. the period of data collection for dumping investigations normally should be twelve months, and in any case no less than six months, ending as close to the date of initiation as is practicable;*
- 3. In order to increase transparency of proceedings, investigating authorities should include in public notices or in the separate reports provided pursuant to Article 12.2 of the Agreement, an*

explanation of the reason for the selection of a particular period for data collection if it differs from that provided for in: paragraph 1 of this recommendation, national legislation, regulation, or established national guidelines." (Emphasis added)

No Case on Merits:

45. *Without prejudice to the aforementioned objections to the very initiation of the investigation, it is submitted that the applicant has not been able to make out any case whatsoever of injury or causal link to merit imposition of anti-dumping duties.*
46. Market Share: *The applicant has claimed that they had lost the market share due to imports from the subject countries. In this connection, it is submitted that it is an admitted position that the market share of the applicant has come down from 99.91% to 94.10% during the POI of six months which is a loss of a meagre 5.81%. The Designated Authority has not appreciated that even this small loss of market share is based on incomplete data. In any case, a drop in market share by about 6% within a short period of six months out of which bulk of the period saw macroeconomic problems, cannot be a ground of injury, let alone material injury.*
47. Production & Capacity Utilization of Domestic Industry: *It has been claimed that the production and capacity utilization of the applicant had come down during the POI. It is submitted that such an analysis is completely flawed as it does not take into account the fact that the applicant had increased its installed capacity by 31.40% increase during 2008-09. Obviously, it cannot be expected that the new capacity shall also operate at the same level as that of the existing capacity. Further, it appears that the fall in the national and international demand has certainly contributed to the drop in production and the capacity utilization during the short POI which has not been factored in at all.*
48. No Price Undercutting: *It can be seen that there is no price undercutting from Indonesia and the price undercutting from China is negligible. Thus, no case for imposition of anti-dumping duties has been made out.*

Other Factors & Absence of Causal Link:

49. *Even assuming that the applicant suffered some slowdown for a short period of time, there is ample evidence to prove that the injury was at best self-inflicted or clearly attributable to factors other than dumping. As per the Anti-Dumping rules, the presence of causal link between dumping and injury is an essential prerequisite for proving material injury to the domestic industry on account of dumping. In the anti-dumping proceedings, it is imperative to prove that the dumping has caused injury to domestic industry. The provisions of Clause (V) of Annexure II of the Anti-Dumping Rules pertaining to the Principles of determination of injury states that:*

"It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs (ii) and (iv) above, causing injury to the domestic industry. The demonstration of a causal relationship between the

dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of relevant evidence before the designated authority. The designated authority shall also examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injury caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption

50. Sales Volume: The domestic industry has also claimed injury on account of declining sales volumes. Here again the various reports of the domestic industry clearly show that the sales volumes have declined but not because of the alleged dumping as claimed by the petitioner. The decline in sales volume are admittedly attributable to the following factors:

- Consumer resisting purchase due to global recessionary trend
- Sharp fall in exports of textile products due to lack of demand accentuated by credit squeeze and credit risk factor
- Moderation in domestic demand
- Global slowdown coupled with inflationary pressure
- Liquidation of inventory in the value chain.

51. The above reasons for decline in sales have been attributed by the domestic industry itself in its various reports/presentations. Thus, it is clear from the above that the reason for decline in sales volume of the domestic industry cannot be attributed to alleged dumping.

52. Pricing Policy of the Applicant: We wish to reiterate our submissions on the pricing policy and strategy adopted by the petitioner in respect of deemed exports. It appears that the petitioner that the domestic industry is offering incentives for their supplies against deemed exports in the form of rebates.

a. As per the pricing policy of the Applicant, rebates are given if the following conditions are met with for their supplies against deemed exports:

- Customers need to furnish a true copy of export contract of VSF based yarns with their foreign buyer, immediately after it is formalized.
- VSF with rebate shall be supplied on replenishment basis against receipt of export proof under DEPB and Duty Drawback Scheme. For the purpose of replenishment, copy of Excise Invoice and AREI will suffice. However, further export proof in terms of shipping bill / bill of lading, Copy of Export Invoice etc., need to be received at our end within 30 days from date of AREI.
- To avail any rebate under the discount schemes, a spinner manufacturing VSF based blended & twisted yarn has to ensure a

minimum VSF content of 35% in the final product manufactured at ring frame stage.

- b. *It is thus clear from the above that the petitioner is offering these incentive schemes in the form of rebates from the basic price of the subject article offered to the customers subject to the above conditions being met. The Authority would appreciate that had the subject article been offered to customers for normal domestic sale, the price charged by the petitioner would have been higher.*
- c. *It has been observed that the price charged for the supplies against deemed exports are much below the price charged for the domestic sales. This may be seen from the price lists of the petitioner.*

It appears from the pricing strategy and policy of the domestic industry that certain sales made to customers for eventual exports have also been included under domestic sales for the purposes of injury analysis.

The paramount objective of anti-dumping measures is to ensure free and fair international trade. They act as remedial measures for removal of injury caused to the petitioner in the domestic market due to unfair trade practices and thus reestablish free and fair competition, providing a level playing field for the domestic industry. Thus, the inclusion of known export sales for injury analysis is inconsistent with the anti-dumping rules and regulations.

- d. *It is relevant to quote the provisions of the Anti-Dumping Rules with reference to injury analysis here. Annexure II regarding principles of determination of injury states that:*
“(i) A determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the affect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products”.
- e. *It may be seen that the applicant is fully aware that the subject goods are meant for eventual exports and therefore it follows a different pricing policy to ensure that the export market is not lost. This has nothing to do with its performance in the domestic market which is the requirement of law. The domestic industry cannot take shelter of injury under alleged dumping when the so-called injury may have been caused due to its own pricing policies. Thus, there is clearly absence of causal link between alleged dumping and injury to the petitioner.*
- f. *We also understand that the petitioner supplies substantial quantities to its related entities. We shall be grateful if this could be looked into and a non-confidential version of all such information is supplied to us for our comments.*

53. *It is also submitted that the various submissions made by or on behalf of the interested parties during the course of the proceedings may be considered as a part of these written submissions as the same are not repeated for the sake of brevity.*
54. *In view of the above submissions, we would request the Hon'ble Designated Authority to terminate the investigations forthwith.*

Rejoinder submissions made on behalf of the domestic industry

A. The Authority may disclose the reasons for not accepting the remand orders of the CESTAT.

55. *It is for the Designated Authority to reply.*

B. The initiation is without jurisdiction for the following reasons:

- a. *The domestic industry has intentionally changed the Application proforma and did not answer Part b of question 6 which needs to be answered prior to initiation of the investigation.*
56. *The Written Submissions are referred and relied upon wherein the issue has been dealt in detail. There is no such intention. Facts are on record. Further, the findings recorded by the Authority establish that in any case there is no change in the scope of the domestic industry.*
- b. *The Authority has no discretion with regard to inclusion of the domestic producers who are either related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers of product under consideration.*
57. *The Written Submissions are referred and relied upon wherein the issue has been dealt in detail.*
- c. *Rule 2(b) prior to the amendment dated 1.12.2011 is applicable because this amendment is effective from the date of publication in the official gazette.*
58. *The amendment shall be applicable.*
59. *The Authority applied Budget 2010 amendment to the on going cases. Therefore, the present amendment should also be applied.*
60. *The petitioner has established that either way, it does not vitiate the position.*

C. The applicant is not eligible to file the present application due to following reasons

- a. *M/s Grasim has related entities.*
61. *The Written Submissions are referred and relied upon wherein the issue has been dealt in detail. The relationship does not debar petitioner from seeking relief. This is without prejudice to our contention that even relationship may not be such as to attract provisions of Rule 2(b). Decision of Designated Authority in the matter of Circular Weaving Machine and emerging jurisprudence is relied upon*

- b. In Final Findings, PT Indo Bharat Rayon, Indonesia (100% subsidiary of the sole domestic producer was adjudged with the maximum anti-dumping duty. It is apparent that the injury to the sole domestic producer is self inflicted injury which ought not to be protected by way of Anti-dumping duty.
62. It is submitted that given the positive dumping margin that has been established in the instant case, it is evident that the unrelated Indonesian producer did resort to dumping, which has been found to be unprovoked and not due to the three small shipments made by PT Indo Bharat Rayon. Significant volume of the subject goods have been exported by PT South Pacific Viscose at dumped prices. Also the dumped imports of the subject goods from the subject countries have caused 'injury' to the domestic industry. It is further submitted that small and sporadic exports have not been a significant factor in such injury. Besides, the focus of M/s Grasim Industries Ltd continues to be production and sale of the subject goods. Thus, there does not appear to be case of self-inflicted injury
- c. Injury if any is caused due to dumped imports from the related entity. The domestic producer along with the related exporter has colluded to ensure that the other competitors are compelled to first lower the prices and then Anti-dumping investigation to block fair competition.
63. Already dealt. No such injury has been caused by those exports. Given the positive dumping margin in respect of other exporters, it is without basis that this was a fair competition.
- a. The true nature of the relationship between Indian producer and PT Indo Bharat Rayon is withheld during investigation who are represented by the same representative and hence parties were prevented from raising objections on standing.
64. There is no legal prohibition. Neither the petitioner nor the Indonesian company has something to hide from the Designated Authority. Nor this has vitiated the position in any manner.
- b. Related entity seeking determination of individual dumping margin goes against the deeming fiction in Rule 2(b).
65. Neither the Indian law nor the WTO Anti-dumping Agreement provides that the Authority should hold a domestic producer as ineligible if it is related to foreign producer in case such related foreign producer participates in the investigation and positive dumping margin is established in respect of its exports. Further, an individual dumping margin is required to be determined in respect of each known exporter and the Act and the AD Rules do not make any distinction between a related and unrelated exporter in this respect. As regards deeming fiction under Rule 2(b), the same unambiguously vests discretion in the Authority in such a case. Such discretion, however, needs to be exercised in an un-biased and objective manner.

- c. As regards the reasoning adopted in Final Findings that imports from the related parties is below 3%, the approach is not valid as no quantum of imports can be a decisive factors for the purpose of exercise of discretion under Rule 2(b)
66. Opposing interested parties have no basis to argue that the criteria based on quantum of exports is not a rational criterion. As the issue at hand is "exports" made by a related exporter; the domestic industry submits that the quantum of imports is indeed an important factor to decide the exclusion of the related domestic producer.
67. Global practices have been shown to the Designated Authority. On the contrary, the opposing interested parties have provided no material in this regard.
- D. Short period of investigation has been taken. None of the factors like financial reporting, characteristics of the product including seasonability and cyclicalities etc. The Designated Authority has selected 6 months period of investigation without any reasoned exercise of discretion. In six months there is substantial fall in demand, and the six months covers four months of recession in which the yarn and the fibre industry suffered.
68. Previous submissions and written submissions are referred and relied upon wherein the issue has been dealt in detail. The petitioner reiterates that as far as guidelines and practice followed by the Designated Authority or the guideline of the Committee on Anti Dumping Practices is concerned, it is submitted that (a) the Designated Authority has adopted 6 months period of investigation in a number of cases, (b) the interested parties agree that consideration of 6 months as the investigation period is not illegal, (c) the stated guidelines cannot be read as mandatory prescription applicable in all situations, irrespective of the facts of a case. Factors such as financial reporting cannot be considered as the same would imply consideration of only one period as the period of investigation viz. April-March. With regard to the argument that 6 months period of investigation covers 4 months of the recessionary period, the petitioner submits that the fact of recession cannot be selectively pleaded in support of export price below normal values; as the fact of recession would equally apply to normal value as well. It is, however, submitted that the domestic prices of the subject goods in Indonesia were materially higher than the export price to India. Thus, recession in the global market cannot be stated as a justified reason to be considered in fixing the period of investigation.
- E. Injury has been self inflicted or at best has been caused due to other factors.
69. Positive dumping margin that has been established in the instant case establishes that the unrelated Indonesian producer did resort to dumping, which has been found to be unprovoked and not due to the three small shipments made by PT Indo Bharat Rayon. Significant volume of the subject goods have been exported by PT South Pacific Viscose at dumped prices. Also the dumped imports of the subject goods from the subject countries have caused 'injury' to the domestic industry. It is further submitted that small and sporadic exports have not been a significant

factor in such injury. Besides, the focus of M/s Grasim Industries Ltd continues to be production and sale of the subject goods. Thus, there does not appear to be case of self-inflicted injury

70. As regards other factors causing injury, the petitioner submits that firstly, it has been wrongly assumed by the interested parties that dumping of the product should be the sole cause of injury to the domestic industry. Though production and sale undisputedly suffered due to decline in demand but dumping of the subject goods caused material injury to the domestic industry. With regard to profitability, as the domestic industry fixes its prices on the basis of import prices; therefore, availability of dumped imports at lower prices in the market forced the domestic industry to offer such prices that did not permit recovery of increase in the input costs.
- F. Market share declined only 6% within a short period of 6 months out of which bulk of the period saw microeconomic problems cannot be a ground for injury.
71. The interested parties are taking the shelter of economic crises in order to refute the argument of injury to the domestic industry, but they are unable to appreciate the fact that exporters ought to have also suffered during the same period. But in the instant case, when the market share of the domestic industry declined that of subject countries increased. Also during period of investigation, when the demand of the product declined, the exporters managed to export the goods into India at a significant rate capturing the domestic market.
- G. While analyzing fall in production and capacity utilization, the factors like new capacities being installed by the company, national and international drop in demand has not been considered.
72. The petitioner submits that if the performance of the domestic industry will be examined on same capacity level, which was there before expansion and it would be seen that even with the same capacity levels, the capacity utilization would declined from 104.27 % in 2007-08 to 85.8% in the POI. Therefore, it clearly establishes that declined in capacity utilization is not due to increase in capacity but due to dumped imports from subject countries.
- H. No price undercutting from Indonesia and price undercutting from China is negligible.
73. As submitted earlier, the domestic industry fixes its prices periodically based on prevailing international prices. It is undisputed fact that the prices of the domestic industry are based on import prices. In fact, this fact itself establishes that the increase in the selling prices was incommensurate with the increase in cost of production because of presence of the dumped imports from the subject countries. Further, the purpose of determining price undercutting is to assess whether such dumped imports are causing injury to the domestic industry. If the import price decline, the domestic industry may also be forced to reduce its selling prices. If the import price increases, but not to the full extent of increase in the cost of production, the domestic industry may be prevented from increasing its prices

commensurate with the increase in the cost of production. Under the AD Rules, the Authority is required to determine whether imports are undercutting the domestic prices or whether the effect of imports was to otherwise depress or suppress the prices of domestic industry in the market. Thus, the rules clearly provide for establishing either price undercutting, price suppression or price depression. In any case, absence of positive undercutting does not mean lack of injury.

74. Domestic industry also refers to the final findings notified by the Designated Authority in the matter of PVC suspension resin, wherein the price undercutting cumulatively from the subject countries was negative. The Designated Authority held as follows –

286. It is also seen that the selling price of the domestic industry is almost at the same level as the weighted average LV of imports from the subject countries. Therefore, the price undercutting at the aggregate level is marginally negative though certain countries have significant positive price undercutting. However, the domestic industry's prices are significantly depressed as the domestic industry apparently kept the prices low to protect its market share and therefore, price undercutting would not give a clear picture of price effect.

75. In the matter of poly propylene, the Designated Authority held as follows –

181. The Authority notes that the landed value from the subject countries over the injury investigation period has increased from 100 (Base year 2005-06) to 133 during POI. The trends in the selling price of the domestic industry show similar rising trends. The landed prices of the imports from the subject countries have always been higher than the domestic selling prices of the domestic industry and hence imports were not undercutting the prices of the domestic industry. Negative price undercutting is seen throughout the injury period. In this context the domestic industry has contended that the comparison of the weighted average landed price with the weighted average selling price does not reflect the true picture in view of the fact that the domestic prices have been pegged on the basis of the consignments coming to India at a lower price. Further, there is a time difference between orders booked by the exporter/producers from the subject countries and the time when these shipments landed into India. Considering that the prices of the subject goods significantly fluctuated during the course of the POI, any comparison on a weighted average basis is likely to give misleading picture. Domestic industry has further claimed that increase in the selling prices of the domestic industry could not be commensurate with the increase in costs. However, the trends in increase in the costs vis-à-vis corresponding increase in the selling prices show that the domestic industry has suffered price-suppression.

1. Sales have declined due to following reason like Consumer resisting to purchase due to global recession, sharp fall in exports of textile due to lack of global demand,

moderation of domestic demand, global slowdown coupled with inflationary pressure, liquidation of inventories in value chain.

76. *It is very interesting to note that the interested parties have highlighted reasons for declining the sales of the domestic industry but ignored the fact that these reasons should also lead to decline in imports but imports have all the more increased. It is submitted that the situation where (a) consumers are restricting purchases from domestic source, but increasing purchases through imports; and (b) domestic prices declined due to import prices in fact establishes that injury to the domestic industry is due to dumped imports.*
- J. Domestic industry is offering incentives for their supplies against deemed exports in form of rebates. Prices charged for supplies against deemed exports are much below the price charged for domestic sales.
77. *The domestic industry follows a well laid down pricing policy. The domestic industry declares and sells the product as per "price list". The prices are not negotiated for each sale transaction. The domestic industry does not follow a system of responding to trade enquiries, giving quotations, price negotiations, procurement and execution of order. The domestic industry declares a "price list" and thereafter sells the material on the basis of declared price list. Barring exceptional circumstances, all sales made by the company are as per the price list with little or no discretion to the operating level of marketing executives to modify the prices.*
 78. *The domestic industry's price list must be used for comparison of imported product price with the domestic industry price. In a situation where the company sells material to different customers at different prices, negotiating prices each time, which vary from customer to customer, it might be relevant and appropriate to determine weighted average selling price for the quantities sold over the relevant period. However, in a situation where the company sells its product at pre-determined, declared public price lists and where such price lists are declared after considering international prices, the price comparison between the imported and domestic product must be carried out on the basis of such price lists. Domestic industry reiterates that the selling prices do not vary with customers and therefore there is no necessity of determining weighted average selling price of the quantities sold in a particular period.*
 79. *The price is fixed in a scientific and transparent manner. The basis of fixation of price is the prevailing international price. Considering prevailing international prices and various factors, which must be accounted for the differences which exists in different countries (such as exchange rate, customs duties etc), the company decides its basic price.*
- K. Inclusion of known exports sales by domestic industry for injury analysis is inconsistent with AD rules and regulations.
80. *It is submitted that The company has termed certain category of sales as "deemed exports". They have no disagreement with the opposing interested parties that*

deemed exports should not form part of domestic sales. However, merely because the company has designated certain sales as deemed exports, these would not become deemed exports.

81. *Deemed exports have been defined under the Foreign Trade Policy. Essential ingredients of deemed export sales are the following:*

"Following categories of supply of goods by main / sub-contractors are regarded as "Deemed Exports" under FTP, provided goods are manufactured in India:

- (a) Supply of goods against Advance Authorization / Advance Authorization for annual requirement / DFIA;*
- (b) Supply of goods to EOUs or STPs or EHTPs or BTPs;*
- (c) Supply of capital goods to holders of Authorizations under EPCG Scheme;*
- (d) Supply of goods to projects financed by multilateral or bilateral agencies / Funds as notified by Department of Economic Affairs (DEA), MOF under International Competitive Bidding (ICB) in accordance with procedures of those agencies / Funds, where legal agreements provide for tender evaluation without including customs duty;*
- (e) Supply and installation of goods and equipment (single responsibility of turnkey contracts) to projects financed by multilateral or bilateral agencies / Funds as notified by DEA, MoF under ICB, in accordance with procedures of those agencies / Funds, which bids may have been invited and evaluated on the basis of Delivered Duty Paid (DDP) prices for goods manufactured abroad;*
- (f) Supply of capital goods, including in unassembled/ disassembled condition, as well as plants, machinery, accessories, tools, dies and such goods which are used for installation purposes till stage of commercial production, and spares to extent of 10% of FOR value to fertilizer plants;*
- (g) Supply of goods to any project or purpose in respect of which the MoF, by a notification, permits import of such goods at zero customs duty;*
- (h) Supply of goods to power projects and refineries not covered in (f) above;*
- (i) Supply of marine freight containers by 100% EOU (Domestic freight containers-manufacturers) provided said containers are exported out of India within 6 months or such further period as permitted by customs;*
- (j) Supply to projects funded by UN agencies; and*
- (k) Supply of goods to nuclear power projects through competitive bidding as opposed to ICB."*

82. *Since the Govt. of India considers deemed export sales as export sales and further since the injury assessment must be made for domestic sales, the opposing interested parties have rightly claimed that deemed export sales should not be included in the domestic sales.*

83. *The domestic sales made by the domestic industry do not qualify as deemed export sales, even though it is using the terminology deemed exports in the market place. In fact, the consumer claims export benefits on the exports they make and the domestic industry uses the nomenclature "deemed export" simply for the reason that the fibre has been consumed in a product, which has been exported. However, all export benefits have been taken by the consumers and not by the domestic*

industry. If these were deemed exports sales, the domestic industry would have been entitled for various benefits granted under Foreign Trade Policy.

84. It is therefore submitted that these sales are not deemed export sales as understood by opposing interested parties but domestic sales only. Therefore, the sales have been rightly included under the head "domestic sales".

L. NCV of information as to supplies made by applicant to its related parties may be provided.

85. There are no supplies made by the petitioner to its related parties.

M. Conclusion

86. The arguments raised by the opposing party are mere conjectures, without any factual and legal basis. Further, the claims are unsubstantiated and without any proper appreciation of the facts of the present investigation.

87. Considering the present investigation carried out by the Authority for the product under consideration, it is evident that –

- a. The present investigations have been rightly initiated by the Designated Authority.
- b. The petitioner company constitutes domestic industry, notwithstanding its relationship with one of the Indonesian producer. The Indonesian producer has had very small volume of exports to India, that too under Advance Licence.
- c. Even when the petitioner had admitted relationship at the time of initiation, petitioner now requests the Designated Authority to kindly examine, more so because of the jurisprudence laid down by the Designated Authority in the matter of Circular Weaving Machine whether at all the petitioner should be treated as related company to the Indonesian producer within the meaning of anti dumping rules.
- d. The product under consideration has been exported to India from the subject countries below associated Normal values.
- e. The domestic industry has suffered material injury in respect of the product under consideration.
- f. The material injury has been caused by the dumped imports from the subject countries.
- g. Definitive anti dumping duties are required to be imposed on imports of the product under consideration in India.

Rejoinder submissions filed on behalf of PT South Pacific Viscose, Indonesia; Indian Spinners Association and Rajasthan Textiles Mills Association

Preliminary Objections:

88. *Kindly recall that in our original submissions also we had sought data, information and evidence filed before the Designated Authority by various interested parties. Before affording the present oral hearing, the same ought to have been provided to us. The obligation to provide full information, data and evidence is mandatory under the present Rules. In any case such an approach is contrary to principles of natural justice and fair play and we are prevented from offering appropriate comments on all aspects of the case as a participating interested party. To that extent, serious prejudice has been caused to the interest of the said above named parties on whose behalf present rejoinder is being filed.*
89. *In view of the above, at the risk of repetition, we are constrained to point out that we are totally handicapped to file full and meaningful rejoinder submissions. In view of the strict time lines followed by the Designated Authority, we are constrained to file limited rejoinder submissions based on written submissions of the applicant industry. Principles of natural justice demand that the opportunity provided should be effective and hence we request that the information/documents/data should be provided and only thereafter we may be called upon to file our full comments thereto.*
90. *Written submissions contrary to Trade Notice: We would like to submit that the written submissions filed by the domestic industry have been without giving proper paragraph numbers to each paragraph contrary to specific instructions contained in Trade Notice 1/2007 dated 22.10.2007. You would kindly appreciate that in the absence of continuous serially numbered paragraphs, it is virtually impossible for any interested party to offer its comments in terms of para 3(i) of the said Trade Notice. It is respectfully submitted that we are bringing this issue to your kind attention only because the requirements of Trade Notice are being flouted almost as a matter of right and practice. We have pointed out the difficulties being faced by other parties to give para-wise rejoinder in the past too but the practice seems to be continuing with impunity. Non-compliance of such procedure we were informed would result in rejection of submissions. In view thereof, we pray that the submissions may not be taken on record.*
91. *It may kindly be noted that there are no written submissions on behalf of the other Indonesian exporter namely PT Indo Bharat Rayon have been made even though the representative on record for the said exporter happens to be the same as that of the applicant.*
92. *Paragraph-wise (to the extent feasible) rejoinder submissions follow hereinafter.*
93. *Contents of un-numbered paragraph 1 of the written submissions of the applicant need no response, as it is reproduction of certain facts without any submissions.*
94. *Contents of un-paragraph 2 of the written submissions of the applicant, it has been stated that they reiterate all the facts, contentions, averments and statements presented in previous submissions filed before the Designated Authority and has requested the Designated Authority to treat them by a deeming fiction as part of their written submissions. The applicant may be called upon to list such submissions*

by reference to the date of such submissions together with the dates on which they were filed. If non-confidential version of such documents were not filed along with confidential version, the same cannot be taken into consideration, as they would be contrary to requirements of Rule 7. We reiterate our request to provide index to the public file so that we can cross check if they are available on record. In any case, we request that the Designated Authority to provide a copy of all submissions made by the applicant together with data/information or evidence. Despite repeated requests made in the past also, we have been denied essential documents, which are being used to reach Final Findings.

95. *Contents of paragraph 1 of the written submissions of the applicant need no response, as it is reproduction of certain facts without any submissions.*
96. *Contents of paragraph 2 of the written submissions of the applicant need no response, as it is reproduction of definition without any submissions.*
97. *Contents of paragraph 3 of the written submissions cannot be taken on record until non-confidential version of all the information which is submitted to the Authority on confidential basis is providing to all the interested parties. Considering the same without giving full non-confidential version to all interested parties would be contrary to the requirement of the Rule 7. Without reference to the dates of letters through which submissions were filed, the submissions cannot be reiterated.*
98. *Contents of paragraph 4 of the written submissions of the applicant need no response, as it is reproduction of certain arguments without any submissions.*
99. *Contents of paragraph 5 are wrong and denied. Grasim Industries Ltd. does not satisfy the requirement of standing in terms of Rule 5(3) nor does it qualify to constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b).*
100. *Contents of paragraph 5 (a) needs no response, as it is reproduction of Rule 5 (3) without any submissions.*
101. *Contents of paragraph 5 (b) to (k) are wrong and denied except to the extent the law has been reproduced. Detailed submissions have already been made as to how the sole producer in the country cannot be considered as the eligible Domestic Industry in terms of Rule 2(b) as it is an admitted fact in the instant case, Grasim Ind. Ltd. is related to exporters from China and Indonesia and, therefore, falls under the excluded category. Since there is a single producer, the question of their having the standing in terms of Rule 5(3) also does not arise. In any case, the issue has now been settled with the decision of the Hon'ble Madras High Court in the case of Saint Gobain Glass India Ltd. Vs. UOI wherein it has been held that under the revised Rule 2(b), the Designated Authority has no discretion to consider the excluded category into the definition of "Domestic Industry". It is respectfully submitted that the said decision is squarely-applicable to the facts and circumstances of this case and is binding on the Designated Authority.*
102. *The Domestic Industry has further submitted that the said Rule 2(b) had undergone changes and the Designated Authority is required to first decide as to which rule*

shall apply in such circumstances. In this context, it is submitted that the Domestic Industry has not made any submissions in this regard. Without prejudice, it is submitted that the Designated Authority draws its power from the Rules which are prevailing at the time when such powers are exercised. There is no question of the Designated Authority operating under the old Rule which in the eyes of law has ceased to exist. Moreover, it is important to note that the issue here relates more to the scope and definition of "Domestic Industry" which has to be ascertained only at the time when the Final Findings are rendered. The "Domestic Industry" at the time of initiation is of no consequence as it would render the entire process of investigation meaningless.

103. *Contents of paragraph 5 (l) are wrong and denied. During the public hearing we have pointed out that the petitioner has intentionally omitted the vital question from the prescribed sets of questions just to avoid the nature of relationship with Indonesia. No such information, document and evidence is still available in the non-confidential version of application provided to the interested parties or the documents in the public file maintained by the Authority till date to support the claim of the petitioner. The Designated Authority is requested to kindly look into this vital issue personally and address it appropriately.*
104. *Contents of paragraph 5(m & n) are wrong and denied. It is submitted that the petitioner has only provided some extracts of the decisions and most of them are not relevant to the case and some of them even contradict the claim of the petitioner as the authority confirmed its decision to keep such entity outside the scope of community industry. We are unable to understand, how such cases advance the case of the applicants in any manner. Further, it is submitted that no reliance can be placed on extracts from such findings. The applicants are obligated to provide full copies of the decisions while placing reliance on them. In the absence of full decisions and appreciation of full facts, we are unable to provide full and meaningful comments. Without prejudice to the aforesaid, it is important to note that the Domestic Industry in its written submissions has agreed that the citations submitted by them do not deal with a situation where the applicant is related to exporters but only those where the applicant is an importer of the subject goods. We strongly deny that the said decisions which deal with the case of importers apply ipso facto to the situation where there is an issue of relationship between the applicant and the foreign exporter. Even the text books cited by the Applicant differentiate between the two situations. Moreover, the Domestic Industry has not cited even a single decision wherein the issue of the very existence of discretion with regard to the excluded category under Rule 2(b) has been questioned. Thus, the plethora of instances cited by the Domestic Industry are nothing more than an indication of some practices prevailing in certain jurisdiction in the context of their own law and jurisprudence. In any event, the Madras High Court in the aforesaid decision has also held that "the Indian rule cannot be understood or interpreted with the aid of other countries' definition or decision based on those provisions which are not identically worded as our provision".*
105. *Contents of paragraph 5(o) and sub para (i to iv) are wrong and denied. It is reiterated that Proforma was intentionally left blank by the petitioner to hide relationship from the Hon'ble Authority. It may also be recalled that during the*

public hearing the representative of the petitioner suggested alternative theory by providing nature of relationship for the first time. As regards the deliberate misrepresentation of the applicant in response to the pointed question of the Designated Authority regarding the nature of relationship, the applicant has given a completely unsatisfactory reply in the written submissions. It has been mentioned that the "information establishing relationship is relevant only in those situations where a party disputes existence of such relationship". With respect, such a response of the applicant is not only incorrect but completely presumptive. It is clearly an attempt to get away with a gross misdeclaration by the applicant. A plain reading of the relevant question reveals that the Designated Authority is seeking the nature of relationship which needs to be answered only if the factum of relationship is admitted. It is more than clear now that the Domestic Industry had deliberately suppressed this vital information by changing the questionnaire itself as full and fair information at that stage of the investigation might have led to non-initiation of investigation itself. It may also be mentioned that the applicant even at this stage has claimed confidentiality on the issue of common directors. No reason for claiming confidentiality on the same has been stated. We reiterate that the full nature of relationship is relevant even when the fact of "relationship" is admitted. This is for the reason that in the absence of such information, the Authority would not be in a position to decide the specific criterion to be adopted for inclusion or exclusion under Rule 2(b). Under the circumstances, the fact that the application format has been altered to get desired results cannot be brushed aside by the Hon'ble Designated Authority as it goes to the very root of the matter of jurisdiction. Copy of relevant pages of Proforma prescribed by the Directorate General of Anti-dumping & Allied Duties, which is expected to be filled by the petitioner, is enclosed as Annexure 1.

106. Contents of paragraph 6 need no response as it is only repetition of information provided in the earlier submissions.
107. In response of paragraph 7, it is submitted that even today the petitioner is keeping the names of the directors and relationship with related entities as confidential. Please appreciate that we are unable to comment on this unless full and meaningful information is provided to us. We reserve our right to submit detail comments once the desired information is provided.
108. Contents of paragraph 8 are wrong and denied. It is submitted that the DGAD has prescribed specific formats to seek specific information (in this case with regard to the nature of relationship).
109. Contents of paragraph 9 are wrong and denied for the reasons stated in earlier paragraphs.
110. Contents of paragraph 10 are wrong and denied for the reasons stated in earlier paragraphs.
111. Contents of paragraph 10 (a - d) need no response as it is only repetition of information provided in the earlier submissions which have been dealt with appropriately.

112. *Contents of paragraph 10 (e-f) are wrong and denied for the reasons stated in earlier paragraphs.*
113. *As regards the amendment in Rule 2(b) on 1st December 2011, it may be noted that by this amendment only the word "only" has been removed. It is submitted that this change is of no consequence as even the removal of the word "only" does not in any manner alter the scope of discretion available to the Designated Authority.*
114. *Without prejudice, we wish to point out that practices followed by rest of the countries emanate from practices and/or specific language employed in their statute even prior to making of the WTO Agreement on Anti-dumping. For example, the language employed by US law specifically vests discretion in the Authority. In Canada, the definition of domestic industry is different for application purposes and different for the purposes of analysis to reach conclusions of injury and causal link. EU continues to follow practices that were in vogue even prior to WTO Agreement on Anti-dumping. Merely because the practices have not been challenged does not mean that such practices are good law and in line with the obligations under the WTO Agreement on Anti-dumping. In any case, none of the findings or decisions relied upon deal with the argument raised by us in the present proceedings that the word "may" in the present amended Rule 2(b) and Article 4 is in the context of rest of the producers and not in the context of the ineligible producers. Clearly, they are distinguishable and not good in view of plain language of Article 4 or even their respective municipal legislations.*
115. *Contents of sub para 10 f (A & B) are wrong and denied. It is reiterated that the practices followed by various countries have no binding precedent value when the Designated Authority is bound by its municipal law. This issue is very well settled by Hon'ble Supreme Court in catena of judicial pronouncements that courts and authorities in India are bound by the Municipal law. As mentioned earlier, the decision of the Hon'ble Madras High Court (WP No. 23515 of 2011) is directly relevant on this issue. Further, the language employed by all such countries or territories is not para-materia to Indian law. In any case, even the tribunal has held that even Dispute Settlement Body decisions viz. Panel Reports or Appellate Body Reports do not have any binding precedent value. In such a situation, it cannot be said that practice followed by a country would have any value while applying plain language of Indian law. Interpretation of the contents in the said section is wrong and denied. In the previous submissions and post remand submissions, we have discussed Rule 2(b) in details. The same for the sake of brevity have not been repeated herein. The said submissions may be treated as having been incorporated herein in reply to submissions of the applicants.*
116. *It is submitted that the plethora of EC as well as Indian decisions referred to by the applicant are of no consequence as they are completely unrelated to the issue at hand. In all the cases cited by the applicant, the authorities were accosted with a situation where the domestic producer itself was an importer of the subject goods. It is submitted that the jurisprudence from the text books have little or no persuasive value as the practices followed by other jurisdictions are not even of persuasive*

value particularly when the language in the Indian law is distinctly different from the language of the WTO Agreement on anti-dumping and the foreign laws.

117. As stated earlier, it is submitted that after the decision of Hon'ble High Court of Madras in the case of Soda Ash, it is clear that there is no discretion vested in Designated Authority under amended Rule 2(b) to include domestic producers that are falling under the excluded categories.
118. Comments on Various Extracts of the Findings cited by the Applicant: Without prejudice to our basic submission regarding the non-admissibility of the decisions by the applicant, we give our comments as follows.
119. This finding at Sl. No.1 is sought to be included under category I which relates to imports by petitioner itself from related exporters. Category I cases are not relevant, as the applicants have not themselves imported subject goods from its related entity. However, without prejudice, it may be pointed that the findings at Sl. 1 was in the context of a supporter and not in the context of Petitioner (Community Industry) as defined. Therefore, this case even does not fall within Category I as has been made out by the Applicants. Further, because of self imports by the Tokai Seiki, domestic producer the authority confirmed its decision to keep such entity outside the scope of community industry. Moreover, the injury data pertaining to Tokai Seiki as not considered for injury finding. We are unable to understand, how this case advances the case of the applicants in any manner.
120. This finding at Sl. No. 2 is sought to be included under category I which relates to imports by petitioner itself from related exporters. Category I cases are not relevant, as the applicants have not themselves imported subject goods from its related entity. Further, the finding relied upon is a provisional finding which by no stretch of imagination can have any persuasive value. We are surprised that the applicants have not placed reliance on the Final Findings as the period that it relates to is 1995 and findings would have been concluded either within the same year or in the next year. In the cited case the main reason for not excluding the producer was that almost all the producers of the same industry fitting pipes are importing, which are outside their manufacturing purpose and the producers cannot be shielded themselves from the dumped imports.
121. This finding at Sl. No. 3 is sought to be included under category I which relates to imports by petitioner itself from related exporters. Category I cases are not relevant, as the applicants have not themselves imported subject goods from its related entity. We are unable to understand how this finding supports the case of the applicants as no imports were found to have been made as per the allegations made. Clearly, cases have been cited to strategically claim and mislead the authority to believe that inclusion was done despite relationship.
122. Finding at Sl. No. 4 is sought to be included under category I which relates to imports by petitioner itself from related exporters. Category I cases are not relevant, as the applicants have not themselves imported subject goods from its related entity. Further, the finding relied upon is a provisional finding which by no stretch of imagination can have any persuasive value. We are surprised that the

applicants have not placed reliance on the Final Findings as the period that it relates to is 1995 and findings would have been concluded either within the same year or in the next year.

- 123. Finding at Sl. No. 5 is sought to be included under category I which relates to imports by petitioner itself from related exporters. Category I cases are not relevant, as the applicants have not themselves imported subject goods from its related entity. Further, this case does not deal with the argument raised by us in the present proceedings. The interpretation of the word "may" was never challenged by alleging that the same is in the context of rest of the producers and not in the context of the ineligible producers. The jurisprudence hence is distinguishable.*
- 124. This finding at Sl. No. 6 is sought to be included under category I which relates to imports by petitioner itself from related exporters. Category I cases are not relevant, as the applicants have not themselves imported subject goods from its related entity. Further, the finding relied upon is a provisional finding which by no stretch of imagination can have any persuasive value. We are surprised that the applicants have not placed reliance on the Final Findings as the period that it relates to is 1998 and findings would have been concluded either within the same year or in the next year. Further, Siemens was excluded due to imports from its related entity. For Philips it was found that it imported components and same were used to produce subject goods by Philips in EU. No exports were found by American Philips during investigation. It was in this context such a conclusion was reached by the authority. The finding does not at all support the case of the applicants.*
- 125. This finding at Sl. No. 7 has no relevance in the present case as the Final Finding was issued dated 22nd February, 2000 by Designated Authority. It has no application to position after 2010 as the same was recorded in the context of Rule 2(b) post 1999 and prior to 2010 amendment. There is no dispute that the amendment in 1999 did confer discretion on Designated Authority. It is for this reason the applicants having strategically omitted to mention the date of the findings.*
- 126. This finding at Sl. No. 8 has no relevance in the present case as the Final Finding was issued dated 2nd February, 2006 by Designated Authority. It has no application to position after 2010 as the same was recorded in the context of Rule 2(b) post 1999 and prior to 2010 amendment. There is no dispute that the amendment in 1999 did confer discretion on Designated Authority. It is for this reason the applicants having strategically omitted to mention the date of the findings.*
- 127. This finding at Sl. No. 9 has no relevance in the present case as the Final Finding was issued dated 24th December, 2009 by Designated Authority. It has no application to position after 2010 as the same was recorded in the context of Rule 2(b) post 1999 and prior to 2010 amendment. There is no dispute that the amendment in 1999 did confer discretion on Designated Authority. It is for this reason the applicants having strategically omitted to mention the date of the findings.*

128. *This finding at Sl. No. 10 are sought to be relied upon by the applicant in support of its case. The finding relied upon are provisional finding which by no stretch of imagination can have any persuasive value. We are surprised that the applicants have not placed reliance on the Final Findings as the period that it relates to is old period. Reference to interim orders without reference to final order and conclusion cannot form the basis of any submission even to have any persuasive value. Further, nothing can be drawn from the extract cited by the petitioner.*
129. *This finding at Sl. No. 11 are sought to be relied upon by the applicant in support of its case. The finding relied upon are provisional finding which by no stretch of imagination can have any persuasive value. We are surprised that the applicants have not placed reliance on the Final Findings as the period that it relates to is old period. Reference to interim orders without reference to final order and conclusion cannot form the basis of any submission even to have any persuasive value. Moreover, one of the producers does not provided the information requested in the format and is considered not to have co-operated with the commission, thus not forming the part of the community industry. Thus, this case is on our line of arguments. In view of the above the case should be immediately terminated as Grasim is the solo producer of the subject goods.*
130. *This finding at Sl. No. 12 are sought to be relied upon by the applicant in support of its case. The finding relied upon are provisional finding which by no stretch of imagination can have any persuasive value. We are surprised that the applicants have not placed reliance on the Final Findings as the period that it relates to is old period. Reference to interim orders without reference to final order and conclusion cannot form the basis of any submission even to have any persuasive value. Further, only for the purpose of preliminary finding the commission is including Europrint members from Japan.*
131. *This finding at Sl. No. 13 to 17 are sought to be relied upon by the applicant in support of its case. The finding relied upon are provisional finding which by no stretch of imagination can have any persuasive value. We are surprised that the applicants have not placed reliance on the Final Findings as the period that it relates to is old period. Reference to interim orders without reference to final order and conclusion cannot form the basis of any submission even to have any persuasive value.*
132. *Finding at Sl. 18, and 19 recorded by Designated Authority has no application to position after 2010 as the same was recorded in the context of Rule 2(b) post 1999 and prior to 2010 amendment. There is no dispute that the amendment in 1999 did confer discretion on Designated Authority. It is for this reason, the applicants have strategically omitted to mention the date of the findings.*
133. *Finding at Sl. No. 20 has no application to the facts of the present case as imports by the community was not from subject country.*
134. *Findings at Sl. No. 21 are sought to be relied upon by the applicant in support of its case. The finding relied upon are provisional finding which by no stretch of*

imagination can have any persuasive value. We are surprised that the applicants have not placed reliance on the Final Findings as the period that it relates to is 1999 and Final Findings were recorded within 18 months of initiation. Reference to interim orders without reference to final order and conclusion cannot form the basis of any submission even to have any persuasive value.

- 135. Finding at Sl. No. 22 is sought to be included under category which relates to imports by petitioner itself from un-related exporters. The Category referred to above is not relevant, as the applicants have not themselves imported subject goods from un-related entity. Further, this case does not deal with the argument raised by us in the present proceedings. The interpretation of the word "may" was never challenged by alleging that the same is in the context of rest of the producers and not in the context of the ineligible producers. The jurisprudence hence is distinguishable.*
- 136. Findings at Sl. No. 23 are sought to be relied upon by the applicant in support of its case. The finding relied upon are provisional finding which by no stretch of imagination can have any persuasive value. We are surprised that the applicants have not placed reliance on the Final Findings as the period that it relates to is 2000 and Final Findings were recorded within 18 months of initiation. Reference to interim orders without reference to final order and conclusion cannot form the basis of any submission even to have any persuasive value.*
- 137. Findings at Sl. No. 24 are sought to be relied upon by the applicant in support of its case. The finding relied upon by no stretch of imagination can have any persuasive value as the case relates to exclusion of a producer who did not make itself known and was found to be related to exporters. Further, Philips Consumer was not treated as "Community Industry" as defined; as BC components represented a major proportion, the case was done on the basis of their information only. The reliance placed is completely misleading and mischievous.*
- 138. Findings at Sl. No. 25 are sought to be relied upon by the applicant in support of its case. The finding relied upon are provisional finding which by no stretch of imagination can have any persuasive value. We are surprised that the applicants have not placed reliance on the Final Findings as the period that it relates to is 2000 and Final Findings were recorded within 18 months of initiation. Reference to interim orders without reference to final order and conclusion cannot form the basis of any submission even to have any persuasive value.*
- 139. Finding at Sl. 26 recorded by Designated Authority has no application to position after 2010 as the same was recorded in the context of Rule 2(b) post 1999 and prior to 2010 amendment. There is no dispute that the amendment in 1999 did confer discretion on Designated Authority. It is for this reason, the applicants have strategically omitted to mention the date of the findings.*
- 140. Findings at Sl. No.27 have no application to the facts of the present case as the authority in that case had reached a conclusion that even after exclusion the remaining industry accounted for over 60% of the total domestic production.*

141. Findings at Sl. No.28 have no application to the facts of the present case as the authority in that case had reached a conclusion that there was injury to community producers irrespective of inclusion of producers with relationship. The conclusions reached were in peculiar facts and circumstances of the case. Without prejudice to the above, the argument raised in the present proceedings in the context of "may" has not been raised therein. Hence, the issue needs to be decided in the facts and circumstances of the pleadings on record.
142. From the above, it is clear that the pact has merely cited a series of decisions without examining the legal relevance or the factual content. In fact, the only two decisions which relate to category of "exporters related to the domestic producer" establish that the quantum of imports are of no consequence for the second situation envisaged under Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules.
143. Contents of paragraph 6 and 7 (page 65) are wrong and denied. It is reiterated that in the instant case, the applicant had requested for a six month period of investigation which was accepted by the Authority by making an exception to the practice and guidelines without any sound basis or reasoning. The Hon'ble Designated Authority has not appreciated that the Applicant strategically claimed injury only for 6 months and requested for examination of pre-conditions of Rule 5 based on such claims contrary to the specific guidelines and practice followed by the Designated Authority. The selection of 6 months period of investigation is also contrary to guidelines of the Committee on Anti-Dumping Practices. It has been the consistent stand of the DGAD that the most desirable period of investigation is a financial year. In several cases, the Designated Authority has insisted that the information should necessarily be of a minimum of one year. It is submitted that even in the written submissions, the applicant has not given any cogent reasons for the exception made in their favour. The legal position is known to everyone. Therefore, it can be presumed that neither the applicant nor the Designated Authority had any basis for restricting the POI to six months. As stated in our written submissions 5% cannot be said as intensified dumping which is the sole ground for taking POI as 6 months. Thus, it is not an appropriate criterion either in law or on facts. The applicant has attempted to link the issue of intensified dumping to the cost of production which is incomprehensible. Our argument that the low dumping margin determined by the Designated Authority cannot lead to a conclusion that there was intensified dumping (which is the only justification for a shorter POI), remains unanswered by the Domestic Industry.
144. In response of paragraph 8 and 9, it is submitted that the petitioner has reiterate, and relied upon all the facts, contentions, averments and statements presented in previous submissions relating to dumping and injury & causal link respectively, filed before the Designated Authority and has requested the Designated Authority to treat them by a deeming fiction as part of their written submissions. It is reiterated, that the applicant may be called upon to list such submissions by reference to the date of such submissions together with the dates on which they were filed. If non-confidential version of such documents were not filed along with confidential version, the same cannot be taken into consideration, as they would be contrary to requirements of Rule 7.

145. Contents of paragraph 10 are wrong and denied. It is reiterated that the applicant has attempted to link the fact of contraction of demand with the marginally increased imports. It is submitted that the issue here is whether there is any contraction in demand or not and if yes, how has that affected the performance of the Domestic Industry. It is further, reiterated that the increase in imports in a short period of six months is of no consequence as the orders in the pipeline and the clearances during the POI cannot be stopped. In any case, contraction in demand is an issue of causal link and cannot be linked logically or legally to increased imports for the reasons mentioned above.
146. In response of the extracts of the decision of the E.C. on page 69, it is submitted that out of the three findings, the two relied upon are provisional findings which cannot have any persuasive value. The citation given by the petitioner (the Council Regulation (EC) No 2080/2001 of 23rd October 2001 imposing anti-dumping duty on imports of internal gear hubs for bicycles originating in Japan) supports our view and contradicts the claim made by the petitioner. In the cited case, the percentage decline in demand was 8% whereas loss of market share of the Community industry was 9%. Hence the loss of market share was lesser than percentage decline in demand. In the present investigation, the decline in demand is 51.98% whereas the loss of market share is 5.81%. Hence, the citation does not support the claim made by the domestic industry. On the contrary, it contradicts the claim of the Domestic Industry.
147. Contents of paragraph 11 (a) are wrong and denied. It is submitted that above mentioned parties had never asked for any confidential information from the domestic industry. We had only requested that the information given in the confidential version should be in indexed form in the non-confidential version thereof so as to offer our fruitful comment on the same. Further, needful information was provided by the interested parties at appropriate time and whenever required by the Authority.
148. Contents of paragraph 10 (b) are wrong and denied. It appears that the applicant has inadvertently copied the argument relating to some other case.
149. Contents of paragraph 10 (c) are wrong and denied. The methodology given by the petitioner for arriving dumping and dumping margin is known to all. We have never argued for the methodology for the final figure of dumping. We have only raised our series objection to the conclusion of Authority to consider 6% of dumping as intensified dumping that is also for the short period of 6 months so as to justify the selection of a shorter period of only six months as the POI. The petitioner and their representative are very well aware of this objection. However, since there is no justification to be offered by the applicant, they are attempting to obfuscate the issue by making irrelevant and misleading submissions.
150. Contents of paragraph 10 (d) are wrong and denied. It is an admitted fact by petitioner in its application on page 19 under the heading of "price effect" that there was significant price difference between gray and dyed. Hence any analysis for dumping margin or injury based on such clubbed data of gray and dyed was flawed. Therefore, to say that interested parties are mere alleging that there is

significant differences are wrong and contrary to the submission made by the petitioner in the application.

151. *Contents of paragraph 10 (e) are wrong and denied. It is submitted that under the present scheme of the Act and the Rules, even if there is dumping resulting in consequent injury to Applicant; no duties can be imposed on imports undertaken under advance license. In other words, no protection can be afforded when imports take place even at dumped prices as they are for export purposes. In view of such a situation, the analysis under advance license was critical to a decision to recommend duty. Further, we have strongly argued that imports undertaken under advance license have huge impact on the current investigation and there is any injury to domestic industry that could be on the account of imports undertaken under advance license.*
152. *Contents of paragraph 10 (f) are wrong and denied. We have never argued that the Authority had not applied Para 7 of Annexure I. It is reiterated that the petitioner is trying to mislead the Authority by providing those arguments which were never raised by us.*
153. *Contents of paragraph 10 (g) are wrong and denied. It is submitted that we have argued that the petitioner has not provided the full and correct information of its related party. We have never raised any question on the dignity of the petitioner even though the conduct in respect of the present application may be suspect. The submission in 10 (g) from the petitioner is surprising.*
154. *Contents of paragraph 10 (h) are wrong and denied. It is respectfully time the petitioner has not disclosed the information about the nature of relationship with Indonesian subsidiary which was to be declared at the time of initiation in the question 6 of Proforma prescribed by the DGAD.*
155. *Contents of paragraph 10 (i) are wrong and denied. However, even the comparison made by the applicant does not justify the view that 6% dumping margin can be considered as intensive dumping.*
156. *Contents of paragraph 10 (j) are wrong and denied. We are unable to understand how domestic industry and exporter, having by nature conflicting interests can hire same consultants. In this context, kind attention of the Authority is invited to the decision of the Hon'ble Supreme Court in the case of ATMA Vs. Designated Authority wherein it has been held that in anti-dumping matters there is a lis between the various interested parties. Once there is a lis between the parties, the conflict of interest is inherent. Therefore, it is preposterous to suggest that there is no legal prohibition for representing both the petitioner as well as one of the respondents. It is more than clear that the applicant along with their related party has manipulated the system to get the protection of an extraordinary duty. It is respectfully submitted that the Designated Authority may kindly consider this fact alone as a basis for reaching the conclusion that the petitioner has not come with clean hands before the Authority.*

157. Contents of paragraph 10 (k) are wrong and denied. It is submitted that the applicant cannot be allowed to change its position and facts which were the very basis of the initiation, Preliminary Findings as well as the Final Findings in remand proceedings. Moreover, if the parties are not related, then it is all the more curious that the same lawyer is representing two unrelated but conflicting parties in the same proceedings. In any case, there is no ground or argument by the applicant as to how they are not related to the Chinese and the Indonesian companies.
158. Contents of paragraph 10 (i) are wrong and denied. We reiterate that the Normal Value, Export Price as well as the dumping margin cannot be kept confidential as they are computed on the basis of non enterprise specific data.
159. In the aforementioned premises, the "Conclusions and Prayer" of the applicants are based on faulty premise and misleading data and information. No relief as contemplated under the Act and the Rules can be provided in such circumstances in terms of the present law and practice relating to anti-dumping. It is a fit case in which proceedings may be terminated immediately.
160. We also pray that a copy of rejoinder submissions filed for and on behalf of applicants and other interested parties may be provided to us in the interest of justice and fair play. Without prejudice to the above, we also request the authority to kindly provide us all correspondence including non-confidential version exchanged with the applicants in the present proceedings before proceeding further with the investigations so that appropriate comments can be filed by us on such correspondence. We would request the authority not to take into consideration any response for which non-confidential version has not been filed and copies provided to us. The authority ought not to allow applicant to prevent interested parties to comment on all data and information filed as it has a direct bearing on the outcome of the proceedings.
161. Without prejudice to the aforesaid, it is submitted that the aforesaid proceedings are without jurisdiction in view of the decision of the Hon'ble Madras High Court in the case of SGGI Vs. UOI [supra] and should be terminated forthwith as the applicant has already enjoyed the protection of illegal anti-dumping duties for a long time.

Examination by the Authority

162. As regards the contention that there was no information filed with the Authority at the time of initiation of the instant investigation that M/s Grasim Industries had related parties in China PR and Indonesia; the Authority notes that the contention is not based on facts as the Authority was aware that M/s Grasim industries had affiliated companies both in China PR and Indonesia right at the initiation stage as would also be evident from para of the initiation notification dated 19th March 2009 on the subject.
163. As regards the contention that they had sought data, information and evidence filed before the Authority by various interested parties and that before affording the present oral hearing, the same ought to have been provided; the Authority notes that AD

Rules & regulations on the subject do not require the Authority to provide data, information and evidence filed before the Authority by various interested parties. The AD Rules only require that the Authority shall provide a copy of the application referred to in sub-rule (1) of Rule 5 to the known exporters or to the concerned trade association where the number of exporters is large, and the governments of the exporting countries and that the Authority shall also make available a copy of the application to any other interested party who makes a request therefor in writing. The AD Rules further require that the Authority shall make available the evidence presented to it by one interested party to the other interested parties, participating in the investigation. To this end as a standard practice, a public file containing the non-confidential version of the information/data/evidence filed by the interested parties is maintained by the Authority. Attention of the interested parties has also been drawn to this fact vide the initiation notification itself. Thus, there is no violation of any Rule including the principles of natural justice as these interested parties have had ample opportunities to have access to the information/data/evidence filed by other interested parties to defend their interests on the subject throughout the course of this investigation; hence the contention is devoid of any merit.

164. As regards, the contention that written submissions are contrary to Trade Notice 1/2007 dated 22.10.2007; the Authority notes that the said trade notice was issued to facilitate examination of the issues raised by the parties and therefore the interested parties should have ordinarily followed the guidelines suggested therein.
165. As regards, the contention that M/s Grasim Industries Ltd. does not satisfy the requirement of 'Standing' in terms of Rule 5(3) nor does it qualify to constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b) as it is an admitted fact in the instant case, Grasim Ind. Ltd. is related to exporters from China and Indonesia and, therefore, falls under the excluded category. Since there is a single producer, the question of their having the standing in terms of Rule 5(3) also does not arise and that the issue has now been settled with the decision of the Hon'ble Madras High Court in the case of Saint Gobain Glass India Ltd. Vs. UOI wherein it has been held that under the revised Rule 2(b), the Designated Authority has no discretion to consider the excluded category into the definition of "Domestic Industry"; the Authority has carefully examined the submissions made by respective interested parties on the subject in the context of the applicable law from time to time.
166. It would be appropriate to mention at the outset, that the Rule 2(b) has been amended once again vide Notification No. 86/2011-Cutoms (N.T.) dated 1st December 2011, that has dropped the word "only" from Rule 2(b) of the AD Rules. It is further noted that this amendment has not been taken cognizance of by the Hon'ble Madras High Court in the matter of Saint Gobain Glass India Ltd. Vs. UOI, as would be clear from the para of the judgement .
167. Rule 2(b) now reads as follows:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are

related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

168. As regards which rule shall apply in such circumstances; the Authority notes that considering the Rule 2(b) as the time of initiating this investigation or considering the Rule 2(b) as on date, in either event, the Authority has a discretion on the subject as would be evident from the following.
169. Rule 2(b) of the AD Rules provides that domestic producers which are related to the exporters or importers or which are themselves importers of the allegedly dumped articles may be excluded when determining the domestic industry in certain situations. The Authority is of the considered view that the use of the word 'may' in Rule 2(b) suggests that the two types of producers in question, i.e. related producers and producers importing the dumped product, are not automatically excluded from being part of the domestic industry. On the contrary, it has been the consistent practice of the investigating authorities that the exclusion of such producers must be decided on a case-by-case basis, on reasonable and equitable grounds, and by taking into consideration all the legal and economic aspects involved.
170. The issue of excluding or including a domestic producer from the ambit and scope of the domestic industry is of significant importance; as the question arises whether or not they are really part of the domestic industry in the sense of Rule 2(b) of the AD Rules, which in turn may have an effect on the 'Standing' of the application i.e. whether or not their (the domestic producers that have filed or supported the application) production reaches the necessary level of representativity as stipulated under the AD Rules; as the output of domestic producers, which are excluded from the definition of the domestic industry because of their relationship to exporters or importers; or because of their own dumped imports, would not be considered while computing total domestic production and determining whether the applicant along with supporting domestic producers represent a major proportion of such production.
171. The Authority notes that Rule 2(b) has been amended a number of times. It is noted that Rule 2(b) as on 1.1.1995 provided no discretion to the Designated Authority in such situations where one or more domestic producer had imported the product under consideration or was related to an importer or exporter of the product under consideration.
172. However, WTO Agreement on Anti Dumping and Municipal laws of other investigating authorities vested discretion to the investigating authorities in such situations, which was to be applied on a case by case basis. Thus, Rule 2(b) was amended with effect from 15th July 1999 vide Customs Notification No.44/1999 (N.T.) vesting discretion to the Designated Authority in such situations, which could be applied on case by case basis. Rule 2 (b) was further amended in 2010 as follows:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are

related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers."

173. However, vide Notification No. 86/2011-Cutoms (N.T.) dated 1st December 2011, the word "only" has been dropped. A stated, the use of the word 'may' in Rule 2(b) suggests that the two types of producers in question, i.e. related producers and producers importing the dumped product, are not automatically excluded from being part of the domestic industry. The Authority considers that the discretion so vested in the Designated Authority with purpose and helps it address situations wherein:-

- (a) Some domestic producers may not wish to support an anti-dumping application merely because they themselves are importing the product, or they are related to an importer or exporter of the product. Such domestic producers may even wish to force closure of other domestic producers in order to eliminate competition through unfair practice of dumping. One reason for vesting the discretion in the Authority could be to exclude such related entities, who may seek to thwart an attempt by the remaining domestic producers to seek redressal of injury caused to them on account of dumping by filing an anti-dumping application and seeking suitable relief against the unfair trade practice of dumping. If it were not so, the remaining domestic producers may not be able to meet the 'Standing' requirement as stipulated under the law and seek suitable remedy against the unfair trade practice of dumping. In short, the law enjoins that there may be a need to exclude certain entities from the scope of domestic industry in order to enable the Authority to address injurious dumping in the Country.
- (b) One or more of the domestic producers might have imported the product under consideration or their related company might have imported or exported the product under consideration for one or more *bona-fide* reasons. Some of these reasons are listed below:
 - (i) imports made under advance license in order to compete in the international market in the downstream product;
 - (ii) imports made at the time of temporary suspension of production (due to variety of *bona-fide* reasons, such as fire, strike, natural calamities etc);
 - (iii) imports made to supplement the product-line by importing a particular type which the applicant may not be producing and which might constitute a very small portion of its total business operations;
 - (iv) imports made for testing, research & development, seed-marketing purposes (imports of the product to test the quality and other parameters when faced with low priced imports);
 - (v) imports of the part of the product, which does not form the core activity in the manufacturing of the product.

174. Axiomatically, the Authority considers that it would be inappropriate to exclude such bona-fide domestic producers from being treated as domestic industry. Thus, the Authority is of the view that the modified Rule provides discretion to the Authority in the above mentioned situations. In other words, the AD Rules have been amended to provide discretion to the Authority to include a domestic producer in certain situations or to exclude a domestic producer in certain situations.
175. The Authority has taken into cognizance the jurisprudence available on the subject, which suggests the circumstances in which a related domestic producer may be included or excluded as follows:-
- (a) one of the important factor in this regard is the balance of business of the domestic producer between manufacturing and importing. If the company predominantly manufactures the product in India, it should be included. However, if the domestic producer closes or reduces its production and instead imports the product or the general emphasis of its business shifts from production to imports, it should be excluded.
 - (b) if a domestic producer has shielded itself from the effect of dumping by resorting to imports or exports to a related party, the company must be excluded.
 - (c) if a domestic producer has participated in some way in the dumping practices or has otherwise unduly benefitted from it, it must be excluded.
 - (d) if inclusion of a domestic producer would distort the injury findings, it must be excluded.
 - (e) if a domestic producer does not co-operate with the Authority, the Authority tends to consider such domestic producer as ineligible.
176. The Authority also notes that the text book written by M/s. Czako, Human and Miranda; inter alia, mentions the criteria applied by the other WTO members in such situations as follows:-
- (a) The percentage of domestic production of the product in question that is accounted for by the related producers.
 - (b) Whether imports of the product in question by the related producers allow them to benefit, or serve to shield them, from the effects of dumping.
 - (c) Whether exclusion of the related parties would unduly skew the data for the remaining members of the industry.
 - (d) The level or long term nature of the commitment shown by the producer to the domestic production, as opposed to importing activities.
 - (e) The ratio of import shipments to domestic production for the related producers.
177. The Authority considers that the purpose of the discretion to include or exclude certain domestic producers is to enable the Authority to come to an objective and undistorted determination with regard to the effects of dumped import on the domestic industry in India by excluding those domestic producers from the relevant domestic industry which have participated in injurious dumping. The Investigating authorities may exclude a related producer, where the related parties either:

- (a) provoked or contributed to a fall in prices on the market,
- (b) are shielded from their effects, or
- (c) where they benefited unduly from them.

178. With regard to the first category, i.e. the participation in dumping practices, the Authority considers that several typical situations may be distinguished. On the one hand, the exclusion is indeed appropriate where the injury of a domestic producer is self-inflicted because imports from dumped producers reduced the use of domestic producers' own capacity, or resulted in the abdication of domestic producers' projects designed to increase their own production. The Authority is of the view that exclusion of a domestic producer is *prima facie* not appropriate, if its participation in the dumping was an act of self-defence. Such a domestic producer should, therefore, be taken into account when defining the relevant domestic industry.
179. The Authority further considers that domestic producers that import the dumped product or whose related party exports the dumped product or whose related party imports the dumped product do not unduly benefit from dumping practices, if these exports /imports do not represent a significant part of their sales or market size. Indeed, no advantage would occur to such domestic producers in such an event because of the competition from other suppliers in the market. Another distinction drawn by the Investigating authorities of other countries while deciding whether a domestic producer should be excluded is: Is the domestic producer merely supplementing its domestic production with some dumped imports or whether it is primarily an importer with relatively limited production? If the focus has shifted from domestic production to imports, then such a company should be excluded from the scope of domestic industry. Thus an important element that needs to be considered on the subject is: whether or not the domestic producer in question is committed to production in the country of imports.
180. While disputing the claim of M/s Grasim Industries Ltd to treat it as the domestic industry, the opposing interested parties have contended that M/s Grasim Industries Ltd should be treated as ineligible for consideration as the domestic industry.
181. After careful examination of the submissions made by interested parties on the subject and considering the legal provisions and facts of the case, the Authority notes that facts on record do not justify exclusion of M/s Grasim Industries Ltd from it being considered as the domestic industry in the instant matter. The opposing parties have argued that the cases referred by the domestic industry are not relevant to the present situations. It is, however, noted that the cases relied upon by the domestic industry are not limited to those situations where the applicant company(s) had imported the product under consideration. The applicant has referred to some decisions wherein one of the domestic producers was related to exporter from subject or non-subject countries and it was found by the investigating authorities that inclusion of such domestic producers within the category of domestic industry was justified. The contention of the opposing parties that the domestic industry is ordinarily to be excluded is neither borne out from a plain reading of the law nor from the jurisprudence on the subject.

182. It is noted that the relevant provision defining the domestic industry grant discretion to the Authority to either include or exclude a related domestic producer from its consideration as a part of the domestic industry. The Authority further notes that in case the applicant is related to a producer in the exporting country, the mere fact of such relationship does not lead to automatic exclusion of such producer from the ambit and scope of the domestic industry. Indeed, discretion granted has to be judiciously exercised by the Authority in such cases, to examine further on case by case basis and consider whether such a related producer should be considered as eligible or ineligible to be considered as a part of the domestic industry. Axiomatically, the impact of relationship on the facts of the case needs to be appreciated for this purpose. Considering the facts available on record, the Authority has, *inter alia*, considered the followings:-
- (a) Whether the behaviour of the related parties is distinct and different as compared to unrelated parties;
 - (b) Whether there is some evidence to show that such related producer triggered or intensified dumping in the Indian market;
 - (c) Whether the related domestic producer has been shielded from the effects of dumping or has unduly benefited from it;
 - (d) Whether the related domestic producer has sought to stifle the competition in the Indian market;
 - (e) Whether there is a case of self-inflicted injury?
183. The Authority considers that apart from being a related party, it is also pertinent to evaluate the impact of the exports/imports, if any, made by the related party in a given case. Whether such related party had exported/imported the product to India during the period, if so, what is the impact thereof on the claims of injury? If not, whether there is any other ground still justifying its exclusion. In case the related party has also exported/imported the subject goods, then the following also need to be evaluated:
- The volume of exports/imports made by such related party;
 - The purpose of such exports/imports made by the related party;
 - Whether there is any evidence to show that injury to the domestic industry was attributable to such exports/imports by the related party;
 - Whether the general emphasis of the related domestic producer was on the production of the subject goods or whether the general emphasis gradually or steadily shifted to imports;
 - Whether the volume of exports/imports by such related parties were such that the related exporter is gradually or steadily substituting the unrelated domestic producers' market;
 - Any other factor which might have been brought to the notice of the Authority by the interested parties during the course of the investigation.
184. PT South Pacific Viscose has, *inter alia*, contended that they have been forced by PT Indo Bharat Rayon to resort to dumping, that is, they have resorted to unfair competition in the form of dumping because the other party was dumping. In this context, the Authority notes that reasons for dumping are entirely irrelevant under the

law and it is only the factum of dumping that is relevant. Only existence and degree of dumping is relevant in an anti-dumping proceeding and the reasons leading to such dumping are not material. Even if one or more foreign producers (from the same or different countries) have been forced to resort to dumping by one or more other foreign producers, the law does not condone the same. Notwithstanding this, The Authority noted that this allegation was found to be false, as PT South Pacific Viscose had exported the subject goods much earlier than the shipments exported by PT Indo Bharat Rayon. Besides, the volumes of exports made by PT South Pacific Viscose were significantly higher than the volume of exports made by PT Indo Bharat Rayon. PT South Pacific Viscose was found to be selling the product concerned even in its domestic market at a loss and therefore, the allegation that they resorted to dumping because the other party was dumping is not factually correct and thus devoid of any merit.

185. As regards the contention that the process of anti-dumping should not be abused by the "sole monopoly producer" in India; the Authority notes that 'dumping' is an unfair trade practice and must be condemned if it causes injury to an established domestic industry, even though there is only one domestic producer; as the intent of anti-dumping duty is only to redress the injury caused to the domestic industry on account of the unfair trade practice of dumping. Imposition of the duties shall not restrict the rights of foreign producers to sell the subject goods at un-dumped prices in the Indian market. Redressal concerning anti-competitive behaviour could always be sought by an entity impacted by such a behaviour by moving the appropriate institution set up to address the same.
186. The Authority also notes that neither the Indian law nor the WTO Anti-dumping Agreement provides that the Authority should hold a domestic producer as ineligible if it is related to foreign producer in case such related foreign producer participates in the investigation and positive dumping margin is established in respect of its exports. Further, an individual dumping margin is required to be determined in respect of each known exporter. The Act and the AD Rules do not make any distinction between a related and unrelated exporter in this respect. As regards deeming fiction under Rule 2(b), the same unambiguously vests discretion in the Authority in such a case. Such discretion, however, needs to be exercised in an un-biased and objective manner.
187. The Authority notes that the opposing interested parties have erred while contending that the criteria based on quantum of exports is not a rational criterion. As the issue at hand is "exports" made by a related exporter; the Authority considers that the quantum of imports is indeed an important factor to decide the exclusion of the related domestic producer; as it would, inter alia, be one of the factors in assessing whether the injury claimed is a self-inflicted injury or otherwise.
188. In the instant case, M/s Grasim Industries Ltd. has affiliated companies in Indonesia and China PR producing & selling the product concerned, namely M/s Birla Jingwai Fibres Company Limited, China PR and PT Indo Bharat Rayon, Indonesia. PT Indo Bharat Rayon – Indonesia have also filed their detailed response to the questionnaire sent, which has been verified by the Authority and has been dealt appropriately in the relevant sections of these findings. PT Indo Bharat Rayon is not a subsidiary of M/s Grasim Industries Ltd. It is noted that M/s Grasim Industries Ltd holds only *** % shareholding in PT Indo Bharat Rayon, Indonesia and ***% in M/s Birla Jingwai

Fibres Company Limited, China PR. M/s Grasim Industries Ltd. is the sole producer of the subject goods in India and has claimed injury on account of the dumped imports from the subject countries.

189. It is important to emphasize that despite having related parties in the subject countries, the Authority did not notice any difference in M/s Grasim Industries Ltd.'s behaviour, *vis a vis* a situation, were it not a related party. There has been evidence on record in respect of stifling the competition by M/s Grasim Industries Ltd. or taking any other undue advantage by seeking application of the anti-dumping duty in the instant matter.
190. Besides, the volume of exports made by PT Indo Bharat Rayon is quite small and sporadic in nature; these imports have been made by the unrelated importers under duty exemption category. M/s Grasim Industries Ltd has not imported the subject goods. The Authority notes in this regard that in a situation where majority of the exports are by other unrelated Indonesian exporter and where only three sales transactions (during the period of investigation) took place between PT Indo Bharat Rayon and Indian importer/consumer, that too for imports of the material under duty exemption scheme, it cannot be concluded that the parties colluded to force other competitors out of Indian market. The Authority further notes that there is no evidence whatsoever provided by opposing interested parties establishing that the two parties have colluded. Besides, no evidence is available on record to establish that the unrelated Indonesian producer has been forced to lower the prices due to alleged low prices quoted by PT Indo Bharat Rayon. The allegation by PT South Pacific Viscose, *inter alia*, that dumping was provoked and triggered by PT Indo Bharat Rayon – Indonesia was looked into during the verification of the two companies and was found to be unfounded and incorrect. This view is further buttressed by the analysis of imports of the subject goods from Indonesia, as seen in the following table.

	Imports in MT		Total Imports	Share of	Share of
	PT Indo Bharat Rayon Exports	PT South Pacific Viscose Exports	From Indonesia	PT Indo Bharat Rayon	PT South Pacific Viscose
2006	-	***	***	0.00%	100.00%
2007	***	***	***	5.51%	94.49%
2008 Jan- June	-	***	***	0.00%	100.00%
POI	***	***	***	2.29%	97.71%

191. The Authority has also examined the share of Indonesia in respect of imports of the product under consideration in India. The imports from Indonesia were only about 38% of total imports into India in 2006-07, but the same increased to 74% in 2007-08,

93% in April-June, 2008 and 84% during POI. Thus, it is evident that share of Indonesian imports steadily increased in gross imports of the subject goods in India. Besides, the share of PT South Pacific Viscose was very high in these imports from Indonesia as may be seen from the following table:

	Gross Imports in India	Imports from Indonesia	Share of Indonesia in gross imports	Export by PT South Pacific Viscose	Share of PT South Pacific Viscose in total imports
2006-07	6,774	2,554	37.70%	***	29.02%
2007-08	6,842	5,069	74.09%	***	71.67%
April-June08	1,890	1,757	92.95%	***	92.95%
POI	6,329	5,305	83.82%	***	81.90%

192. With regard to the WTO decision referred to by the interested parties, the Authority notes that the issue in that case is not relevant to the present case. The issue in that case was whether the transactions between the affiliated parties could be considered as transactions in the ordinary course of trade for the purpose of determination of normal value. Thus, while the issue in that case arose in the context of normal value and transactions between related parties; the issue under consideration in the present case is whether M/s Grasim Industries Ltd. should be held as ineligible as a domestic industry within the meaning of Rule 2(b) in view of its relationship with its affiliates in the subject countries. It is also relevant to note that even in the context of determination of normal value; all transactions between the related parties may not be treated as reliable or unreliable and thus is to be examined on the merits of each case. Whereas in the instant case, the transactions are not even between such related parties but are between PT Indo Bharat Rayon and unrelated Indian consumers.

193. It has also been argued by opposing interested parties that the domestic industry and PT Indo Bharat Rayon's objective was to block fair competition in the Indian market. However, given the positive dumping margin that has been established in the instant case, it is evident that the unrelated Indonesian producer resorted to dumping due to its own commercial interests and this dumping has been found to be unprovoked and not due to the three small shipments made by PT Indo Bharat Rayon and significant volume of the subject goods have been exported by PT South Pacific Viscose at dumped prices. The Authority on investigation has come to the conclusion that dumped imports of the subject goods from the subject countries have caused 'injury' to the domestic industry. The Authority further notes that small and sporadic exports by PT Indo Bharat Rayon have not been a significant factor in such injury. Besides, the focus of M/s Grasim Industries Ltd continues to be production and sale of the subject goods. Thus, there does not appear to be case of self-inflicted injury. The Authority has also taken note of anti-dumping cases, wherein even though the imports were effected by the related domestic producer from its affiliate, then too they have been considered by the investigating authorities as a part of the domestic industry.

Thus, the Authority does not find any justifiable reason to exclude M/s Grasim Industries Ltd from the ambit and scope of the domestic industry.

194. The Authority therefore, reiterates that the M/s Grasim Industries Ltd is not required to be excluded from the scope of the domestic industry under Rule 2(b) of the AD Rules. Thus, the application has been filed by Association of Man Made Fibre Industry of India on behalf of the domestic industry. M/s Grasim Industries Ltd. is the sole producer of the Like Article in India and has provided injury and costing information. The claim of the applicant that there is no other producer of the Like Article in India has not been disputed by any interested party. As per the evidence available on record, the production of M/s Grasim Industries Ltd. accounts for a major proportion of the domestic production of the subject goods, as M/s Grasim Industries Ltd. is the sole producer of the subject goods in India.
195. Thus, the Authority reiterates its view that it is appropriate to consider M/s Grasim Industries Ltd. as the domestic industry under Rule 2(b) of the AD Rules. Accordingly, the Authority has determined that the application satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.
196. As regards the issue that the petitioner has intentionally omitted the vital question from the prescribed sets of questions just to avoid the nature of relationship with Indonesia.

Period of investigation

197. As regards the six-months period of investigation adopted in the instant matter, the Authority has noted the submissions made by the interested parties. The Authority notes that there is no prescription either in the AD Rules or in the WTO's Anti-dumping Agreement regarding the precise period of POI. The investigation authorities have adopted the POI ranging from a six months period to 18 months period. As regards the recommendations of the CADP, the Authority notes that these are only recommendations and even these recommendations acknowledge that the POI could be of lesser duration than a 12 months period. Adoption of six-months POI has also been upheld by the Hon'ble CESTAT in the matter of Virchow laboratories ltd. v/s Ministry of Finance.
198. The Authority has already recorded that POI in the instant matter was appropriately chosen considering the facts of the case, which also covers the most recent available data on the subject. Besides, the opposing interested parties also concede that fixation of six-months period as the period of investigation is not illegal. The Authority notes that it is incorrect to state that it is the DGAD's practice to take 12 months period as the POI; in fact the Authority has adopted six-months period to eighteen months period as the POI.
199. The Authority notes that it has adopted six-months period as POI in a number of cases. As stated, even the interested parties agree that consideration of 6 months as the investigation period is not illegal. CADP guidelines cannot be read as mandatory prescription. In any case, these guidelines cannot apply in all situations, irrespective of the facts of a case. Factors, such as, financial reporting cannot be considered alone;

as it would imply consideration of only one period as the period of investigation viz. April-March. As regards the argument that 6 months period of investigation covers 4 months of the recessionary period; the Authority notes that the fact of recession cannot be selectively pleaded in support of export price below normal values; as the fact of recession would equally apply to normal value as well. It is, however, noted that the domestic prices of the subject goods in Indonesia were materially higher than the export price to India. Thus, recession in the global market cannot be stated as a justified reason to be considered in fixing the period of investigation.

200. As regards the fall in demand, the Authority notes that the drop in demand should have equally impacted the domestic industry and the imports. But in the instant matter, while the demand of the subject goods has fallen but the volume of imports from the subject countries has increased. The Authority considers that 6 months period of investigation was justified in view of significant drop in import prices and significant deterioration in financial situation of the domestic industry.
201. The Authority notes that product under consideration in the present investigation is Viscose staple fibre – except bamboo fibre. The Customs' classification for the product under consideration does not exclude bamboo fibre. Therefore, summary information published by the Applicant cannot be relied upon as it may include imports of product other than product under consideration. The domestic industry has furnished information as provided by TIPS, which was accepted at the time of initiating the investigation.
202. The domestic industry has alleged that significant import volumes have been reported under Customs Sub-heading No. 5504 9090. The Authority requested the O/o DGCI&S for import information for Custom classification Nos. 55041000 and 55049090, which has been received and analysed. Accordingly, the imports volumes of the subject goods have been determined. A comparison of imports claimed by the Applicant as per TIPS data and as per DGCI&S data shows the following:

	TIPS data		DGCI&S data	
	Qty Kg	Rs./Kg	Qty Kg	Rs./Kg
China PR	907252	96.03	1023971	94.13
Indonesia	4533741	98.44	4689364	98.47

203. From the material available on record, it is seen that there are no imports of the subject goods from any other country except from the subject countries during the POI. Further, the volume and price as per DGCI&S and TIPS are broadly comparable.
204. As regards the determination of Normal value in respect of China PR, the Authority notes that consequent upon the initiation notice issued by the Authority; none of the Chinese producers/exporters submitted any response including the market economy questionnaire response and thus failed to rebut the non-market economy presumption. In the initiation notification itself, the Authority had indicated that the Applicant has suggested Indonesia as appropriate surrogate country. Interested parties were requested to make submissions in this regard. However, none of the exporter/producer

from China PR responded and made any submissions in response thereto. Thus, the Authority examined whether Indonesia could be considered as a surrogate market economy for the purpose of determination of Normal value for China PR. For this purpose, the Authority took into cognizance the level of development of Indonesia and that of the subject goods in question. It was, *inter alia*, noted that there were two major producers of the subject goods in Indonesia and incidentally both had co-operated in this investigation. It was also noted that significant domestic sales were made by these producers in the domestic market of Indonesia. Thus, the Authority considered it appropriate to consider Indonesia as an appropriate surrogate country in the instant matter. Thus, considering Indonesia as an appropriate surrogate country for China PR, the Authority confirms that it rightly adopted the weighted average Normal value of Indonesia so determined for China PR, in terms of the relevant provisions of the AD Rules.

205. The Authority has taken note of submissions made by various interested parties; including the domestic industry's contention that since no benefit has been obtained by them under the foreign trade policy for the so-called "deemed exports", such sales should be treated as domestic sales. These were cross checked during the spot verification by the team and seen that these sales were in fact domestic sales.
206. Annexure II of AD Rules provides for objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in domestic market, for the like article; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products. While examining the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to price effect of dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increase, which would have otherwise occurred to a significant degree.
207. As regards the impact of dumped imports on the domestic industry, para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows:
- "The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."*
208. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and submissions of the interested parties. Since there are more than one country involved in the present investigation, the Authority has examined whether the conditions for cumulative assessment are satisfied. The Authority observes that:
- i. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the

de-minimis limits prescribed;

ii. The volume of imports from each of the subject countries is more than the *de-minimis* limits prescribed;

iii. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete with the like article offered by the domestic industry in the Indian market. This is, *inter alia*, evident from the fact that the domestic product and imported product are like Article; imports from each of the subject countries are significant; goods produced by the Indian Producers and imported from the subject countries are in direct competition; common parties are resorting to use of imported material and domestic material; Indian users/customers are using domestic material and imported material interchangeably; the exporters from the subject countries and the domestic industry have sold the subject goods in the same periods to the same set of customers,

In view of the above, the Authority considers it would be appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from the dumped imports of the subject goods from the subject countries.

Demand and market share:-

209. Demand of the product in the Country has been assessed as the sum of the domestic sales of the domestic producers and imports from all sources.

	2005-06	2006-07	2007-08	April-June 08	July-Dec 08 (POI)	April-June 08	POI Annualized
In MT							
Sales of	223,147	226,178	237,395	49,784	100,925	199,136	201,850
Indexed	100	101	106	89	90	8	90
Imports in	198	6,774	6,842	1,890	6,329	7,561	12,658
Indexed	100	3,421	3,456	3,818	6,392	3,818	6,392
Demand	223,345	232,952	244,237	51,674	107,254	206,697	214,508
Indexed	100	104	109	93	96	9	96
Market Share in Demand							
Subject	0.06%	1.34%	2.78%	3.66%	5.90%	3.66%	5.90%
Other Countries	0.03%	1.57%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Domestic	99.91%	97.09%	97.20%	96.34%	94.10%	96.34%	94.10%

- It is noted that the demand for the product under consideration was increasing till 2007- 08. The same has however declined (on prorata basis) during April-June 08 period and the period of investigation.
- It is also noted that although demand for the product under consideration has shown decline during the POI as against same year; import volumes have increased significantly (on prorata basis).
- It has been argued by opposing parties that there is a decline in demand of product in India and therefore, injury to the domestic industry, if any, is not

from the alleged imports. The Authority, however, notes that impact of decline in demand should have resulted into decline in imports as well on proportionate basis, but it is seen that the imports of the subject goods at dumped prices have increased.

- iv. The market share of dumped imports from subject countries is significantly higher during the POI as against the base year.

Import volumes and market share

210. The imports of the subject goods and the market share are given in the following table:

	2005-06	2006-07	2007-08	April- June 08	July- Dec 08 (POI)	April- June 08	In MT POI Annualized
Imports from the Subject Countries	125	3,121	6,779	1,890	6,329	7,561	12,658
Imports from Other Countries	73	3,653	62	-	-	-	-
Total Imports	198	6,774	6,841	1,890	6,329	7,561	12,658
Dumped Imports in relation to -							
- Indian Production	0.05%	1.26%	2.44%	3.27%	10.05%	3.27%	10.05%
- Indian Consumption	0.06%	1.34%	2.78%	3.66%	5.90%	3.66%	5.90%
Market Share of Domestic Industry	99.91%	97.09%	97.20%	96.34%	94.10%	96.34%	94.10%

It is observed that:

- The imports have shown a significant increase in absolute terms during the POI (Annualised on prorata basis).
- The imports have increased in relation to production and consumption in India.
- While the market shares of the subject countries have increased but that of the domestic industry has declined.
- With regard to the argument that the decline in market share is insignificant, particularly in view of macro-economic problems, the Authority holds that there is no legal prescription with regard to the extent to which indices would show deterioration to conclude that the domestic industry has or has not suffered injury. As per the legal provisions, while there is no de-minimis criterion on the basis of market share in demand either in the AD Rules or the

WTO's AD Agreement, some authorities do consider 1% market share of imports as significant. If 1% of market share of import from a particular country in consumption can be considered as "significant", the decline in market share by Nearly 6% cannot be considered as insignificant

- v. With regard to macro-economic problems (the interested parties are apparently referring to the global meltdown), however, the Authority notes that existence of such factors do not justify dumping and stop redressal of consequent injury to the domestic industry. In a situation where domestic demand for the product has fallen, increase in imports only aggravates the injury.

Price effect of imports

211. It is seen from the following table that there is marginal negative price-undercutting.

Rs/Kg.	China PR	Indonesia
CIF Import Price	94.13	95.39
Landed Price	99.03	100.35
Net Selling price of Domestic Industry	98.72	98.72
Price Undercutting	(0.31)	(0.31)
Price Undercutting % range	-1% to 1%	-2% to 2%

212. However, the Domestic industry has claimed that it fixes the prices periodically based on the prevailing international prices. If the import price decline, the domestic industry may also be forced to reduce its selling prices. If the import price increases, but not to the full extent of increase in the cost of production, the domestic industry may be prevented from increasing its price commensurate with the increase in cost of production. Absence of positive undercutting does not mean lack of injury.

213. The Authority notes that the price effect of the dumped imports has been adverse as regards the domestic industry. The Authority has further made comparison of the cost of production and the selling price of the domestic industry along with the landed price of imports, which is given in the following table:

Rs /Kg.	2005-06	2006-07	2007-08	April-June 08	July-Dec 08 (POI)
Cost of Production	60.54	64.28	71.09	90.99	88.677
Indexed	100	106	117	150	146
Selling Price	72.94	84.89	102.62	108.60	98.72
Indexed	100	116	141	149	135
Landed Price China PR	138.02	86.59	112.66	110.79	99.03
Indexed	100	63	82	80	72
Landed Price Indonesia	77.28	87.58	99.47	107.78	100.35
Indexed	100	113	129	139	130

Average Landed Price from the subject countries	77.77	87.40	102.80	108.07	100.14
Indexed	100.00	112.39	132.19	138.97	128.77

214. It is seen that while selling price of the domestic industry increased from 100 in base year to 135 during the POI. However, its cost of production increased from 100 in the base year to 146 during the POI. Apparently, the domestic industry could not increase its selling price in line with the increase in its cost of production; thereby indicating that the dumped imports are significantly suppressing the prices of the domestic industry.
215. The Authority has also examined price underselling of the domestic industry and notes that the landed value from subject countries is significantly below the non-injurious price of domestic industry as may be seen from the following table.

In Rs./Kg.	NIP (Grey fibre)	Landed price	Price Underselling	Price Underselling
China PR	107.97	99.03	8.94	5 to 15
Indonesia	107.97	100.35	7.62	5 to 15
Subject Countries	107.97	100.14	7.83	5 to 15

Apparently the domestic industry is forced to sell the subject goods below the non-injurious price due to the presence of dumped imports.

Economic Parameters of the Domestic Industry

216. Annexure II to the AD Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below:

Sales volumes

217. The sales volumes of domestic industry are given in the following table:

In MT	2005-06	2006-07	2007-08	April-June	July-Dec 08 (POI)	April-June 08	POI - Annualize
-------	---------	---------	---------	------------	-------------------	---------------	-----------------

Sales volume	223,147	226,178	237,395	49,784	100,925	199,136	201,850
Trend indexed	100	101	106	89	90	89	90

218. It is noted that sales of domestic industry had increased up to 2007-08 and then declined during April-June 08 period and the POI. Though, decline in demand would have resulted in decline in sales but the imports have not declined proportionately, but have actually increased.

219. With regard to the argument that sales volumes have declined due to consumers restricting purchases and sharp fall in exports of textile products, the Authority notes that situation where (a) consumers are restricting purchases from domestic source, but increasing purchases through imports; and (b) domestic prices decline due to import prices in fact establishes that injury to the domestic industry is due to dumped imports.

Production, Capacity and Capacity utilization

220. Information relating to production, capacity and capacity utilization is given in the following table:

In MT	2005-06	2006-07	2007-08	April-June 08	July-Dec 08 (POI)	April-June 08 Annualized	POI Annualized
Capacity	253,450	266,450	266,450	82,355	166,520	329,420	333,040
Indexed	100	105	105	130	131	130	131
Production	228,981	246,832	277,818	57,829	114,314	231,317	228,628
Indexed	100	108	121	101	100	101	100
Capacity Utilization	90.35%	92.64%	104.27%	70.22%	68.65%	70.22%	68.65%
Indexed	100	103	115	78	76	78	76

221. It is seen that production and capacity utilization of the domestic industry was improving till 2007-08, which declined during the April-June 08 period and the POI. It has been alleged by some interested parties that domestic industry had increased its capacity in March 2008 and a new capacity cannot perform at same level of old capacity. The Authority has examined performance of domestic industry on same capacity level, which was there before expansion and notes that even with the same capacity levels, the capacity utilization has declined from 104.27 % in 2007-08 to 85.8% in the POI.

Profit/Loss, return on investment and cash profits

222. Information relating to profit/loss, return on investment and cash profits is given in the following table:

	2005-06	2006-07	2007-08	April-June	July-Dec 08 (POI)	April-June 08 Annualized	POI Annualized
PBT Rs. Lacs	27,670	46,615	7485	8767	10143	35068	20286

Indexed	100	168	27	127	73	127	73
PBT Rs. KG	12	21	32	18	10	18	10
Indexed	100	166	25	142	81	142	81
PBIT Rs. Lacs	30,990	50474	7968	1068	149272	42756	298555
Indexed	100	163	25	138	96	138	9
PBIT Rs. Kg	14	22	34	21	15	21	15
Indexed	100	161	24	155	107	155	10
Cash Profit Rs. Lacs	31083	50703	7926	10169	130555	40676	2610909
Indexed	100	163	25	131	84	131	8
Cash Profit Rs. Kg	14	22	33	20	13	20	13
Indexed	100	161	24	147	93	147	93
ROI - GFA Basis	23.55%	34.97%	43.54	23.4	14.69%	23.46	14.69
Indexed	100	149	18	100	62	100	6
ROI - NFA Basis	37.44%	55.64%	63.90	32.4	21.16%	32.42	21.16
Indexed	100	149	17	8	57	87	57

223. The Authority notes that the profitability was improving till 2007-08, which declined thereafter significantly. The return on investment and the cash profits have followed the same trend as that of profitability. It is noted that though during the POI, the average return on investment was positive, however, it declined significantly over the injury period. The Authority further examined profits and ROI situation of the domestic industry on quarterly basis within the POI. It is further noted that performance of the domestic industry declined significantly in the 2nd quarter of POI, as may be seen from the following table:

	Jul-Sept 08	Oct-Dec 08	July-Dec 08 (POI)
ROI - GFA Basis	20.04%	9.19%	14.69%
Indexed	100	46	73
ROI - NFA Basis	28.21%	13.13%	21.16%
Indexed	100	47	75

Inventories:

224. Inventory levels of the domestic industry have been as under:

In MT	2005-06	2006-07	2007-08	April-June 08	July-Dec 08 (POI)
Inventory	13,654	5236	8233	13587	13539
Inventory – equal to no. of days sales	20	7	11	21	20

It is noted that inventory of the domestic industry declined in 2006-07, which again increased in 2007-08. The inventory further increased during April-June 08 period and the POI as compared to the 2007-08 period.

Employment, wages and productivity

225. Information relating to employment, wages and productivity of the domestic industry has been as under:

	2005-06	2006-07	2007-08	April-June 08	July-Dec 08 (POI)	July-Dec 08 (POI Annualized)
Employment	4813	4683	4640	4552	4563	4563
Indexed	100	97	96	93	95	95
Wages Rs. Lacs	5037	5893	6292	1719	3088	6176
Indexed	100	117	125	137	123	123
Productivity per day	654	705	794	661	653	653
Indexed	100	108	121	101	100	100
Productivity per Employee	48	53	60	51	50	50
Indexed	100	111	126	107	105	105

It is noted that employment level of the domestic industry declined over the injury period.

226. The Authority, however, notes that this decline is not only seen in the POI, but was there even before the POI. The wages of the domestic industry shows normal increase. As regards productivity per employee, it increased till 2007-08 and showed a decline during April-June 08 period and the POI.

Dumping Margin:

227. It is observed that dumping margin in respect of the exports from the subject countries is positive and more than the de-minimis limits prescribed.

Growth

228. The Authority notes that the growth of the domestic industry is negative in terms of volume parameters such as sales (declined by 9.54% from the base year and 16% from 2007-08), production (0.15% from the base year and 21.48% from 2007-08) and capacity utilization (declined by about 24% from the base year and 39.42 % from 2007-08). The growth in price parameters is also seen as negative. Profits before tax (declined by 26.69% from the base year and 197 % from 2007-08) of the domestic industry and the

12934712-35

ROI (declined by 43.49 % from the base year and 114.13 % from 2007-08) too deteriorated significantly during the POI.

Threat of material injury

229. The Authority has taken note of the submissions made by the domestic industry regarding availability of surplus capacities of the subject goods in the subject countries. From the information available on record, it is seen that there is a significant increase in the capacities in the subject countries, whereas the capacity utilization has gone down significantly, indicating the surplus capacities of the subject goods in the subject countries. The Authority notes that the rate of increase of dumped imports over the injury period has been significant, indicating the likelihood of substantially increased importation. The data of the co-operating exporters from Indonesia shows significant increase in their inventory levels. There is a significant price underselling and significant price suppression indicating the threat of material injury to the domestic industry. This view is further buttressed if the landed value of the subject goods from the subject countries during the quarter immediately following the POI is seen. It is noted that the landed value has further fallen by 7.81 % as may be seen from the following table in case of imports from Indonesia. As regards imports from China PR during the period, it is seen that the landed value has fallen by 18.03 %. Cumulatively, the landed value of the subject goods from the subject countries has fallen by 7.97% during the period.

Rs./Kg.	Jul-Dec08 (POI)	Jan-Mar09 (Post POI quarter)
Landed Value –China PR	99.03	81.17
Landed Value -Indonesia	100.35	92.51
Average Landed Value from the subject countries	100.02	92.05

Causal Link

Views of the Domestic Industry

230. The Authority has already examined all other known factors. Regarding injury due to decline in demand, the same has been examined by the Authority in the preliminary finding. As regards global downturn, it has not been demonstrated that profitability should indeed decline, because of global downturn. As regards increase in input cost, the same is specially covered under the Rules.
231. As regards weakening of INR, the same should have benefitted the domestic industry rather than going against the domestic industry. While the applicant depends upon the imported wood pulp only and would have got adversely impacted on this account only because of this, landed price of imported pulp have substantially increased.
232. As regards capacity expansion, the same are results of earlier decisions. In any case, the domestic industry cannot be expected to terminate its expansion plans only because of dumping.

Views of other interested parties

233. The Authority should have examined other factors, which might have caused injury to the domestic industry.
234. In its annual report, the domestic industry have stated that deterioration in production and sales and profits is due to (1) lower demand, (2) global turndown, (3) steep rise in input cost and weakening of INR. Thus injury due to alleged dumping is a false allegations and conjunctures.
235. The price reductions have nothing to do with the alleged dumping. (Reference has been made to the Annual report of 2007-08 in this regard)
236. Lower profitability is due to increase in input costs, lower volumes and weak margins. Interest and depreciation cost appears to be very high. (reference has been made to the Annual report of 2007-08, corporate presentation, Q2FY09 presentation, Q3FY09 presentation).
237. Despite restrained outlook, the domestic industry expended its capacity.
238. Decline in sales is due to (1) consumer resisting purchases, (2) decline in textile exports led to decline in demand, (3) Global slowdown with inflationary pressure, (4) liquidation of inventory in value chain.
239. Capacity expended, hence no injury on account of ability of increase capacity/expansion. (reference has been made to the Annual report of 2007-08).
240. As per Q3 report, the production was curtailed due to lower demand. Different statements have been made by the domestic industry before different forums.
241. In Dept 09-H1 performance, the production increased by 15% inspite of NAGDA plant was shut for 48 days due to water shortage, 19% growth in sales, new divisional revenue increased by 17% and PBIDT increased by 35%.
242. The domestic industry is planning to invest in a project of 80000 MT in Vilayat in Gujarat.

Examination by the Authority

243. The Authority has examined whether other parameters could have contributed to the injury caused to the domestic industry. Following parameters were analyzed in this regard:
- a) Imports from Third Countries: - The Authority has collected the transaction-wise imports data of the subject goods from DGCI&S. From the information available on record, the Authority notes that there are no imports of the subject goods from any other country during the POI.
 - b) Contraction in Demand:- The Authority notes that the demand for the subject goods has shown significant improvement till 2007-08, and then shows

decline during the POI. However, as compared to the demand, the imports have increased significantly, which ordinarily should have declined with the decline in demand. It is noted that within the available demand, the domestic industry has lost its market share. Apparently, the domestic industry was already facing the problem of declining demand, but the same was compounded by the dumped imports.

c) Pattern of consumption:- No significant change in the pattern of consumption has been noticed. Apparently, the product supplied by the domestic industry is directly competing with that of imported material from the subject countries.

d) Conditions of competition:- As per facts available on record, there is no evidence that conditions of competition or trade restrictive practices have caused injury to the domestic industry.

e) Developments in technology:- As per facts available on record, there appears to be no change in technology over the injury period which could have caused injury to the domestic industry.

f) Export performance of the domestic industry: - The performance of the domestic industry has been segregated for domestic sales and exports sales; and only domestic performance of the domestic industry has been considered while assessing the injury to the domestic industry.

244. The Authority notes that the performance of the domestic industry over the injury period has deteriorated due to dumped imports from the subject countries. This is established by the following:
245. The imports from the subject countries have significantly increased over the injury period. It is noted that while the market share of the domestic industry has declined, that of the imports from the subject countries have increased.
246. There is price suppression as the domestic industry has not been able to increase its prices in proportion to the increase in the cost of production. The significant price-suppression caused by the dumped imports has adversely impacted the domestic industry, resulting in significant decline in profits and cash flow.
247. A comparison of the landed value of the subject goods with the NIP of the domestic industry shows that there is a case of price underselling as well.
248. Some interested parties have contended that production, sales and profitability had deteriorated due to lower demand, prevailing global down trend, steep rise in input costs and weakening of Indian Rupee; the Authority notes that these public statements in the Annual Report does not alter the conclusion that dumping of the product has contributed to injury to the domestic industry. Firstly, it has been wrongly assumed by the interested parties that dumping of the product should be the sole cause of injury to the domestic industry. Though production and sale undisputedly suffered due to decline in demand but dumping of the subject goods also caused material injury to the domestic industry. With regard to profitability, as the domestic industry fixes its prices on the basis of import prices; therefore, availability of dumped imports at lower prices in the market apparently

have forced the domestic industry to offer such prices that did not permit recovery of increase in the input costs.

249. As regards the issue relating to steep increase in input costs, the Authority notes that if the domestic industry is not able to increase its prices in tandem with the increase in costs of production, then it would be a clear case of price suppression, which is an important injury indicator. As regards weakening of Indian Rupee, the Authority notes that the same should have reduced injury from imports, as the weakening of Indian Rupee should have had an impact of making imports less attractive.

Magnitude of Injury and Injury margin:-

In Rs/Kg.	Indonesia			China PR
	PT Indo	PT South Pacific	Others	
	Bharat Rayon	Viscose		
NIP	107.97	107.97	107.97	107.97
Landed Value	97.30	100.42	77.94	99.03
Injury Margin	10.67	7.55	30.03	8.94
Injury margin%	9.88%	6.99%	27.81%	8.28%
Injury margin Range (%)	5-15	5-15	25-35	5-15

Submissions made by interested parties on the Disclosure Statement

250. The following submissions, in brief, have been made by on behalf of M/s PT South Pacific Viscose, Indonesia; M/s Indian Spinners Association and M/s Rajasthan Textiles Mills Association.
- Preliminary Objection: it has been contended that the present proceedings are being conducted in pursuance to remand directions dated 13.08.2011 issued by Appellate Tribunal. The Appellate Tribunal specifically directed that the process of carrying out any modification to the Customs Notification shall be completed within 6 months from the date of the order of the Appellate Tribunal. The said 6 months period lapsed on 12.02.2012. After lapse of said period, they have not been served with any order of the Appellate Tribunal by which the time period of 6 months for carrying out the modification if any, has been extended and that the Designated Authority cannot seek extension of time from the Appellate Tribunal as Designated Authority has not accepted the said order and has filed several Appeals before the Hon'ble Supreme Court in several other cases.
 - As the proceedings have not been completed within the time period of 6 months fixed by the Appellate Tribunal, no further steps can be taken in furtherance to remand direction in subject proceedings.

- Non-Compliance of Trade Notice No. 1/2007: It has been concluded in the para 164 of the disclosure statement that trade notice are only issued to facilitate the examination of issues raised and therefore it is not necessary for interested parties to follow the guidelines suggested therein.
- Common Directors: It is submitted that from the disclosure statement for the first time we came to know that Grasim Ind. Ltd., Birla Jingwai Fibers Company Ltd. China and PT Indo Bharat Rayon, Indonesia have common directors. By not disclosing relevant facts at appropriate stage of the investigations the Designated Authority has violated principles of natural justice.
- Standing of the Petitioner: The Authority has relied greatly on the December 2011 amendment vide Notification No. 86/2011-Customs (NT) which results in deletion of the word “only” from the definition of ‘domestic industry’ under Rule 2(b) of the AD Rules, 1995. It does not result in shifting of the discretion from the ‘rest of the producers’ to the ‘excluded category of producers’. It is therefore submitted that the December 2011 amendment has no bearing on the issue in controversy and that no reference needs to be made to the same. In any case the Designated Authority is legally bound to take law that was holding the field during the 18 month period prescribed under Rule 17 and not thereafter. Reference in this regard has been made to the views of the Ministry of Finance in Soda Ash case before Madras High Court on the interpretation of Rule 2(b). In view of the above, it has been contended that removal of word “only” has no bearing on the case and petitioner cannot be said to qualify for the domestic industry in terms of Rule 2(b). The petitioner has only provided some extracts of the decisions and most of them are not relevant to the case and some of them even contradict the claim of the petitioner. In para 186, the Authority concludes that there is no distinction available in the AD Rules between related and unrelated exporter. In this context, it has been contended that related party can plan its exports as initiation of anti-dumping investigation brings no surprise element for the related party. Therefore, to treat both the related and unrelated exporters on same level is incorrect. It has been contended that without examination of data and information and verification of the Chinese entity, there is no material based on which it can be concluded that there were no exports by Chinese entity directly or indirectly.
- Documents in Public File: Despite our request copies of documents in public file were never provided. Therefore, to mention that the Authority has kept public file in terms of AD Rule is not sufficient.
- Quantity of Exports: Even sales offers can disrupt the market and are enough to disturb the prevailing prices in the market. PT Indo Bharat Rayon has exported small quantities and this small and sporadic export kept PT South Pacific Viscose at price check. Therefore, we request the Authority to kindly evaluate the purpose of exports and not the volume and number of shipments made by the related exporter. In this connection, we also like to submit that even in small exports PT Indo Bharat Rayon is liable for positive dumping margin. This factor is standalone enough to disentitle the applicant to be treated as domestic industry.

- **Short Period of Investigation:** We have never argued that the Authority cannot take 6 months as period of Investigation. In this connection we have only pointed out that 5% dumping margin cannot be said as intensified dumping which is the sole ground for taking POI as 6 months. Thus, it is not an appropriate criterion either in law or on facts. The applicant has attempted to link the issue of intensified dumping to the cost of production which is incomprehensible. Our argument that the low dumping margin determined by the Authority cannot lead to a conclusion that there was intensified dumping (which is the only justification for a shorter POI), remains unanswered by the Authority. In view of the above, there is no apparent reason on record for proceeding with the present POI.
- **Injury:** Deemed exports cannot be considered as domestic sales as the petitioner is availing the benefits which are available only because of export sales and simultaneously want to get benefited by adding these sales in normal domestic sales. Profit of the petitioner had only declined in 2008-09 that is only because of the economic turmoil worldwide. Accept that period petitioner is doing exceptionally well. Referring to the financial performance of 10 years, it has been contended that in 2008-09 petitioner profit declined by 16% as compared to previous year, whereas in next year i.e. in 2009-10 the profit increased by 41% in comparison to 2008-09 and 19% as compared to 2007-08. This fact clearly establishes that the injury, if any, to the Domestic Industry is certainly on account of global slowdown.

Submissions made on behalf of the domestic industry

251. The domestic industry, in brief, has contended that:

- The rules do not specify that the Authority shall “provide” evidence presented by one interested party to other interested parties. The Rules provide that the Authority shall “make available” evidence provided. This is done by the Authority through public file. It simply “make such files available” for “inspection and taking notes”. In fact, this is the requirement under the law. The law does not specify that copies of such documents shall be provided by the Designated Authority to interested parties. This cannot therefore be raised as a matter of legal right.
- Submissions may not be taken on record as the written submissions filed by applicants are without paragraph numbers: the argument is beyond the law and therefore must be rejected. Even electronic medium cannot be forced by the Designated Authority, leave aside things like paragraph numbering.
- On ‘Standing’ issue, the Saint Gobin decision has been stayed by the division bench of the Hon’ble High Court and therefore same cannot be quoted for the purpose of the present investigation.
- It has been contended that the rule prevailing at the stage of initiation and now when the findings are to be recorded shall apply. Without prejudice, 2010 amendment also grants discretion to the Authority.

- As regards relationship, all relevant information is on the record of the Authority. It was clearly stated that it has production set ups in the subject countries. Since petitioner itself had agreed that these entities are related, the basis on which these companies are related becomes irrelevant. Information establishing relationship is relevant only in those situations where a party disputes existence of such relationship.
- All the cases cited are relevant in order to determine whether the Authority has discretion.
- On shorter POI, it has contended that the intensified dumping was within the investigation period. If the data for the investigation period is considered on month by month basis, the same shall clearly establish intensified dumping. Information of imports in Jan.-March, 09 period shows that there was further significant decline in prices from subject countries. In fact, these are the orders booked at the end of POI and must therefore have been included in the questionnaire responses of the responding exporters.
- On injury and causal link, it has been contended that while there is decline in demand, the same is not the sole or principal cause of injury to the domestic industry. Firstly, decline in demand should have equally impacted the domestic industry and Foreign Producers. However, whereas the Foreign Producers gained significant market share, the domestic industry lost the same. Secondly, the Foreign Producers have reduced the prices too significantly. Resultantly, the domestic industry was forced to undertake too significant price cuts. Deterioration in the performance of the domestic industry in respect of price parameters is due to dumped imports.
- Applicant cannot be allowed to change its position and facts which were the very basis of the initiation, Preliminary Findings as well as the Final Findings in remand proceedings. Moreover, if the parties are not related, then it is all the more curious that the same lawyer is representing two unrelated but conflicting parties in the same proceedings. - One lawyer has several times represented more than one related party. Does this mean that all those foreign producers were related? For instance, the same lawyer represented foreign producers from different countries, have no relationship at all. Does this common lawyer representing them make them related? The same lawyer in the present case is representing foreign producer and Indian consumer association. Does this make these foreign producer and Indian consumer association related?
- On Injury and Causal Link: the domestic industry has reiterated its submissions. The injury to the domestic industry is established as the imports from the subject countries have significantly increased over the injury period. While the market share of the domestic industry has declined, those of the imports from the subject countries have increased. There is price suppression as the domestic industry has not been able to increase its prices in proportion to the increase in the cost of production. The significant price-suppression caused by the dumped imports has adversely impacted the domestic industry, resulting in significant decline in profits and cash flow. A

comparison of the landed value of the subject goods with the NIP of the domestic industry shows that there is a case of price underselling as well.

- It has been contended that the anti dumping duty may be imposed only as fixed quantum of anti dumping duty and on dollar basis.

Examination by the Authority

252. The submissions made by the interested parties that were considered pertinent to this investigation, have been examined as follows:

- As regards the preliminary objection; the Authority notes that it has taken appropriate steps seeking extension of time from the Appellate Tribunal. Besides, the Authority does not concur with the view that as it has filed Appeals before the Hon'ble Supreme Court; no further steps can be taken in furtherance to remand direction in subject proceedings.
- As regards non-compliance of Trade Notice No. 1/2007; the Authority reiterates its view that the said trade notice was issued to facilitate examination of the issues raised by the parties and therefore the interested parties should have ordinarily followed the guidelines suggested therein.
- As regards Common Directors; the Authority notes that information/data filed by the interested parties was kept in a public file, which was accessible to all the interested parties participating in the investigation in terms of the AD Rules.
- As regards 'Standing of the Petitioner'; the Authority notes that it has examined the issue at length, and reiterates that it has a discretion to exclude or include a domestic producer to qualify for the domestic industry in terms of Rule 2(b) and reiterates its findings on the issue.
- As regards the documents in Public File; the Authority notes that information/data filed by the interested parties was kept in a public file, which was accessible to all the interested parties participating in the investigation in terms of the AD Rules.
- As regards the quantity of exports by M/s PT Indo Bharat Rayon; the Authority notes that it has examined the issue and reiterates its findings on the subject based on the facts available on record.
- As regards the Period of Investigation; the Authority reiterates its findings on the subject. Further, the issue of intensified dumping needs also to be seen *vis a vis* the volume of the subject goods sold at dumped prices.
- As regards the injury; the Authority notes all pertinent issues have already been appropriately addressed in the Final findings dated 17th May 2010 and therefore the same is confirmed.

- As regards the form of duty, the Authority notes that the duty has already been recommended on fixed from basis and does not find any reason to modify the same.

Conclusion:

253. Having given opportunity in terms of the orders of Hon'ble CESTAT to all the parties to make oral as well as written submissions, the Authority has examined the same in the paras given above. After having examined the submissions of all the parties, the Authority confirms the conclusions arrived at earlier and indicated in the final findings dated 17th May 2010.
254. The Authority therefore confirms its earlier recommendation of imposition of the definitive anti-dumping duties on the subject goods from the date of notification issued in this regard by the Central Government on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries. The Authority further concludes that no change to the relevant Government of India, Ministry of Finance's Notification is warranted.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority